सत्यमेव जयते

भारत सरकार

परिणाम बजट
2010-2011

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1
बाल फिल्म समिति, भारत 2
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 2
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 3
फिल्म समारोह निदेशालय 3
फिल्म प्रभाग 4
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी 4
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 5
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 5
भारतीय जनसंचार संस्थान 5
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 6
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 6
पत्र सूचना कार्यालय 7
भारतीय प्रेस परिषद 8
फोटो प्रभाग 10
प्रकाशन विभाग 10
एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 11
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 11
गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 11
गीत एवं नाटक प्रभाग 12
एफ.एम. रेडियो (निजी) 12
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 13
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 13
सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां 13
सूचना भवन का निर्माण 14
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 14
मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण 14
प्रसार भारती 15

अध्याय - I

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 19
बाल फिल्म समिति, भारत 20
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 21
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 22
फिल्म समारोह निदेशालय 22
फिल्म प्रभाग 23
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी 23
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 24
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 26
भारतीय जनसंचार संस्थान 30
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 32
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 32
पत्र सूचना कार्यालय 33
भारतीय प्रेस परिषद 35
फोटो प्रभाग 36
प्रकाशन विभाग 36
एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 43
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 44
गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 44
गीत एवं नाटक प्रभाग 46
एफ.एम. रेडियो (निजी) 47
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 47
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 47
सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां 47
सूचना भवन का निर्माण 48
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 48
मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण 48
प्रसार भारती 49

अध्याय - II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 55
बाल फिल्म समिति, भारत 57
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 58
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 62
फिल्म समारोह निदेशालय 63
फिल्म प्रभाग 66
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी 68
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 70
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 76
भारतीय जनसंचार संस्थान 82
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 84
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 85
पत्र सूचना कार्यालय 86
भारतीय प्रेस परिषद 90
फोटो प्रभाग 91
प्रकाशन विभाग 95
एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 97
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 100
गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 102
गीत एवं नाटक प्रभाग 107
एफ.एम. रेडियो (निजी) 111
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 112
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 113
सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां 114
सूचना भवन का निर्माण 115
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 116
मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण 117
प्रसार भारती 118

अध्याय - III

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 142

बाल फिल्म समिति, भारत 142
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 142
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 143
फिल्म समारोह निदेशालय 143
फिल्म प्रभाग 143
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी 144
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 144
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 145
भारतीय जनसंचार संस्थान 145
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 145
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 146
पत्र सूचना कार्यालय 146
भारतीय प्रेस परिषद 147
फोटो प्रभाग 148
प्रकाशन विभाग 148
एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 149
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 149
गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 150
गीत एवं नाटक प्रभाग 150
एफ. एम. रेडियो (निजी) 151
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 151
अन्तर्राष्ट्रीय चैनल 151
सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां 152
सूचना भवन का निर्माण 152
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 153
मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण 153
प्रसार भारती 153

अध्याय - IV

पिछले कार्यप्रदर्शन की समीक्षा

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 156
बाल फिल्म समिति, भारत 159
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 160
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 161

फिल्म समारोह निदेशालय 165
फिल्म प्रभाग 167
भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी 169
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 170
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 171
भारतीय जनसंचार संस्थान 172
भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय 175
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड 176
पत्र सूचना कार्यालय 177
भारतीय प्रेस परिषद 180
फोटो प्रभाग 183
प्रकाशन विभाग 184
एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 189
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक 190
गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग 194
गीत एवं नाटक प्रभाग 198
एफ. एम. रेडियो (निजी) 201
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र 203
अंतर्राष्ट्रीय चैनल 204
सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां 205
सूचना भवन का निर्माण 206
विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना) 207
मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 208
प्रसार भारती 209

अध्याय - V - वित्तीय समीक्षा 248

अध्याय - VI - स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और कार्य-निष्पादन

बाल फिल्म समिति, भारत 267
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 268
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 269
भारतीय जन संचार संस्थान 271
भारतीय प्रेस परिषद 272
प्रसार भारती 273

कार्यकारी सारांश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपने जनसंचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रकाशन संस्थानों, विज्ञापनों और नृत्य एवं नाटक जैसे परंपरागत माध्यमों के ज़रिये लोगों तक सूचना पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मंत्रालय राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन, महिलाओं बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित मामलों के प्रति ध्यान दिलाने के लिये विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की बौद्धिक जरूरतों और मनोरंजन करने का कार्य करता है। मंत्रालय को तीन घटकों में बांटा गया है – सूचना स्कंध, प्रसारण स्कंध और फिल्म स्कंध।

मंत्रालय के कार्य विभाजन नियम के अनुसार इस प्रकार है:

– देश में विभिन्न जन माध्यमों के स्वस्थ विकास के लिये नीतिगत ढांचा तैयार करने और उसके लिये समुचित वातावरण तैयार करना।

– जन माध्यमों के जरिये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देना।

– सरकार की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां और कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना।

– सूचना और प्रसार के क्षेत्र में राज्य सरकारों और उसके संगठनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

– सरकार और मीडिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना और केन्द्र सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित प्रमाणिक आंकड़े और अधिकारिक सूचनाएं पहुंचाना।

मंत्रालय मीडिया इकाइयों द्वारा दिये जा रहे समाचारों और विचारों के प्रभावी प्रचार के लिये नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। हालांकि मीडिया इकाइयों को स्वायत्त रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता है। मंत्रालय इन इकाइयों के बीच समन्वय, सहायता, निगरानी और नियंत्रण रखता है ताकि इन इकाइयों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। विभिन्न मीडिया इकाइयां लोगों की आवश्यकता लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई तरह के कार्यक्रम तैयार करती हैं।

मंत्रालय अपने अधीन 14 कार्यालयों और छह स्वायत्त संगठनों और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता से कार्य करता है।

मंत्रालय के अधीन कार्यालयों, स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति और विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय ने सभी संबद्ध आंकड़े वेबसाइट www.cbfcindia.gov.in के जरिए इंटरनेट पर उपलब्ध कराए हैं। इनमें बजट आबंटन, सीबीएफसी के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा आहरित मूल वेतन सहित कुल आहरित वेतन संबंधी आंकड़े भी शामिल हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 के मद्देनजर इसे द्विभाषी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की सभी खरीद की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। ऐसा करते समय क्षेत्रीय प्रमुखों से भी सलाह-मशवरा किया जाता है। उन्हें धन आबंटित करने से पहले भी उनका परामर्श लिया जाता है।

बाल फिल्म समिति, भारत

बाल फिल्म समिति, भारत की स्थापना 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत मई, 1955 में हुई थी। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्तशासी निकाय के तौर पर कार्य करती है और इसे अपनी योजना और गैर योजना गतिविधियों के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। बाल फिल्म समिति, भारत (सीएफएसआई) बच्चों को मूल्यपरक मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही फिल्मों के माध्यम से उनकी मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है।

इसका अध्यक्ष, सिनेमा के क्षेत्र की किसी प्रतिष्ठित हस्ती को बनाया जाता है। अध्यक्ष कार्यकारी परिषद तथा आम सभा का भी प्रमुख होता है जिसके सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सभी विभागों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के तहत कार्य करते हैं। कार्यकारी अधिकारी प्रशासन, निर्माण, विपणन और लेखा विभाग की दैनिक गतिविधियों का संचालन करता है। समिति का मुख्यालय मुंबई में तथा शाखा कार्यालय नई दिल्ली और चेन्नई में हैं।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में आमलोगों को जानकारी देना और लक्षित समूहों में विशेषकर दूर दराज के लोगों में स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

सूचना को और तीव्र गति से तथा प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय मल्टीमीडिया प्रोजेक्टरों, डीवीडी प्लेयरों और वायरलेस पब्लिक ऐड्रेस प्रणालियों आदि के माध्यमों, फिल्म प्रदर्शनों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि का उपयोग करता है। प्रचार के लिए यह विभिन्न भाषाओं में अनेक विषयों पर अलग-अलग माध्यमों-फिल्म प्रभाग, एनएफडीसी, सीएफडी, आदि के माध्यम से फिल्मों और कैसेटों की खरीद भी करता है। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय देश भर की सभी 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाईयों के लिए उपकरणों, नवीनतम कम्प्यूटरों के साथ-साथ अन्य सहायक उपकरणों का भी खरीद करता है और उन्हें इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराता है जिससे वे एक-दूसरे के साथ अच्छी तरह से संपर्क कायम रखें और जब भी आवश्यकता पड़े, तत्काल सूचना उपलब्ध करा सकें। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के काम-काज की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए देश भर से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं। व्यय की स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय से समय-समय पर व्यय विवरणों और तिमाही कार्य निष्पादन रिपोर्टें भी मंगाई जाती हैं। किसी महीने के कार्यक्रम के विभिन्न स्वरूपों का इस्तेमाल करके चलाए गए कार्यक्रमों की संख्या के बारे में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय से भी इसी प्रकार की रिपोर्टें मंगाई जाती हैं और किसी अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में उनकी जांच परख भी की जाती है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की वेबसाइट को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है और ऐसी सभी तर्कसंगत सूचनाओं को साइट में सम्मिलित कर लिया जाता है ताकि आमलोग आसानी से उन तक पहुंच सकें।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और प्रचार निदेशालय भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रचारित करने वाली नोडल मल्टी मीडिया एजेंसी है। यह प्रेस विज्ञापनों, टीवी स्पॉट तथा केबल और सेटेलाइट नेटवर्क चैनलों, रेडियो/टेलीविजन पर प्रायोजित कार्यक्रमों, स्पॉट/जिंगल्स, डिजीटल सिनेमा, प्रदर्शनियों, मुद्रित प्रचार सामग्रियों और बाहरी प्रचार माध्यमों की सहायता से केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रचार अभियान चलाती है। केन्द्र सरकार प्रचार कार्यक्रमों को मजबूत बनाने और अपनी सेवाओं को प्रभावी रूप से चलाने के लिए दो नियोजित योजनाएं, 1. विकास प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार (जारी योजना) और 2. डीएवीपी का आधुनिकीकरण (नई योजना) को 11वीं योजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई है। सरकार में प्रचार और विज्ञापनों के विभिन्न पहलुओं को सुव्यवस्थित करने और इस काम में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने मुद्रित माध्यम के लिए नई विज्ञापन नीति लागू की है। इसी प्रकार की नीति आडियो-विजुअल माध्यम में इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए विज्ञापन/प्रचार करने के लिए बनाई गई है। डीएवीपी की वार्षिक योजना के तहत निर्देशित लक्ष्यों का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ योजनाबद्ध कार्यक्रमों पर वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों की समीक्षा के जरिए निरंतर मानीटरिंग की जाती है।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) के माध्यम से तीन योजना स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

(1) भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों के माध्यम से निर्यात संवर्धन

(2) सीरीफोर्ट सांस्कृतिक परिसर में संयोजन और बदलाव

(3) प्रिंट यूनिट का उन्नयन

स्कीमों के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- देश के अंदर अच्छे भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना तथा उत्कृष्ट भारतीय फिल्मों को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना।
- समारोहों में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय निर्देशकों की फिल्मों का प्रदर्शन।

फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना देश में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने के लिए की गई थी। डीएफएफ विदेशी समारोहों में भारत की भागीदारी में मदद करता है। भारत में विदेशी फिल्मों तथा विदेश में भारतीय फिल्मों के कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित करता है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साधन के रूप में, डीएफएफ अंतर्राष्ट्रीय मित्रता को बढ़ावा देता है, विश्व सिनेमा में नए आयामों तक पहुंच मुहैया कराता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करता है और इस प्रक्रिया में, भारतीय फिल्मों का स्तर सुधारने में मदद करता है।

डीएफएफ निम्नलिखित प्रमुख आयोजन करता है :

(1) भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

(2) भारतीय पैनोरमा का चयन

(3) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

(4) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी

(5) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की स्थापना वृत्तचित्र, एनीमेशन, छोटी एवं कार्टून फिल्में बनाने के लिये की गई थीं जिन्हें जन सूचना, शिक्षा, प्रोत्साहन और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। फिल्म प्रभाग सिनेमा प्रायोजकों को सांविधिक तौर पर सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952 और अनेक राज्य नियमों के अंतर्गत 'पारित फिल्मों' के प्रदर्शन में सहायता देता है। फिल्म प्रभाग भारत में वृत्तचित्र निर्माण को भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्र निर्माताओं के जरिये प्रोत्साहन देता है, साथ ही यह वृत्तचित्रों, छोटी एवं एनीमेशन फिल्मों का मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) भी आयोजित करता है। फिल्म प्रभाग के अभिलेखागार में 8000 से अधिक फिल्में हैं जो सिनेमा प्रेमियों और सभी के लिए संदर्भ सामग्री के तौर पर उपलब्ध हैं। प्रभाग ने अपनी इन दुर्लभ फिल्मों को बड़े पर्दे से वीडियो में बदलने की शुरुआत कर दी है।

अपने मुंबई स्थित मुख्यालय और बंगलुरु, कोलकाता और नई दिल्ली स्थिति क्षेत्रीय निर्माण केंद्रों में फिल्म प्रभाग के पास प्रोडक्शन पूर्व एवं बाद की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में फैली इसकी 10 शाखाएं फिल्म-प्रेमियों की जरूरतों को पूर्ण करने के साथ-साथ 12,000 सिनेमा घरों को सिनेमेटोग्राफी अधिनियम-1952 के अंतर्गत 'पारित' फिल्में सप्लाई करती हैं। फिल्म प्रभाग का मुखिया प्रमुख महानिदेशक होता है।

भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

इस मंत्रालय की दो मुख्य सचिवालय योजनाएं हैं अर्थात (I) विदेशी समारोहों/बाजारों में भागीदारी तथा (ii) एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना तथा वीएफएक्स। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा दोनों योजनाओं के लिए क्रमशः 11.0 करोड़ तथा 52.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दोनों योजनाएं मुख्य सचिवालय द्वारा लागू की जानी हैं।

2009-10 के दौरान योजना स्कीम 'भारत तथा विदेश में फिल्म समारोहों/बाजारों में भागीदारी' के लिए 2.20 करोड़ रुपये निर्दिष्ट किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को विदेश में बतौर निवेश विपणन करने और शूटिंग स्थल के रूप में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। साथ ही मंत्रालय का केंस फिल्म समारोह 2009, एन्नेसी फिल्म समारोह 2009, यूरोपीय फिल्म बाजार 2010; बर्लिन तथा फिल्म बाजार में भागीदारी का प्रस्ताव है। यह गोवा के भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2009 (आईएफएफआई) के अतिरिक्त है।

एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष 2009-10 के लिए 1 करोड़ रुपये निर्दिष्ट किए गए हैं। एक मानव संसाधन अध्ययन के पश्चात स्कीम के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए इस मंत्रालय ने योजना आयोग से संपर्क साधा था। योजना आयोग ने मंत्रालय से एफआर तथा डीपीआर दाखिल करने को कहा था। विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया जा चुका है और एफआर/डीपीआर तैयार करने के लिए मंत्रालय एक परामर्शक नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

अपने क्षेत्र का प्रमुख संस्थान होने के नाते भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी निभा रहा है। एफटीआईआई विभिन्न वर्गों में फिल्म एवं टेलीविजन प्रशिक्षण में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी आयोजित कर रहा है। यह वर्ग हैं- निर्देशन, सिनेमेटोग्राफी, ऑडियोग्राफी तथा संपादन, अभिनय, कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एमीमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी वीडियो संपादन तथा ऑडियोग्राफी और टेलीवजिन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में टेलीविजन का एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। कार्यरत पेशेवरों और संबंधित पसंद के लोगो के लिए एफटीआईआई विभिन्न लघु पाठ्यक्रम चलाता है।

अनुदान सहायता की किश्त जारी करने तथा शासी परिषद की बैठक के दौरान , स्थायी वित्त समिति इत्यादि के दौरान सस्थान के कार्य की निगरानी सरकार समय समय पर करती है। जिसमें इनके साथ सूचना और प्रसारम मंत्रालय के प्रतिनिधि भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) का मुख्य उद्देश्य फिल्म एवं टेलीविजन उद्योग के लिए प्रशिक्षित और सृजनशील पेशेवर प्रदान करना है।

संस्थान निर्देशन एवं पटकथा लेखन,चलचित्र फोटोग्राफी, एडीटिंग एवं साउंड रिकार्डिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। मुख्य धारा के पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान स्व-वित्त पोषित आधार पर लघु अवधि पाठ्यक्रम संचालित/प्रस्तावित करता है। फिल्म एवं टेलीविजन की समाजिक, संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा खोजी अध्ययन एसआरएफटीआई में फोकस का एक और क्षेत्र है।

संस्थान के कार्य की निगरानी सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है। अनुदान सहायता जारी करने और शासी परिषद, स्थाई वित्त समिति इत्यादि की बैठकों के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा का ऑडिट किया हुआ विवरण से इसका निष्पादन संतोषजनक पाया गया है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारत सरकार ने वर्ष 1965 में भारतीय जन संचार की स्थापना की थी। यह संस्थान 18.8.1966 को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम (XXI), 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में दर्ज किया गया था।

भारतीय जन संचार संस्थान के मुख्य लक्ष्य हैं देश के सामाजिक - आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में जन संचार के मीडिया के प्रयोग एवं विकास में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध का आयोजन करना।

भारत सरकार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से कुल वार्षिक मदद अनुदान के रूप में इस संस्थान को वित्त प्रदान करता है।

भारतीय जन संचार संस्थान के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स आम लोगों के लिए खुले हैं और लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यह संस्थान विदेश मंत्रालय के सहयोग से विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान विकास पत्रकारिता में दो कोर्सों का आयोजन करता है।

यह संस्थान भारतीय सूचना सेवा (आई आई एस) के ग्रुप 'ए''और ग्रुप 'बी' के परिक्षार्थियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों के अधिकारियों के लिए और आम लोगों के लिए भी कई अन्य अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई आई एम सी को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया विश्व विद्यालय में बदलने के लिए सिद्धांतत: मंजूरी दे दी है।

भारतीय जनसंचार संस्थान की वेबसाइट (www.iimc.gov.in) आम लोगों के लिए उपलब्ध है और वे इस वेबसाइट के माध्यम से आई आई एम सी की सारी गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

11वीं योजना (2007-2012) के दौरान भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पास 30 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निम्नलिखित अनुमोदित योजना स्कीमें हैं :-

'अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति और प्रदर्शन'

एनएफएआई की योजना स्कीमों की प्रगति की निगरानी मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक वास्तविक और वित्तीय प्रगति विवरणों के माध्यम से की जाती है जो नियमित रूप से मंत्रालय को भेजे जाते हैं। विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत एनएफएआई द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों में हुई प्रगति की सूचना एनएफएआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इस मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न है।

1. निर्देशक की पहली फीचर फिल्म के निर्माण की शत-प्रतिशत जिम्मेदारी उठाकर नयी प्रतिभा को बढ़ावा देना,
2. नयी फिल्म पटकथा के विकास में सहायता प्रदान करना
3. भारतीय और विदेशी फिल्म निर्माताओं के साथ व्यावसायिक तौर पर बेहतरीन गुणवत्ता वाली फिल्मों का सहनिर्माण करना,
4. भारतीय सिनेमा कलाकार कल्याण निधि (सीएडब्ल्यूएफआई) के जरिये जरूरतमंद सिनेमा कलाकारों के लिये कल्याणकारी उपाय करना तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिये मदद करना।

निगम को क्षेत्रीय फिल्म निर्माण में सक्षम बनाने के उद्देश्य से ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिये 30 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके लिये राज्य सरकार से राज्य विकास निधियों की जरूरत होगी ताकि उन्हें जो मदद चाहिये वह दी जा सके। वर्ष 2008-09 के दौरान ''विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण'' की योजना के तहत 6.50 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटन था जिससे एनएफडीसी ने 7 फिल्में निर्मित की हैं। इनमें से 5 बन चुकी हैं 2 निर्माणोत्तर स्थिति में हैं। वर्ष 2009-2010 के लिये 7.84 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान आबंटित किया गया है। 6.50 करोड़ रुपये निगम को जारी कर दिए गए हैं। योजना स्कीम " विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण" के अंतर्गत एनएफडीसी का लक्ष्य 2009-10 में पांच फिल्में बनाने का है। चूंकि ये फिल्में जिस लागत में बनती हैं उस हिसाब से उनका उतना बाजार मूल्य नहीं होता है और इसलिये ऐसी फिल्मों पर निवेश के एक हिस्से की पूर्ति निगम के सहयोग से होती है इसलिये ऐसी क्षेत्रीय फिल्मों का विकास पूरी तरह से मुनाफे की दृष्टि को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि विकासवादी लक्ष्यों के लिये होना चाहिये।

पत्र सूचना कार्यालय

लोगो का सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की अग्रणी संस्था है। मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) के साथ संवाद के प्रमुख सरकारी चैनेल के रूप में पत्र सूचना कार्यालय इस मूल विचार के साथ काम करता है कि लोकतंत्र में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी नीतियां और कार्यक्रम प्रेस और अन्य मीडिया के जरिए सही और उपयुक्त तरीके से उन लोगो तक पहुंचे जिनके समर्थन और विश्वास पर वह सत्ता में है।

पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय के अधिकारी मीडिया को सूचना प्रदान करने और फीड बैक उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध किए जाते हैं। वे मीडिया परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं और प्रचार कार्य का समन्वयन करते हैं।

इसके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए जुड़े हैं। कार्यालय का इंटरनेट पर एक होमपेज भी है जिसे www.pib.nic.in पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए प्रचार सामग्री इस होमपेज पर डाली जाती है। पीआईबी की प्रेस विज्ञप्तियां अब कम्पयूटर के जरिए स्थानीय समाचार पत्रों, महत्वपूर्ण बाहरी समाचार पत्रों के स्थानीय संवाददाताओं और इसके क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भेजी जाती हैं। विशेष लेख और ग्राफिक्स आदि भी इंटरनेट के साथ-साथ पीआईबी नेटवर्क के जरिए जारी किये जाते है।

यह कार्यालय मीडिया प्रतिनिधियों को पेशागत सुविधाएं उपलब्ध करता है। इसके लिए यह भारतीय और विदेशी मीडिया प्रतिनिधियों, न्यूज कैमरामैनों और तकनीशियनों को प्रत्यायन उपलब्ध कराता है। दिसंबर 2009 तक 1618 संवाददाता, 476 कैमरामैन, 152 तकनीशियन और 84 सम्पादक मीडिया समीक्षक इसके मुख्यालय से प्रत्यायित थे। भारतीय और विदेशी संवाददाताओ की आवश्कताओं को पूरा करने के लिए पीआईबी का नई दिल्ली में आधुनिक संचार सुविधाओ वाला एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र कार्यरत है।

मीडिया को जानकारी प्रदान करने के लिए यह कार्यालय विभिन्न तरीके अपनाता है—प्रेस विज्ञाप्तियों और विशेष लेख, प्रेस ब्रीफिंग्स, संवाददाता सम्मेलन और प्रेस टूर।

प्रेस विज्ञप्तियों, संवाददाता सम्मेलनों, विशेष लेखो आदि के संदर्भ में पीआईबी के कार्य निष्पादन की निगरानी तत्काल की जाती है और यह समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की संख्या से परिलक्षित होती है। पीआईबी के कार्य की देख-रेख सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत अन्य मीडिया इकाइयों की ही भांति की जाती है।

समग्र निष्पादन

वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान स्वीकृत प्रावधान 2503 लाख रुपये का है। दिसंबर 2009 तक योजना के अंतर्गत 490 लाख रु. व्यय किये गये। वर्ष 2009-10 के दौरान (दिसंबर 2009 तक) वित्तीय संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय का प्रदर्शन इस प्रकार रहा।

(लाख रुपये में)

क्र.सं.		योजना	गैर-योजना	कुल
1.	बजट अनुमान 2009-10	2503.00	3422.00	5925.00
2.	संशोधित अनुमान 2008-09	2403.00	3726.00	6129.00
3.	वास्तविक खर्च दिसंबर 2009 तक	490.00	3110.41	3600.41
4.	बजट अनुमान 2010-11	4650.00	3688.00	8338.00

भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद संसद के उस विश्वास को सुदृढ़ करने वाली संस्था है जो प्रेस के अन्य स्तर और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा का वचन देती है। यह एक अर्द्ध न्यायिक संस्था है जिसके परामर्शदायी और नियामक उत्तरदायित्व भी हैं। 2009-10 के दौरान इसकी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

अर्द्ध न्यायिक कार्य : 655 मामले पंजीकृत, 367 मामले निपटाए गए और 288 मामलों में सुनवाई अग्रिम स्थिति में है।

प्रेस का स्तर : अधिनियम की धारा 13(2)(ग) के अंतर्गत प्रेस हेतु आचरण संहिता तैयार की गई।

प्रेस की स्वतंत्रता : स्व संज्ञान हस्तक्षेपों, निर्णयों, राज्यों आदि के जरिए प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों की निगरानी की गई।

स्वयं सज्ञान : परिषद ने चेन्नई में देनामलार के समाचार सम्पादक की गिरफ्तारी पर स्वयं सज्ञान लेते हुए घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया। दिनामलार के सम्पादक और तमिलनाडू सरकार के मुख्य सचिव एवं सचिव गृह (पुलिस) विभाग से भी टिप्पणी मांगी गयी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मीडिया को पूर्ण सुरक्षा देने तथा न्याय सुनिश्चित करने की अपनी सरकार की प्रतिवद्धता दोहराई। मामला प्रक्रियाधीन है।

परामर्शदायी कार्य : इन विषयों पर राय दी गई : द्वितीय एआरसी - 8वीं रिपोर्ट-आतंकवाद निरोधी टिप्पणी; अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग; राज्यों में प्रेस परिषद की शाखाओं की स्थापना; पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का सम्मेलन 2007; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ तथा विशेष कार्यबल (उप्र.) लखनऊ के एसएसपी श्री अमिताभ व्यास की शिकायत।

प्रेस की कार्यप्रणाली की निगरानी : प्रेस संबंधी मामलों की सतत् दिन-प्रतिदिन निगरानी।

समाचारों के लिए भुगतान

- परिषद ने 9.6.2009 को आयोजित एक बैठक में अप्रैल/मई 2009 में लोकसभा चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के कवरेज के लिए मीडिया द्वारा अनैतिक भुगतान लेते/प्राप्त करने संबंधी अभिवेदनों पर विचार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में एक उप-समिति गठित कर दी गई है जो चुनाव आयोग सहित सभी पत्रकारों के विचार/सबूत इकट्ठा करेगी।
- मीडिया ट्रायल, स्टिंग आपरेशन और फोटो पत्रकारिता पर मार्गनिर्देश तैयार किए गए।
- बटला हाउस मुठभेड़ की मीडिया कवरेज पर रिपोर्ट स्वीकार की गई।

अंतर्राष्ट्रीय बातचीत

परिषद विश्व के विभिन्न भागों की समान संस्थाओं और प्रेस/मीडिया की समस्याओं को समझने और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में मशविरा देने के लिए उनसे लगातार विचार-विमर्श करती रहती है।

प्रेस एवं पंजीकरण अपीली बोर्ड (पीआरबी): पीआरबी एक्ट 1867 की धारा 8(ग) के अंतर्गत संसद द्वारा दिए गए अतिरिक्त उत्तरदायित्व "प्रेस एवं पंजीकरण अपीली बोर्ड" का कार्य भी संतोषप्रद तरीके से निपटाया गया।

वित्तीय परिव्यय : परिषद अपनी वित्तीय आवश्यकताएं नोडल मंत्रालय के जरिए संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान से पूरा करती है। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि समाचारपत्रों से शुल्क वसूल कर प्राप्त की जाती है। वर्ष 2009-10 के दौरान परिषद के समक्ष गंभीर वित्तीय संकट रहा जिसकी वजह से इसे अपने कई कार्यों को टालना/छोड़ देना पड़ा।

प्रेस परिषद ने ने अपना काम दक्षतापूर्वक करते हुए मीडिया और आम लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसने अपनी क्षमता और कार्यप्रणाली के प्रति सम्मान प्राप्त किया है। साथ ही, वित्तीय दृष्टि से लगभग पूरी तरह सरकार पर आश्रित होने के बावजूद यह सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त रहने में सफल रही है।

लक्ष्य : 2010-11

- 1979 से प्रेस परिषद द्वारा आरंभिक चरण पर निपटाई गई शिकायतों का डेटाबेस तैयार करना;
- पुस्तकें जारी करने और लौटाने सहित सभी विवरणों के साथ पुस्तकालय के रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण;
- 2009-10 में दिए गए निर्णयों का हिंदी अनुवाद कराना;
- प्रेस की आज़ादी के बारे में धारा 13 (2) (ख) के अंतर्गत शर्तों का नवीनीकरण;
- 2009-10 के बचे हुए लक्ष्यों की पूर्ति।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग भारत सरकार की एक मीडिया इकाई है जो आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए फोटोग्राफ्स तैयार करने और दृश्य प्रलेखन के लिए उत्तरदायी है। फोटो प्रभाग देश के विकास के विभिन्न पहलुओं और ऐतिहासिक घटनाओं का रिकार्ड रखता है तथा देश को एक समग्र फोटोग्राफिक दस्तावेज उपलब्ध कराता है। यह फोटो प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करता है। प्रभाग की एक मूल्य योजना भी है जिसके अंतर्गत आम जनता को भुगतान करने पर फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाते हैं। फोटोग्राफिक उद्योग की बदलती प्रवृत्तियों के मद्देनजर, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र नामक एक प्लान योजना कार्यान्वित की गई है जिससे प्रयोक्ताओं और ग्राहकों को बेहतर सेवा और गुणवत्ता दी जा सके और उनकी वर्तमान भागों को पूरा किया जा सके। पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान नाम से एक अन्य प्लान योजना भी शुरू की है। इस योजना में इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के सबसे बड़े प्रकाशन भवनों में से एक है। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशन विभाग द्वारा निकलने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उनके माध्यम से इस देश के लोगों की समझ का विकास हो सके।

प्रकाशन विभाग का कार्य है लोकप्रिय पुस्तकों और पत्रिकाओं का उत्पादन, बिक्री और वितरण करना। अपने कार्य के द्वारा यह विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है :

(i) राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुस्तकों का प्रकाशित करना जिन विषयों पर अन्य प्रकाशकों ने ध्यान नहीं दिया हो और ऐसी पुस्तकों को कम कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध बनाना।

(ii) विविधता में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि की विचारधारा और आत्मा को मजबूत करना और बढ़ावा देना।

(iii) वर्ष 2010-2011 के दौरान प्रकाशन विभाग निदेशालय ने 20 पत्रिकाएं और 100 पुस्तकें प्रकाशित करने का लक्ष्य बनाया है। प्रकाशन विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित बिक्री केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं को बेच रहा है। समय के साथ चलने के लिए प्रकाशन विभाग ने चरणबद्ध तरीके से अपने बिक्री केंद्रों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव किया है क्योंकि ये बिक्री केंद्र ढीली-ढाली स्थिति में है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था को दर्शाते हैं जबकि इसकी तुलना में इसके प्रतिद्वंदी प्रमुख इलाकों में स्थित सुव्यवस्थित शोरुमों के माध्यम से अपनी किताबें बेच रहे हैं।

(iv) प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्र नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरुअनंतपुरम में स्थित हैं। बिक्री के आउटलेट बंगलुरु, गुवाहाटी और अहमदाबाद में स्थित हैं।

(v) वर्ष 2010-2011 के लिए बजट आकलन गैर योजना में 2104.00 लाख रुपये और योजना में 20.00 लाख रुपये है।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

साप्ताहिक रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, विदेशी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, ब्रिटिश काउंसिल आदि में नौकरियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रवेश अधिसूचनाएं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे संगठनों तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों की परीक्षा अधिसूचनाएं और उनके परिणामों तथा मध्य-स्तरीय रोजगार उन्नयन के अवसरों (प्रतिनियुक्तियों) की सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादकीय हिस्सा भी है जो कैरियर से सम्बन्धित दो मुख्य लेख प्रकाशित करता है।

रोजगार समाचार प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य समूह सिविल सेवा के अभ्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों में बैठने वाले तथा रोजगार अवसरों की खोज में जुटे युवा लोग हैं।

इस साप्ताहिक पत्र का उद्देश्य इसको पढ़ने वाले लोगों को जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने लिए सर्वोत्तम उपलब्ध कैरियर चुन सकें।

रोजगार समाचार की रोजगार उन्मुख वेबसाइट employmentnews.gov.in है। वेबसाइट अभूतपूर्व सफल है और नौजवानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस वेबसाइट को रोज करीब तीन लाख लोग सर्च करते हैं।

भारत के समाचारपत्र के पंजीयक का कार्यालय

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण कानून, 1867 के अन्तर्गत देश में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का अद्यतन रिकार्ड तथा आंकड़े संभाल कर रखता है, नये प्रकाशनों के लिए शीर्षक उपलब्ध कराता है, पंजीकरण के प्रमाणपत्र जारी करता है, प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रसार दावों की समीक्षा करता है तथा 'भारत के समाचारपत्र' नामक शीर्षक से प्रिंट मीडिया के हालात पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। आरएनआई समाचारपत्रों के प्रसार के दावों पर भी नियन्त्रण रखता है। अपने वैधानिक कार्यों के अलावा, यह कार्यालय अखबारी कागज के आयात के लिए समाचारपत्रों को पात्रता प्रमाणपत्र जारी करता है। इसके अलावा, आरएनआई समाचारपत्रों द्वारा अपेक्षित प्रिंटिंग मशीनरी तथा सम्बद्ध सामग्री के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करता है।

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यालय है। इस प्रभाग की भूमिका मीडिया इकाइयों को शोध के संबंध में एकत्रित, संकलित और तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करना है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सारांश निर्मित करना और सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन एवं पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है।

यह प्रभाग प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को कोई सेवा प्रदान नहीं करता है। वास्तविक लक्ष्यों को सामान्यत: वार्षिक बजट योजना के रूप में बनाया जाता है और इनकी इस प्रभाग द्वारा निगरानी की जाती है।

सार्वजनिक सूचना प्रणाली के संबंध में प्रभाग की वेबसाइट rrtd.gov.in जन अधिकार के क्षेत्र में आती है और आम जनता इसे देख सकती है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में आकाशवाणी की एक इकाई के रूप में की गई थी और 1956 में इसे विकासात्मक संचार की अनिवार्यता के साथ ही स्वतंत्र मीडिया इकाई का दर्जा दे दिया गया। इस विभाग की स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- देश की प्रगति में सहायक सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों और आदर्शों को लोगों के बीच पहुंचाने और जागरुकता जगाने के लिए।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच रक्षात्मक भावना और देश के अन्य भागों के लोगों के साथ उनके सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए।
- लोक कलाओं और शहरी कलाओं दोनों के माध्यम से दूरदराज के कठिन इलाकों में तैनात सेना के जवानों में साहस का संचार करने के लिए।

गीत एवं नाटक प्रभाव प्रदर्शन कलाओं को संचार माध्यम के साथ इस्तेमाल करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन है। प्रभाग नाटक, नृत्य नाटिका, गीत नाट्य, लोक कलाओं, पारंपरिक गीतों, कठपुतली कला जैसी कलाओं का प्रदर्शन करता है। प्रभाग सांप्रदायिक सदभाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करने के लिये, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्शखा जैसे विषयों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गीत एवं नाट्य कार्यक्रम आयोजित करता है।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

भारत सरकार ने 1999 में निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो का क्षेत्र खोलने की नीति का शुभारम्भ किया था और 11 चरण के अंतर्गत 2005 में इसका और विस्तार किया गया। नीति के अंतर्गत यह अनिवार्य बना दिया गया कि जहां कहीं प्रसार भारती के टावर से संप्रेषण सुविधा साथ-साथ प्राप्त की जा सकेगी वहां से उसे प्राप्त कर लिया जाएगा लेकिन जहां प्रसार भारती के टावर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे वहां सरकार निजी एफ एम प्रसारकों के लिए मेसर्स बेसिल के माध्यम से नए टावरों का निर्माण कराएगी। चरण II के अंतर्गत चिह्नित 91 शहरों में से 84 शहरों में प्रसार भारती के टावर हैं और बाकी 7 नगरों जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु और जयपुर में नए टावरों के लिए प्रस्ताव किया गया था।

2. निजी एफएम रेडियो नामक एक योजना के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मेसर्स के माध्यम से 18.18 करोड़ रुपये की कुल लागत से सात शहरों में नए टावरों के निर्माण का प्रस्ताव किया था जिसे योजना आयोग ने 2006 में स्वीकृत किया। जैसा कि प्रसार भारती टावरों के मामले में प्रसार भारती करता है, इन टावरों की निर्माण की लागत वार्षिक किराए के माध्यम से निजी एफएम प्रसारकों से वसूल करके पूरी की जाएगी। तत्पश्चात् दो अन्य शहरों में प्रसार भारती के टावर उपलब्ध कराए गए। इस बीच सरकार ने देहरादून में एक नया टावर लगाने का फैसला किया क्योंकि वहां कोई प्रसार भारती का टावर उपलब्ध नहीं था। इसलिए दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद और देहरादून जैसे 6 शहरों में नए टावरों के निर्माण की आवश्यकता हुई। दसवीं योजना में इसके लिए प्लान योजना वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए स्वीकृति दी गई। चूंकि योजना आयोग की सैद्धान्तिक मंजूरी जनवरी 2006 में प्राप्त हुई और अग्रिम राशि मार्च 2006 में जारी की गई इसलिए वास्तविक कार्य अप्रैल 2006 से ही शुरू हो सका। इसके अलावा बेसिल को साइट सौंपे जाने तक देरी के कारण परियोजना परिकल्पित अवधि मार्च 2007 तक पूरी नहीं हो सकी। पांच शहरों जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली और देहरादून में टावरों का निर्माण पूरा हो गया है। दो शहरों के लिए टावरों के निर्माण का इरादा छोड़ दिया गया और देहरादून के लिए एक टावर बाद में जोड़ा गया इसलिए 6 शहरों में टावरों के निर्माण के लिए परियोजना की कुल संभावित लागत 13.1124 करोड़ रुपये ठहरती है। 9.73 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि मेसर्स बेसिल को मार्च 2009 तक जारी कर दी गई। 2009-10 के लिए 2.0 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई है जिसमें से चालू वर्ष के दौरान बेसिल के लिए 1.08 करोड़ रुपये (लगभग) की रकम जारी कर दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अनुश्रवण केन्द्र (जिसे पहले केन्द्रीय अनुश्रवण केन्द्र कहा जाता था) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी-

(i) भारत में डाउनलिंक किए जा रहे सभी टीवी चैनलों का अनुश्रवण ताकि केबल टेलीविजन (विनियमन), अधिनियम, 1995 और इसके तहत बने नियमों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन को रोका जा सके।

(ii) इसी प्रकार निजी एफ-एम रेडियो चैनलों का अनुश्रवण; और

(iii) सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारण क्षेत्र की विषय वस्तु के अनुश्रवण से संबंधित कार्य करना शामिल है।

वर्ष 2010-11 के लिए योजना के तहत 2.18 करोड़ रुपये की राशि और गैर योजना के तहत 4.10 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय चैनल

भूमंडलीकरण के युग में किसी भी देश के खास तौर पर भारत जैसे देश के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है अंतर्राष्ट्रीय चैनल को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। बीबीसी, सीएनएन इत्यादि विश्व के अत्यंत ही प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं। मुख्य उद्देश्य है भारत की स्थिति का दुनिया भर में उसी प्रकार प्रचार करना जिस तरह से अलजजीरा, बीसीसी, सीएनएन, सीसीटीवी इत्यादि चैनल करते हैं। इसके लिए डीडी इंडिया, जिसे बहुत से देशों में देखा जाता है, पर प्रसारण के साथ-साथ वर्तमान डीडी न्यूज चैनल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी।

सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां

रेडियो देश के सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में जन संचार माध्यम के रुप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है खासकर जबकि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में नियमित तथा लगातार बिजली की सप्लाई के अबाव में लोगों को सूचना पाने, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए रेडियो पर आश्रित होना पड़ता है। सामुदायिक रेडियो, सार्वजनिक प्रसारण सेवा से भिन्न, एक छोटे समुदाय को करीब लाता है तथा आम आदमी के रोजमर्रा की चिंताओं पर फोकस कर स्थानीय

एक तरह से हम कह सकते है सामुदायिक रेडियो का लक्ष्य स्थानीय समुदाय के जीवन को ध्यान में रखकर विषयों का चुनाव उस समुदाय की जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि, ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास के मुद्दों पर केंद्रित होगा। विषय सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय मुद्दों पर आधारित हो सकता है तथा इसके फारमेट, विषय, प्रस्तुति तथा भाषा में स्थानीयता की झलक तथा खुशबू का प्रभाव रहेगा। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने आम जनता के बीच नीतियों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को चलाने के लिए कार्यशालाएं तथा सेमिनार का आयोजन करने का प्रस्ताव है।

सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन का निर्माण सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक प्रमुख परियोजना है। मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों को यथोचित स्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से, यह निर्णय किया गया कि विभिन्न स्थलों पर बिखरे मीडिया इकाइयों के कार्यालयों (आकाशवाणी महानिदेशालय और दूरदर्शन महानिदेशालय के अतिरिक्त) को एक स्थान पर लाने के लिये मंत्रालय को स्वयं का एक भवन निर्मित करना चाहिए। योजना आयोग ने इस योजना को मंजूर किया और इसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया। तदनुसार, 1981 में मंत्रालय को लोधी रोड के एनवलप संख्या 8 पर 8364.3 वर्गमीटर आकार का भूमि का टुकड़ा आबंटित किया गया। हालांकि, इस पर निर्माण कार्य 1985 में शुरू हो पाया। वित्तीय बाधाओं के चलते, निर्माण कार्य चरणों में किया जा रहा है। इस भवन का निर्माण कार्य आकाशवाणी के सिविल कंस्ट्रक्शन विंग द्वारा किया जा रहा है। अब तक I, II, III और IV चरण पूरे हो चुके हैं। इन चार चरणों के तहत, केवल 38 प्रतिशत क्षेत्र (27,259 वर्ग मीटर) पर निर्माण कार्य हुआ है। सूचना भवन के निर्माण के चरण V के लिये कार्यवृत्त शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बचे हुए 62 प्रतिशत क्षेत्र (45,500 वर्गमीटर) पर निर्माण किया जायेगा।

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

अर्थव्यवस्था के तहत मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान उच्च वृद्धि की उम्मीद है। विकास की इस गति से लाभ उठाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र संबंधी विभिन्न स्कीम/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि निर्धारित लक्ष्यों/उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में इस नई स्कीम को लागू किया जा रहा है।

इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को विकसित करना।
- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों से संबंधित नियामक और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन करना।

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

11वीं योजना के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिये विदेशों में स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास का प्रशिक्षण संबंधी नई योजना शामिल की गई हैं। इसके लिये वर्ष 2010-11 में 150 लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है।

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश की एक सार्वजनिक प्रसारक सेवा है और उसके दो संघटक हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन। यह 23 नवंबर 1997 से अस्तित्व में आया। इस सेवा का उद्देश्य सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में सर्वसाधारण को जानकारी देना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना एवं देश में प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है।

संगठनात्मक ढांचा

निगम के मामलों का सामान्य निरीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारतीय बोर्ड करता है। बोर्ड समय-समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करता है एवं नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य निगम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं। सीईओ बोर्ड में इस तरह अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा और अपने सभी कार्य इस प्रकार करेगा जिस प्रकार अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रमुख के तौर पर कार्य करते हैं। बोर्ड के नीति निर्देश और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की दैनंदिन मामलों के प्रबंधन के लिए वे सदस्य(वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, प्रशासन, वित्त और समाचार के लिए व्यापक स्तर पर चार भिन्न खंड हैं।

आकाशवाणी

आकाशवाणी (एआईआर)प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में दिए गए प्रावधान के तहत कार्य करता है। 500 डब्ल्यू मीडियम वेव ट्रांसमीटर से शुरुआत करते हुए आकाशवाणी आज प्रमुख प्रसारक संगठन बन गया है। 375 रेडियो ट्रांसमीटर के सात यह 91.82 प्रतिशत क्षेत्र और 99.16 प्रतिशत आबादी के दायरे में फैला हुआ है। आकाशवाणी विभिन्न स्टेशनों पर अपने कार्यक्रम प्रसारणों के माध्यम से सर्वसाधारण को जानकारी देता है, उन्हें शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। ध्वनि प्रसारण के माध्यम से यह देश के सभी लोगों को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी देता है। इसके कार्यक्रम संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, महत्वपूर्ण समाचार और प्रासंगिक रुचि की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। यह राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रसारण के माध्यम से विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम संतुलित और निष्पक्ष हैं(अध्याय-1)।

वार्षिक योजना 2010-11 के लिए आकाशवाणी का प्रत्यक्ष बजट सहयोग 183.48 करोड़ रुपए है जिसमें 168.48 करोड़ रुपए पूंजी घटक के अंतर्गत एफएम सेवा के विस्तार, उत्तर पूर्व के विशेष पैकेज के तहत एफएम सेवा के विस्तार, आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए और 15 करोड़ रुपए सीमांत क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के दायरे को मजबूत करने और राजस्व फुटकर व राजस्व सॉफ्टवेयर के लिए सुनिश्चित हैं। पूंजी योजना परियोजनाएं सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा वित्त पोषित होती हैं जबकि राजस्व योजना परियोजनाएं अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं (अध्याय-2)।

सार्वजनिक प्रसारक के रूप में संगठन के अधिक विकास से संबंधित नीतिगत फैसलों के आधार पर आकाशवाणी द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। इन्हें आम जनता की जरूरतों और विशेष लक्षित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कल्याण, महिला सशक्तीकरण और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है (अध्याय-3)।

वार्षिक योजना 2008-09 और 2009-10 (31 दिसंबर 2009 तक) के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन का योजनागत विवरण अध्याय 4 में दिया गया है। वार्षिक योजना 2008-09 की स्वीकृत लागत 195.00 करोड़ रुपए थी और खर्चा 56.43 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार वार्षिक योजना 2009-10 की कुल लागत 261.00 करोड़ रुपए थी।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान का योजनागत विवरण और संशोधित अनुमान तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 (31 दिसंबर 2009 तक) की जानकारी अध्याय-5 में दी गई है। वित्तीय वर्ष 2008-09 तक जारी किए गए अनुदान के संदर्भ में आवश्यक उपयोग सर्टिफिकेट (यूसी) प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रसार भारती (आकाशवाणी) द्वारा जुटाए गए हैं और कोई लंबित यूसी नहीं है।

निरीक्षण प्रणाली

विभिन्न स्तरों पर समीक्षा और प्रसार भारती को जारी अनुदान के समय ही मासिक व्यय विवरण के माध्यम से आकाशवाणी की सभी योजना परियोजनाओं के प्रदर्शन का नियमित निरीक्षण किया जाता है। लागत के विकास और मंत्रालय द्वारा रखी गई अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर अनुदान को जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत फॉरमेट में अर्द्ध वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एचपीआर)को तैयार किया जाता है जो समग्र रूप से सभी योजनाओं के विकास की समीक्षा करती है।

प्रसार भारती के सीईओ द्वारा आकाशवाणी के वित्तीय प्रदर्शन के योजनागत विवरण का नियमित निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना समन्वय इकाई मासिक वक्तव्य के आधार पर भी इसका निरीक्षण करती है। सीईओ, पीबी और सचिव(सूचना और प्रसारण)के स्तर की समीक्षा बैठकों में उनके वित्तीय एवं भौतिक प्रचालनों के विकास की समीक्षा की जाती है।

दूरदर्शन

भारत में दूरदर्शन की शुरुआत, दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रसारण के माध्यम से सितंबर 1958 में की गई जिसे बाद में 1965 में एक स्थायी सेवा के तौर पर जारी किया गया। 1976 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का ही हिस्सा रहा, तत्पश्चात इसे अलग किया गया और महानिदेशक की अध्यक्षता में इसे अलग विभाग बना दिया गया। रंगीन टीवी और राष्ट्रीय प्रसार की शुरुआत 1982 में की गई। तब से दूरदर्शन विश्व के प्रमुख सार्वजनिक प्रसारक के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है। निशुल्क डीटीएच सेवा के साथ, दूरदर्शन 31 चैनलों का संचालन करता है। दूरदर्शन का 66 स्टूडियो का क्षेत्रीय नेटवर्क है और देश के भू-भागीय रूप को देखते हुए दूरदर्शन ने देशभर में 1416 ट्रांसमीटर लगाए हैं। इसके 31 चैनल इस प्रकार हैं :

डीडी 1- राष्ट्रीय चैनल

डीडी न्यूज- समाचार चैनल

डीडी भारती- समृद्धि चैनल

डीडी स्पोर्ट्स- खेल चैनल

डीडी राज्य सभा- संसद चैनल

डीडी उर्दू- उर्दू भाषा चैनल

क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल- कुल 11

मलयालम, (केरलम), तमिल (पोदिगई), उड़िया, तेलुगू, (सप्तगिरी), बंगाली (बांग्ला), कन्नड़ (चंदना), मराठी (सहयाद्रि), गुजराती, कश्मीरी (कशीर), उत्तर पूर्व, पंजाबी

राज्य नेटवर्क- 12

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय

डीडी भारत - अंतरराष्ट्रीय चैनल

ज्ञान दर्शन- शैक्षिक चैनल

क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से दूरदर्शन देश की 92 प्रतिशत आबादी को अपने दायरे में लेता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्यों, नीतिगत ढांचे से संबंधित जानकारी अध्याय- 1 में दी गई है।

वर्ष 2010-11 के लिए दूरदर्शन के संदर्भ में वित्तीय लागत, प्रस्तावित उत्पादन और प्रस्तावित परिणाम की जानकारी अध्याय-2 में दी गई है, जो जम्मू-कश्मीर, निरंतर योजनाओं के उत्तर पूर्व विशेष पैकेज और कुछ नई योजनाओं के तहत दिए गए हैं। वार्षिक योजना 2010 के दौरान प्रत्यक्ष बजटीय सहयोग 157.00 करोड़ रुपए है जिसमें 100 करोड़ रुपए पूंजी घटक के तहत ट्रांसमीटरों, स्टूडियो के डिजिटलीकरण और एचडीटीवी के लिए है और 57 करोड़ रुपए जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष योजना, उत्तर पूर्व के लिए विशेष पैकेज और सॉफ्टवेयर अधिग्रहण के लिए राजस्व योजना के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली 2010 के लिए प्रसार भारती का कुल बजट प्रावधान 449.62 करोड़ रुपए है। इसमें से 7.85 कोरड़ रुपए पुणे में 2008 में हुए राष्ट्रमंडल युवा खेल को दिए जा चुके हैं। 441.77 करोड़े के शेष प्रावधान को वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए सुनिश्चित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें आईटीपीओ के लिए 11.00 करोड़ शामिल है। वर्ष 2010-11 के लिए 296.77 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। इसमें प्रसार भारती के लिए 232.00 करोड़ रुपए और आईटीपीओ के लिए 64.77 करोड़ रुपए शामिल हैं। पूंजी योजना परियोजनाएं सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा वित्त पोषित होती हैं जबकि राजस्व योजना परियोजनाएं अनुदान के रूप मेंप्रदान की जाती हैं (अध्याय-2)।

सार्वजनिक प्रसारक के रूप में संगठन के अधिक विकास से संबंधित नीतिगत फैसलों के आधार पर दूरदर्शन द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। इन्हें आम जनता की जरूरतों और विशेष लक्षित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कल्याण, महिला सशक्तीकरण और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है (अध्याय-3)।

वार्षिक योजना 2008-09 और 2009-10 (31 दिसंबर 2009 तक) के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन की योजनागत विवरण अध्याय 4 में दिया गया है। वार्षिक योजना 2008-09 की स्वीकृत लागत 280 करोड़ रुपए थी और खर्चा 221.77 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार वार्षिक योजना 2009-10 की कुल लागत 251.00 करोड़ रुपए थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 तक जारी किए गए अनुदान के संदर्भ में आवश्यक उपयोग सर्टिफिकेट (यूसी) प्रासंगिक नियमों के अनुसार प्रसार भारती (आकाशवाणी) द्वारा जुटाए गए हैं और कोई लंबित यूसी नहीं है।

गैर योजना के संदर्भ में प्रत्यक्ष बजटीय सहयोग 1412.35 करोड़ रुपए का प्रावधान है और प्रसार भारती के लिए अनुवर्ती अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/आईबीईआर के रूप में 1000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2010-11 का कुल व्यय 3162 करोड़ है जिसके परिणामस्वरूप 650 करोड़ रुपए का बजट अंतराल अपरिहार्य होता है।

वैधानिक और स्वायत्त निकाय के रूप में प्रसार भारती के प्रदर्शन की समीक्षा अध्याय- 4 में की गई है।

राष्ट्रमंडल खेल 2010

19 वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 3-14 अक्टूबर 2010 के दौरान दिल्ली में किया जाएगा। इसमें 12 प्रतियोगी स्थलों और 5 गैर प्रतियोगी उद्घाटन एवं समापन समारोहों के अतिरिक्त 17 खेलों का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति- राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली 2010 ने दूरदर्शन, प्रसार भारती के एक संघटक को खेलों के मेजबान प्रसारक (होस्ट ब्रॉडकास्टर) के रूप में नियुक्त किया है। मेजबान प्रसारक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ रूप में खेलों को कवरेज करेगा। मेजबान प्रसारक आईबीसी पर विभिन्न देशों के राइट होल्डिंग ब्रॉडकास्टर्स को बेसिक फीड सिग्नल उपलब्ध कराएगा। आईबीसी (अंतरराष्ट्रीय प्रसारक केंद्र) बेसिक फीड सिग्नल के वितरण और ट्रांसमिशन का तकनीकी हब होगा और इसे आईटीपीओ, प्रगति मैदान, दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। मुख्य प्रेस केंद्र आईटीपीओ में स्थापित किया जाएगा। खेलों का पूरा कवरेज एचडीटीवी फॉरमेट में करने की योजना है।

राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008, पुणे और राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली 2010 के लिए कुल बजट प्रावधान 482.57 करोड़ रुपए है। इसमें से 9.05 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रमंडल युवा खेल, पुणे 2008 को दी गई है।

473.52 करोड़ रुपए के शेष प्रावधान को वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए बजट किया गया है। वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए 155.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रसार भारती के लिए 134 करोड़ रुपए, पीआईबी के लिए 10 करोड़ रुपए और आईटीपीओ के लिए 11 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वर्ष 2010-11 के लिए 318.52 करोड़ रुपए की लागत को स्वीकृत किया गया है।

निरीक्षण प्रणाली

दूरदर्शन की परियोजनाओं की योजना, उनका प्रतिपादन और प्रणाली तैयार करने का काम दूरदर्शन निदेशालय का है। योजनाओं को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थिति जोनल कार्यालयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में लागू किया जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उत्तर पूर्व के लिए अलग जोन बनाया गया है जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। लोक सेवा से संबंधित परियोजनाओं को आकाशवाणी और दूरदर्शन के लोक निर्माण खंड द्वारा लागू किया जाता है। परियोजनाओं से संबंधित प्रमुख गतिविधियों का निरीक्षण निदेशालय स्तर पर किया जाता है। जोनल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, सीसीडब्ल्यू परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं जो उनके क्षेत्र में आते हैं।

प्रत्येक वर्ष दूरदर्शन की सभी प्रमुख परियोजनाओं के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जिनका निरीक्षण जोनल कार्यालयों और निदेशालय द्वारा किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निश्चित लागत के साथ परियोजनाएं पूरी हो जाएं। लोक सेवा के विकास की समीक्षा के लिए जोनल चीफ इंजीनियर सीसीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। ई-इन सी स्तर पर नियमित रूप से निदेशालय के अधिकारियों, जोनल अधिकारियों और सीसीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। दूरदर्शन के महानिदेशक और प्रसार भारती के सीईओ के स्तर की सावधि समीक्षा भी की जाती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय दूरदर्शन की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है।

अध्याय-1

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन का प्रमाणपत्र देने के उद्देश्य से सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952 (1852 का 37) के तहत की गई थी। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, तिरुअनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में हैं। बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं :

(i) गैर प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म को प्रमाणपत्र देना (यू प्रमाणपत्र)

(ii) वयस्कों (जो 18 वर्ष के हो चुके हैं) के लिए फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र देना (ए प्रमाणपत्र)

(iii) गैर-प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए इस चेतावनी के साथ प्रमाणपत्र जारी करना कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे माता-पिता के साथ ही फिल्म देखने आएंगे (यूए प्रमाणपत्र)

(iv) किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र देना (एस प्रमाणपत्र)

(v) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड फिल्म को प्रमाणपत्र देने से पहले कुछ अंशों को हटाने का आदेश दे सकता है और बोर्ड प्रमाणपत्र देने से इंकार भी कर सकता है।

सीबीएफसी की वार्षिक योजना 2010-11 की स्कीमें निम्नलिखित हैं :

1. कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना तथा ढांचागत उन्नयन

स्कीम में एनआईसी की सहायता से सीबीएफसी के सभी कार्यों का कंप्यूटरीकरण करने का विचार है। ढांचागत उन्नयन के साथ तकनीकी उपकरण जैसे टीवी, वीसीडी तथा डीवीडी प्लेयर प्रदान करना भी है। इस स्कीम के लिए 11वीं योजना में स्वीकृत परिव्यय 350.00 लाख रुपये है।

2. नई दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

नई दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में इन क्षेत्रों में निर्मित फिल्मों के प्रमाणन के लिए सीबीएफसी कार्यालय खोलने की आवश्कता है। वर्तमान में इन कार्यालयों को मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाईयों से लिए गए स्टाफ/अधिकारी देख रहे हैं। इन तीन कार्यालयों को संभालने के लिए तीन क्षेत्रीय अधिकारियों तथा तीन पद एलडीसी के सृजित किए गए हैं। स्कीम के लिए 11वीं योजना में कुल परिव्यय 312 लाख रुपये है।

3. प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी और आधुनिकीकरण

स्कीम में पर्यवेक्षण अधिकारियों/बोर्ड सदस्यों तथा फिल्म प्रकाशन में पैनल सदस्यों के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित करना; प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक कार्यशाला तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी के लिए एवं अखिल भारतीय पैनल कार्यशाला। इसके लिए 11 वीं योजना में स्वीकृत परिव्यय 500.00 लाख रुपये है।

बाल फिल्म समिति, भारत

सीएफएसआई की विभिन्न गतिविधियां निम्नलिखित हैं :

1. निर्माण और खरीद : सीएफएसआई बच्चों तथा युवाओं के लिए फिल्म तथा वीडियो फॉरमेट में फीचर फिल्म, लघु फीचर फिल्म, एनीमेशन, लघु फिल्म, पपेट फिल्म तथा टीवी सीरियल बनाता है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लोकप्रिय रही कुछ फिल्मों के प्रदर्शन अधिकार भी खरीदता है। इन फिल्मों तथा समिति द्वारा निर्मित फिल्मों की विभिन्न भारतीय भाषाओं में डबिंग कराई जाती है।

2. फिल्म समारोह

क. अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह : सीएफएसआई हर दूसरे साल प्रतियोगी बाल फिल्म समारोह का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म केंद्र जोकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों को नियंत्रित करने वाली यूनेस्को से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ने इसे ए श्रेणी में रखा है।

ख. अंतर्राष्ट्रीय बाल समारोहों में भागीदारी : सीएफएसआई की फिल्में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित हुई हैं, इससे विदेशों में बच्चों की फिल्मों को बढ़ावा देने में मदद मिली है। हर दूसरे साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में राष्ट्रीय डिजिटल फिल्म समारोह आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

3. आधुनिकीकरण तथा संवर्धन : सीएफएसआई ने अपने कार्यालय का कंप्यूटरीकरण किया है तथा मौजूदा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया जा रहा है।

4. एनिमेशन तथा फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं : सीएफएसआई बच्चों को फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए फिल्म निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया तथा एनीमेशन पर कार्यशालाएं आयोजित करती है। इनमें एनिमेशन कार्यशाला, पटकथा लेखन कार्यशाला, फिल्म समालोचना कार्यशाला तथा फिल्म निर्माण कार्यशालाएं शामिल हैं।

5. सीएफएसआई फिल्मों का डिजिटल रूपांतरण तथा वेबकास्टिंग : सीएफएसआई द्वारा (निर्मित, डब की हुई तथा उपशीर्षक सहित) सभी फिल्मों को अभिलेखन के उद्देश्य से डिजिटल रूप में रूपांतरित करना तथा उन्हें इंटरनेट/वेब पर उपलब्ध कराना

6. फिल्मों का प्रदर्शन और वितरण

क. निजी प्रदर्शन

कई स्कूल और व्यक्ति, स्कूलों या सिनेमाहॉल में 35 मिमी, 16 मिमी प्रोजेक्टरों के जरिए गैर व्यावसायिक प्रदर्शनों के लिए नियत शुल्क देकर इन फिल्मों को किराए पर लेते हैं।

ख. जिला और राज्य स्तर के समारोह

यह गतिविधि जिला प्रशासनों के साथ मिलकर की जाती है। विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों को चिन्हित कर वहां मामूली प्रवेश शुल्क पर फिल्में दिखाई जाती हैं। सरकारी निगम, स्कूलों या जिला परिषद के स्कूलों में जाने वाले बच्चों को ये फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007-08 से यह निर्णय लिया गया है कि सीएफएसआई फिल्मों के प्रदर्शन के लिए बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ग. सिनेमाहॉल के बाहर मुफ्त प्रदर्शन

ग्रामीण और मनोरंजन के दूसरे साधनों से वंचित बच्चों तक पहुंचने के लिए सीएफएसआई ने सरकारी स्कूलों के बच्चों और आदिवासी बच्चों को मुफ्त फिल्में दिखाने की एक नई योजना शुरू की है। नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे गैर सरकारी संगठनों की इसमें मदद ली जा सकती है। मुफ्त प्रदर्शनों पर होने वाला खर्च सीएफएसआई, इस मद में सरकार से मिलने वाले सहायक अनुदान से पूरा करती है। इस योजना में सुधार गृहों, अनाथालयों आदि में रहने वाले बच्चों को भी फिल्में दिखाने का मौका दिया जाता है।

घ. वितरकों के जरिए प्रदर्शन

सीएफएसआई, स्कूल और सिनेमाहॉलों में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए वितरकों/आयोजकों से भी सहयोग लेती है। यह एक तय मासिक शुल्क लेकर फिल्में ले लेते हैं और आवंटित क्षेत्र में उनका प्रदर्शन करते हैं।

च. टेलीविजन पर फिल्मों का प्रदर्शन

समिति की फिल्में दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और क्षेत्रीय चैनलों के अलावा निजी चैनलों पर दिखाई जाती हैं।

छ. पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू-कश्मीर में गतिविधियां

समिति पूर्वोत्तर राज्यों सहित क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण पर कार्यशालाओं के आयोजन और प्रदर्शन के जरिए उन्हें प्रोत्साहन देती है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां कार्यरत हैं और देश भर में 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण में ये कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार की इन नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं पर उनका लक्ष्य और उद्देश्य केन्द्रित है जिनमें लोगों के उत्थान पर अधिक जोर दिया गया है। इस प्रकार इनके कार्यकाल देश के ग्रामीण, पिछड़े, सीमावर्ती तथा जनजातीय क्षेत्रों तक केन्द्रित हैं। बहुमाध्यम अभियानों, फिल्म प्रदर्शनों, फोटो प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, ग्रुप विचार-विमर्शों तथा विशेष वार्ता कार्यक्रमों जिनमें गोष्ठी, संगोष्ठी, रैलियां तथा ग्रामीण खेल आदि शामिल हैं, के माध्यम से संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाता है। निदेशालय के लक्ष्य और उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार हैं—

(1) लोगों और सामग्री को एक दूसरे के निकट लाकर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना और उनके लाभ के लिए कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में जानकारी देना।

(2) लोगों को लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के बुनियादी राष्ट्रीय मूल्यों की जानकारी देना तथा लगातार व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से ऐसे मूल्यों में उनकी आस्था को दृढ़ बनाना।

(3) विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय, सहभागिता के लिए सबसे निचले स्तर के लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना और कल्याण तथा विकास कार्यों पर अमल करने के संबंध में जनमत को भी सक्रिय करना।

(4) सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया हासिल करना। इस प्रकार निदेशालय सरकार और जनता के बीच संचार के दो तरफा चैनल की तरह कार्य करता है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की प्रमुख मल्टी मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचाने का काम करती है। डीएवीपी अनेक स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचार आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। समाज से जुड़े संदेशों का आम आदमी तक पहुंचाने के लिए यह निम्नलिखित माध्यमों का सहारा लेती है–

(क) समाचारपत्रों में विज्ञापनों के जरिए,

(ख) श्रव्य/दृश्य स्पॉट, जिंगल्स इत्यादि,

(ग) मुद्रित प्रचार साहित्य, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, पोस्टर इत्यादि,

(घ) बाह्य प्रचार माध्यमों – होर्डिंग्स, मेट्रो रेल पैनल, बस पैनल, कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि।

(ङ) ग्रामीण तथा कस्बाई क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले इलाके जैसे कि मेले इत्यादि में फोटो प्रदर्शिनी के आयोजन द्वारा,

(च) डीएवीपी का आधुनिकीकरण :

साफ्टवेयर, आफिस के बुनियादी ढांचे और कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि।

कुल मिलाकर डीएवीपी कई वर्षों से सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और यह जनता के बीच जागरूकता निभाने, विकासात्मक गतिविधियों में जनता की भागीदारी प्राप्त करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। मुद्रित माध्यम प्रचार तथा श्रव्य–दृश्य प्रचार को भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी क्रमशः विज्ञापन नीति और दृश्य–श्रव्य प्रचार नीति के तहत किया जाता है।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय को अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों (आईएफएफआई) का आयोजन करने, देश और विदेश में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने, फिल्म सप्ताहों का आयोजन तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

निदेशालय भारत में और विदेशों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के प्रयास भी करता है। निदेशालय द्वारा आयोजित फिल्म समारोह भारत और विदेश के एक जैसी सोच वाले पेशेवरों के लिए विचार विनिमय और अपने दृष्टिकोण और अवधारणाओं को एक–दूसरे के साथ बांटने के एक मंच के रूप में कार्य करते हैं।

निदेशालय की गतिविधियां 'भारत और विदेशों में फिल्म समारोह के जरिए निर्यात संवर्धन' योजना के माध्यम से चलाई जाती हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

(ख) भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों में भारतीय पैनोरमा फिल्मों की भागीदारी

(ग) भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन

फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के दृष्टिकोण से निदेशालय को एक तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रिंट यूनिट, जो प्रिंटों की लम्बी अवधि तक भंडारण में मदद करेगी, प्रदान करने के लिए एक नई योजना का भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है।

इसके अलावा, सीरीफोर्ट फिल्म समारोह परिसर के रख-रखाव तथा देखभाल की जिम्मेदारी भी निदेशालय की है। परिसर में सुविधाएं/सुधार का कार्य 'फिल्म समारोह परिसर - संयोजन और बदलाव' योजना स्कीम के माध्यम से हाथ में लिया गया है।

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की स्थापना वृत्तचित्र, एनीमेशन, छोटी और कार्टून फिल्मों का निर्माण करने और उसका वितरण जनसूचना, शिक्षा, प्रोत्साहन और सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए किया गया है। फिल्म प्रभाग का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी निर्माण ईकाई दिल्ली में स्थापित है जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए वृत्तचित्र का निर्माण करती है। इसके साथ दो अन्य निर्माण केंद्र बंगलुरु और कोलकाता में है जो विडियो फिल्म एवं फिचरहेड फिल्मों का निर्माण करती है। यह ग्रामीण कहानियों पर आधारित फिल्मों का निर्माण करते हैं। चौदह वरिष्ठ कैमरामैन और दो सहायक कैमरामैन विभिन्न राज्यों की राजधानी में नियुक्त हैं जो कि वहां की विशेष राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गतिविधियों को कवरेज करते हैं। फिल्मों का वितरण दस शाखाओं से किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार और अन्य फिल्म हस्तियों के सहयोग से फिल्म प्रभाग दो-वर्षीय फिल्मोत्सव का आयोजन करता है।

भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म स्कंध ''फिल्मों का निर्यात और विपणन'' नामक कार्यक्रम के घटक ''भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' का कामकाज मंत्रालय देख रहा है, जबकि ''भारत और विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्द्धन'' घटक डीएफएफ द्वारा लागू किया जा रहा है।

भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

''भारत और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' घटक के कार्यान्वयन का प्रयोजन भारतीय फिल्मों की पहुंच को वैश्विक आधार प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी से उनके परिचय को बढ़ावा मिलता है और फिल्मों की उपलब्धता की जानकारी प्रचारित होती है। निर्यात की संभावनाएं मौजूदा बाजारों और छोटे तथा गैर-पारंपरिक बाजारों जैसे लेटिन अमरीका, चीन और स्केंडिनेवियन देशों में बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भागादारी के जरिए हम अन्य देशों में अपनी फिल्में प्रदर्शित कर यह सब हासिल कर सकते हैं। इन बाजारों में केंस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और अमरीकन फिल्म बाजार-लॉस ऐंजेल्स आदि शामिल हैं। पारंपरिक फिल्म बाजारों के अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत एनीमेशन फिल्म समारोह/बाजारों, बाल फिल्म बाजार और/अथवा वृत्तचित्र फिल्म क्षेत्र में भागीदारी का प्रस्ताव है। योजना का लक्ष्य फ्रांस में एन्नेसी-एनीमेशन फिल्म समारोह/बाजार केंस में अक्टूबर में आयोजति ऑडियो-विजुअल कंटेंट इंडस्ट्री बाजार (मिपकोम) में भागीदारी का है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ फिल्म बाजार का भी आयोजन किया जाता है। इन बाजारों में भागीदारी की संभावनाओं का आकलन वार्षिक आधार पर किया जाता है तथा साल दर साल भिन्न हो सकता है।

ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

तीव्र प्रौद्योगिकी विकास ने एनीमेशन, गेमिंग और विशेष दृश्य प्रभावों के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया है। एनीमेशन सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों का इस्तेमाल कंटेंट विकसित करने के लिए 2 डी सैल एनीमेशन तथा 3 डी सैल एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल होता है। 3 डी मोशन केप्चर एनीमेशन तकनीकों का इस्तेमाल लो रिजोल्युशन गेम, इंटरनेट करेक्टर्स, विशेष प्रभाव इत्यादि में होता है। इसी तरह, गेमिंग उद्योग गेम डिजाइन, प्लेटफार्म डिजाइन तथा प्ले करेक्टरिस्टिक सिस्टम के लिए आधुनिक गेमिंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर है। भारतीय गेमिंग उद्योग मोबाइल तथा ऑन लाइन गेमिंग क्षेत्र में अवसरों का इस्तेमाल करना चाहता है। ऐनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव उद्योग प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी/व्यवसायिक दोनों मानवशक्ति की मांग वाला क्षेत्र है। भारतीय उद्योग पहले से ही विरोध का सामना कर रहा है। ऐसे में जब इन उद्योगों में भारत का एक छोटा हिस्सा है, वैश्विक मांग और भारत में आईटी व्यावसायिकों का विशाल पूल होने के नाते अत्यधिक संभावनाएं हैं।

दृश्य प्रभाव एक उच्च कौशल वाली गतिविधि है और ऑडियो-वीडियो उद्योग में काफी महत्व रखती है। यह कौशल विकास एनीमेशन और गेमिंग के अनुरूप है और इसमें राजस्व की अत्यंत संभावनाएं हैं। यद्यपि, तेजी से बढ़ रहे एनीमेशन और गेमिंग तथा दृश्य प्रभाव उद्योग को प्रशिक्षित व्यावसायिकों की कमी का पहले से ही सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न रिपोर्टों से अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में लगभग 10,000 एनीमेशन व्यावसायिकों की आवश्यकता है जबकि मात्र 3000 व्यावसायिक ही उपलब्ध हैं। इसी प्रकार गेमिंग उद्योग में लगभग 6000 व्यावसायिक हैं जबकि मांग इससे कहीं अधिक है। उद्योग की गति को देखते हुए कुशल व्यावसायिकों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत एनीमेशन, गेमिंग और दृश्य प्रभाव क्षेत्र में प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के उपाय सुनिश्चित करे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, एक एचआर योजना की इस क्षेत्र को आवश्यकता है ताकि प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या तीव्रता से बढ़ सके। इस प्रकार उच्च शिक्षा में स्कूल पाठ्यक्रम तथा एनीमेशन प्रशिक्षण के बीच स्पष्ट-सह-संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त उद्देश्यों के साथ यह विचार किया गया है कि सार्वजनिक/निजी भागादारी में एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव क्षेत्र के लिए एक विशेषीकृत प्रशिक्षण और परामर्श संस्थान स्थापित किया जाए। यह संस्थान इन क्षेत्रों में स्तरीय अध्ययन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक बेंचमार्क स्थापित करे और संपूर्ण क्षेत्र के लिए नेतृत्व प्रदान करे। भारत में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान होने के चलते संस्थान क्षेत्र में अनुसंधान अवसर भी प्रदान करेगा। इससे प्रौद्योगिकीय पहल और सॉफ्टवेयर विकास में सहायता मिलेगी। आगे चलकर, अनुसंधान न केवल बौद्धिक संपदा पैदा करने बल्कि राजस्व बढ़ाने तथा संबंधित क्षेत्र में नेतृत्व की स्वीकृति प्रदान करता है।

एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मानव संसाधन पर एक अध्ययन हेतु मेसर्स पीडब्ल्यूसी को नियुक्त किया था। पीडब्ल्यूसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें ऐसे केंद्र की स्थापना की सिफारिश की है। इसी के अनुरूप मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी के लिए योजना आयोग से संपर्क किया है। योजना आयोग की सलाह पर यह मंत्रालय एफआर/डीपीआर तैयार करने के लिए एक परामर्शक नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

फिल्म संस्थान की स्थापना 1960 में पुणे में, कला तथा फिल्म निर्माण तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख संस्थान के रुप में की गई थी। 1974 से इसने टेलीविजन निर्माण में भी दूरदर्शन के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया और संस्थान का नाम भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्तान रख दिया। एफटीआईआई फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन प्रशिक्षण में संस्थान द्वारा संचालित अकादामिक पाठ्यक्रम :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	वर्तमान में छात्रों की संख्या
(क).	फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	
1.	निर्देशन	50
2.	सिनेमाटोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन)	50
3.	संपादन (फिल्म एवं टेलीविजन)	36
4.	ऑडियोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन)	37
(ख).	दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम	
1.	अभिनय	40
2.	कला निर्देशन तथा निर्माण डिजाइन	36
(ग).	एमीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	24
(घ).	टेलीविजन में एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	
1.	निर्देशन	11
2.	इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी	11
3.	वीडियो संपादन	11
4.	ऑडियोग्राफी एवं टेलीविजन इंजीनियरिंग	09
(ई).	फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	12
	कुल	**337**

लघु पाठ्यक्रम

एफटीआईआई कार्यरत पेशेवरों और संबंधित क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए विभिन्न लघु पाठ्यक्रम चलाता है।

योजना स्कीमें

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित दो स्कीमों को प्रस्तावित किया गया है :

(क) I. एफटीआईआई को अनुदान सहायता

II. मशीनरी और उपकरण

III. सिविल निर्माण और विद्युतीय कार्य

IV. सामुदायिक रेडियो की स्थापना

V. केप्टिव टीवी चैनल की स्थापना

VI. छात्रों के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ छात्रवृत्ति और आादन-प्रदान कार्यक्रमों सहित एचआरडी आयाम।

नई स्कीम

ग्लोबल फिल्म स्कूल (नई)

(क) जारी स्कीम

I. **एफटीआईआई, पुणे को अनुदान सहायता :** स्कीम का उद्देश्य ढांचागत कमी से उबरना और उद्योग में बेहतर वातावरण के साथ उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाना है। इस स्कीम के लाभार्थी सीधे तौर पर छात्र और प्रशिक्षु हैं।

मानव संसाधन विकास से संबंधित योजना में संस्थान के छात्रों तथा संकाय सदस्यों के लिए लाभ बढ़ाने के संबंध में परिणाम के साथ कुछ प्राथमिक प्रयास किए गए हैं। हालांकि इस मौजूदा योजना के कुछ तत्वों को अधिकतम लाभ की दिशा में पुनर्आकार देने की आवश्कता हो सकती है, इसको जारी रखने की आवश्यकता है।

ग्लोबल फिल्म स्कूल (नई योजना): ग्लोबल फिल्म स्कूल का विचार और प्रस्ताव अंतराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने की दिशा में ढांचा उन्नयन तथा एफटीआईआई को अंतर्राष्ट्रीय परिसर में विकसित करने के लिए संस्थान के पाठ्यक्रम को अद्यतन करता है। उद्देश्य विश्वभर के छात्रों को एफटीआईआई पुणे तक आकर्षित करना तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त फिल्म स्कूल के साथ छात्र आदान-प्रदान की अनुमति प्रदान करना है। जिसके लिए एफटीआईआई द्वारा दिए गए श्रेय को मान्यता की आवश्कता होगी।

इस उद्देश्य के लिए नियुक्त परामर्शक के साथ इस मामले में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कार्य किया जाएगा।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने के मकसद से भारत सरकार ने एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कोलकाता के सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना की थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। कोलकाता में संस्थान की स्थापना का विशेष उद्देश्य पूर्वी तथा उत्तरपूर्वी भारत के लिए फिल्म एवं टेलीविजन निर्माण में शिक्षा प्रदान करना है।

संस्थान का प्राथामिक मूल उद्देश्य छात्रों के लिए फिल्म और टेलीविजन पर विभिन्न पाठ्यक्रम चलाना है। प्रति वर्ष यहां से लगभग 40 छात्र निकलते हैं। टेलीविजन उद्योग के लिए और फिल्म उद्योग के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है।

संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्र छायांकन, सम्पादन और ध्वन्यांकन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराता है। इनमें से प्रत्येक शाखा में दस-दस छात्र लिए जाते हैं। फिल्म तथा टेलीविजन से जुड़े अन्य क्षेत्रों में बुनियादी डिप्लोमा कोर्सों के अतिरिक्त समाजशास्त्र, संस्कृति और फिल्म तथा टेलीविजन टेक्नोलाजी के बारे में अनुसंधान और खोजी अध्ययनों पर भी यह संस्थान ध्यान देता है। पाठ्यक्रम में छात्रों की परियोजनाएं शामिल हैं जैसे—निरंतरता, मिस-एन-सीन, एड-प्रोमो, डाक्यूमेंटरी, पार्श्व गायन तथा डिप्लोमा फिल्में आदि। कक्षा की पढ़ाई के अतिरिक्त, प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियों द्वारा विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। फिल्म निर्माण में आधुनिक तरीके तथा तकनीक को बेहतर रूप में समझने के लिए देसी तथा विदेशी फिल्मों का नियमित प्रदर्शन किया जाता है।

विभाग-वार वर्तमान छात्र संख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	छात्रों की वर्तमान संख्या
(क)	फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	
1	निर्देशन	28
2.	सिनेमेटोग्राफी (एमपीपी)	28
3.	संपादन	30
4.	ऑडियोग्राफी (साउंड रिकार्डिंग)	26
	कुल	**112**

बुनियादी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान, विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर विभिन्न अल्पावधि पाठ्यक्रम और विभिन्न परियोजनाएं हाथ में लेता है।

प्रवेश प्रक्रिया जारी है और 2009-12 बैच के लिए कक्षाएं 29 मार्च 2010 से शुरू होंगी।

अजा/अजजा

यह संस्थान पदों को भरने अथवा प्रवेश में अजा/जजा/अपिब/शाअ लोगों के आरक्षण के संबंध में तय नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करता है।

एसआरएफटीआई, कोलकाता की अनुदान सहायता की योजना स्कीम

संस्थान ने 10वीं योजना के दौरान शुरू की गई उन विभिन्न स्कीमों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में संस्थान के एकल सहायता अनुदान में मिला दिया है जो अभी चल रही हैं। स्कीम में चल रही स्कीमों के अलावा दो नई स्कीमें भी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक स्कीम का संक्षिप्त परिणाम नीचे दिया गया है :

सहायता अनुदान स्कीम में निम्नलिखित भाग हैं :

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम
(क)	**जारी स्कीम**
1.	सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना
2.	केप्टिव टीवी सॉफ्टवेयर निर्माण केंद्र की स्थापना
3.	प्रशिक्षण और कौशल विकास डब्ल्यु.आर.टी सामाजिक सुसंगत फिल्म निर्माण
4.	छात्रवृत्ति, छात्र/संकाय आदान प्रदान कार्यक्रम
5.	मानवशक्ति सहित ढांचागत प्रावधानों के साथ कंप्यूटरीकरण, आधुनिकीकरण

(ख)	नई स्कीम
1.	एनीमेशन तथा इलेक्ट्रानिक इमेजिंग विभाग
2.	फिल्म एवं टेलीविजन में निर्माण प्रबंधन विभाग

जारी स्कीम

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की स्थापना संस्थान में एफएम आधारित रेडियो स्टेशन के रूप में इस विचार से की गई कि छात्रों को ऑन-लाइन प्रसारण में प्रशिक्षण दिया जा सके। एफ एम चैनलों की बढ़ती लोकप्रियता जन शिक्षा और मनोरंजन, स्थानीय रुचियों और स्टाइल के मनमाफिक तैयार कार्यक्रमों के लिए एक प्रभावी मीडिया के रूप में स्थानीय प्रसारण प्रणालियों के संचालन की उर्वर भूमि की मौजूदगी दर्शाती है। अपने मौजूदा तैयार ढांचे तथा युवा, ओजस्वी छात्र संसाधन के साथ एसआरएफटीआई सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना तथा सफलतापूर्वक इसे चलाने के लिए उपयुक्त स्थान है। परियोजना को ताकत निम्नलिखित से मिलती है :

स्कीम का उद्देश्य संस्थान में दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में मूल्य वर्धन के साथ इस क्षेत्र में भविष्य के रोजगार तथा उत्कृष्टता के विस्तार को अनिवार्य रूप से बढ़ाना है। यद्यपि, एक बार परियोजना शुरू हो गई तब प्रायोजक मिलने की संभावना है जिससे पूरी अथवा आंशिक निर्माण लागत निकल आएगी।

केप्टिव टीवी सॉफ्टवेयर केंद्र की स्थापना

परियोजना का उल्लेखनीय उद्देश्य ऑन-लाइन टेलीकास्ट की कला और तकनीक की शुरुआत करना है और छात्रों को दिए जा रहे प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाना है। इसमें अनिवार्य रूप से कम शक्ति/उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों (एलपीटी/एचपीटी) के जरिए प्राप्त किए गए दैनिक/साप्ताहिक स्लॉट में प्रसारण के लिए छात्रों और शिक्षकों द्वारा टीवी सॉफ्टवेयरों का निर्माण शामिल है। कार्यक्रम मुख्य रूप से स्थानीय रुचियों के हिसाब से परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोरंजन के सामाजिक मुद्दों से संबंधित होते हैं।

डब्ल्यु.आर.टी. सामाजिक संदर्भ वाले फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण और कौशल विकास

संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चुने गए 120 प्रतियोगी युवाओं के लिए फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करता है। परियोजना का उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रशिक्षण पा रहे युवा छात्रों के लिए प्रशिक्षण में अति वांछित मूल्य जोड़ना है। इस स्कीम के तहत संस्थान की मौजूदा प्रशिक्षण गतिविधियों में प्रस्तावित तत्वों से छात्रों को इस उद्योग की कठिनाइयों से सामना करने में सहायता मिलेगी।

छात्रवृत्ति छात्र/संकाय आदान प्रदान कार्यक्रम

स्कीम का उद्देश्य संस्थान के छात्रों के लिए एक सहयोगी आधार तैयार करना है जहां विदेशी प्रतिष्ठित फिल्म स्कूलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों/फोरमों तथा छात्र आदान प्रदान कार्यक्रमों के जरिए फिल्म निर्माण की उभरती प्रौद्योगिकी तथा तकनीकों से परिचित कराना है। फिल्म एवं टीवी उद्योग में प्रशिक्षण मनोरंजन उद्योग में हालिया प्रौद्योगिकीय बदलावों को समझने में यह स्कीम शिक्षकों की भी मदद करेगी। स्कीम में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तथा विदेशी उद्योगों और फिल्म उद्योगों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं।

मानव शक्ति सहित ढांचे के कंप्युटरीकरण, आधुनिकीकरण का प्रावधान

संस्थान का मुख्य उद्देश्य फिल्म और टेलीविजन मीडिया के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति प्रदान करने के लिए फिल्म और टीवी पर विभिन्न पाठयक्रमों में प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में संस्थान चार शाखाओं में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम संचालित कर रहा है। ये शाखाएं हैं : निर्देशिन तथा पटकथा लेखन, साउंड रिकार्डिंग तथा मोशन पिक्चर फोटोग्राफी। पहले केवल एक बैच के लिए पाठ्यक्रम चलाने के लिए ढांचा तैयार किया गया और उसी के अनुरूप पद सृजित किए गए। धीरे धीरे, बैच बढ़ने के साथ ढांचागत विकास और पदों का सृजन नहीं हुआ, परिणामस्वरूप संस्थान को तीनों बैच एक साथ संचालित करने के लिए ढांचागत कमी और मानव शक्ति की कमी का कठिन सामना करना पड़ रहा है। स्कीम से संस्थान को पर्याप्त ढांचा प्रदान करने में सहायता मिलेगी तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण पा रहे छात्रों को आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल हो सकेगी।

नई स्कीम

ऐनीमेशन और इलेक्ट्रॅनिक इमेजिंग विभाग

पिछले कुछ सालों में दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के निर्माण की दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन आया है। एक प्रमुख क्षेत्र जिसमें उल्लेखनीय विकास हुआ है, वह ऐनीमेशन और मल्टी-मीडिया प्रयोगों का है। एनीमेशन की लोकप्रियता और संभावनाओं के बारे में हर कोई जानता है और इस बारे में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वेब से जुड़े प्रयोगों और एनीमेशन फिल्मों के साथ-साथ मल्टी मीडिया सीडी-रोम्स/गेम्स का एक विशाल गतिशील और संभावनाओं से भरा बाजार मौजूद है। अगले कुछ सालों में भारत एनीमेशन से जुड़े काम के लिए एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इन गतिविधियो में मदद करने वाले प्रशिक्षित मानव संसाधन की भारी मांग है।

इसलिए संस्थान में एनीमेशन और इलेक्ट्रानिक इमेजिंग में दो साल का एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है जिसमें प्रत्येक बैच में 10-10 छात्रों का लेने का प्रस्ताव है। अगर इस स्कीम को मान लिया गया और मंजूरी प्रदान कर दी गई तो फिलहाल यह कोर्स 2011 के बाद से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए वांछित बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा तथा लोगों की भर्ती की जाएगी।

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रम प्रबंध विभाग

दृश्य श्रव्य मीडिया, एक बहु-आयामी मीडिया है और वह भी व्यापक विविधता को लिए हुए। एक सफल कार्यक्रम के निर्माण के लिए सभी विविधताओं को एक व्यविस्थित और किफायती एकजुटता में उसमें कुशल और पेशेवर प्ररबंधन को लाने के लिए मीडिया के कार्यकलापों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले योग्यता प्राप्त प्रबंधकों का होना अनिवार्य है। ये प्रबंधक व्यापार से जुड़ा अनुशासन और पारदर्शिता लाने में कामयाब हो सकेंगे जिससे कार्यक्रम निर्माण आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक हो सकेगा। चूंकि आज विशेषज्ञता का युग है, इसलिए उद्योग की जरूरतों के अनसार मानव संसाधनों को प्रशिक्षित और प्रयोग करना जरूरी हो गया है।

फिल्मों और टेलीविजन में निर्माण प्रबंधन में विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती मांग को देखते हुए संस्थान ने 2011 से फिल्म और टीवी में निर्माण प्रबंधन में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का इरादा है। ढांचा और व्यक्तियों की भर्ती के बाद प्रत्येक बैच में 10-10 छात्र लिए जाएंगे।

गैर योजना

संस्थान का मुख्य उद्देश्य फिल्म एवं टीवी उद्योग के लिए प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराना है। संस्थान निर्देशन और पटकथा लेखन, साउंड रिकार्डिंग, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी, एडीटिंग एवं साउंड रिकार्डिंग में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। तीन बैचों में कुल 120 छात्र हैं। नियमित गतिविधियों में निरंतरता, लघु फिल्म, वृत्तचित्र, पार्श्वगायन तथा डिप्लोमा फिल्में बनाने जैसी परियोजनाएं हैं। कक्षा में फिल्मी हस्तियों द्वारा कार्यशालाएं आयोजित कराई जाती हैं। 32 छात्र अपनी फिल्म परियोजनाएं पूरी करने वाले हैं। परियोजना अवधि में 30 मिनट की 10 लघु फिल्में बनाई जानी हैं। इस अवधि में नए प्रवेश किए जाएंगे। गैर-योजना खर्च के तहत संस्थान का बुनियादी ढांचा बनाए रखने की जरूरत है ताकि संस्थान के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

भारतीय जनसंचार संस्थान

आईआईएमसी पर संक्षिप्त नोट

आई आई एम सी 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इस संस्थान का उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इस संस्थान की स्थापना जन संचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध कार्य के उद्देश्य से की गई थी। यूनेस्को के दो परामर्शदाताओं समेत कुछ कर्मचारियों के साथ शुरू किया गया था जिसमें मुख्य तौर पर केन्द्रीय सूचना सेवा अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम और छोटे स्तर पर शोध अध्ययन का आयोजन होता था लेकिन पिछले लगभग 45 वर्षों में यह संस्थान आधुनिक समय में तेजी से बढ़ते हुए और बदलते हुए मीडिया एवं संचार उद्योग की विविध और बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कोर्स आयोजित करने वाला संस्थान बन गया।

हाल के समय में जन संचार में काफी बदलाव आया है और यह निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली गतिविधि के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति ने मास मीडया के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसने इस विधा के छात्रों, शिक्षकों और प्रयोगकर्ताओं के लिए बड़ी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। तेजी से बदलती हुछी प्रौद्योगिकी इस विद्या के पूरे रंग को एक ऐसे रूप में बदल रही है जिसके बारे में शैक्षणिक गतिविधि के किसी अन्य क्षेत्र में कोई जानकारी नहीं है। निस्संदेह समय की मांग है मीडया और संचार के निर्वाह और प्रभाव क्षमता को बढ़ाने के लिए आने वाली चुनौतियों का कारगर ढंग से जवाब देना।

यह संस्थान एक ऐसे सूचना ढांचे के निर्माण और उसकी मजबूती में योगदान करता है जो न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों की आवश्यकताओं के लिए भी अनुकूल होता है। यह संस्थान देश के और विदेश के अन्य संस्थानों/निकायों को अपनी विशेषज्ञ और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय जनसंचार संस्थान केन्द्रीय/राज सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त किए गए अनुरोध के जवाब में प्रशिक्षण, शोध और परामर्श सेवा प्रदान करता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियों की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्रीय आकांक्षा को पूरा करने के लिए इस संस्थान ने पूर्वी क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए 1993 में उड़ीसा के ढेंकनाल में एक शाखा खोली। वर्तमान में इस शाखा में दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पत्रकारिता (अंग्रेजी) और पत्रकारिता (ओड़िया) का आयोजन किया जाता है।

भारत सरकार सूचना व प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारतीय जन संचार संस्थान को वित्तीय सहयोग प्रदान कर रहा है। इस संस्थान की गतिविधियों का मार्ग निर्देशन इसके कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव इस कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होते हैं और इस संस्थान (सोसायटी) के भी अध्यक्ष होते हैं।

इस परिषद के अन्य सदस्यों में अन्य लोगों के साथ-साथ दुनिया की विख्यात हस्तियां शामिल हैं।

शैक्षणिक कार्यक्रम

संस्थान की गतिविधियां तीन क्षेत्रों - शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध पर केंद्रित हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

1. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप ए और बी) के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम
2. नई दिल्ली और ढेंकनाल में पत्रकारिता (अंग्रेजी) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
3. पत्रकारिता (हिन्दी) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम,
4. विज्ञापन और जनसंपर्क में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम,
5. रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम,

6 पत्रकारिता (ओड़िया) का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, और

7. विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

क्रम संख्या-7 का पाठ्यक्रम विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए है। अफ्रीका, एशिया और लातिन अमरीका के मध्य स्तर पर कार्यरत पत्रकार इस पाठ्यक्रम में शामिल होने के बेहद इच्छुक रहते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष औसतन 20-25 लोगों को दाखिला दिया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो पाठ्यक्रमों का संचालन होता है।

भारतीय सूचना सेवा के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम

आई आई एम सी, भारतीय सूचना सेवा (आई आई एस) के अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। यह संस्थान इस सेवा के अधिकारियों को संचार तकनीकों को सीखने का अवसर देता है तथा उन्हें जन सूचना प्रणाली के प्रति अभिमुख करता है। पाठ्यक्रम में सूचना नीतियों और रणनीतियों पर विशेष फोकस है।

अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी और सम्मेलन

भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा भारत और विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में जन संचार के मुद्दों की बेहतर समझ के प्रति सहयोग की दृष्टि से संचार के विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। संस्थान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के कार्मिकों के लिए नियमित और लघु-अवधि के पाठ्यक्रमों को चलाता है। रक्षा अधिकारियों और केंद्र/राज्य और निजी क्षेत्र के विभिन्न मीडिया/सूचना संगठनों में कार्य कर रहे कार्मिकों के लिए एक सप्ताह से तीन माह तक की अवधि वाले कई अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

शोध व प्रकाशन

भारतीय जन संस्थान जन संचार शोध का एक शीर्ष केन्द्र रहा है। इन वर्षों में संस्थान ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठ/नों, सरकार और गैर सरकारी निकायों के लिए प्रमुख शोध अध्ययनों का आयोजन किया है। संस्थान ने पहले 165 से भी अधिक शोध व मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया था और इसके अलावा यहां लगभग 1500 शोध-निर्बंध तैयार किए गए हैं। इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले अधिकांश शोध अध्ययनों को प्रायोजकों द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है। यह संस्थान अपनी वार्षिक योजनाओं के हिस्से के रूप में मास मीडिया से संबंधित मुद्दों के विविध पहलुओं पर भी शोध अध्ययन आयोजित करता है।

संस्थान अंग्रेजी में 'कम्यूनिकेटर' और हिन्दी में 'संचार मध्यम' अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है। यह लेबोरेटरी पत्रिकाओं (विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों के छात्रों द्वारा) जैसी अन्य पत्रिकाओं को अपनी गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट और पत्रकारिता/जनसंचार पर पुस्तकों को प्रकाशित करता है।

योजनाएं

1. आई आई एम सी को अन्तरराष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय में बदलना

2. शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से आई आई एम सी के पी जी डिप्लोमा कोर्सों को दो वर्ष की अवधि का करने के लिए प्रस्ताव किया गया है ताकि इन कोर्सों को मास्टर डिग्री के समतुल्य बनाया जा सके।

शोध अध्ययन

संस्थान ने वर्ष 2009-10 के दौरान 7 जारी अध्ययनों को पूरा कर लिया है। इन अध्ययनों को पूरा करने के अलावा संस्थान ने सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर ''नीति के मुद्दों और भारत में विदेशी समाचार एजेंसियों के न्यूज ऑपरेशन'' नामक एक नया प्रायोजित अध्ययन भी शुरू किया है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

विश्व भर में कलाकृतियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में फिल्मों को संरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। सिनेमा को उसकी सभी विविधतापूर्ण अभिव्यक्तियों और स्वरूपों के साथ संरक्षित करने का दायित्व किसी ऐसे राष्ट्रीय संगठन को दिया जाता है जिसके पास पर्याप्त संसाधन, एक स्थाई व्यवस्था और फिल्म उद्योग का आत्मविश्वास जोकि फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में स्थापना हुई थी। इसके लिए, एनएफएआई की एक योजना स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत एनएफएआई अपने अभिलेखागार में फिल्मों का डिजिटाइजेशन और जीर्णोद्धार भी कर रही है। 'द रीस्टोरेशन ऑफ मास्टर्स' कार्य को प्राथमिकता के रूप में लिया गया है।

क्रियान्वयन के अंतर्गत स्कीमों/कार्यक्रमों के नाम:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं. स्कीम/कार्यक्रम का नाम	स्वीकृत 11वां योजना परिव्यय 2007-2012	एस.बी.जी. 2008-09	आर.ई. 2008-09	अंतिम अनुदान 2008-09	2008-09 के दौरान वास्तविक व्यय
जारी स्कीम					
अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति और प्रदर्शन	30.00	3.00	3.00	1.77	1.76
कुल	**30.00**	**3.00**	**3.00**	**1.77**	**1.76**

वास्तविक उपलब्धियां

वर्ष 2008-09 के दौरान, एनएफएआई ने 483 फिल्में, 6 वीडियो कैसेट, 316 डीवीडी, 343 पुस्तकें, 770 पटकथाएं, 1498 स्टिल्स, 1151 वाल पोस्टर, 303 गीत पुस्तिकाएं, 200 पत्र कतरनें, 10 पेंफलेट्स/फिल्म फोल्डर, 64 स्लाइडें, 15 डिस्क रिकार्ड, 18 इमेज सीडी पर रूपांतरित की गई और पोस्टर, स्टिल्स इत्यादि 1,42,352 अनुषंगी सामग्री प्राप्त की।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

1. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय एजेंसी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना भारतीय फिल्म उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहित करने और सिनेमा में श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के लिए की गयी है।

2. एनएफडीसी द्वारा वित्त पोषित/निर्मित फिल्मों और उनके निर्माण से संबंधित कलाकारों ने पूर्व में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं। एनएफडीसी

(पूर्ववर्ती फिल्म वित्त निगम सहित), ने अब तक करीब 300 ऐसी फिल्मों का निर्माण/सहनिर्माण/वित्तपोषण किया है। भारतीय फिल्म उद्योग ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में सिनेमा को समाविष्ट किया है और 17 से अधिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सह-निर्माण किया है।

3. एनएफडीसी का लक्ष्य उत्कृष्ट फिल्मों को बढ़ावा देना और विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों द्वारा भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है।

4. योजना स्कीम के अंतर्गत जारी फंड के उपयोग की समय-समय पर मंत्रालय तथा एनएफडीसी के बोर्ड निदेशकों द्वारा नियमित निगरानी की जाती है।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की उन प्रमुख एजेंसियों में से एक है जिनका काम नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और हैदराबाद में स्थित हैं। इसके 27 शाखा कार्यालय, 5 कार्यालय-सह-सूचना केंद्र और दो सूचना केंद्र हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। इन स्थानों से अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और नित्य प्रति बड़ी संख्या में पत्रकार वहां आते रहते हैं। कभी-कभी अति विशिष्ट व्यक्तियों/मंत्रियों/सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार की नीतियों की जानकारी देने के लिए प्रेस कांफ्रेस/प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करनी होती है, ऐसी हालत में ये कार्यालय बहुत सहायक सिद्ध होते हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान समाचार जगत में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, - प्रथम, इंटरनेट का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार और दूसरे-चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों का अभ्युदय। इन दोनों के कारण संचार की गति बहुत तेज हो गई है, राष्ट्रों की सीमाएं महत्वहीन हो रही हैं और समाचार संग्रह तथा वितरण में बहुत तेजी और त्वरित महत्व आ गया है। इन हालात में जहां परंपरागत मीडिया-खासतौर से प्रिंट मीडिया का महत्व बना हुआ है, वहीं अब पत्र सूचना कार्यालय को नए माध्यमों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काम करना है। नए उभरते साधनों का इस्तेमाल करते हुए अब उसे पूरी जनसंख्या तक पहुंचना है।

चूंकि आजकल इंटरनेट के जरिए सूचनाएं जल्दी मिल जाती हैं और उनमें पारदर्शिता रहती है अत: इस कार्यालय के पुराने साधनों को आधुनिक और आज के मीडिया की जरूरतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए पत्र सूचना कार्यालय को आज के ग्राहकों को तुरन्त और रोचक तरीके से सूचना पेश करने के लिए नई गतिविधियां शुरू करनी होंगी।

पत्र सूचना कार्यालय अखबारों और अन्य मीडिया से मिलने वाली प्रतिक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध कराता है ताकि वे उसके अनुकूल कदम उठा सकें और अपने प्रयासों को नई दिशा दे सकें।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों/स्कीमों/परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है :

1. नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को कान्फ्रेंस हाल, प्रेस लांज, ब्रीफिंग/कान्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी तथा अन्य आधुनिक उपकरणों सहित अति आधुनिक सुविधा एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए ब्यूरो का नई दिल्ली में अलग इमारत में एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2009-10 के दौरान इस कार्यालय का नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। नवंबर-दिसंबर 2008 में डीयूएसी तथा एनडीएमसी जैसे विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इस संबंधी वैधानिक अनुमोदन नवंबर/दिसंबर, 2008 में ही एनडीएमसी, डीयूएसी इत्यादि से प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि, एफएआर बढ़ने के चलते कुल लागत बढ़ चुकी है। एफएआर में डिजाइन फॉर्म, पार्किंग स्थान की मांग से लागत बढ़ी है। मंत्रालय/ईएफसी से नया अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। परियोजना के आकार और लागत में वृद्धि के कारण इस परियोजना की लागत बढ़कर 60 करोड़ रुपए हो चुकी है। तदनुसार, एक संशोधित ईएफसी मीमों स्वीकृति हेतु मंत्रालय को भेजा गया, जो 15 सितम्बर 2009 को प्राप्त हो गई। एनबीसीसी के साथ नए समझौते को अंतिम रुप दिया जा रहा है और उसके बाद

जल्द ही निर्माण कार्य शुरु होगा। 2009-10 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार 4 करोड़ रुपये इस कार्य के लिए आबंटित किए गए। वर्ष 2010-11 के लिए 10 करोड़ रुपये आबंटित किए गए है।

2. मीडिया आउटरीच कार्यक्रम

इस स्कीम का उद्देश्य जन सूचना अभियानों, मीडिया से बातचीत, सफलता की कहानियों तथा प्रेस दौरे आयोजित कर सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सूचना देना है। 11वीं योजना के दौरान 49.00 करोड़ रुपये का प्रशासनिक अनुमोदन 16.11.2007 को प्राप्त हुआ था। 2009-10 की अवधि में पीआईसी, मीडिया से बातचीत, 9 प्रेस दौरों और 100 सफलता की कहनियों के लिए 9.50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। दिसंबर 2009 तक 49 पीआईबी, 49 सफलता की कहानियों और 3 प्रेस दौरों पर 4.37 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वित्त वर्ष के अंत तक बाकी बची राशि भी खर्च कर ली जाएगी। एसएफसी राशि को संशोधित अनुमानों में भी बरकरार रखा गया है।

वर्ष 20010-11 के दौरान इस स्कीम के लिए 14.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

3. विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार

इस स्कीम के तीन हिस्से हैं जो इस प्रकार हैं :

क. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

फिल्म समारोह स्थल पर मीडिया केंद्र की स्थापना तथा पत्रकारों को विशेष मान्यता, स्वागत व्यवस्थाएं, प्रेस कान्फ्रेंस, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, समाचारपत्र, स्टेशनरी, फोटो कॉपियर इत्यादि सुविधाओं वाले प्रेस विज्ञप्ति वर्क रूम जैसी सुविधाओं का विस्तार। वर्ष 2009-10 के इस कार्यालय को गोवा में फिल्म समारोह हेतु 7.50 लाख रुपये आवंटित हुए। चूंकि यह समारोह नवंबर-दिसंबर 2009 में आयोजित हुआ, अत: दिसंबर 2009 में 3.20 लाख रुपए ही व्यय हो सके। एसबीजी राशि को संशोधित अनुमानों में बरकरार रखा गया। आईएफएफआई के लिए वार्षिक योजना 2010-11 के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार 8 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

ख. प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

पत्र सूचना कार्यालय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान मीडिया की सुविधा के लिए अपने अधिकारी नियुक्त करता है जो मौके पर ही पत्रकारों की सुविधा और मीडिया केंद्र में कंप्यूटर उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान टोकन प्रावधान के रूप में 1.00 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। स्कीम 3.3.2008 को अनुमोदित हुई। चूंकि प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी-फरवरी 2010 में आयोजित होना है अत: इसकीराशि उक्त अवधि में व्यय की जाएगी। एसबीसी राशि कोसंशोधित अनुमानों में बरकरार रखा गया है। 2009-10 के दौरान, जनवरी 2010 में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के लिए 1.80 लाख रुपये आवंटित किए गए। 2010-11 के लिए, जनवरी 20100 में होने वाले आयोजन हेतु 1.25 लाख रुपए आबंटित किए गए है।

ग. मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम

इस स्कीम का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच बेहतर समझ विकसित करने और मीडियाकर्मियों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। साथ ही इस बात पर भी जोर देना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और विभिन्न समाजों में सहनशीलता को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध सुदृढ़ बनाए जाते हैं और सूचना तथा मास मीडिया के क्षेत्र में निकट संबंध विकसित करने के लिए लोगों में समान इच्छाओं की प्रेरणा प्रदान की जाती है।

इस स्कीम के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सीईपी)
- संयुक्त कार्यदल
- सूचना क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता।

2009-10 के लिए 43.70 लाख रुपये इस स्कीम के लिए आवंटित किए गए थे। ईरान के दूतावास से एक बारतीय पत्रकार दल के लिए आमंत्रण प्राप्त हुआ है, जिसपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस पर लगभग 25 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है।

वर्ष 2010-11 के लिए सीईपी के लिए 15.75 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

4. पुणे में राष्ट्रमंडल युवा खेल, 2008 तथा दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए मुख्य प्रेस केंद्र और अन्य मीडिया केंद्र

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में लागू की जाने वाली यह एक नई स्कीम है। इसके लिए 3.11.2008 को 20.00 करोड़ रुपये अनुमोदित लागत के रूप में स्वीकृत हुए हैं जो 2008-09 से 2010-11 के बीच तीन वर्षों में वितरित हैं। वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, मीडिया केंद्र की स्थापना तथा शुरुआत करने और दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2010 के बारे में समय पर स्टीक जानकारी और मीडिया जागरूकता फैलाने के लिए 10.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 की आयोजन समिति के साथ बैठकों और चर्चाओं के कई दौरों के पश्चात पीआईबी के कार्यक्षेत्र और लागत को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस की गई। गहन समीक्षा के बाद, मुख्य प्रेस कंद्र की स्थापना और इसकी एवं आयोजन स्थल मीडिया केंद्रों के रखरखाव की लागत 31.75 करोड़ रुपए आंकी गई। तदनुसार, वर्ष 2009-10 के लिए एसबीसी राशि को संसोधित अनुमानों के चरण में 10 करोड़ रुपए पर ही रखा गया। वर्ष 2010-1 के लिए 21.75 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद की स्थापना और कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1966 में की गयी थी। प्रेस की आजादी को बनाये रखने और उसके स्तर में सुधार लाने के अपने दोहरे उत्तरदायित्व की पूर्ति की दिशा में परिषद बहुमुखी भूमिका अदा करती है। एक ओर यह सिविल न्यायालय की शक्तियों सहित न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, वहीं परामर्शदायी भूमिका में यह प्रेस और सरकारी अधिकारियों को प्रेस की आजादी और उसके संरक्षण से जुड़े मसलों पर मागनिर्देश भी देती है।

प्रेस परिषद का मुखिया चेयरमैन कहलाता है जो परंपरा से सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके 28 अन्य सदस्यों में 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और 3 संसद से आते हैं और 3 सदस्य सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधि के क्षेत्र से होते हैं। जिन्हें क्रमश: साहित्य अकादमी, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय बार काउन्सिल द्वारा नामित किया जाता है।

परिषद का वित्त पोषण मुख्यत: भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता द्वारा होता है। पंजीकृत समाचार पत्रों पर उनकी प्रसार संख्या के अनुसार शुल्क भी वसूला जाता है, धनराशि की कमी केन्द्र सरकार के अनुदान से पूरी की जाती है हालांकि काफी हद तक परिषद वित्तीय रूप से सरकार पर आश्रित है, फिर भी अपने काम में इसने कभी भी किसी बाहरी प्रभाव को हावी नहीं होने दिया है।

परिषद के अर्ध न्यायिक कार्य प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 14 और 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किये जाते हैं और परामर्शदायी एवं मार्ग निर्देशन कार्य धारा 13 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत किये जाते हैं।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का मुख्य कार्य सरकार और सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनों द्वारा विकास कार्यक्रमों और देश में इनके परिणामस्वरूप हो रहे बुनियादी ढांचागत परिवर्तनों का अभिलेखन करना है। प्रभाग द्वारा चित्र आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए, पत्र सूचना कार्यालय को, देश में समाचार पत्रों को आंतरिक प्रचार के लिए तथा डीएवीपी को उनके प्रर्दशन के लिए तथा प्रकाशन और बाह्य प्रकाशन प्रभाग को प्रचार के लिए उपलब्ध कायो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त फोटो प्रभाग भुगतान करने पर अन्य माध्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल्य योजना के अंतर्गत केन्द्रीय/राज्य सरकार विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों को भी फोटोग्राफ उपलब्ध कराता है। प्रभाग का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख घटनाओं से संबंधित फोटोग्राफ्स संबंधी प्रचार सामग्री उपलब्ध कराता है और ऐसी सामग्रियां अपने संग्रहालयों के लिए (आर्काइव्स को) भुगतान करने पर भी उपलब्ध कराता है। प्रभाग का एक मुख्य कार्य यह भी है कि उनको अपने संग्रहालयों के लिए (आर्काइव्स को) भुगतान करने पर भी उपलब्ध कराता है। प्रभाग का एक मुख्य कार्य यह भी है कि उनको अपने संग्रहालयों को तैयार करने और अपने पास सुरक्षित रखने के लिए फोटोग्राफ प्रचार सामग्री अपने क्षेत्रों में प्रमुख घटनाओं से संबंधित सामग्री तैयार रख सके।

तकनीकी विकास के वर्तमान परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्रभाग ने सक्षम अधिकारियों से विचार-विमर्श करते हुए अपनी योजना स्कीम को फिर से तैयार करने का निश्चय किया है।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश के सबसे बड़े प्रकाशन भवनों में से एक है। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशन विभाग द्वारा निकलने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उनके माध्यम से इस देश के लोगों की समझ का विकास हो सके। इन प्रकाशनों का लक्ष्य है इस देश के जीवन और संस्कृति के रंग-बिरंगे रुपों पर तथा पंचवर्षीय योजनाओं समेत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज की गई प्रगति पर सूचना को सम्प्रेषित करना। इस विभाग के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में महात्मा गांधी के कार्यों के संग्रह पर गौरवशाली श्रृंखलाएं, राष्ट्रीय नेताओं के भाषण, राष्ट्रीय महत्व के विषयों तथा बाल साहित्य पर शिक्षाप्रद और जानकारी देने वाली किताबें और रोजगार समाचार शामिल हैं।

प्रकाशन विभाग का कार्य है देश और विदेश में आम लोगों को भारत के बारे में अद्यतन और सही जानकारी देने के लिए आंतरिक और बाहरी प्रचार के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर लोकप्रिय पुस्तकों, पत्रिकाओं का उत्पादन, उनकी बिक्री और उनका वितरण करना। ऐसा करते हुए प्रकाशन विभाग निम्ननिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना है :-

(i) राष्ट्रीय महत्व के उन विषयों पर पुस्तकों को प्रकाशित करना जिन विषयों पर अन्य प्रकाशकों ने ध्यान नहीं दिया हो और ऐसी पुस्तकों को कम कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध बनाना।

(ii) विविधता में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि की विचारधारा और आत्मा को मजबूत करना और बढ़ावा देना।

वर्ष 2008-09 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है -

अनुलग्नक II

वर्ष 2008-09 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची :

भाषा : हिंदी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	भारतीय लोक नृत्य
2.	नाना साहेब पेशवा
3.	महापुरुषों के मनोविनोद
4.	बहादुरशाह जफर
5.	सफेद बाघ
6.	पर्वतारोहण का रोमांच
7.	ईसा की लघु कथाएं
8.	भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास (भाग-III) पुनर्मुद्रण
9.	किस्सा चार दरवेश का
10.	देश विदेश के त्यौहार
11.	बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष
12.	पी एम स्पीचेज (वाल्यूम-III)
13.	प्रकाश भारती
14.	सूचना भारती
15.	कथा कालिदास की
16.	जातक कथाएं

17. अमर शहीद भगत सिंह
18. दयाल सिंह मजीठिया
19. डा. राजेंद्र प्रसाद सचित्र जीवनी (पुनर्मुद्रण)
20. उपभोक्ता संरक्षण
21. भारतीय डाक टिकटों का इतिहास
22 राजगुरु
23. कहानियां बलिदान की
24. लोरिक चंदा (पुनर्प्रकाशित)
25. भारत की सांस्कृतिक एकता (पुनर्मुद्रण)
26. अनोखी दुनिया अनोखे लोग (पुनर्मुद्रण)
27. अपनी हिंदी सुधारें (पुनर्मुद्रण)
28. विज्ञान बारामासा
29. रामधारी सिंह दिनकर
30. भारत छोड़ो आंदोलन (पुनर्मुद्रण)
31. छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं (पुनर्मुद्रण)
32. छऊ नृत्य कला
33. सिंह (पुनर्मुद्रण)
34. मन जिसका मजबूत (पुनर्मुद्रण)
35. अष्टधाप कवि परमानंददास
36. कहावतों की कहानियां
37. अष्टछाप कवि कुंभनदास
38. ग्रामीण जीवन में विज्ञान
39. बुंदेलखंड के मूर्तिशिल्प
40. अपनी हिंदी सवारें
41. अल्बर्ट आईंस्टीन (डीलक्स)
42. संस्कृत लोकोक्ति कोश (पुनर्मुद्रण)
43. बेगम हजरत महल
44. खेल नियम और प्रशिक्षण (पुनर्मुद्रण)
45. झारखंड
46. एक पाती

47. भारत के राष्ट्रीय उद्यान
48. भारत – 2009
49. ग्रामीण जीवन में विज्ञान (पुनर्मुद्रण)
50. विज्ञान हमारे आसपास (पुनर्मुद्रण)
51. नीति कथायें (पुनर्मुद्रण)
52. सरस कथाएं (पुनर्मुद्रण)
53. बाल महाभारत (भाग–I) (पुनर्मुद्रण)
54. आंवला दान (पुनर्मुद्रण)
55. आदिवासी गढ़ छत्तीसगढ़ (पुनर्मुद्रण)
56. नेताजी संपूर्ण वांड्मय (भाग – II)
57. पर्यावरण
58. तिलक का मुकदमा
59. जमनालाल बजाज (बीएमआई) (पुनर्मुद्रण)
60. संत कबीर (पुनर्मुद्रण)
61. राष्ट्रमंडल खेल : सफरनामा मैत्री खेलों का
62. भूमंडलीकरण
63. एम.ए. अंसारी (बीएमआई)
64. शहीदों का परिचय (पुनर्मुद्रण)
65. बिधान चंद्र राय (बीएमआई)
66. भारत के समाचार पत्र
67. पुलिस जांच में विज्ञान

अंग्रेजी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	इंडिया इन स्पेस
2.	गांधी ऑर्डेन्ड इन साउथ अफ्रीका (पॉप)
	गांधी ऑर्डेन्ड इन साउथ अफ्रीका (डीलक्स)
3.	वैदिक लोर
4.	मास मीडिया इन इंडिया – 2008

5. सेलेक्टेड स्पीचेज ऑफ पी एम वॉल्यूम-IV (डीलक्स)
6. आचार्य नरेंद्र देव
7. खुदीराम बोस
8. सी डब्ल्यू एम जी (वॉल्यूम-4) पुनर्मुद्रण डीलक्स
9. सी डब्ल्यू एम जी (वॉल्यूम - 23) पुनर्मुद्रण डीलक्स
10. अर्थ इन पेरिल
11. डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैन डेवलपमेंट इन इंडिया
12. प्रेस इन इंडिया 2006-07
13. एसे ऑन इंडियन इकॉनॉमिक्स
14. डा. शांति स्वरूप भटनागर
15. इंडिया मिडिवल हिस्ट्री (पुनर्मुद्रण)
16. इंडिया - सोसायटी, रिलिजियन एंड कल्चर इन एनसियेंट एंड मिडिवल पीरियड - पुनर्मुद्रण
17. इंडिया - 2009 (ए रेफरेन्स एन्युअल)
18. इंडिया : प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड (पुनर्मुद्रण)
19. ह्वाइ पीपुल प्रोटेस्ट
20. इंडिया : आर्ट एंड आर्किटेक्चर (पुनर्मुद्रण)
21. रिपोर्ट फॉर वोट ऑन अकाउंट - (2009-10)
22. इन्सक्रिप्सन्स ऑफ अशोका (पुनर्मुद्रण)
23. सेलिब्रेटिंग सीजन्स
24. इंडिया अर्ली हिस्ट्री (पुनर्मुद्रण)
25. इंडिया गवर्नमेंट इकॉनॉमिक्स लाइफ इन एनसियेंट एंड मिडिवल पीरियड (पुनर्मुद्रण)
26. 2500 इयर्स ऑफ बुद्धिज्म (पुनर्मुद्रण)
27. सी डब्ल्यू एम जी (वॉल्यूम - 21) पुनर्मुद्रण (डीलक्स)
28. सी डब्ल्यू एम जी (वॉल्यूम - 24) पुनर्मुद्रण (डीलक्स)
29. सी डब्ल्यू एम जी (वॉल्यूम - 25) पुनर्मुद्रण (डीलक्स)
30. सी डब्ल्यू एम जी (वॉल्यूम - 41) पुनर्मुद्रण (डीलक्स)

क्षेत्रीय भाषाएं

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	बुद्ध गाथा (उड़िया)
2.	विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं - III (मराठी)
3.	गांधी - ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (गुजराती)
4.	सेक्शनल केटेलॉग (बाइलिंगुअल) (अंग्रेजी/हिंदी)
5.	बापू के साथ (पुनर्मुद्रण) (तेलुगु)
6.	विदेशी यात्रियों की नजर में भारत - (पुनर्मुद्रण) (तमिल)
7.	बहादुर बच्चे (पुनर्मुद्रण) (तेलुगु)
8.	पंजाब दे लोक नाच (पंजाबी)
9.	सी. एन. अन्नादुरई (बी एम आई)(पुनर्मुद्रण) (तमिल)
10.	श्रीनिवास आयंगर (बी एम आई) (पुनर्मुद्रण) (तमिल)
11.	देश-विदेश की कहानियां (बंगाली)
12.	इंडियन फोक डांसेज (पंजाबी)
13.	रोचक एतिहासिक कहानियां (मराठी)
14.	रोचक एतिहासिक कहानियां (तमिल)
15.	खजीरा-ए-ग़ालिब (उर्दू)
16.	क्रांतिदूत अजीमुल्लाह खान (पंजाबी)
17.	विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं - (पार्ट - II) (उड़िया)
18.	विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं - (पार्ट - IV) (उड़िया)

वर्ष 2009-10 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की सूची :

हिंदी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	1857 की जनक्रांति - विविध आयाम (आजकल के आलेखों का संकलन)
2.	परिणाम बजट (2009-10) (आउटकम बजट 2009-10)

3. वार्षिक रिपोर्ट (2008-09) (एनुअल रिपोर्ट 2008-09)
4. चतुर्भुज दास - अष्ट छाप कवि
5. दलित देवो भव - II
6. दशकुमार चरित
7. गुरु नानक
8. हाथी दादा की चौपाल
9. इंडियन रेलवेज (भारतीय रेल)
10. लालू का मोबाइल
11. नेताजी संपूर्ण वांड्मय, वॉल्यूम-10 (सुभाष चंद्र बोस)
12. प्रेरणा दीप
13. रोजगार की नई दिशाएं (इम्पलॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार से संग्रह)
14. पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानी
15. तिरूक्कुरल
16. गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहब तक

अंग्रेजी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	ट्राइबल फ्रीडम फायटर्स ऑफ इंडिया
2.	आउटकम बजट 2009-10
3.	एनुअल रिपोर्ट 2008-09
4.	चिल्ड्रेन इन इंडिया - ए लीगल पर्सपेक्टिव
5.	सर छोटू राम
6.	स्टेम सेल
7.	केटेलॉग - 2009
8.	बदरुद्दीन तैय्यबजी (बीएमआई)
9.	ग्रेट लाइवस, ग्रेट वर्ड्स
10.	प्रेस इन इंडिया 2007-08

भाषा : क्षेत्रीय भाषाएं

क्र.सं.	पुस्तक का नाम
1.	इंडियन कॉस्ट्यूम्स (भारतीय पोशाक) बंगाली
2.	बेताल कथाएँ (फेंटम टेल्स) उड़िया
3.	एन इंट्रोडक्सन टू इंडियन म्यूजिक (तमिल)
4.	दुर्गा बाई देशमुख (तेलुगु)
5.	जवाहरलाल नेहरु – ए पिक्टोरियल बायोग्राफी (मलयालम)
6.	सरदार वल्लभभाई पटेल (बीएमआई) बंगाली

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

साप्ताहिक रोजगार समाचार अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख प्रकाशन है। इस साप्ताहिक पत्र में केंद्रीय एवं राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, स्वायत्त निकायों, विश्वविद्यालयों, विदेशी संस्थानों जैसे फोर्ड फाउंडेशन, ब्रिटिश काउंसिल आदि में नौकरियों के विज्ञापन, व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए प्रवेश अधिसूचनाएं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे संगठनों तथा अन्य सामान्य भर्ती निकायों की परीक्षा अधिसूचनाएं और उनके परिणामों तथा मध्य-स्तरीय रोजगार उन्नयन के अवसरों (प्रतिनियुक्तियों) की सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक सम्पादकीय हिस्सा भी है जो कैरियर से सम्बन्धित दो मुख्य लेख प्रकाशित करता है।

इस साप्ताहिक पत्र का मूल लक्ष्य सिविल सेवा के अभ्यार्थियों, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में बैठने वाले उम्मीदवारों, अपने कैरियर तथा पेशे को चुनने के लिए तैयार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेवारी, जिसके लिए इस पत्र को शुरू किया गया था, निभाने के साथ-साथ एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार नियमित रूप से पर्याप्त लाभ कमा रहा है। यह पत्र, जिसे सबसे अधिक प्रसारित साप्ताहिक पत्रों में शामिल होने का गौरव प्राप्त है, हर शनिवार को देश के कोने-कोने में उपलब्ध होता है।

सरकार के इस इंटरेक्टिव कैरियर साप्ताहिक ने अपनी कैरियर वेबसाइट www.employmentnews.gov.in खोलकर अपने खाते में एक और उपलब्धि दर्ज की है। यह वेबसाइट बहुत अधिक सफल रही है तथा युवाओं में बहुत लोकप्रिय हो रही है। हर रोज 3 लाख से अधिक लोग इस वेबसाइट को खोलते हैं। सरकारी क्षेत्र में यह सबसे अधिक हिट पेज है। वेबसाइट के जरिये पेश की जा रही ऑनलाइन सेवाओं में कैरियर परामर्श, सरकारी क्षेत्र में रिक्तियों के बारे में अग्रिम जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

भारत के समाचार पत्र पंजीयक का कार्यालय की स्थापना पहली जुलाई 1956 को प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 में संशोधन करके की गई थी। यह कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विधि विहित कार्य इस प्रकार हैं :

(1) देश भर में प्रकाशित समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का एक रजिस्टर तैयार काना उसका रख-रखाव करना तथा उसमें समाचार पत्रों/पत्रिकाओं का विवरण संकलित करना।

(2) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सिफारिश के बाद समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के शीर्षक की उपलब्धता की जांच के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना।

(3) समाचार पत्रों के प्रकाशकों द्वारा प्रेस एवं पुस्त्क पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन की जानकारी सुनिश्चित करना।

(4) प्रकाशकों द्वारा समाचार पत्रों की प्रसार संख्या के दावों की जांच करना।

(5) भारत में प्रेस के बारे में उपलब्ध समस्त सूचनाओं, आंकड़ों और विशेष तौर पर विभिन्न श्रेणियों के समाचार पत्रों पत्रिकाओं के आए बदलावों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

इसके अतिरिक्त कार्यालय के सामान्य कार्य इस प्रकार हैं :

(क) अखबारी कागज आंबटन के लिए समाचार पत्रों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना ताकि वह अखबारी कागज का आयात कर सकें।

(ख) समाचार प्रतिष्ठानों की प्रिंटिंग मशीनें (मुद्रण) और अन्य संबंधित सामग्री आयात करने की आवश्यक जरूरतों का मुल्यांकन ओर प्रमाणपत्र जारी करना।

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों को शोध के संबंध में एकत्रित, संकलित और तैयार सामग्री के प्रकाशन कार्य आदि में सहायता करता है। मीडिया इकाइयों के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी का सारांश निर्मित करना और सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन एवं पृष्ठभूमि नोट तैयार करना भी इस प्रभाग का दायित्व है। 1945 में स्थापित किया गया यह विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं इसकी अनेक मीडिया इकाइयों के लिए सूचना प्रदान करने वाली एक इकाई के रूप में काम करता है। यह प्रभाग जनसंचार क्षेत्र की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए जनसंचार की संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा को कायम रखता है। प्रभाग मंत्रालय, इसकी मीडिया इकाइयों तथा जनसंचार से संबद्ध अन्य इकाइयों को पृष्ठभूमि, संदर्भ तथा शोध सामग्री उपलब्ध कराता है।

यह प्रभाग वर्ष के दौरान दो वार्षिक संदर्भ ग्रंथ तैयार करता है, इंडिया - संदर्भ वार्षिकी, यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ-शासित क्षेत्रों तथा पीएसयू/स्वायत्त निकायों द्वारा किए गए विकास और उन्नति का संकलन है। भारत में मास मीडिया (मास मीडिया इन इंडिया) यह भारत के जनसंचार पर एक विस्तृत प्रकाशन है। साथ ही इंडिया को हिंदी में भारत शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है। गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग ने 15 जनवरी 2010 को वार्षिक संदर्भग्रंथ-इंडिया-2010 के 54वें संस्करण को सफलतापूर्वक जारी किया।

यह प्रभाग नियमित रूप से हर पखवाड़े 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालता है जो अभिलेख और संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित होता है। यह प्रभाग विषय विशेष पर आधारित पत्रिकाओं की मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। इन पत्रिकाओं में एफडीआई की हिस्सेदारी होती है और ये विषय विशेष से संबंधित होती हैं जिसके लिए इन्हें भारत में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाती है। इन पत्रिकाओं का अनुवीक्षण यह देखने के लिए किया जाता है कि ये सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन कर रही हैं अथवा नहीं।

संदर्भ पुस्तकालय

इस प्रभाग का पुस्तकालय विभिन्न विषयों पर दस्तावेजों के बड़े संग्रह, चुनी हुई पत्रिकाओं के सजिल्द ग्रंथों तथा मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टों से सुसज्जित है। इसके संग्रह में पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन एवं दृश्य-श्रव्य प्रचार माध्यम, प्रमुख विश्वकोष, सम-सामयिक लेख और वार्षिकी शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त पुस्तकालय की सुविधाएं मान्यता प्राप्त भारतीय एवं विदेशी पत्रकारों के लिए भी उपलब्ध हैं। जगह की कमी के चलते वर्ष 2009-2010 के दौरान (जनवरी 2010 तक) केवल 19 नई किताबें ही शामिल की जा सकीं। अब तक लगभग 27 हजार पुस्तकों के संबंध में डाटा एंट्री कार्य पूरा किया जा चुका है। पुस्तकालय पहले शास्त्री भवन में स्थित था। इसे वर्ष 2008 में सूचना भवन में स्थानांतरित किया गया।

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केन्द्र (एनडीसीएमसी) का गठन 1976 में मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इसकी सावधिक सेवाओं के माध्यम से जन संचार माध्यम की प्रवृत्तियों और उनसे जुड़ी घटनाओं की जानकारी एकत्र कर उनकी व्याख्या करना इसका मुख्य दायित्व है। एनडीसीएमसी जनसंपर्क/संचार पर उपलब्ध बड़े समाचारों, लेखों तथा सूचनाओं का प्रलेखन करता है। यह पूरे देश में जनसंचार के विकास के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रवाह में शामिल होने के लिए सूचना के संग्रहण और प्रलेखन से लेकर इसके प्रचार-प्रसार तक समसामयिक गतिविधियों का केंद्रीय क्षेत्र है।

एकत्रित सूचना को विभिन्न सेवाओं के द्वारा अनुरक्षित एवं प्रचारित किया जाता है जैसे - समसामयिक जागरूकता सेवा - केंद्र द्वारा खरीदे जा रहे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में मास मीडिया पर चुनिंदा लेखों की प्रकाशित सूची, **संदर्भ ग्रंथ सेवा** - केंद्र द्वारा खरीदे जा रहे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में पिछले एक वर्ष के दौरान प्रकाशित मास मीडिया पर लेखों की विषय सूची, **फिल्म बुलेटिन** - भारत के फिल्म उद्योग के विकास का एक सारांश, **संदर्भ सूचना सेवा** - मास मीडिया क्षेत्र के प्रासंगिक हितों के विषयों पर पृष्ठभूमि दस्तावेज, - **हूज हू इन मास मीडिया**-लोक प्रसिद्ध विभिन्न मीडिया व्यक्तियों की जीवनियां, जनसंचार में कौन क्या है, **जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कार** - वर्ष के दौरान जनसंचारकों को दिए गए पुरस्कारों के साथ-साथ घोषित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की झलकियां और **मीडिया अपडेट** - यह प्रलेख और संदर्भ के लिए बड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को केंद्रित करती है।

राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केंद्र **मास मीडिया इन इंडिया** नामक एक संदर्भ पुस्तक का संकलन एवं संपादन भी करता है। इस वार्षिकी में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मीडिया संगठनों की स्थिति पर सूचना और मास मीडिया के कई पहलुओं पर लेखों को शामिल किया जाता है। इस अवधि के दौरान **मास मीडिया इन इंडिया** का **21वां** संस्करण जारी किया गया। इसमें प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आम सूचना को भी शामिल किया जाता है। गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के अधीन राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केंद्र ने वर्ष 2009-10 के दौरान (जनवरी 2009 तक) मास मीडिया के विविध पहलुओं पर 46 सेवाएं जारी कीं।

वर्ष 2009-10 की झलकियां

- गवेषणा संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग ने 15 जनवरी 2010 को संदर्भ वार्षिकी - इंडिया 2010 का 54वां संस्करण सफलतापूर्वक प्रकाशित किया।

- गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग की एक इकाई राष्ट्रीय जनसंचार प्रलेखन केंद्र ने वर्ष 2009-10 के दौरान (जनवरी 2009 तक) मास मीडिया के विभिन्न पहलुओं पर 46 सेवाएं जारी कीं।

- प्रभाग के पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 27000 पुस्तकों का डाटा एंट्री कार्य पूरा किया गया।

गीत एवं नाटक प्रभाग

परिचय

प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार माध्यम के रूप में पारंपरिक कलाओं और विलुप्त हो चुकी लोक कलाओं को फिर से पुर्नजीवित करने के उद्देश्य से एक छोटी प्रयोगात्मक इकाई के रूप में की गई थी। प्रभाग ने कलाओं के माध्यम से समकालिक विचारों, मुद्दों और तरीकों को उपनाकर लोगों के साथ तात्कालिक तादात्म्य स्थापित किया जिससे लोगों के बीच में एक जीवन्त माध्यम के रूपमें लोकप्रियता हासिल की है। प्रभाग ने दुर्गम पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान और सीमावर्ती क्षेत्रों निचले स्तर पर लोगों के साथ प्रभावी ढंग से सम्पर्क स्थापित करके अपनी पहुंच और प्रभाव के क्षेत्र में बहुत विस्तार किया है।

उद्देश्य

प्रभाग के कार्यों के बारे में इसकी वेबसाइट में विस्तार से बताया गया है। इसके मुख्य कार्यों में देश की प्रगति के अनुकूल सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों को आम जनता में जागरूकता और भावनात्मक स्वीकार्यता पैदा करना है। यह सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में रक्षा की तैयारियों और देश के बाकी हिस्सों से सांस्कृतिक एकजुटता को लेकर विश्वास पैदा करने के लिए काम करता है। इसके कामकाज में सीमा के अलग थलग इलाकों में तैनात सैनिकों के मनोबल को बनाए रखना भी शामिल है। यह अपना काम मनोरंजन के जीवंत साधनों के जरिए करता है जिनमें देश के सभी क्षेत्रों की शहरी नाटय विधाएं और लोक विधाएं भी शामिल हैं।

अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रभाग नाटक, नृत्य नाटिका, ओपेरा, वाचन और कठपुतली जैसी विभिन्न लोक और पारंपरिक विधाओं का सहारा लेता है। यह प्राचीन परंपरा वाले सैकड़ों जादुगरों की सेवाएं भी लेता है। इसके अलावा यह ध्वनि और प्रकाश की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए साम्प्रदायिक सदभाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम करता है जिनमें सैकड़ों कलाकारों की सेवाएं ली जाती हैं।

इस तरह प्रभाग देश के विभिन्न हिस्सों की अनगिनत लोक और पारंपिक विधाओं को पुनर्जीवित करने और उनहें बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही वह हजारों कलाकारों की कलाओं का सोद्देश्य संवाद के लिए उनकी भाषाओं, मुहावरों और बोलियों में इस्तेमाल कर उन्हें आजीविका भी मुहैया करता है।

प्रभाग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका प्रमुख एक निदेशक होता है। इसके 10 क्षेत्रीय केन्द्र बंगलूरू, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में हैं। दरभंगा, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, इंफाल, नैनीताल और शिमला में इसके सात सीमा केन्द्र हैं। प्रभाग के छह विभागीय नाटय दल भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर में हैं। इसके अलावा सशस्त्र बल मनोरंजन शाखा योजना के तहत कलाकारों के आठ दल दिल्ली में और एक चेन्नई में है। इन नौ दलों की जिम्मेदारी सीमा के सुदूर और अलग-थलग इलाकों में सशस्त्र बलों का मनोरंजन करना है।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, प्रेस प्रकाशनों, विज्ञापन और नृत्य तथा नाटक जैसे परम्परागत तरीकों से सूचना के गुप्त प्रवाह तक लोगों की पहुंच करने में सहायता देकर प्रभावी भूमिका निभाता है। मंत्रालय राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों का ध्यान केन्द्रित करने के लिए मनोरंजन और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की बौद्धिक आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। इसके लिए मंत्रालय को सूचना शाखा, प्रसारण शाखा, फिल्म शाखा और समेकित वित्त शाखा जैसी चार शाखाओं की सहायता मिलती है। 'निजी एफएम रेडियो' योजना स्कीम, निजी एफएम प्रसारकों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराती है जिससे वे स्पेक्ट्रम के प्रभावली उपयोग के लिए किसी सामान्य स्थान पर उन्हें संप्रेशन सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र

केन्द्रीय अनुश्रवण सेवा को राष्ट्रीय तकनीक शोध संगठन (एनटीआरओ)में बदलने के बाद, सरकार की प्रसारण सामग्री के विषयों के अनुश्रवण के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) की स्थापना का निर्णय लिया गया। निरंतर बढ़ रहे निजी और विदेशी टीवी चैनलों के विषयों के अनुश्रवण करने की जरूरत महसूस की गई ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत बने नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन को रोकने के लिए नियम बनाए जा सकें। साथ ही हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के बाद निजी और विदेशी चैनलों के अनुश्रवण की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय चैनल

भूमंडलीकरण के युग में किसी भी देश के खास तौर पर भारत जैसे देश के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है अंतर्राष्ट्रीय चैनल को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। बीबीसी, सीएनएन इत्यादि विश्व के अत्यंत ही प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चैनल हैं। मुख्य उद्देश्य है भारत की स्थिति का दुनिया भर में उसी प्रकार प्रचार करना जिस तरह से अलजजीरा, बीसीसी, सीएनएन, सीसीटीवी इत्यादि चैनल करते हैं। इसके लिए डीडी इंडिया, जिसे बहुत से देशों में देखा जाता है, पर प्रसारण के साथ-साथ वर्तमान डीडी न्यूज चैनल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी।

सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां

दिसंबर 2006 में, भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो के लिये नीति को लचीला बनाया और अलाभकारी संस्थाओं को रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये अनुमति देने का निर्णय लिया। यह संगठन नागरिक समुदाय तथा स्वैच्छिक संगठन, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विज्ञान केंद्र, पंजीकृत सोसायटी आदि स्वायत्त निकाय और सोसायटी अधिनियम अथवा एसे ही किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट जो कि एसी गतिविधियों में शामिल हो और जो अर्हता शर्तों को पूरा करता हो।

सूचना भवन का निर्माण

सूचना भवन के निर्माण पर होने वाला व्यय योजना आयोग की मंजूरी के पश्चात इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए गये योजना बजट से पूरा किया जाता है। अब तक उपलब्ध निर्मित स्थान विभिन्न मीडिया इकाइयों को आबंटित किया गया है, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन विंग, गीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, फिल्म प्रभाग, प्रकाशन विभाग, गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग, भारतीय प्रेस परिषद, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (अंशत:) और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। सूचना भवन के चरण V के पूरा होने पर उपलब्ध निर्मित स्थान का आबंटन बाकी मीडिया इकाईयों को किया जाएगा और यदि फिर भी स्थान बचता है, तो उसे अन्य विभागों को किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा।

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

अर्थव्यवस्था के तहत मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान उच्च वृद्धि की उम्मीद है। विकास की इस गति से लाभ उठाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों संबंधी विभिन्न स्कीम/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि निर्धारित लक्ष्यों/उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। प्रत्येक स्कीम/कार्यक्रम से संबंधित कार्ययोजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें भौतिक और वित्तीय दोनों तरह से लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा। कार्यान्वयन प्रगति की मंत्रालय स्तर पर भी निगरानी की जाएगी। इन स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा छमाही आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी तथा रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा।

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्र में प्रमुख मंत्रालय की भूमिका के रुप में कार्य करता है। यह मंत्रालय मीडिया से संबंधित नीतियों को बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी निभाता है। मंत्रालय अपनी विभिन्न मीडिया इकाईयों के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने, बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और फिल्मों सहित विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए जागरुकता पैदा करने का कार्य कर रहा है। मंत्रालय की मीडिया इकाईयां, स्वायत्त संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के कामकाज में उसकी सहायता करते हैं।

भारतीय सूचना सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और डेपुटेशन में अन्य सेवाओं से आए कई अन्य सेवाओं के अधिकारियों को विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों और मीडिया इकाइयों की आवश्कता अनुरुप विदेशों में प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस योजना में व्यय केवल राजस्व व्यय के अंतर्गत किया जाता है। मंत्रालय की आवश्कताओं और पाठ्यक्रम की उपयुक्तता के अनुसार लघु अवधि और दीर्घावधि के विवेक सम्मत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाएंगे। मंत्रालय अपने अधिकारियों को संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजता है।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य जनसंचार का कामकाज कर रहे अधिकारियों को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में आये बदलावों से रूबरू कराना ताकि वह अपने संगठनों के विकास और उत्थान के लिए बेहतर कार्य कर सकें।

प्रसार भारती

अधिदेश

अधिदेश प्रसार भारती नाम से भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना के प्रावधान बनाए गए। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को 15 सितंबर 1997 से लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि निगम सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण का कार्य करेगा। यानी जो कार्य पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन करते थे, वह कार्य अब यह निगम करेगा। निगम के सामान्य पर्यवेक्षण निर्देशन और प्रबंध के कार्य प्रसार भारती बोर्ड को सौंपे जाएंगे। यह बोर्ड अपने ऐसे सभी अधिकारों का इस्तेमाल और अपने ऐसे सभी कार्य उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार इस अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

निगम अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अधिनियम में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानूनी तौर पर इस बारे में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार निगम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इक्विटी सहायता अनुदान या ऋण के रूप में धनराशि प्रदान कर सकती है। निगम का अपना कोष होगा और निगम की सारी प्राप्तियां इसी कोष में जमा की जाएंगी और निगम सभी भुगतान इसी कोष से करेगा।

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम का प्राथमिक दायित्व सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा को संचालन करना तथा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना होगा। स्पष्टीकरण—शंका दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस खंड के प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अलावा होंगे, न कि अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध होंगे।

2. निगम अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा :

(क) देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में निहित मूल्यों का संरक्षण।

(ख) सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में मुक्त, सच्ची तथा निष्पक्ष सूचना प्राप्त करने के नागरिक के अधिकार का संरक्षण तथा अपनी विचारधारा या किसी राय को जोड़े बिना विविध दृष्टिकोणों सहित सूचना की निष्पक्ष तथा संतुलित प्रस्तुति।

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में एवं साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं तकनीक पर विशेष ध्यान देना।

(घ) उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा देश के विविध क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं भाषाओं को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।

(ङ) क्रीड़ा एवं खेल को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना जिससे कि स्वस्थ प्रतियोगिता एवं खेल भावना को बढ़ावा मिले।

(च) युवाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(छ) महिलाओं की स्थिति एवं समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाना तथा महिला उत्थान पर विशेष ध्यान देना।

(ज) शोषण, असमानता को दूर करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने एवं छुआ-छूत जैसी बुराई को दूर करने तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करना।

(झ) कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देना।

(ञ) कमजोर एवं ग्रामीण वर्ग तथा सीमावर्ती क्षेत्र, पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना।

(ट) अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(ठ) बच्चों, नेत्रहीनों, बूढ़ों, अपंगों एवं जनता के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।

(ड) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, ऐसे प्रसारण करना जो भारत में विभिन्न भाषाओं के जरिए संवाद को बढ़ाते हों और हर राज्य में वहां की भाषा में क्षेत्रीय प्रसारण को बढ़ावा देना।

(ढ) उपयुक्त तकनीक द्वारा समग्र प्रसारण कवरेज प्रदान कराना तथा प्रसारण फ्रीक्वेंसी का सर्वोत्तम उपयोग एवं उच्च-स्तरीय उपलब्धियां सुनिश्चित करना।

(ण) रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के निरंतर विकास के क्रम में शोध एवं विकास कार्य को आगे बढ़ाना।

(त) विभिन्न स्तरों पर प्रसारण के विभिन्न चैनलों की स्थापना द्वारा प्रसारण सुविधाओं का विस्तार।

3. विशेष रूप से एवं बिना पूर्वाग्रह के सामान्य रूप से, वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप, निगम कुछ कदम उठा सकता है :

(क) कार्यक्रमों के निर्माण एवं उपलब्धता को लोकसेवा के रूप में संचालित करने के लिए प्रसारण को सुनिश्चित करना।

(ख) रेडियो एवं टेलीविजन के लिए समाचार एकत्र करने के लिए एक व्यवस्था की स्थापना।

(ग) खेल प्रतियोगिताओं, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, फिल्मों, सीरियलों, समारोहों, बैठकों तथा जनहित की अन्य घटनाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए खरीद अथवा प्राप्ति के लिए बातचीत करना और ऐसे कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(घ) रेडियो, टेलीविजन या अन्य सामग्री के लिए लाइब्रेरी की स्थापना एवं देखभाल।

(ङ) समय-समय पर कार्यक्रम, दर्शक शोध, बाजार या तकनीकी सेवाओं को संचालित या प्रारंभ करना, जो उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त तरीकों और नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य किए जा सके।

(च) नियमों द्वारा विर्निदिष्ट हो सकने वाली अन्य सेवाओं को प्रदान करना।

4. उपखंड (2) और (3) निगम की कोई बात निगम को, ऐसे नियमों एवं शर्तों के अनुसार जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हों, विदेशी सेवाओं के प्रसारण और ऐसे विदेशी प्रसारण की निगरानी से नहीं रोक सकती जिनके प्रसारण के लिए केंद्र सरकार से भुगतान किया जाना हो।

5. इस खंड में स्थापित उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया गया है, इनकी सुनिश्चितता के उद्देश्य के लिए विज्ञापन के संबंध में केंद्र सरकार को प्रसारण समय की अधिकतम सीमा के निर्धारण की शक्ति होगी।

6. निगम की मात्र इस आधार पर कोई भी सिविल जवाबदेही नहीं होगी कि वह इस खंड के किसी भी प्रावधान को पूरा करने में असफल रहा है।

7. निगम को विज्ञापन या ऐसे कार्यक्रम, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो, के संबंध में फीस या अन्य सेवा शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा।

इस खंड के अधीन इकट्ठा किए गए फीस या अन्य सेवा शुल्क समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वैसी सीमाओं से बाहर नहीं हो।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो), प्रसार भारती का एक अभिन्न भाग है, जो उपरोक्त दिए गए आदेशों को निरंतर पूरा कर रहा है। आकाशवाणी अपने विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों द्वारा लोगों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। यह पूरे देश की जनता को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की सूचना श्रव्य-प्रसारण के माध्यम से देता है और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित

करता है। यह पूरे देश की जनता को महत्वपूर्ण समाचार तथा सम-सामयिक घटनाओं की जानकारी देता है। यह विचारों के विभिन्न बिंदुओं को प्रस्तुत करता है ताकि इसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम संतुलित एवं निष्पक्ष हों। यह शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने तीव्र प्रसार के द्वारा जनता एवं सरकारी विभागों को समय पर सूचना प्रदान करता है। यह एक व्यवसायिक सेवा (विविध भारती) भी संचालित करता है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के विज्ञापन भी देता है। इसका विदेश सेवा प्रभाग विदेशी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे ताजा समाचार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आकाशवाणी का एफएम और डीटीएच चैनल दिन-रात संगीत, गाने आदि के जरिये लोगों का मनोरंजन करते हैं।

नीति वक्तव्य

सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती के उद्देश्य हैं

- गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बनाना और
- महिलाओं, बच्चों, सुविधाविहीन, विशिष्ट भाषाई समूहों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रदान करने, शिक्षा देने और मनोरंजन करने के प्रयोजन को पूरा करना।

प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी, प्रसार भारती के अधिदेश को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयत्न करता है। अनेक प्रकार की नई पहल की जा रही है, जैसे 86 चुने हुए आकाशवाणी स्टेशनों से खेत और घर से जुड़े कार्यक्रम- किसान वाणी कार्यक्रम, पर्यावरण, परिवार कल्याण, ग्रामीण बच्चों और छोटे बच्चों को केंद्र में रखकर बनए गए विशेष कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, शैक्षिक प्रसारण (इग्नू/एसीईआरटी/सीआईईटी) दिखाए जा रहे हैं। एचआईवी/एड्स पर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम और दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों, इग्नू के सहयोग के साथ कार्यक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका (विज्ञान भारती), सीसेम स्ट्रीट कार्यक्रमों को आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया है, साथ ही संगीत और नाटक से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाता है। पहल के इंजीनियरिंग पक्ष की ओर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज कार्यक्रम चलाए गए हैं और एफएम सेवाओं का विस्तार, प्रॉडक्शन कार्यक्रमों और ट्रांसमिशन सुविधाओं का डिजिटलीकरण एवं नई तकनीक को प्रस्तावित किया गया है। समाचार सेवा प्रभाग और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित गतिविधियों को भी संचालित किया गया है।

सभी प्रकार की पहल के उचित एवं समयाबद्ध कार्यान्वयन को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

भारतीय क्लासिक योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम का निर्माण और देश की समृद्ध संस्कृति तथा साहित्यिक विरासत को संरक्षित रखना है। योजना के अंतर्गत सभी कार्यक्रम सभी भारतीय भाषाओं में बनाए गए हैं और इन साहित्यिक रचनाओं को अन्य भाषाओं में डब किया गया है जिससे देश के सभी दर्शकों को लाभ प्राप्त हो।

दूरदर्शन में, महाराणा रंजीत सिंह की ऐतिहासिक गाथा पर 52 एपीसोड की श्रृंखला निर्माणाधीन है। फोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, कॉमन वरशिप सेंटर्स जैसे चुनींदा विषयों पर विशेष कार्यक्रम निर्माणाधीन हैं।

दूरदर्शन सार्वजनिक सेवा प्रसारण कोष के सहयोग से व्यापक स्तर के विषयों पर वृत्तचित्रों का निर्माण कर रहा है। इसके अंतर्गत हर वर्ष चार वृत्तचित्रों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

डीडी उर्दू

पांच करोड़ 20 लाख उर्दू भाषी आबादी की जरूरतों को देखते हुए और उर्दू की साहित्यिक व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए 15 अगस्त 2006 को डीडी उर्दू अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य इस चैनल पर अच्छे विषय और लक्षित दर्शकों के कल्याण के लि अनेक कार्यक्रमों को प्रसारित करना है। इसके लिए डीडी की अधिग्रहण परियोजना के माध्यम से सॉफ्टवेयर खरीदा गया है और डीडी में इसे तैयार भी किया गया है।

डीडी न्यूज

डीडी न्यूज पहला और एकमात्र क्षेत्रीय न्यूज चैनल है जो देश की लगभग आधी आबादी तक पहुंचता है। इस चैनल की शुरुआत नवंबर 2003 में हुई थी। डीडी न्यूज बिना सनसनी के, संतुलित समाचारों के प्रसारण को सुनिश्चित करते हुए सत्य, सर्वत्र, संपूर्ण (पूरा सच हमेशा) का आदर्श वाक्य देता है।

आज के मीडिया परिदृश्य में, जहां 24 घंटे के अनेक निजी समाचार चैनल मौजूद हैं, डीडी न्यूज जैसे 24 घंटे के क्षेत्रीय सेटेलाइट राष्ट्रीय समाचार चैनल की मजबूत उपस्थिति की जरूरत है। सरकारी दृष्टिकोण, विशेष रूप से विकास नीतियों और कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए यह अनिवार्य है। डीडी न्यूज एकमात्र भारतीय न्यूज चैनल है जो देश के 50 प्रतिशत लोगों तक पहुंचता है, विशेष रूप से समाज के सुविधाविहीन और अभावग्रस्त तबकों तक जो केबल सेटेलाइट के जरिए देश से जुड़े हुए नहीं हैं। राष्ट्रीय आपदा, विनाश आदि की स्थिति में, सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

श्रोता अनुसंधान खंड

श्रोता अनुसंधान खंड अनुसंधान और आंकड़ा एकत्रीकरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से चैनलों पर कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनकी गुणवत्ता सुधारने में महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोता अनुसंधान डीटीएच पेनेट्रेशन और कृषि कार्यक्रमों की नेरोकास्टिंग की मदद से देश भर में सर्वेक्षण करता है। श्रोता अनुसंधान खंड देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपनी 18 इकाइयों के सहयोग से शहरी और ग्रामीण इलाकों में डार्ट सर्वेक्षण भी करता है। वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव पर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा किया गया है।

इन हाउस सर्वेक्षणों के अतिरिक्त दूरदर्शन ने टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से रेटिंग डेटा और एमआरयूसी से बेसलाइन डेटा प्राप्त करेगा और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में चैनल प्रबंधकों एवं मार्केटिंग विभाग को प्रदान करेगा।

डीडी भारती

डीडी भारती एक सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने वाला चैनल है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तावित, प्रोत्साहित और संरक्षित रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है। चैनल संगीत, नृत्य, विरासत, स्वास्थ्य, बच्चों पर केंद्रित है और भारतीय जीवन शैली, दर्शन, कला और संस्कृति पर बल देता है। चैनल संगीत और नृत्य, पर्व, विशेष घटनाओं, मुशायरा, कवि सम्मेलन आदि के लाइव कवरेज को भी प्रसारित करता है। फिक्स प्वाइंट चार्ट्स में परिवर्तन के साथ, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए चैनल ने नए कार्यक्रमों को भी प्रस्तावित किया है। कार्यक्रमों में वैविध्य तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए नए कार्यक्रम भी खरीदे गए हैं। कार्यक्रमों, विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कार्यक्रमों में सुधार के लिए फिर कमीशनिंग प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय प्रसारण

देश की सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नता के मद्देनजर दूरदर्शन देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं –तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, असमी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और कश्मीरी – बोलने वाले लोगों के हित के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। मुख्य भाषा के कार्यक्रमों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय भाषाओं के 1१ सेटेलाइट चैनल भी उर्दू, सिंधी, संस्कृत, टुलु, कोंकणी, डोगरी, हिमाचली, हरियाणवी, नेपाली और उत्तर पूर्व की सबी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम राज्य में विभिन्न एचपीटी और एलपीटी के क्षेत्रीय सहयोग के साथ सेटेलाइट पर, जमीनी ट्रांसमीटरों के माध्यम से डीडी 1 की क्षेत्रीय विंडो के रूप में दोपहर तीन बजे से शाम आठ बजे तक उपलब्ध रहते हैं। तमिलनाडु में यह क्षेत्रीय सहयोग रात 11 बजे तक रहता है।

इन क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित विभिन्न कार्यक्रम और फॉरमेट उपलब्ध कराए जाते हैं और इन्हें संबंधित राज्य के राजधानी केंद्र से फीड और प्रसारित किया जाता है। इन चैनलों पर फीचर फिल्में, फिल्मी गाने, धारावाहिक, शास्त्रीय-सुगम-लोक संगीत, नृत्य, समाचार और समसामयिक कार्यक्रम, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि प्रसारित किए जाते हैं जोकि श्रोता विशेष की रुचि के कार्यक्रमों के साथ समाज के सभी तबकों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं का रंजन करते हैं।

राज्य नेटवर्क

दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेवा प्रसारण भी हैं जिन्हें राज्य नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए है। एचपीटी और एलपीटी के इन सभी राज्य नेटवर्कों के माध्यम से डीडीके, दिल्ली से सोमवार से शनिवार को दोपहर तीन से चार बजे तक एक घंटे के लिए उत्तरी नेटवर्क धारावाहिक आधारित मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और रविवार को हिंदी फीचर फिल्म प्रसारित की जाती है। इसलिए संबंधित राज्य की राजधानी से दोपहर चार से शाम आठ बजे के बीच कार्यक्रम बीम किए जाते हैं और उस राज्य के जमीनी ट्रांसमीटर से रिले किए जाते हैं जिससे क्षेत्र की प्रमुख स्थानीय बोली में आयोजित होने वाली गतिविधियों को कनेक्ट किया जा सके।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के अतिरिक्त वर्ष भर सबसे ज्यादा बल फ्लैगशिप कार्यक्रमों को दिया जाता है। अपनी क्षमता का ध्यान न करते हुए क्षेत्रीय केंद्रों ने फ्लैगशिप कार्यक्रमों और लोक सेवा कार्यक्रमों को प्रमुखता देने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

डीडी अभिलेखागार

डीडी अभिलेखागार 40 वर्षों से सृजित मीडिया कन्टेंट का परिरक्षक है। किसी भी मीडिया संगठन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी परिसंपत्ति को कैसे प्रबंधित करता है। ब्रॉडकास्टिंग चैनल के रूप में वह मौजूदा घटनाओं की प्रासंगिकता के अधिक से अधिक फाइल फुटेज पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त डीडी अभिलेखागार का सांस्कृतिक कन्टेंट बहुत मूल्यवान है, चूंकि डीडी अभिलेखागार ऐसा एकमात्र माध्यम है जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, जिसमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, आदिवासी संगीत और नृत्य शैलियां, परंपरागत और आधुनिक रंगमंच आदि शामिल है, के संरक्षण के उत्तरदायित्व को मान्यता देता है। यह बहुमूल्य कन्टेंट उस देश के स्पंदमान सांस्कृतिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक बपौती के लिए जाना जाता है। डीडी अभिलेखागार ने अपने कन्टेंट को संरक्षण का अभियान चलाया है जो भविष्य और देश की समृद्धि के लिए अतीत और वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। अगले चार वर्षों में डीडी अभिलेखागर विश्व के सर्वश्रेष्ठ ब्रॉडकास्टिंग अभिलेखागारों में से एक हो जाएगा।

स्व वित्त कमीशनिंग (एसएफसी)

दूरदर्शन ने देश के प्रतिष्ठित निर्माताओं से अपने फ्लैगशिप चैनल डीडी 1 के लिए गुणवत्तापूर्ण मनोरंजक कन्टेंट आउटसोर्स करने के लिए स्व वित्त कमीशनिंग की नई योजना प्रतिपादित की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ फिल्मकारों और टेलीविजन निर्माताओं द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर को दूरदर्शन की ओर से वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के स्वामित्व वाले कन्टेंट को दूसरे चैनलों द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। यह योजना दूरदर्शन के प्राइम टाइम के दौरान अच्छा राजस्व अर्जित कर रही है।

डीडी एसएफसी कार्यक्रमों द्वारा सभी प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लॉट्स को अधिग्रहित करने को प्रतिबद्ध है। प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लॉट्स के अतिरिक्त एसएफसी कार्यक्रमों के लिए नॉन प्राइम टाइम स्लॉट्स को लेने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि हर वर्ष निर्माण की लागत बढ़ रही है और गुणवत्ता के लिहाज से दूसरे सेटेलाइट चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें एपीसोड के मूल्य को बढ़ाना चाहिए।

इस योजना के तहत निर्मित कार्यक्रम केवल दूरदर्शन की संपत्ति हैं। डीडी इस संपत्ति को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के, दूरदर्शन के किसी दूसरे चैनल पर जब चाहे प्रयोग कर सकता है। एक समय निवेश और बहुउपयोग का यह अधिकार, बिना किसी आवर्ती व्यय के, दूरदर्शन को प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ नहीं मिलता। राजस्व में बढ़ोतरी के

अतिरिक्त, डीडी मार्केटिंग एजेंसियों/प्रायोजकों के देय की समस्या से भी निजात पा लेता है क्योंकि डीडी सीधा ग्राहकों के संपर्क में होता है। अदालती मामलों/पंचाट से भी छुटकारा मिलता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, प्राइम टाइम पर दैनिक धारावाहिक को प्रस्तावित करने का प्रयोग भी किया गया जो दर्शक संख्या बढ़ाने के साथ-साथ दूरदर्शन का राजस्व भी बढ़ाएगा।

वर्ष 2010-11 के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- उर्दू उपन्यासों पर देश के प्रख्यात फिल्मकारों से बहु श्रृंखला वाले धारावाहिकों का निर्माण
- भारत की प्रख्यात रंगकर्मियों द्वारा किए गए उर्दू नाटकों का पुनर्निर्माण
- दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों, यूरोप और अमेरिका के कलाकारों के अंतरराष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम
- उर्दू भाषा और साहित्यिक पृष्ठभूमि वाले फिल्मकारों द्वारा उर्दू भाषा की कहानियों पर उर्दू फीचर फिल्मों का निर्माण

सॉफ्टवेयर की कमीशनिंग

- हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, पटना, जयपुर, श्रीनगर, जम्मू स्थित केंद्रों के माध्यम से इन हाउस प्रॉडक्शन गतिविधियों का संचालन
- इस वर्ष के दौरान घोषित कमीशंड योजनाओं पर काम चल रहा है, जो कि चैनल के लिए वर्ष 2010-11 में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम प्रदान करेंगी।

अध्याय–2

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11			परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
			गैर-योजना बजट	**योजना बजट**	**पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन**				
1.	कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	एनआईसी की सहायता से सीएफसी के समूचे कामकाज का आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए तकनीकी उपकरण प्रदान करना	550.00	90.00	—	सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों में नेटवर्किंग सुविधाएं। साफ्टवेयर उपलब्ध कराना तथा साफ्टवेयर का विकास कम्प्यूटर के लिए एएमसी अनुबंध का भुगतान, कार्यालय परिसर का सुधार तथा बोर्ड के लिए डीवीडी/ टीवी/वीसीडी तथा अन्य तकनीकी उपकरणों की खरीद।	इससे क्षेत्रीय कार्यालयों में डाटा और संचार में तेजी आएगी, आवेदक फिल्म प्रमाणीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सीबीएफसी के पास आधुनिक उपकरण होंगे। सिविल तथा विद्युत ढांचा उन्नयन।	—	—
2.	नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों का प्रारम्भ।	इन क्षेत्रों में बनने वाली फिल्मों के प्रमाणन की व्यवस्था करना	—	80.00	—	क्षेत्रीय अधिकारी के नए सृजित तीन पदों और तीन एलडीसी के पद भरने की प्रक्रिया जारी।	क्षेत्रीय अधिकारी के नए सृजित तीन पदों और तीन एलडीसी के पद भरने की प्रक्रिया जारी।	रोज़गार समाचार में विज्ञापित तीन क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ तीन पद एलडीसी के एसएससी के माध्यम से भरे जाएंगे	स्टाफ तथा ढांचा प्रदान किया जाएगा।

3.	प्रमाणन प्रक्रिया की जांच और आधुनिकीकरण	बोर्ड सदस्यों/ पैनल के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, अध्ययन करवाना।	—	50.00	—	नियमित अंतराल पर बोर्ड के सदस्यों और सलाहकार पैनल के सदस्यों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन।	सभी पैनल तथा बोर्ड सदस्य प्रमाणन दिशा-निर्देशों से परिचित होंगे और विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रमाणन के क्रियान्वयन में समानता लाएंगे	—	—
	कुल		**550.00**	**220.00**					

बाल फिल्म समिति, भारत

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11		वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2009-10)	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट				
1	सीएफएसआई को सरकार से अनुदान	1. फिल्मों के माध्यम से शिक्षा तथा संस्कृति को बेहतर बनाना और स्वस्थ मनोरंजन के लिए बच्चों में फिल्म समालोचना को प्रोत्साहन देना। 2. अभिलेख के उद्देश्य से डिजिटल रूप में सीएफएसआई की फिल्मों का रूपांतरण (170 घंटे की फिल्मों का डिजटिलीकरण किया जाएगा) 3. बाल फिल्मों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना 4. राज्य और जिला प्रशासन, नेहरू युवा केंद्रों तथा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से देश के सभी बच्चों तक पहुंचना	143.00	4.00	5 फीचर फिल्में, 2 लघु फिल्में, 14 डबिंग, 6 उपशीर्षक, 243 फिल्म खरीदी जाएंगी। सीएफएसआई की सभी फिल्में (निर्मित, डब और उपशीर्षक सहित अभिलेख तथा आम प्रदर्शन के उद्देश्य से डिजिटल फॉरमेट में रूपांतरित की जाएंगी। लाइब्रेरी के रूप में सीएफएसआई की सभी फिल्मों की वेबकास्टिंग तथा सीएफएसआई की फिल्मों की इंटरनेट पर उपलब्धता। 25 लाख दर्शकों को लाभांवित करने के लिए 5000 प्रदर्शनों का आयोजन।	राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बाल फिल्में उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएफएसआई की सभी फिल्मों का अभिलेख डिजिटल फॉरमेट में उपलब्ध होगा जिससे सुगमता से उन्हें संग्रहित किया जा सकेगा। सीएफएसआई की सभी फिल्मों की वेबकास्टिंग तथा सीएफएसआई की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना।	31.03. 2011	अनुदानों की उपयोगिता में किसी प्रकार के जोखिम की आशंका नहीं है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/उत्पादन वास्तविक भौतिक	प्रदर्शित परिणाम	प्रक्रिया/ समयरेखा	टिप्पणी
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित)	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
I.	**राजस्व (नई स्कीम)** आपूर्ति एवं सामग्री (i) आयोजित यात्रा/दक्षता उन्नयन	स्कीम का उद्देश्य नेताओं/ संसाधन व्यक्तियों की राय से परिचित कराना जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से युवा सम्मिलित हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विकास कार्यों से सम्बद्ध हैं। इस ग्रुप में सामाजिक कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, किसान, दस्तकार, स्कूलों के अध्यापक और छात्र आदि शामिल हैं।	—	55.00	—	वर्ष 2010-11 के दौरान क्षेत्रीय कार्यलयों द्वारा 11 (ग्यारह) यात्राएं आयोजित की जाएंगी	आयोजित यात्रा में सम्मिलित सदस्य केन्द्रीय सरकार की नीतियों और योजनाओं के संदेश वाहक हो जाते हैं। आयोजित यात्रा के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में संचालन में विभिन्न कल्याण स्कीमों के बारे में स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं।	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के यात्रा कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के बाद वर्ष के दौरान यात्रा पूरी हो जाएंगी।	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
	पूंजी (नई स्कीम) आधुनिकीकरण तथा उन्नयन (अ) क्षेत्रीय कार्यालयों/ इकाइयों का कम्प्यूटरीकरण। (ब) ए.बी. हार्डवेयर का उन्नयन/डाटा प्रोजेक्टर की खरीद डी.वी.डी. प्लेयर/ वायरलेस पब्लिक एड्रेस सिस्टम/ डिजिटल वीडियो कैमरों की खरीद।	हाल ही में लागू सूचना का अधिकार के तहत देश में प्रत्येक नागरिक सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की जानकारी पा सकता है। यह सूचना देशभर में फैले 22 क्षेत्रीय कार्यालयों और 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। फिल्म शो, परस्पर वार्ता कार्यक्रम, चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के संदेशों/योजनाओं एवं नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय यूनिटों को उचित आडियो/ वीडियो उपकरण प्रदान करना		500.00	-	फिल्म प्रभाग से 15 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, 29 डी.वी.डी. प्लेयर तथा 01 डिजिटल वीडियो कैमरे, 20 वायरलैस पीए सिस्टम से अधिक से अधिक फिल्में प्राप्त करना। 10 डिजिटल फोटो-कॉपीयर, 90 सादा फोटो कॉपी पर, 100 फैक्स सह-स्केनर मशीनें, 90 डिजिटल कैमरे, 11 लालटेन, 78 वाहन तथा प्रचार के लिए प्रतिमाह 7 वाहन किराए पर लेना	उपकरणों का इस्तेमाल लोगों के बीच सूचना संप्रेषण तथा सामाजिक मुद्दों पर शिक्षित करने में होगा।	टेंडर प्रक्रिया पूरी करना आपूर्ति आर्डर देना और बिल भुगतान शर्तें पूरी होने पर वर्ष के दौरान पूर्ण हो जाएंगे।	
		कुल		**555.00**					

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक/परिमाणात्मक वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	लघु कार्य	क्षेत्रीय प्रचर इकाइयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा डीएफपी (मु.) में दृश्य-श्रव्य उपकरणों का मरम्मत कार्य	44.00	शून्य	शून्य	वर्ष के दौरान डीएफपी के दृश्य-श्रव्य उपकरणों की मरम्मत आदि के कार्य के प्रावधान को पूरा किया जाएगा।	इससे क्षेत्रीय स्तर पर उपकरणों की कार्य प्रणाली में सुधार के साथ कार्य करने में आसानी होगी।	कार्य का निष्पादन वर्ष के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमानों की मंजूरी के पश्चात पूरा किया जायेगा।	
2.	अन्य अधिभार	सरकार की नीतियों एवं कल्याण योजनाओं का फिल्म शो, परस्पर वार्ता कार्यक्रमों, और चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से जन समूह में प्रचार-प्रसार करना। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की 207 यूनिटें, 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण में यह कार्य संपादित करती हैं।	74.50	शून्य	शून्य	46,500 फिल्म शो, 4,968 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन।	इन कार्यक्रमों का उपयोग सामाजिक विषयों एवं सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए किया जाएगा, इससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।	कार्यक्रमों के लिए कार्ययोजना बनाना। कार्यक्रम आयोजित करना एवं फीडबैक एकत्रित करना यह कार्य वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा।	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक/परिमाणात्मक वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
3.	पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट	सरकार की नीतियों एवं कल्याण योजनाओं का फिल्म शो, परस्पर वार्ता कार्यक्रमों, और चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से जन समूह में प्रचार-प्रसार करना। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की 207 यूनिटें 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण में यह कार्य संपादित करती हैं।	176.35	शून्य	शून्य	सीमावर्ती, पिछड़े, जनजातीय तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करना।	इन कार्यक्रमों का उपयोग सामाजिक विषयों एवं सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए किया जाएगा। इससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।	वर्ष के दौरान सामान्य गतिविधियां	
4.	घरेलू यात्रा व्यय	सरकार की नीतियों एवं कल्याण योजनाओं का फिल्म शो, परस्पर वार्ता कार्यक्रमों, और चुनिन्दा विषयों पर विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से जन समूह में प्रचार-प्रसार करना। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की 207 यूनिटें 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण में यह कार्य संपादित करती हैं।	158.00	शून्य	शून्य	सीमावर्ती, पिछड़े, जनजातीय तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यक्रमों/अभियानों के आयोजन के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करना। इन प्रचार गतिविधियों के लिए प्रत्येक क्षे.प्र.इ. को माह में 10-12 दिनों का भ्रमण करना है।	इन कार्यक्रमों का उपयोग सामाजिक विषयों एवं सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए किया जाएगा, इससे वे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।	वर्ष के दौरान सामान्य गतिविधियां	

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

(लाख रुपये में)

क्र. स.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य परिणाम	परिव्यय 2009-10			परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय/ वास्तविक प्रतिफल	परिमाणनीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
	प्लान योजना का नाम		4 (i) गैर-योजना बजट	4 (ii) योजना बजट	4 (iii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम अवधारणा और प्रसार	1. स्थापना 2. प्रदर्शनी 3. डिस्प्ले वर्गीकृत 4. रेडियो स्पॉट 5. मुद्रित प्रचार 6. वितरण 7. बाह्य प्रचार	2261.00 185.00 3242.00 200.00 240.00 - 100.00	— 174.00 1305.00 2175.00 348.00 - 318.00	— — — — — — —	— 500 15600 5300 152 — 250	सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक आर्थिक उत्थान के बारे में विभिन्न माध्यमों-बाह्य प्रचार, रेडियो, दूरदर्शन, समाचारपत्र और पोस्टर/ पुस्तिकाओं के जरिए प्रचार करने से जन समुदाय में जागरूकता पैदा होगी और विकास में उनकी भागीदारी को प्रेरित किया जा सकेगा।	आवश्यकता अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य किए जाएंगे।	
		कुल (1)	**6228.00**	**4350.00**					
2	डीएवीपी का आधुनिकीकरण	1.कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण 2.कार्यालय ढांचा 3.मानव संसाधन विकास		— 100.00 100.00	— — —	— — —	कंप्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण, कार्यालय ढांचा और मानव संसाधान विकास		
		कुल (2)		**200.00**					
		कुल **(1 और 2)**	**6228.00**	**4450.00**					

फिल्म समारोह निदेशालय

गैर-योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रतिस्थापना संबंधी खर्चे	वेतन, भत्ते, ओई,डीटीई आदि	213.00	-	-	-	-
2.	लघु कार्य	सीरीफोर्ट सांस्कृतिक परिसर का रख-रखाव	354.00	कला संस्कृति तथा सिनेमा के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए सभागार सुसज्जित करना तथा किराए पर देना	किराए से उच्च आय की उम्मीद	एक वर्ष	-
3.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह	विश्वभर में समृद्ध और विविध संस्कृति को फैलाना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की उपस्थिति बढ़ाना	25.00	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत भारत और विदेशों में 25 फिल्म समारोहों का आयोजन।	भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना।	सीईबी का वर्ष भर आयोजन	
4.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर की मान्यता।	200.00	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करना।	भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में सुधार लाना तथा बेहतर प्रतिभाओं को मान्यता प्रदान करना ताकि भारतीय सिनेमा को बेहतर बनाया जा सके।	एक वर्ष	
		कुल	225.00				

फिल्म समारोह निदेशालय

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात प्रोत्साहन (योजना राजस्व **क.** भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह **ख.** विदेशी फिल्म समारोहों में भाग लेना **ग.** भारतीय पैनोरमा फिल्मों का चयन।	इस योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया ताकि फिल्म समारोहों में भाग लेकर और निर्यात को प्रोत्साहन देकर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा दिया जा सके।	450.00	क. भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन। **ख.** विभिन्न देशों में आयोजित 35 विदेशी फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी। **ग.** 26 फीचर और 21 गैर-फीचर फिल्मों का चयन।	फिल्म समारोहों में निर्यात को प्रोत्साहन देकर बेहतर भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना। इससे पूरे विश्व में भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को सिनेमा के माध्यम से फैलाने में मदद मिलेगी।	वित्तीय वर्ष 2010-11 में कार्यान्वित होगा।
2.	फिल्म समारोह परिसर-फेरबदल और अतिरिक्त निर्माण-प्रमुख कार्य (योजना पूंजी)	सीरीफोर्ट परिसर का नवीनीकरण और सुविधाओं में सुधार ताकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिसर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।	400.00	अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नवीनीकृत ऑडिटोरियम विशेषकर राष्ट्रमंडल खेल 2010 को ध्यान में रखते हुए।	घरेलू और निर्यात क्षमता वाली भारतीय फिल्मों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए तथा समृद्ध एवं विविध भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए भी केन्द्र/नवीनीकृत ऑडिटोरियम/परिसर को अन्य पार्टियों को किराए पर देकर अधिक राजस्व अर्जित करना।	वित्तीय वर्ष 2010-11 में कार्यान्वित होगा।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता
1	2	3	4	5	6	7
3.	(पूंजी अनुभाग) डीएफएफ में प्रिंट यूनिट का उन्नयन	इस नई योजना के अंतर्गत फिल्म समारोह निदेशालय को एक तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रिंट यूनिट प्रदान की जाएगी जिससे प्रिंटों के लम्बे समय तक भंडारण में मदद मिलेगी। यह फिल्म समारोहों के जरिए भारत तथा विदेश में निर्यात संवर्धन की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के मंतव्य से है।	100.00	207 भारतीय पेनोरमा फिल्मों का डिजिटली-करण तथा यू मेटिक डीजी बीथ तथा एसपी बीटा प्लेयर की खरीद।	भारतीय तथा विदेशी फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों की भागीदारी के जरिए अच्छे भारतीय सिनेमा के निर्यात को बढ़ावा देना जिससे समृद्ध भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।	वर्ष 2010-11 में कार्यान्वित होगा।

फिल्म प्रभाग

वित्तीय परिव्यय, परियोजना का वास्तविक उपलब्धियों, अनुमानित परिणाम का परिणाम बजट में 2010-11

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय ब.अ. 2010-11	वास्तविक/मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
1	अन्तर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह	मुंबई में दो-वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनीमेशन फिल्म समारोह आयोजित करना।	10.00	देश में वृत्तचित्र अभियान को प्रोत्साहन; (फिल्मों के सशक्त माध्यम से वैश्विक स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि का प्रदर्शन।	11वें मिफ्फ 2010 के आयोजन हेतु एवं 12वें मिफ्फ 2012 की तैयारी	द्विवार्षिक मिफ्फ समारोह में विश्व भर से फिल्मकारों द्वारा आवेदन पत्र/प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं और प्रतिष्ठित ज्यूरी की सिफारिश पर भागीदारों को 22.75 लाख राशि के पुरस्कार। इस दौरान डाक्यूमेंटरी और लघु फिल्मों के क्षेत्र में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए डा. वी शांताराम पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।	विशिष्ट जोखिम नहीं
2	डाक्यूमेंटरी फिल्मों का निर्माण	बाहरी निर्माताओं/ एनजीओ के जरिए डाक्यूमेंटरी फिल्मों का निर्माण करना, जिनमें सामाजिक मुद्दों और समस्याओं के साथ-साथ उनके सुझावों को भी दर्शाया जाए।	500.00	सरकार के राष्ट्र निर्माण प्रयासों की दिशा में डाक्यूमेंटरी फिल्मों का निर्माण करना।	डाक्यूमेंटरी फिल्मों का निर्माण।	निर्माताओं और एनजीओ की तलाश के पश्चात उनसे डाक्यूमेंटरी फिल्मों का निर्माण कराना।	कोई जोखिम नहीं।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/उपलब्धियां	वित्तीय परिव्यय ब.अ. 2010-11	वास्तविक मात्रात्मक उपलब्धियां	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/अवधि	टिप्पणी/ जोखिम के घटक
3	मूविंग इमेज संग्रहालय की स्थापना	आंगुतकों/फिल्म प्रेमियों के लाभार्थ प्रख्यात निर्देशकों, निर्माताओं, संस्थानों, आदि की कृतियों का प्रदर्शन और फिल्म निर्माण से संबंधित सामग्री दर्शाने के लिए एक स्थाई संग्रहालय की स्थापना करना।	2900	फिल्म प्रभाग, मुम्बई में एक संग्रहालय की स्थापना करना, जिसमें दृश्य-श्रव्य माध्यम से भारतीय सिनेमा का इतिहास और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्म निर्माण सामग्री दर्शाई जाएगी।	एनबीसीसी द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट के आधार पर फिल्म प्रभाग, मुम्बई में एमओएमआई नामक संग्रहालय की स्थापना करना।	स्कीम को स्वीकृति मिलना और एनबीसीसी द्वारा निर्माण गतिविधियां।	निश्चित अवधि से अधिक समय लगने का जोखिम, क्योंकि यह प्लान स्कीम एनबीसीसी द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उसके द्वारा ठेके देने से सीधे संबंधित है।
4	प्रभाग की फिल्मों का डिजिटलीकरण तथा वेबकास्टिंग	अधिलेखागार की सभी फिल्मों का डिजिटलीकरण तथा उन्हें इंटरनेट पर डालना।	100	प्रभाग के अभिलेखागार की फिल्मों को डिजिटल फार्मेट में लाना। मूल फिल्म को मूल रूप में ही संरक्षित रखा जाएगा तथा डिजिटल फार्मेट को नियमित प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।	अभिलेखागार की 8131 फिल्मों का डिजिटलीकरण किया जाएगा।	चालू योजना अवधि में कार्य पूर्ण होने की संभावना।	कोई जोखिम नहीं।

भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

(लाख रुपये में)

क्र. स.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11			परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
1.	विदेशी फिल्म समारोह/बाजारों में भागीदारी	भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और भारतीय फिल्मों के लिए बाजार का विस्तार करते हुए फिल्मों को एक उद्योग के रूप में मजबूती प्रदान करना।	-	220.00	-	• केन्स फिल्म बाजार-मई, 2010 में भागीदारी। • एनएबी शो 2010 लास वेगास, यूएसए में भागीदारी। • फिल्म बाजार/ आईएफएफआई का आयोजन- नवंबर-दिसंबर 10 • एन्नेसी फिल्म समारोह (एनीमेशन क्षेत्र) जून, 2010 में भागीदारी • बर्लिन फिल्म समारोह -फरवरी, 2011 में हिस्सा लेना। • विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सहायता से भारतीय फिल्मों का प्रचार।	विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की उपस्थिति बढ़ाना और भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देना।	मंत्रालय द्वारा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक कार्यक्रम में हिस्सेदारी की योजना पर विचार करने के लिए बाजारों के शुरू होने से काफी समय पहले बैठकें आयोजित की जायेंगी।	कालम पांच में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त फिल्मों की उपस्थिति बढ़ाने के उपायों पर अतिरिक्त खर्च।

2.	ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी नई योजना	उच्च प्रौद्योगिकी विषयवस्तु उद्योग में कार्मिकों की समस्या के समाधान के लिए ऐनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव में उत्कृष्टता के लिए सरकारी-निजी भागीदारी में केंद्र की स्थापना।	–	100.00	–	(i) एम/एस पीडब्ल्युसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उत्कृष्टता केंद्र और बीएफएक्स की स्थापना के लिए सिफारिश की है। (ii) एम/एस पी डबल्यु सी द्वारा सौंपे गए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। (iii) संपूर्ण स्कीम के लिए योजना आयोग का अनुमोदन	विस्तृत डीपीआर के आधार पर तथा नई स्कीम पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना।	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 'उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना के लिए अपेक्षित धन की व्यवस्था और स्थापना में लगने वाले समय के मुद्दे स्पष्ट होंगे।	यह योजना सरकारी-निजी भागीदारी में लागू की जानी है। इसलिए निजी पार्टियों के योगदान की पहचान करनी होगी।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

योजना

(करोड़ रुपये में)

परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण (2010-11) (परिणाम बजट 2010-11 के अनुसार) तथा वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
(अ)	**चालू योजनाएँ**						
(i)	**संस्थान को अनुदान राशि**						
(i)	मशीनरी एवं उपकरण	(i) फिल्म तथा टीवी उद्योग दोनों में आधुनिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप पुराने एवं अप्रचलित उपकरणों के स्थान पर नये उपकरणों की खरीद और संसाधनों में वृद्धि।	3.69	सामान प्राप्त हो गया है और मंत्रालय के एसएफसी के अनुमोदन के मुताबिक कार्य संपन्न कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तय कर दिए गए हैं और उपलब्धि की नजदीकी से विभागीय बैठकों, मासिक व्यय रिपोर्टों और मंत्रालय के अर्द्धवार्षिक निष्पादन के माध्यम से निगरानी की जाती है।	व्याख्यात्मक नोट अलग से सलंग्न	(1) उपयोगकर्ता विभाग से इंडेंट प्राप्ति (2) जब भी आवश्यक हो समाचार पत्रों में टेंडर प्रकाशन के लिए कोटेशन मंगाना (3) विशिष्ट अवधि के बाद कोटेशनों/टेंडरों को खोलना तथा जांचना (5) आपूर्ति/खरीद/ निष्पादन आदेश देना (6) उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सामग्री/ सामान का निरीक्षण (7) मात्रा/ गुणवत्ता इत्यादि के लिए सामानों की जांच रिपोर्ट/खरीद आदेश में उपरकण का प्रदर्शन और अन्य शर्तों की जांच। विभागीय बैठकों में समयबद्धता पर विचार किया जाता है और त्रैमासिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्य योजना की तिथि बताई जाती है।	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्षिप्त परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
		(ii) नई तकनीकों जैसे हाई डेफिनेशन टी.वी., विकसित कंप्यूटर एनिमेशन, डिजिटल फिल्म रिकार्डिंग आदि का समावेश।				प्रक्रिया (i) विभाग द्वारा इंडेंट की रसीद (ii), आवश्यकता-नुसार समाचारपत्रों में निविदाओं के प्रकाशन हेतु कोटेशन मंगवाना, (iii) निश्चित अवधि के पश्चात कोटेशन/ निविदाओं को खोलना तथा उनकी जांच, (iv) वित्तीय संस्तुति लेना, (v) आपूर्ति/ खरीद/ प्रदर्शन आदेश देना, (vi) प्रयोक्ता विभाग द्वारा सामग्री का निरीक्षण, (vii) मात्रा/ गुणवत्ता के आधार पर सामग्री के निरीक्षण की रिपोर्ट, उपकरण का प्रदर्शन तथा अन्य शर्तों को खरीद आर्डर में निर्दिष्ट करना। विभागीय बैठकों में समयबद्धता पर विचार किया जाता है तथा अर्द्धवार्षिक भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्ययोजना की तिथि बताई जाती है।	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्षिप्त परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
		(iii) एफटीआईआई के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के आयोजन तथा ढांचागत विकास के लिए अतिरिक्त आवश्यकता है।					
(ii)	भवन निर्माण	छात्रों के रहने तथा कार्यक्रमों के लिए वर्तमान में स्थान की कमी है। वर्तमान योजना 100 कमरों के छात्रावास निर्माण की है। एक आधुनिक संसाधन तथा ज्ञान केंद्र की याजेना भी है। जैसे पुस्तकालय, ई-पुस्तकालय, इंटरनेट, विद्यार्थी केंद्र, फैकल्टी के लिए विचार-विमर्श कक्ष तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग केंद्र का समन्वय	1.62	100 कमरों वाल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।			
(iii)	कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण		0.20				
(iv)	सामुदायिक रेडियो की स्थापना	विद्यार्थियों को रेडियो प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में शोध तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	0.05	10वीं योजना की समाप्ति के साथ ही रेडियो कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्माण रिले तथा प्रसारण प्रणाली की देख रेख के लिए प्रावधान किया गया है।			
(v)	कैप्टिव टीवी चैनल की स्थापना	छात्रों को प्रोग्रामिंग तथा प्रसारण के क्षेत्र में प्रयोग तथा रचनात्मकता के अवसर उपलब्ध कराने के एकमात्र उद्देश्य वाली यह स्कीम 10वीं योजना से ही चलाई जा रही है। मुख्य विचार लक्षित श्रोताओं के साथ नजदीकी और सीधी बातचीत करना है।	0.10	कार्यक्रमों की शूटिंग हो चुकी है और अतिरिक्त शूटिंग और बाद में इसके प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है।			

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्षिप्त परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
(vi)	एच.आर.डी पक्ष जिसमें छात्रों के लिए छात्रवृति तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान शामिल है।	1. एफ.टी.आई. की गतिविधियों को और आगे बढ़ाना। छात्रों एवं संकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक गतिविधियों का अध्ययन एच.आर.डी. कार्यक्रम के आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना। 2. एफटीआईआई के स्वर्णजयंती वर्ष आयोजन के अंतर्गत उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, अनुसंधान तथा फेलोशिप आयोजन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।	1.34	आदान-प्रदान कार्यक्रम की गतिविधि से छात्र अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर, फिल्म स्कूलों से मिलकर फिल्म निर्माण के नये विचार प्राप्त करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आधुनिक तकनीक से परिचित हों। एफटीआईआई की योजना है कि भारत के विश्वविद्यालयों एवं फिल्म स्कूलों के साथ-साथ देश में अपनी गतिविधि बढ़ाएं। संकाय/स्टाफ का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से संबंधित पत्रिका जैसे लेनसाईट का प्रकाशन खरीद, सेमिनार, लेक्चर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का आयोजन, एचआरडी संबंधी पुस्तकों की खरीद तथा लाइब्रेरी के लिए डीवीडी की खरीद।			
		कुल : (क)	**7.00**				

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिव्यय	प्रक्षिप्त परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
(ब)	**नयी योजना**						
	वैश्विक फिल्म स्कूल	एफटीआईआई इंटरनेट प्रौद्योगिकी, वायर के साथ साथ सेटेलाइट के जरिए लाभ उठाने की सोच रही है ताकि अपने सभी भागों को देश में और देश के बाहर जोड़ सके और इस प्रकार ग्लोबल फिल्म स्कूल का हिस्सा बन सके।	1.00	यह नई स्कीम है। अनुमोनित खर्च सिनेमेटोग्राफी तथा टीवी इंजीनियरिंग विभाग के लिए मशीनरी तथा उपकरण के लिए है, मास्टर प्लान में शामिल है-ऑडिटोरियम, क्लास रूम थिएटर, अंदर की सड़क पार्किंग शेड, पैदल चलने वालों का क्षेत्र तथा इमारत निर्माण कार्य शामिल है जिसमें प्रशासनिक भवन, स्टूडियो फ्लोर, ऑडिटोरियम प्रिव्यू थिएटर, छात्रावास तथा स्टॉफ क्वार्टर शामिल हैं।		(1) उपयोगकर्ता विभाग से इंडेंट प्राप्ति (2) जब भी आवश्यक हो समाचार पत्रों में टेंडर प्रकाशन के लिए कोटेशन मंगाना (3) विशिष्ट अवधि के बाद कोटेशनों/टेंडरों को खोलना तथा जांचना (5) आपूर्ति/ खरीद/निष्पादन आदेश देना (6) उपयोगकर्ता विभाग द्वारा सामग्री/सामान का निरीक्षण (7) मात्रा/ गुणवत्ता इत्यादि के लिए सामानों की जांच रिपोर्ट/ खरीद आदेश में उपरकण का प्रदर्शन और अन्य शर्तों की जांच। विभागीय बैठकों में समयबद्धता पर विचार किया जाता है और त्रैमासिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कार्य योजना की तिथि बताई जाती है।	
		(ब)	1.00				
		कुल : (अ + ब)	8.00				

गैर योजना समीक्षा (2009-2010)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उप शीर्ष/विनियोजन इकाई	उद्देश्य/परिणाम	एस.बी.जी. 2010-11	निर्धारणीय/वितरणीय भौतिक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7
	वेतन, पेंशन ग्रेच्युटि, अवकाश वेतन अनुदान, यात्रा, किराया दर/कर, बिजली, टेलीफोन, कच्चा माल, उपकरण, भवन देखरेख तथा खर्च के अन्य विविध शीर्ष	निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप संस्थान द्वारा फिल्म/टीवी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।	12.50	संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत सभी दावों की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें निपटा दिया गया है।	मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एस.बी.जी./आर.ई. के मुताबिक खर्च किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिथि के मुताबिक मासिक खर्च विवरण भेजा जा रहा है। स्वीकृत अनुदान के भीतर खर्च करने के लिए प्रगति की समीक्षा के लिए आंतरिक प्रणाली भी मौजूद है।	

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1.	सत्यजीत रे फिल्म एवं टीवी विजन संस्थान कोलकाता	संस्थान का मूल उद्देश्य फिल्म एवं टीवी उद्योग के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को मुहैया कराना है, संस्थान निर्देशन तथा पटकथा लेखन, चलचित्र फोटोग्राफी, संपादन और साउंड रिकार्डिंग में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कुल 120 छात्रों की क्षमता संस्थान के तीन समवर्ती बैचों में फैली है।	6.00	पाठ्यक्रम विभिन्न छात्र परियोजनाएं प्रदान करता है। ये हैं : निरंतरता, लघु फिल्म, वृत्तचित्र, पार्श्वगायन तथा डिप्लोमा फिल्म आदि जो कि नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। कक्षा में शिक्षा का पूरक बनाने के लिए प्रख्यात फिल्मी हस्तियों द्वारा विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। फिल्म निर्माण में आधुनिक चलन तथा तकनीक को समग्र रूप से समझने के रूप में देसी और विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन भी नियमित रूप से किए जाते हैं।	संस्थान निर्देशन तथा पटकथा लेखन, चलचित्र फोटोग्राफी संपादन तथा साउंड रिकार्डिंग में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक में 10 छात्र लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष कुल 40 छात्र पढ़कर बाहर निकलते हैं। मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान लघु अवधि के पाठ्यक्रम भी चलाता है जो विभिन्न संगठनों की आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। इनके अतिरिक्त, संस्थान अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन भी करता है।	**माध्यमिक/अंतिम** अंतिम वर्ष बैच (2005-08 सत्र का छठा बैच) के 32 छात्र अपनी अंतिम परियोजनाएं पूरी कर रहे होंगे। परियोजना अवधि में 30 मिनट अवधि की 10 लघु फिल्में (डिप्लोमा फिल्में) निर्मित की जाती हैं। 2007-10 सत्र का 7वां बैच तथा 2008-11 का 8वां बैच (जूनियर) परियोजना कार्य सहित निर्धारित समयसीमा के मुताबिक अपने पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहा होगा। इस अवधि में 2009-12 के 9वें नए बैच के प्रवेश का कार्य शुरू किया जाएगा।	1. अनुमानित परिणाम/प्रतिफल की उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संस्थान के नियंत्रण से बाहर का कोई कारक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1.	एस आर एफ टी आई कोलकाता में केप्टिव टीवी चैनल स्कीम	स्कीम एसआरएफटीआई, कोलकाता में ''ए फीडर टेलीविजन सॉफ्टवेयर बेस'' के विकास के विचार से शरू की गई।	0.02	स्कीम समाज तथा सामुदायिक विकास के लक्ष्य के साथ नए उभरते स्थानीय टी वी नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के ऑन लाइन टीवी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नए रास्ते खोलेगी।	स्कीम का उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता में नए मूल्य जोड़ना है जिससे छात्रों को भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें तथा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।	बेसिल से उपकरण प्राप्त कर लिए गए हैं। परियोजना शुरू करने के लिए स्टूडियो की स्थापना तथा कंटेंट विकास का कार्य शुरू किया जाएगा।	1. स्कीम के लक्ष्य की उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. लाइसेंस के लिए सरकारी अनुमति की प्राप्ति 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर का कोई कारक
2.	एस आर एफ टी आई में सामुदायिक रेडियो	स्कीम का मुख्य उद्देश्य रेडियो के क्षेत्र में छात्रों को ऑन-लाइन प्रशिक्षण देना है।	0.10	स्कीम परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय रुचि खासकर मनोरंजक कार्यक्रमों जैसी जन जागरूकता के लिए है।	स्कीम का उद्देश्य प्रशिक्षण की गुणवत्ता में नए मूल्य जोड़ना है जिससे छात्रों को भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें तथा क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। एक बार परियोजना समेकित हो जाए तो सरकारी विभागों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों से रेडियो कार्यक्रम प्रायोजित होने लगेंगे जिससे निर्माण लागत आंशिक या पूरी निकल आएगी।	बेसिल ने परियोजना चालू करने का कार्य पूरा कर लिया है और प्रसारण लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। 24 मई 2008 को सी आर सी का प्रसारण शुरू हो चुका है। तब से कार्यक्रम नियमित प्रसारित हो रहे हैं। लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कार्यक्रमों की विषयवस्तु को विविधता प्रदान की जाएगी, प्रसारण समय 3 घंटे (सुबह) से +2 घंटे पुन: प्रसारण कर बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
3.	एस एआर एफ टी आई में छात्रवृत्ति तथा आदान-प्रदान कार्यक्रम सहित एच आर डी पहलू	स्कीम की परिकल्पना फिल्म निर्माण में उभरते चलन तथा प्रौद्योगिकी पर ज्ञान की आपसी समझ साझा करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित विदेशी फिल्म स्कूलों के साथ निरंतर छात्र/ संकाय-आदान प्रदान करना है।	0.20	1. छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित करना 2. छात्रवृत्ति अनुदान 3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भागीदारी आयोजित करना	स्कीम का उद्देश्य नए मूल्यों के साथ प्रशिक्षण में गुणवत्ता बढ़ाना है जिससे भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ सकें।	छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम का अगला चरण शुरू किया जाएगा, छात्रवृत्ति/इंटर्नशिप कार्यक्रम जून 2010 में स्कॉटलैंड के प्रस्तावित छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम से जारी रहेंगे।	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक
4.	प्रशिक्षण और कौशल विकास डब्ल्यु. आर. टी. सामाजिक सुसंगत फिल्म निर्माण	परियोजना अनिवार्य रूप से संस्थान द्वारा फिल्म एवं टीवी के क्षेत्र में नौजवान छात्रों को दिए जा रहे प्रशिक्षण में वांछित मूल्य वर्धन करना है। स्कीम के तहत प्रस्तावित तत्वों से संस्थान की मौजूदा प्रशिक्षण गतिविधियों को और बढ़ाएंगी जिससे उद्योग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे छात्रों को सहायता मिल सके।	0.80	1. फिल्म और टी वी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास के साथ परिचय कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना 2. सामाजिक रूप से सुसंगत फिल्मों का निर्माण 3. न्यूज लैटर का प्रकाशन	सिनेमा और टीवी के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकीय बदलावों से परिचय में स्कीम संकाय सदस्यों की मदद करेगी। स्थानीय कार्यक्रम में कलाकार प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ विचारों के आदान प्रदान में सहायता करेंगे। छात्रों को भी इस अवसर पर बातचीत का मौका मिलेगा फिल्म निर्माण के प्रावधान से निर्माण में छात्रों को सीधा अनुभव मिलेगा जो उनके कैरियर की चुनौतियों से निपटने में मददगार साबित होगा अपनी फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन	1. संकाय चक्रानुक्रम में फिल्म निर्माण और उससे संबंधित पहलुओं पर लघु पाठ्यक्रम शुरू करेगा। उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सेमिनारों, महोत्सवों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 2. स्थानीय कार्यक्रमों में अंतराष्ट्रीय-राष्ट्रीय कलाकार होंगे जिनसे छात्र-संकाय को बातचीत का मौका मिलेगा। 3. छात्रों की भागीदारी से योजना वर्षों में संकाय पूरी फीचर फिल्म तथा वृत्त चित्र का निर्माण करेगा। 4. स्कीम में छात्र	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
					से उन्हें संस्थान के छात्र के रूप में अपनी प्रतिभा आकलन का अवसर मिलेगा।	फिल्मोत्सव 'क्लेप्स्टिक' तथा 'डोसेज' छात्रों तथा फिल्मकारों के बीच फिल्म जागरूकता फैलाएंगे। संस्थान की अकादिम विशेषताएं तथा कार्यक्रमों को बताने के लिए न्यूज लैटर प्रकाशित होगा 5. संस्थान अपनी अकादमिक तथा अन्य गतिविधियों को प्रमुखता से द्विवार्षिक न्यूज लैटर (टेकवन) में प्रकाशित करेगा।	
5.	मानव शक्ति के प्रावधान सहित ढांचे के कंप्यूटरी-करण तथा आधुनिकी-करण का प्रावधान	फिल्म और टीवी के क्षेत्र में एक साथ तीन बैचों के छात्रों के लिए पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फिल्म संस्थान में अपेक्षित ढांचा (उपकरण आधार) और पर्याप्त मानव शक्ति बढ़ाने के लिए परियोजना	3.20	1. नए फिल्म स्टूडियो तथा फिल्म अभिलेखागार का निर्माण 2. नए स्थाई/अर्द्ध स्थाई सेटों का निर्माण 3. उपकरण, कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर की प्राप्ति, ईआरपी का क्रियान्वयन 4. आत्म विश्वास प्राप्त करने के लिए मानवशक्ति की नियुक्ति	संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य पूरा होगा और संस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। छात्र समुदाय लाभान्वित होगी और अपने पाठ्यक्रम समय से पूरा कर सकेगी। नियमित गतिविधियों को व्यवस्थित करने पर, संस्थान का और विकास होगा और भारतीय मीडिया की गुणवत्ता में सुधार होगा।	सीसीडब्ल्यु, एआईआर द्वारा निर्माण और रूपांतरण कार्य हाथ में लिया जाएगा। विभागीय खरीद से ही उपकरण प्राप्ति होगी। इसके लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक मानवशक्ति की नियुक्ति की जाएगी	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
6.	एनीमेशन तथा इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग विभाग	पिछले कुछ वर्षों में, दृश्य-श्रव्य निर्माण की दुनिया में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र एनीमेशन तथा मल्टी-मीडिया संबंधी एप्लीकेशन हैं जो तेजी से विकसित हुई हैं। एनीमेशन की प्रसिद्ध और समृद्धि जग जाहिर है जिसके बारे में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। एनीमेशन फिल्मों के अतिरिक्त वेब संबंधी एप्लीकेशन तथा मल्टी मीडिया सीडी-रोम्स/ गेम्स डेवलपमेंट का विशाल बाजार और संभावनाएं हैं। अगले पांच वर्षों में भारत एनीमेशन संबंधी कार्य के लिए प्रमुख आउटसोर्स केंद्र बन जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की भारी मांग है। इसलिए इस पाठ्यक्रम को शुरू करने का यही सबसे उचित समय है। बदलते परिदृश्य को देखते हुए संस्थान में इसकी नई शाखा खोलने की आवश्यकता है। इसलिए संस्थान का दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव जिसमें प्रत्येक बैच में 10 छात्र होंगे।	1.24	1. नए अकादमिक ब्लॉक का निर्माण 2. कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर और एनीमेशन तथा डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर प्राप्त करना 3. मानवशक्ति की नियुक्ति	संस्थान की स्थापना का उद्देश्य पूरा होगा छात्र समुदाय लाभान्वित होगा और छात्रों को नए पाठ्यक्रम के अध्ययन का अवसर मिलेगा। उभरते क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। संस्थान भारतीय मीडिया की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाएगी और प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध कराकर उद्योग को सहयोग देगा।	सीसीडब्ल्यु, एआईआर द्वारा निर्माण और रूपांतरण कार्य हाथ में लिया जाएगा। विभागीय खरीद से ही उपकरण प्राप्ति होगी। इसके लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक मानवशक्ति की नियुक्ति की जाएगी।	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2010-11 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
7.	फिल्म एवं टीवी में निर्माण प्रबंधन विभाग	दृश्य श्रव्य मीडिया बहुअनुशासनात्मक है जोकि काफी भिन्न भी है। एक सफल निर्माण को सभी भिन्नताओं के सरल और आर्थिक संयोजन की आवश्यकता होती है। प्रभावी और पेशेवर प्रबंधन के लिए व्यावहारिक ज्ञान और पेशेवर लोगों का होना आवश्यक है। ये प्रबंधक व्यापार संबंधी अनुशासन और पारदर्शिता लाने में समर्थ होंगे जिससे निर्माण आर्थिक रूप से सही और शाखपूर्ण रहेगा चूंकि यह संकुचित विशेषज्ञता का युग है इसलिए उद्योग के मुताबिक मानव संसाधन को प्रशिक्षित और इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।	1.44	1. नए अकादमिक ब्लॉक का निर्माण 2. कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर और एनीमेशन तथा डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर प्राप्त करना 3. मानवशक्ति की नियुक्ति	संस्थान की स्थापना का उद्देश्य पूरा होगा छात्र समुदाय लाभान्वित होगा और छात्रों को नए पाठ्यक्रम के अध्ययन का अवसर मिलेगा। उभरते क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। संस्थान भारतीय मीडिया की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाएगी और प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध कराकर उद्योग को सहयोग देगा	सीसीडब्ल्यु, एआईआर द्वारा निर्माण और रूपांतरण कार्य हाथ में लिया जाएगा। विभागीय खरीद से ही उपकरण प्राप्ति होगी। इसके लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक मानवशक्ति की नियुक्ति की जाएगी	1. लक्ष्य उपलब्धि धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2. संचालन लाइसेंस का नवीनीकरण तथा फ्रीक्वेंसी लाइसेंस 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर के कारक

भारतीय जनसंचार संस्थान
परिणाम बजट 2010-11 के अध्याय 11 में सारणी का प्रारूप

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4(i) गैर-नियोजित बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	जनसंचार में शोध व प्रशिक्षण : भारतीय जन संचार संस्थान	पत्रकारिता/जनसंचार के क्षेत्र में आईआईएमसी द्वारा आयोजित किए गए शोध अध्ययन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ गति बनए रखने के लिए उपयोगी है।	6.70	—	3.50	पी जी डिप्लोमा कोर्स आयोजित करना : नई दिल्ली और ढेंकवाल में पत्रकारिता (अंग्रेजी); नई दिल्ली में पत्रकारिता (हिन्दी), नई दिल्ली में रेडियो व टीवी पत्रकारिता, विज्ञापन व पब्लिक रिलेशंस और ढेंकनाल में ओड़िया पत्रकारिता (325); विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (40-45); आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के सेवा के दौरान पाठ्यक्रम (मंत्रालय की आवश्यकतानुसार) अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (600-700)	**पी जी, डिप्लोमा कोर्स आयोजित करना:** -पत्रकारिता (हिन्दी) 62 - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62) -पत्रकारिता (ओड़िया) (23) -एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस (70) -रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46) -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा कोर्स (40-45) **अल्पकालीन कार्यक्रम** -अल्पकालीन कोर्स/ कार्यशालाएं (600-700) -आई आई एस अधिकारियों के चल रहे कोर्सों को पूरा करना। -शोध अध्ययन (4 से 5 अध्ययन)। **प्रकाशन :** अंग्रेजी में कम्यूनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम जैसी अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं का, वार्षिक रिपोर्ट और छात्रों के लंब जर्नलों को प्रकाशित करना।	प्रवेश प्रक्रिया : (जुलाई 2010 तक 2 वर्ष की अवधि के सभी डिप्लोमा कोर्सों के लिए अखिल भारतीय आधार पर प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। पत्रिकाओं को अद्धवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार समय-समय पर शोध अध्ययन आयोजित किया जाएगा।	एन आर आई, शारीरिक रूप से विकलांग और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जैसे कुछ आरक्षित श्रेणियों में 100 प्रतिशत सीटों का नहीं भरना था अन्य संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिलने के कारण या व्यक्तिगत कारणों से आई आई एम सी को छोड़ देने की संभावना भी रहती है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2009-10			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4(i) गैर-नियोजित बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
2.	आई आई एम सी को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय में रूपान्तरित करना	जनसंचार में श्रेष्ठ और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय की स्थापना। विश्वभर के मीडिया उद्योग के लिए अच्छे फ्रोफेशनल को तैयार किया जाएगा। इस प्रस्तावित विश्व विद्यालय में- 1. आम सीट विस्तार के साथ-साथ ओबीसी उम्मीदवारों को 27% आरक्षण मिलेगा। 2. मास मीडिया से संबंधित मुद्दों पर आधुनिक प्रशिक्षण व शोध के लिए तीसरी दुनिया के देशों के भागीदारों को अवसर दिया जाएगा। कक्षाओं और कैम्पस में विभिन्न संस्कृति के छात्रों के बीच बातचीत से विकासशील और विकसित देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।	—	3.70	—	जनसंचार के विविध पहलुओं पर शोध अध्ययन आयोजित करना (3-4 अध्ययन) और दो अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं को निकालना (अंग्रेजी में कम्यूनिकेटर और हिन्दी में संचार माध्यम) निवेश पूर्व की गतिविधियों की जिम्मेदारी भी ली जाएगी।	डिप्लोमा कोर्सों में ओबीसी आरक्षण कोटा के तीसरे और अंतिम चरण का क्रियान्वयन भवनों के 50 प्रतिशत कार्यों का निर्माण और कुछ शिक्षण सहयोगी उपकरण की खरीद और प्राध्यापकों के रिक्त पदों को भरने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।	भवनों के निर्माण के लिए जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2010-11 के पहले तिमाही में शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।	इस स्कीम को अभी ईएफसी की मंजूरी प्राप्त करनी है और फरवरी/ मार्च 2010 तक इसे मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है।

नोट : कोष्ठक के अंदर दिए गए आंकड़े छात्रों की इस संख्या को दर्शाते हैं जो प्रवेश लेंगे।

* शैक्षणिक वर्ष 2010-11 से वर्तमान एक वर्ष की अवधि वाले पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स को मास्टर डिग्री के समतुल्य बनाने के लिए दो वर्ष की अवधि का बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। इन पाठ्यक्रमों, अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और शोध परियोजनाओं को आयोजित करने के अलावा इस संस्थान ने ईएफपी की मंजूरी मिलने के बाद ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अपनी नई योजना स्कीम है आई आई एम सी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय में रूपांतरित करना। ओबीसी आरक्षण का दूसरा और तीसरा चरण भी इस वर्ष के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			(i)	(ii)	(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक बजट अतिरिक्त संसाधन				
1.	अभिलेख फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन।	फिल्मों की प्राप्ति एवं फिल्म संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना	3.15	5.00	शून्य	600 फिल्में/डीवीडी/ प्राप्त करना। 300 फिल्मों तथा पोस्टर, स्टिल्स आदि अनुषंगी सामग्री का डिजिटलीकरण	फिल्मों की प्राप्ति डिजिटलीकरण एवं फिल्म संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना।	वार्षिक आधार	वार्षिक बजट आबंटन का प्रयोग करना
	कुल		**3.15**	**5.00**	शून्य				

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वित्तीय परिव्यय (बी ई 2010-11)	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का उत्पादन	भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने और फिल्म निर्माण में नई प्रतिभाओं को लाना	10.00	6 फिल्में	यह क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों और भारतीय सिनेमा के दर्शक को बढ़ायेगा और इस क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगा	फिल्में करीब एक साल में निर्मित होंगी	फिल्म के प्रति दर्शक की प्रतिक्रिया काफी लचीली और गैर अनुमान वाली है।
2.	इक्विटी भागीदारी	एनएफडीसी का प्राधिकार तथा प्रदत्त पूंजी आधार बढ़ाना ताकि अपने अधिदेश को पाने के लिए निगम के पास फंड उपलब्ध रहे।	3.00	—	फिल्म निर्माण को प्रभावी बनाने के अधिदेश का पालन करने के लिए यह निगम को पर्याप्त कोष उपलब्ध करायेगा।	एनएफसीडी ने इसके रिवाइवल को मापने के लिए बी आर पी एस ई को अधिकार दिया है और इसके लिए कुछ समय लगेगा। हालांकि इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है	यह योजना अभी स्वीकृत होनी है। केबिनेट द्वारा एनएफडीसी की इक्विटी में निवेश के प्रस्ताव की मंजूरी के बाद ही फंड जारी किया जा सकता है।

पत्र सूचना कार्यालय

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की स्थापना	नई दिल्ली में पीआईबी के लिए राष्ट्रीय मीडिया केंद्र का निर्माण	1000.00	मिट्टी की खुदाई का कार्य, नींव का कार्य, तहखाने भूतल, प्रथम तथा द्वितीय तल हेतु आरसीसी का कार्य तथा सभी तलों की फिनिशिंग	अनुलग्नक के अनुसार	संशोधित ईएफसी सीओ के अनुसार
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	सार्वजनिक सूचना अभियान (पी.आई.सी.) चला कर,प्रेस वार्ताएं आयोजित करके, सफलता की कहानियां जारी करके और प्रेस दौरे आयोजित करके केन्द्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना	1450.00	100 जन-सूचना अभियान चलाना, 4 प्रेस वार्ताएं, 100 सफलता समाचार और 10 प्रेस दौरे आयोजित करना	कालम 5 में वर्णन के अनुसार	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7
					दूसरी तिमाही 24 पीआईसी, 1 प्रेस वार्ता, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना। **तीसरी तिमाही** 30 पीआईसी, 1 प्रेस वार्ता, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना **चौथी तिमाही** 30 पीआईसी, 1 प्रेस वार्ता, 25 सफलता समाचार और पत्रकारों के 3 दौरे आयोजित करना।	
3	विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार इस योजना के तीन अंग हैं:					
i	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	मौके पर मीडिया केंद्र की स्थापना करके पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन, प्रेस वार्ताएं, विज्ञप्तियां, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, अखबार, फोटोकापी आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना।	8.00	मौके पर मीडिया केंद्र खोलना, सुविधाओं की व्यवस्था करना और पत्रकारों को विज्ञप्तियों, इंटरनेट, फोन, कंप्यूटर, फोटो कापी आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना	**तीसरी तिमाही** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां तीसरी तिमाही में शुरू की जाएंगी। फिल्म समारोह हर साल नवंबर-दिसंबर में गोवा में आयोजित होता है।	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7
ii	प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	पसूका विशेष प्रत्यायन हेतु अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए तैयार मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी जुटाते हैं।	1.25	प्रवासी दिवस समारोह में पसूका विशेष प्रत्यायन के लिए अधिकारी भेजता है। वे पत्रकारों के लिए तैयार मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर आदि सुविधाएं भी जुटाते हैं।	**चौथी तिमाही** कालम 5 में वर्णित सभी गतिविधियां चौथी तिमाही में की जाएंगी क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस समारोह हर वर्ष नई दिल्ली में जनवरी में होता है।	
iii	मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम	सूचना एवं मास मीडिया क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम एवं संयुक्त कार्यकारी आयोग/समझौते	15.75	सूचना एवं मास मीडिया क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान के 6 कार्यक्रम और 2 कार्यकारी आयोग/ समझौते	**प्रथम तिमाही**-2 सां.आ.प्र. (1 प्रतिनिधि मंडल आएगा, 1 जाएगा) **दूसरी तिमाही**-2 सां.अ.प्र. (1 प्रतिनिधि मंडल आएगा 1 जाएगा), **तृतीय तिमाही**-1 सं.अ.प्र (1 प्रतिनिधि मंडल आएगा) 1 संयुक्त कार्यकारी आयोग आएगा। **चतुर्थ तिमाही**-1 सां.अ.प्र. (जानेवाला) और 1 संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जाएगा	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4	5	6	7
4.	राष्ट्रमंडल खेल 2010 एवं राष्ट्रमंडल युवा खेल पुणे 2008 हेतु मुख्य प्रेस केंद्र तथा अन्य मीडिया केंद्र।	पत्रकारों के लिए प्रेस सेंटर तथा मीडिया सेंटर की स्थापना तथा पत्रकारों के लिये प्रेस सम्मेलन, प्रेस रिलीज देना और कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, समाचार पत्र, फोटोकॉपी आदि सुविधाओं सहित वर्क रूम की स्थापना।	2175.00	रुचि जगाना, समय पर सटीक सूचना देना, इन खेलों के प्रति मीडिया में जागरूकता लाना। ये खेल नई दिल्ली में 2010 में होंगे।	प्रेस केंद्र तथा मीडिया केंद्र की स्थापना के लिये कार्य शरू करना तथा रुचि पैदा करने और दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2011 के बारे में मीडिया के बीच जागरूकता फैलाना।	परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के चलते राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए मुख्य प्रेस केन्द्र और आयोजन स्थल पर मीडिया केन्द्रों की स्थापना की लागत अब 3175 लाख रुपए आंकी गई है। इसमें से 1000 लाख रुपये की आवश्यकता चालु वित्त वर्ष 2009-10 में होगी और इसे संशोधित अनुमानों में दर्शाया गया है। बाकी बची 2175 लाख रुप. की राशि वार्षिक योजना 2010-11 में रखी गई है।
		कुल	**4650.00**			

भारतीय प्रेस परिषद

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक/निष्पादन प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था होने के कारण परिषद कोई स्कीम नहीं चला रही है।	प्रेस की आज़ादी का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्तर को बनाए रखते हुए उसमें सुधार लाना	421.00	अप्रयोज्य	परिषद पंजीकृत समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और समाचार एजेन्सियों से प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शुल्क वसूल करती है और जमाराशियों पर ब्याज कमाती है। वर्ष 2009-10 में परिषद का लक्ष्य लेती और अन्य प्राप्तियों के शुल्क के रूप में 44.58 लाख रुपए इकट्ठा करके भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता को कम करता है।	चूंकि प्रेस परिषद् के कार्य अर्द्धन्यायिक प्रकृति के हैं और यह प्रेस के आचरण संबंधी स्तर का नियामन करती है, अत: इसके भौतिक प्रतिफल/परिणामों को आंकना संभव नहीं है।	कॉलम 5 के अनुसार	यह वादियों द्वारा आवश्यक शर्तें पूरा करने और परिषद द्वारा जांच पूरी करने पर निर्भर करता है।	शिकायतों के निपटारे में कोई जोखिम शामिल नहीं है।

फोटो प्रभाग

परिणाम बजट 2010-11 के अध्याय 2 में तालिकाओं का प्रारूप

(लाख रुपये में)

गैर-योजना

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रलेखन, प्रचार तथा अन्योन्य संदर्भ, फोटो द्वारा सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रसार	राजनीतिक, अर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रचार तथा अभिलेख तैयार करना।	355.00	नियमित फोटो प्रलेखन भावी पीढ़ियों के लिए परिवर्तन की दृश्य रिपोर्ट होगा। संभवत: ये अत्यधिक मूल्यवान प्रलेख होंगे जिन्हें जब जरूरत होगी दुबारा प्रयोग किया जाएगा।	यह प्रलेखन अन्योन्य संदर्भ द्वारा देश के सही इतिहास को जानने में मदद करेगा।	—	—

योजना

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**फोटोग्राफी राष्ट्रीय केंद्र** क. बाह्य स्रोत से सहयोग	पुस्तकालयकर्मी, पुस्तकालय सहायक, आईटी विशेषज्ञ (प्रोग्रामर्स, डाटा इंट्री ऑपरेटर) की भागीदारी	15.00	क. प्रभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन प्रयोग के लिए फोटो अभिलेखागार को कारगर बनाना	क. एक अच्छी फोटो लाइब्रेरी के माध्यम से प्रयोक्ता को किसी भी फोटो को सरलता से उपलब्ध कराना	एक वर्ष	—
	ख. फोटो और डिजिटल प्रबंधन के लिए बाह्य स्रोत का प्रयोग	बाहर से फोटोग्राफ्स का प्रबंध और वर्तमान फोटोग्राफ्स का डिजिटल प्रबंध, किताबों और अलमारियों को हासिल करना	15.00	ख. राष्ट्रीय महत्व की विविध फोटोग्राफ्स के साथ अभिलेखागार को समृद्ध करना।	ख. जनसाधारण को गुणवत्तावान फोटो उपलब्ध कराना।		—

	ग. तापमान नियंत्रण इकाई का प्रावधान	डिजिटल फोटो लाइब्रेरी में एयर कंडीशनर और नमी रोकने की व्यवस्था करना और विशेष सुरक्षा प्रणाली	20.00	ग. डिजिटल फॉरमेट में उपलब्ध संचयित फोटोग्राफ्स को संरक्षित करना	ग. एतिहासिक महत्व के दृश्य प्रलेखन का संरक्षण		—
	घ. अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संदर्भ साम्रगी	राष्ट्रीय फोटो केन्द्र के लिए डिजिटल फोटोग्राफी पर संदर्भ पुस्तकालय को गठित करने लिए पुस्तकों और संबंधित अध्ययन साम्रगी को हासिल करना	10.00	घ. अभिलेखागार में साम्रग्रियों के साथ पुस्तकालय का अंतर्सम्बंध बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह व्यावसायिक सहयोग स्वाभाविक रूप से साथ-साथ होना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सामग्रियों को सहयोग देना चाहिए	घ. गुणवत्तावान निर्माण में मदद		—
	ड. राष्ट्रमंडल खेंलों का फोटो अभिलेखन	वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के सिलसिले में 15 से 20 पेशेवर फोटोग्राफरों के दल को बाहर से नियुक्त करना जो राष्ट्रमंडल खेलों को समाचार देने और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के कवरेज और फोटोग्राफर में तालमेल रखेंगे	5.00	राष्ट्रमंडल खेल 2010 की सघन फोटोग्राफी तथा हार्ड कापी/सॉफ्ट कॉपी प्रेस को देना/वेबसाइट पर इमेज डाउनलोड करना	अंतर्राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम-राष्ट्रमंडल खेल-2010 का फोटो प्रचार		
2.	डिजिटल मोड में व्यापक फोटो कवरेज	फोटोग्राफरों को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक प्रभाग। नए तथा पेशेवर दोनों की तरह के फोटोग्राफरों के लिए राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार की शुरूआत तथा एमेच्योर फोटोग्राफरों को इसके राष्ट्रीय फोटोग्राफिक केन्द्र के भाग के रूप में रखा जाएगा।	20.00	आज के संदर्भ में फोटोग्राफी के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रभाग अधिक से अधिक फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करेगा कि वे देश के हित में अच्छा कार्य करें।	आज के संदर्भ में फोटोग्राफी के महत्व का विस्तार करना	—	—

3.	देश के प्रमुख शहरों में सचल प्रदर्शनी लगाना	2009-10 की अवधि के दौरान सचल प्रदर्शनी लगाने की परिकल्पना की गई जिसके अंतर्गत देश के प्रमुख नगरों में प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। स्वतंत्रता काल के बाद की अवधि में विकास की प्रक्रिया (प्रथम चरण से 1984 तक)	50.00	स्वतंत्रता के संदेश का प्रचार करना तथा विभिन्न अवधि में देश की उपलब्धियों की सूचना का प्रसार करना	विकास के संदेश का प्रसार	—	—
4.	दो और ऐसी ही प्रदर्शनियां विचाराधीन हैं।	कम से कम ऐसी दो और प्रदर्शिनयां अन्य विषय पर रखने का कार्यक्रम। दूसरी प्रदर्शनी चरण-2 1984 तक	25.00	वही	वही		
5.	कॉफी टेबल पुस्तकें	प्रलेखन पर दो कॉफी टेबल पुस्तकों का प्रकाशन	20.00	पुस्तक स्थायी संग्रह में भी शामिल की जाएगी तथा उसे विभिन्न पुस्तकालयों में रखा जाएगा ताकि वे भविष्य के लिए उपादेय हों	एक ही एलबम में विकास की प्रक्रिया का स्थायी संग्रह		
6.	प्रथम और आठवें एशियाई खेलों, सार्क खेलों, राष्ट्रमंडल युवा खेलों, के चित्रों की विशेष प्रदर्शनी	खेल के क्षेत्र में देश की प्रगति पर केन्द्रित प्रदर्शनी तथा प्रथम और आठवें एशियाई खेलों तथा सार्क खेलों और राष्ट्रमंडल युवा खेलों जो कि देश के खेल के विकास के संबंध में सरकार के योगदान पर केन्द्रित हैं उनपर विशेष ध्यान देना	20.00	खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों की अवधि में देश द्वारा खेल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।	खेलों के महत्व और उनके विकास को प्रस्तुत करना।		

7.	राष्ट्रमंडल खेलों में रीले के लिए इस्तेमाल क्वींस वैटन पर कॉफी टेबल पुस्तक	एक अनुपम कॉफी टेबल पुस्तक का प्रकाशन। 71 राष्ट्रमंडल देशों से गुजरते हुए क्वींस वैटन की गाथा।	25.00	प्रभाग को क्वींस वैटन रीले के गुजरते हुए समुचे दृश्य का प्रलेखन करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ है। इस पुस्तक में राष्ट्रमंडल के 71 देशों से गुजरते हुए दृश्य को इस पुस्तक में समाहित किया गया है।	वैटन के आवागमन के माध्यम से एकता के महत्व के संदेश का विस्तार करना	—	—
8.	सार्क स्तर की फोटो प्रतियोगता	सार्क स्तर की फोटो प्रतियोगिता का प्रस्ताव	25.00	फोटोग्राफर की सूझबूझ पैदा करना, क्षेत्र में, सार्क के अंतर्गत आने वाले देशों में फोटोग्राफर के कार्य का आदान-प्रदान	सार्क देशों में एकता	—	—
9.	उत्तर-पूर्व, जम्मू-काश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान के तहत डिजिटल मोड में व्यापक फोटो कवरेज	चिह्नित विकास परियोजनाओं की पहचान एवं प्रलेखन का कार्यान्वयन। उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में जीवन और पर्यावरण।	5.00	पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर आदि में विशेष अभियान। कम से कम दो विकासात्मक कार्य कला पांच राज्यों में चलाए जाएंगे।	विकास के ऐसे क्षेत्रों पर विशेष प्रकाश डालना जिनके बारे में अभी अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है।	—	—
		कुल	**255.00**				

प्रकाशन विभाग

गैर योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11		परिमाणात्मक कार्य/ भौतिक उत्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			गैर-योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	-	पत्रिकाओं व पुस्तकों को निकालना	2104.00	-	20 पत्रिकाएं और 100 से अधिक पुस्तकों को निकालना। दिल्ली में और दिल्ली के बाहर 150 पुस्तक प्रदर्शनियां/मेले आयोजित किए जाएंगे।	प्रकाशन विभाग का लक्ष्य है निम्नलिखित परिणामों को प्राप्त करना : 1. राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों पर पुस्तक छापना जिन पर अन्य प्रकाशन भवनों ने ध्यान नहीं दिया हो ऐसी पुस्तकों को कम कीमतों पर आम लोगों को उपलब्ध कराना। 2. विविधता में एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि की विचारधारा को मजबूत करना और बढ़ावा देना।	वार्षिक आधार पर	—

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11		परिमाणात्मक कार्य/ भौतिक उत्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	प्रकाशन विभाग का आधुनिकीकरण	दो बिक्री केन्द्रों (सेल्स इम्पोरिया) का आधुनिकीकरण और बिक्री केन्द्रों के लिए मोबाइल बुक वैन प्रदान करना।	20.00	-	दो बिक्री केन्द्रों (एस ई) का आधुनिकीकरण और एक मोबाइल बुक वैन की खरीद	भाषा विज्ञान और सूची प्रबंधन के स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ बिक्री केन्द्रों (एस ई) का जीर्णोद्धार करना और बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करना।	वार्षिक आधार	-
		कुल	**20.00**					

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

गैर योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11 (रुपये लाख में)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार	एम्पलायमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार का प्रकाशन, बेरोजगार युवाओं और लोगों को रोजगार के अवसर की जानकारी देना	2846.00	—	अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में एम्पलायमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार के 52 साप्ताहिक अंक निकालना	एम्पलायमेंट न्यूज प्रकाशित करके यह एकक निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य रखता है। (i) केंद्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में नौकरियां, यूपीएससी, एसएससी, राष्ट्रीयकृत बैंकों, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के परिणामों तथा प्रवेश अधिसूचनाओं/परीक्षा	वार्षिक आधार पर	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			गैर-योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
						अधिसूचनाओं की जानकारी देना। (ii) स्व-उद्यमिता तथा विभिन्न उभरते क्षेत्रों तथा परम्परागत क्षेत्रों में कैरियर पर लेखों की शृंखला निकालकर रोजगार के आयामों की जानकारी लोगों को देना। (iii) एम्पलायमेंट न्यूज की वेबसाइट के जरिए सरकारी क्षेत्र में रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध की जा रही है। वेबसाइट के जरिए आधुनिकतम मूल्य-संबंधित सेवाएं जैसे ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग तथा पाठकों को सीधे ई-मेल पर जानकारी आदि प्रदान की जा रही हैं।		

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 20010-11 (रुपये लाख में)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	रोजगार समाचार का आधुनिकीकरण	सरकारी मंत्रालयों/ विभागों को उनके विज्ञापन के प्रकाशन के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए इम्पलायमेंट न्यूज के दफ्तर का कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण	6.00	–	**(क)** अनुभागों का पुनरुद्धार **(ख)** 1 कम्प्यूटर एवं प्रिंटर की खरीद **(ग)** आउटसोर्सिंग सेवाओं द्वारा स्वचालित प्रणाली की देखरेख	**(क)** कैश अनुभाग का पुनरुद्धार **(ख)** प्रसार अनुभाग में कम्प्यूटर तथा सॉफ्टवेयर की आधुनिकतम तकनीक का प्रावधान	वार्षिक आधार पर	पुनरुद्धार/ अधिग्रहण का कार्य चालू काम को बिना बाधा पहुंचाए किया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह पूर्णतया स्वचालित कार्य माहौल में तब्दील हो जाए।

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

गैर-योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ उपलब्धियां	परिव्यय 2008-09		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			गैर योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	वेतन, ओवर टाइम, चिकित्सीय व्यय, यात्रा व्यय, कार्यालय खर्च, प्रकाशन	कार्यालय के विभिन्न कार्यों को पूरा करना जैसे—शीर्षक जारी करना, पंजीयक प्रमाणपत्र जारी करना, अखबारी कागज के आयात के लिए योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना, रियायती शुल्क पर प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करना, प्रिंट मीडिया के विकास पर वार्षिक रिपोर्ट 'प्रेस इन इंडिया' का प्रकाशन इत्यादि।	359.00	शून्य	शीर्षक सत्यापन, पंजीकरण मामले, समाचार पत्र प्रमाणपत्र, अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों को पात्रता प्रमाणपत्र*, प्रिंटिंग मशीन के आयात के लिए प्रकाशकों को अनिवार्यता प्रमाणपत्र*, प्रसार के दावों की समीक्षा* प्रकाशकों से प्राप्त आवेदन पत्रो/प्रार्थनाओं पर आधारित	इन गतिविधियों से पीआरबी अधिनियम 1867 में निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त मीडिया परिदृश्य के प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। प्रसार दावों की समीक्षा के बाद आरएनआई द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर इन प्रकाशनों को डीएवीपी द्वारा सरकारी विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे प्रिंट मीडिया द्वारा सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करने में मदद मिलेगी।	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार	लागू नहीं

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय (योजनाबद्ध स्कीम)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			गैर योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	आरएनआई का सुदृढ़ीकरण	समाचार-पत्रों को त्वरित, कुशल एवं पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीआरबी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की कड़ी जांच करना। वर्ष 2007-12 की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में और मध्य क्षेत्र में भोपाल में दो क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।	17.00	शून्य	गुवाहाटी और भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालयों में कामकाज शुरु किया जाएगा।	नये शीर्षकों के पंजीकरण, समाचार पत्रों की जांच, समाचार पत्रों की ओर से किये गए दावों की जांच जैसे कार्यों के लिए आरएनआई के मुख्यालय में आये बिना क्षेत्रीय कार्यालयों में ही कामकाज निपटाना।	नागरिक चार्टर में निर्धारित मानकों के अनुसार।	लागू नहीं

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	**गैर-योजना**		1.97						
	अ) मास मीडिया के विविध पहलुओं से सम्बंधित प्रलेखन सेवाओं को प्रदर्शित करना	मास मीडिया में इसकी सावधिक सेवाओं के माध्यम से इसकी घटनाओं और प्रवृत्तियों की सूचना एकत्रित, व्याख्यायित और प्रचार-प्रसारित करना	बजट में अलग से प्रावधान नहीं। व्यय सामान्य तौर पर कार्यालय खर्च से पूरा किया जाता है (0.28 लाख रुपये)	-	-	इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान प्रभाग का लक्ष्य 56 प्रलेखन सेवाओं को लाने का है। (विस्तृत जानकारी अध्याय-1 में दी गई है)	सभी वास्तविक प्रतिफल कॉलम 5 में दिए गए हैं।	समयावधि के अनुसार	कोई विशेष जोखिम नहीं है।
	ब) भारत में मास मीडिया का संकलन और संपादन—एक वार्षिक प्रकाशन	मास मीडिया पत्रकारिता से संबंधित मीडिया कर्ताओं, मीडिया नीति-निर्धारकों,	- वही -	-	-	भारत में मास मीडिया-इन इंडिया का **22वां** संस्करण प्रकाशित करना।	कॉलम 5 के अनुसार	- वही -	- वही -

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
		अध्यापकों और छात्रों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है							
	स) इंडिया एक वार्षिक संदर्भ का संकलन और संपादन	देश के विविध पहलुओं इसके भौगोलिक और जन सांख्यिकीय आकारों, राज्य व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को सूचना का बहुमूल्य स्रोत प्रदान करता है।	- वही -	-	-	इंडिया — एक वार्षिक संदर्भ - 2011 को निकालना	- वही -	- वही -	- वही -

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	**4(ii)**	**4(iii)**				
			गैर-योजना बजट	**योजना बजट**	**पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन**				
	द) घटनाक्रमों की पाक्षिक डायरी तैयार करना	मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दैनिक महत्वपूर्ण विकास की जानकारी देना।	- वही -	-	-	इस योजना के अन्तर्गत कार्यालय ने 24 पाक्षिक 'डायरी ऑफ इवेंट्स' निकालने का लक्ष्य रखा है।	कॉलम 5 में दिए गए सभी वास्तविक प्रतिफल	- वही -	- वही -
	योजना			0.25					
	गवेषणा इकाई मास मीडिया में अनुसंधान	किसी विशेष मीडिया संबंधी मुद्दे पर शोध किया जाएगा और जनता की राय ली जाएगी। ताकि नई नीति बनाई जा सके, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपनी मीडिया यूनिटों के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर लागू कर सके।	-	0.15	-	11वीं पंचवर्षीय योजना की यह योजना वर्ष 2010-11 में चौथे वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस वर्ष इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्षेत्रीय और स्थानीय विषय/ शीर्षक पर एक शोध पत्र निकाला जाएगा।	सभी वास्तविक प्रतिफल कॉलम पांच में दिये गये हैं।	यह नयी योजना है। बहुत कुछ बाहरी संस्थानों, छात्रों और विशिष्ट व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। इससे गहन निगरानी की आवश्यकता है।	- वही -

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ अतिरिक्त बजट संसाधन				
2.	अ) संदर्भ यूनिट-लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण	इस योजना के तहत प्रस्तावित राष्ट्रीय मीडिया लाइब्रेरी केंद्रीय मीडिया संदर्भ लाइब्रेरी के रूप में कार्य करेगी। इस लाइब्रेरी का उपयोग सूचना प्रसारण मंत्रालय, और उसकी मीडिया यूनिटों के अलावा पत्रकार, शोधकर्ता और विशिष्ट व्यक्ति भी कर सकेंगे। इस लाइब्रेरी को देश-विदेश की महत्वपूर्ण लाइब्रेरियों से जोड़ा जाएगा और 11वीं योजना के चौथे और पांचवें वर्ष में इस लाइब्रेरी को वर्चुअल लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया जाएगा।	-	-	-	वर्ष 2010-11 में इस प्रभाग ने 500 किताबें/ई-बुक आवर्ती पत्रिकाएं और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के लिए एएमसी खरीदने की कार्य योजना बनायी है।	सभी वास्तविक प्रतिफल कॉलम 5 में दर्शाये गये हैं।	लागू नहीं	स्थान की कमी

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	मानार्थ अतिरिक्त बजट संसाधन				
3.	संदर्भ यूनिट राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार	मीडिया को सामाजिक प्रतिबद्धता स्मरण कराने के लिए, जनता की भलाई के लिए मीडिया की शक्ति का उपयोग करना। सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की जिम्मेदारी निभाने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढावा देने में मीडिया की मदद लेना। उत्कृष्ट पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा कराना। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए कार्य करना। निजी मीडिया को प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना और सार्वजनिक प्रसारण में से समय स्लॉट देकर उन्हें भागीदार बनाना।		0.10		इस योजना के तहत प्रभाग ने प्रिंट मीडिया की सात श्रेणियों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के लिए एक-एक पुरस्कार (21 राष्ट्रीय मीडिया सम्मान) शुरू करने का प्रस्ताव किया है।	मार्ग निर्देशों में प्रस्तावित समयबद्धता के अनुरूप	- वही -	- वही -

गीत एवं नाटक प्रभाग

वार्षिक योजना 2010-11

ग्रामीण भारत के लिए सजीव कला और संस्कृति। इस योजना के निम्नलिखित अवयव हैं :

1. **पर्वतीय, आदिवासी, रेगिस्तानी, संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में आई सी टी गतिविधियां और मूल्यांकन :** सीमा पार से दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए प्रभाग जम्मू कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर क्षेत्र के संवेदनशील और अंदरूनी सीमावर्ती इलाकों में विशेष प्रचार अभियान चलाता है। इस तरह के अभियानों का उद्देश्य इन इलाकों के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ना भी है। सभी सीमा केन्द्र अपने क्षेत्रों में विशेष सेवा ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और अन्य रक्षा एजेंसियों के सहयोग से विभागीय और पंजीकृत निजी दलों, कैजुअल कलाकारों और भाड़े के वाहन लेकर विशेष प्रचार अभियान चलाते हैं।

   प्रभाग आदिवासी, पर्वतीय और रेगिस्तानी इलाकों में वहां के लोगों को उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विकास गतिविधियों की जानकारी देने के लिवए कार्यक्रम करता है। कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें वे समझा सकें। इन कार्यक्रमों का मकसद लोगों में देश के प्रति निकटता की भावना जगाना और विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रमों के लिए दल स्थानीय कलाकारों के बीच से बनाए जाते हैं। वे अपने कार्यक्रमों में स्थानीय बोलियों, मुहावरों और कला स्वरूपों का इस्तेमाल करते हैं। प्रभाग की योजना 2010-11 में ऐसे 4200 कार्यक्रम करने की है। निर्धारित रकम में निगरानी, परिवहन, संपर्क, आंकलन और मूल्यांकन तथा इकाई मुख्यालय और क्षेत्र में अन्य व्यवस्थाओं का खर्च शामिल है।

2. **राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर नाटकों का प्रदर्शन :** संगीत एवं नाटक प्रभाग ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम सचल है जिसे प्रदर्शनों के लिए जगह-जगह से लाया जाता है। इसमें थिएटर प्रोडक्शन की विभिन्न विधाओं से संबंधित 25 से 30 तकनीशियन और भाड़े के वाहन भी शामिल होते हैं। यह माध्यम जनता और खास तौर से युवाओं को देश की सांस्कृतिक विरासत, जनजीवन, महान हस्तियों के विचारों और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बेहद असरदार है। इसका एक अहम पहलू 100 से 120 स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों की भागीदारी है। प्रभाग का दिल्ली और बंगलुरू में स्थित अपनी दो ध्वनि एवं प्रकाश इकाइयों के जरिए 50 ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है।

3. **संगीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण :** प्रभाग ने बंगलूरू और दिल्ली में स्थित अपनी ध्वनि एवं प्रकाश इकाइयों को 10वीं योजना में एक तार्किक समय सीमा के भीतर पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करने की योजना बनाई थी। प्रभाग की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा क्षेत्रीय इकाइयों के अलावा 11वीं योजना के दौरान खोली गई या प्रस्तावित केन्द्रों को भी अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस किए जाने की जरूरत है। प्रभाग ने इन उपकरणों और प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए 5.00 लाख रुपए का प्रावधान किया है।

4. **पचहत्तर चिह्नित जिलों में गतिविधियां :** योजना आयोग ने 75 चिह्नित जिलों में 880 लाइव शो आयोजित करने के लिए 44 लाख रुपए प्रदान किए हैं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सौहार्द्र, आतंकवाद का विरोध और देशभक्ति पर केन्द्रित होंगे।

5. **साझा न्यूनतम कार्यक्रम का प्रचार :** प्रभाग 2010-11 में साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रचार के लिए 620 कार्यक्रम करेगा। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और रोजगार के मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित होंगे। इस काम के लिए 40 लाख रुपए का आवंटन किया गया है।

6. **जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष गतिविधियां :** इसके तहत प्रभाग 2010-11 में 560 कार्यक्रम आयोजित करेगा जिनके लिए 49 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से अतिरिक्त कोष मुहैया कराया गया है। लक्ष्य को भी इसी के अनुरूप बढ़ा दिया जाएगा।

गीत एवं नाटक प्रभाग

वार्षिक योजना 2010-11

योजना

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वर्ष 2010-11 का परिव्यय (योजना)			मात्रात्मक / वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3		4		5	6	7
			4(i)	4(ii)	4(iii)			
			गैर-योजना बजट	योजनागत बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन			
1.	ग्रामीण भारत के लिए जीवंत कला एवं संस्कृति	प्रचार कार्यक्रम	-	627.00	-	6310*	2010-11	
	घटकवार विवरण :							
	अ. पर्वतीय/जनजातीय/रेगिस्तानी /संवेदनशील/सीमावर्ती क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां के तहत प्रचार एवं प्रभाव मूल्यांकन	- वही -	-	256.00	-	4200	2010-11	
	ब. 75 चिन्हित जिलों में गतिविधियां	- वही -	-	44.00	-	880	2010-11	
	स. न्यूनतम साझा कार्यक्रम का प्रचार	- वही -	-	40.00	-	620	2010-11	
	द. जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर में विशेष गतिविधियां	- वही -	-	150.00	-	560*	2010-11	
	ध. राष्ट्रीय/सामाजिक मुद्दों पर रंगमंचीय कार्यक्रम	- वही -	-	50.00	-	50*	2010-11	
	च. गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण	- वही -	-	5.00	-	-	2010-11	
	छ. अनुसंधान/विकास एवं प्रशिक्षण			22.00			- वही -	
	ज. आईआईएमसी द्वारा प्रभाव मूल्यांकन			04.00			- वही -	

* अतिरिक्त कोष आबंटित होने के साथ ही लक्ष्य के घटकों में भी वृद्धि होगी।

गैर योजना बजट की वार्षिक योजना 2010-11 के दौरान प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	निर्धारित/ बजट (स्कीम का नाम)	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11 (गैर योजना)	मात्रात्मक वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/
1	2	3	4	5	6	7
1.	व्यवसायिक (सेवाएं)	विभागीय/निजी/ सूचीबद्ध कलाकारों द्वारा कार्यक्रम	300.00	6000 कार्यक्रम	2010-11	
2.	आपूर्ति एवं सामग्री		31,00	460 कार्यक्रम	2010-11	

गीत एवं नाटक प्रभाग

वार्षिक योजना 2010-11 के अनुमानित परिणाम

अनुलग्नक

1. 63,100 कार्य दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध करा जायेंगे जिससे 3155000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंच सकेगा।

2. i. 42000 कार्य दिवसों के लिए रोजगार सृजन होगा 21,00,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   ii. 88000 कार्य दिवसों के लिए रोजगार सृजित होंगे, 4,40,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   iii. 6200 कार्य दिवसों के लिए रोजगार का सृजन होगा 3,10,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   iv. 5,600 कार्य दिवसों के लिए रोजगार का सृजन होगा 2,80,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंचेगा।

   v. 10,000 कार्य दिवसों के लिए रोजगार का सृजन होगा, 1,50,000 व्यक्तियों तक सूचना/संदेश पहुंच सकेगा।

   vi.&vii. कार्यक्रमों की गुणवत्ता में कई गुणा वृद्धि होगी।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लि. (बेसिल) मंत्रालय की ओर से 6 नगरों में एफ.एम. टावर स्थापित करने के लिए परियोजना 'निजी एफ.एम. रेडियो' के अमल पर कार्यरत है।

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	योजना कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	निजी एफएम रेडियो (6 शहरों जैसे दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता और देहरादून) में नए टावरों को लगाने का कार्य	निजी एफएम प्रसारकों के लिए ट्रांसमिशन उपकरणों को सह-स्थापित करने के लिए नए ट्रांसमिशन टावरों को लगाने का कार्य	—	0.01	—	दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद और देहरादून में पांच टावरों के लगाने का कार्य पूरा हो गया है। कोलकाता में टावर लगाने के लिए वैकल्पिक स्थान की तलाश जारी है। 2008-09 तक 973 लाख रुपये की रकम जारी की जा चुकी है। 2009-10 में (जनवरी 2010) तक 1.08 रुपये जारी किये जा चुके है। स्कीम के तहत कुल स्वीकृत परिव्यय 1311.24 लाख रुपये है।	6 टावरों में से पांच टावर पूरे किए जा चुके है और अगस्त 2009-10 तक 50.66 लाख रुपये टावर के किराए के रुप में प्राप्त किए जा चुके है।		कोलकाता टावर के लिए वैकल्पिक स्थल की तलाश की जा रही है क्योंकि जो पहले स्थान चुना गया था वहां स्थानीय लोगों के रूकावट डालने के कारण उसे शुरू नहीं किया जा सका।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र

योजना/गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	इलेक्ट्रानिक मीडिया अनुश्रवण केन्द्र (ई एम एम सी) की स्थापना।	निजी/विदेशी टी वी चैनलों के कार्यक्रमों की मानिटरिंग ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में निर्धारित विज्ञापनों और कार्यक्रमों के कोड का अनुपालन निश्चित किया जा सके।	4.10	2.18	शून्य	चूंकि यह एक मानिंटरिंग सुविधा है इसलिए लाभ की मात्रा निश्चित नहीं की जा सकती। भौतिक लाभ सुविधा के शुरू हो जाने के कारण 9 जून 2008 से लगभग 150 चैनलों का चौबीसों घंटे अनुश्रवण किया जा रहा है। इसकी क्षमता 300 टीवी चैनलों तक बढ़ाई जा रही है।	वर्तमान में चौबीसों घंटे 150 चैनलों की निगरानी हो रही है। 300 चैनलों तक क्षमता बढ़ाई जा रही है।	300 चैनलों तक क्षमता बढ़ाई जा रही है। यह मार्च 2010 तक प्राप्त हो जाएगी।	9 जून 2008 से कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो गया है और वर्तमान में 150 चैनलों का अनुश्रवण (24×7) हो रहा है। इसकी क्षमता को 300 चैनलों तक बढ़ाया जा रहा है और इसके मार्च 2010 में पूरी होने की संभावना है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

चूंकि योजना आरंभिक चरण में है, इसके लिए वर्ष 2009-10 के बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2009-10			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर-योजना बजट	गैर-योजना बजट	कांम्पली-मेंटरी अतिरिक्त बजट संसाधन				
1	2	3		4		5	6	7	8
1.	अंतर्राष्ट्रीय चैनल	प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में भारत की स्थिति को उसी प्रकार प्रस्तुत करना है, जैसा अलजज़ीरा बीबीसी, सीएनएन, सीसीटीवी, आदि पर किया जाता है।	-	0.01	-	इसके लिये डीडी इंडिया जिसे बहुत से देशों में देखा जाता है, पर प्रसारण के साथ-साथ वर्तमान डीडी न्यूज़ चैनल के जरिये अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और कार्यक्रमों की शुरुआत करनी होगी।	संवेदनशील मसलों पर भारत की स्थिति और दृष्टिकोण को संभवत: अधिकतम देशों में यथाशीघ्र पहुंचाना।	प्रस्ताव प्रतिपादन के चरण में है।	

सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां

सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस नीति के बारे में आम जनता में जागरूकता जगाने की योजना का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए देश भर के विभिन्न भागों में सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए आम नागरिकों और विभिन्न स्वसंयेवी संस्थाओं को जनसंचार के कौशल को विकसित करने के बारे में जानकारी और शिक्षित करने के लिए सेमीनार और कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त कार्य कर रहे सामुदायिक रेडियो संचालकों का क्षमता निर्माण भी आवश्यक है। परिव्यय बजट (2010-11) के अंतर्गत 'आईईसी' गतिविधियां सामुदायिक रेडियो के लिए निम्न है :

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11			परिमाणकीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल	लक्षित परिव्यय	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां	सामुदायिक रेडियो प्रसारण के लिए अनुदान	-	80.00	-	एन जी ओ/सीएसओ के बीच नीति के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान में कार्य कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों संचालकों की क्षमता निर्माण करना।	समाज और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकात्मकता के जरिए सामुदायिक विकास।	देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यशालाएं/ परामर्श और प्रचार का आयोजन।	

सूचना भवन का निर्माण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2009-10			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	सूचना भवन के पांचवें चरण का निर्माण	1. सिविल कार्यों का आरंभ 2. विद्युतीय विकास कार्य	-	10.00	-	1. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करना 2. विद्युतीय विकास कार्य और सिविल कार्यों का आरम्भ	**विद्युतीय कार्य :** 1. लिफ्ट 2. सब स्टेशन 3. फायर अलार्म और आग से बचाव के उपाय **सिविल कार्य :** 1. नींव की खुदाई और पाइल वर्क 2. बेसमेंट और बड़ी संरचना का आरंभ	फ्लोचार्ट के अनुसार	दिसंबर 2009 में शुरू किया गया वास्तविक कार्य प्रगति पर है। पाइल कार्य और नींव का कार्य 2009-10 में समाप्त हो जाएगा। **जौखिम :** कॉमन वेल्थ खेलों के कारण जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के बहुत नजदीक होने की वजह से सूचना भवन के निर्माण कार्य में बाधा आ सकती है।

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 (योजना)		परिमाणनीय/ वितरण योग्य/ भौतिक नतीजे	अनुमानित परिणाम	प्रोसेस/ समयबद्धता	अभियुक्ति/ जोखिम घटक
1.	2	3	4		5	6	7	8
			4 (i) योजना बजट	4 (ii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	विकास संबंधी पहल का आर्थिक विश्लेषण	-फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करना; -फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्र के बारे में नियामक और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन	0.50		● एमआईएस विकास ● अध्ययन आयोजित किए जाने हैं	i) इससे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र-के विकास में आने वाली रुकावटों, विकास में इसके योगदान के बारे में मौजूदा ज्ञान के आधार का विस्तार होगा। ii) इससे मंत्रालय के स्तर पर नीति निर्माण प्रक्रिया मजबूत करने में सहायता मिलेगी। iii) लोक क्षेत्र के लिए सूचना संप्रेषण		

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

इस स्कीम के लिए वर्ष 2010-11 हेतु अनुमानित वार्षिक योजना परिव्यय 150 लाख रुपए है। मंत्रालय के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु विशिष्ट होने के कारण इसका (i) जेंडर बजट, (ii) अजजा बजट, और (iii) पूर्वोत्तर बजट संबंधी कोई विशिष्ट भाग नहीं है। हालांकि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को नामित करते समय महिलाओं, अजा/अजजा अधिकारियों और पूर्वोत्तर के प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जाता है।

परिणाम बजट 2009-10 के तालिकाओं का प्रपत्र

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11 योजना	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1.	आईआईएस अधिकारियों के लिये विदेश स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण	1. मानव संसाधन विकास के अंतर्गत मंत्रालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना ताकि उनकी योग्यता में इजाफा हो। 2. मंत्रालय के अधिकारियों को मीडिया/प्रशासन से संबंधित कई क्षेत्रों में विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण देना। 3. अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और जरूरतों को समझने के लिये विदेशों में स्थित संस्थान जैसे बीबीसी, थॉमसन फाउंडेशन, यूके, रेडियो नीदरलैंड, हार्वड यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना। 4. आईआईएस अधिकारियों को विभिन्न मीडिया इकाइयों में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिये उनके कैरियर के निरंतर विकास के लिये तैयार कार्यक्रमों का प्रशिक्षण।	150.00	(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष 2010-11 में मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों के 10-12 अधिकारियों को विदेश स्थित संस्थानों और आईआईएमसी में विदेशी व्याख्यानकारों को बुलाकर प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव। (ख) प्रत्येक वर्ष भारतीय सूचना सेवा के 120-140 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।	अधिकारियों की क्षमता में सुधार / उन्नयन के जरिए संगठन के प्रभाव को सुधारना	विभिन्न संस्थानों / संगठनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार इसे वर्ष भर में बांटा जाएगा।	कोई विशिष्ट जोखिम नहीं

आकाशवाणी - वार्षिक योजना (2010-11)

परिणाम बजट में परिणाम/लक्ष्य

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
	जारी स्कीम					
1.	जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष पैकेज (चरण-I & चरण II)	जे एंड के राज्य में रेडियो कवरेज का विस्तार	3.50	जे एंड के पैकेज चरण-I पूरा। द्वितीय चरण का एसआईटीसी पूरा। डीजी सेट 1 एमवीए (3) 2 के लिए कार्य सौंपा गया। तीसरे के लिए 1.78 करोड़ रुपये मिलने पर कार्य शुरू। चरण-II के लिए 5.70 करोड़ प्रदान।	डीटी सेट 1 एम वी ए (3) क्यू-2-प्रतिस्थापन पूर्ण क्यू 3-परीक्षण पूर्ण	जम्मू-कश्मीर में मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त डीजी सेटों एवं यूपीएस उपलब्ध कराने से कैप्टिव बिजली आपूर्ति मजबूत होगी एवं बिजली चले जाने पर और आपातकाल या प्राकृतिक आपदा के दौरान सतत प्रसारण सुनिश्चित हो सकेगा।
	पूंजी		1.50	डीटी सेट 500 केवीए (2) कार्य सौंपा गया।	डीटी सेट 1 एम वी ए (3) क्यू-2-प्रतिस्थापन पूर्ण क्यू 3-परीक्षण पूर्ण	
	राजस्व		2.00			
2.	पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज	पूर्वोत्तर में रेडियो कवरेज बढ़ाना	40.00	1. **19 नए एफएम स्टेशन** (1) साइट-15 को अंतिम रूप दिया गया (14 के लिए अधिग्रहण 1 का शीघ्र ही) बाकी 4 का अधिग्रहण किया जाना है। (2) **निर्माण कार्य** उदयपुर तथा नूतन बाज़ार में निर्माण कार्य 9 स्थानों पर कार्य प्रगति पर	1. **19 नए एफएम स्टेशन साइट** : बाकी 4 साइटों का अधिग्रहण किया जाना है। **निर्माण कार्य :** क्यू 1-9 स्थानों पर फेंसिंग कार्य पूरा	इससे सीमावर्ती तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कवरेज में सुधार होगा। संबंधित राज्य सरकारों को चेम्फाई, फेक, गोलवाड़ा और कोलासिब में आकाशवाणी साइट्स तक सड़क मार्ग बनाना होगा। तउपंग और कोलासिब अब स्थानीय लोकनिर्माण विभाग
	पूंजी		37.00			

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
				बोमडिला, गोलपाडा, लमडिंग, दापोरिजो, खोनसा, तोंपाग, चैंफई और कोलासिब लक्ष्य-जून 2010 चेरापूंजी, करीमगंज, वोखा और फेक में मार्च 2010 तक कार्य शुरू होने की उम्मीद बाकी चार साइटों के लिए अधिग्रहण का प्रावधान	क्यू-2, चार स्थानों पर कार्य पूरा होने की उम्मीद	द्वारा अभी एचटी लाइन शिफ्ट करना बाकी है जो हमारी जमीन पर है। इससे कार्य में बाधा आ रही है। इस विषय पर काम बाकी है।
	राजस्व		3.00			
				बी.टी.आर भवन और उपकरण स्थापन 8 स्थानों के लिए आंकलन स्वीकृत खानसा के लिए प्रक्रियाधीन निर्मार्ण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर लक्ष्य-अक्टूबर 2010 वर्ष 2010-11 के दौरान इन स्थानों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर होगा बाकी चार साइटों के लिए अधिग्रहण के बाद आकलन तैयार किया जाएगा उपकरण - टी आर एस प्राप्त - 50 एम टावर, प्रक्रियाधीन टेंडर मांगे जा रहे हैं।	ट्रांस भवन क्यू-1 15 साइटों पर भवन निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद, टावर के लिए आदेश होने हैं क्यू-2 टावर खड़े करने का कार्य शुरू होने की उम्मीद क्यू-3 8 स्थानों के लिए भवन निर्माण और प्रतिस्थापन का कार्य सौंपा गया क्यू-4 8 स्थानों का स्थापन कार्य पूरा होने की ओर	मणिपुर, नगालैंड और असम में कानून और व्यवस्था की समस्या
				2. सिलचर-5 के.डब्लू एफ एम ट्रांस और पैनल एंटीना की प्राप्ति और स्थापना खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन चैनल एंटीना के लिए टैंडर तकनीकी मूल्यांकन के अधीन	सिलचर-5 के.वी.एफ.एम. ट्रांस. क्यू-2 ट्रांस उपकरण की प्राप्ति और स्थापन कार्य शुरू क्यू 3 एंटीना प्राप्त क्यू-4 परीक्षण कार्य सम्पन्न	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
				3 गैंगटॉक- 10 केवी के एफएम ट्रांसमीटर- कानूनी प्रक्रिया के कारण ट्रांसमीटर की खरीद में विलंब हो गया। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायाल में 21.05.09 को निरस्त हो गया। बहरहाल, एल-1 फर्म अपेक्षित फॉरमेट के अनुसार, प्रदर्शन बैंक गारंटी नहीं दे पाई। आगे की कार्रवाई के लिए इस मामले पर काम चल रहा है।	3 गैंगटोक-10 केवी के ट्रांस, क्यू 1 दोबारा टेंडर करने पर ट्रां. के लिए आदेश पारित किए जाने हैं हॉस्टल निर्माण शुरू करना। क्यू-3 ट्रां. की प्राप्ति और स्थापना क्यू-4 स्थापना और हॉस्टल निर्माण पूर्ण	
				4 चिन्सुरा- 1000 केवी के मीडियम वेव ट्रांसमीटर- निर्माण कार्य पूरा, भवन के भीतर को छोड़कर, जो औपचारिक एटी देने के बाद शुरू होगी। एडवांस एडी के खिलाफ मामला उच्चतम न्यायालय मे दिया गया था। ट्रांसमीटर की खरीद के लिए औपचारिक एटी देने के साथ नवंबर 2010 तक उसकी डिलिवरी देनी है।	4 चिन्सुरा-1000 के वी के ट्रां. क्यू-1 ट्रां. भवन के अंदर सिविल कार्य पूर्ण क्यू-2 विभागीयकार्य जारी क्यू-3 ट्रां. की प्राप्ति और स्थापन शुरू क्यू-4 स्थापन पूर्ण, परीक्षण शुरू	
				5 डीएसएनजी- एमएसएस टर्मिनल- (१) डीएसएनजी निविदा स्वीकृत नहीं हुई और दोबारा मंगाई गई। (२) एमएसएस टर्मिनल के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं लेकिन फर्म द्वारा कोटेशन में दर्ज उपकरणों की मॉडल संख्या में फेरबदल किया गया जो स्वीकार्य नहीं था। ऑर्डर रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया।	क्यू 1-मार्च 2010 के बाद बचे स्थानों पर स्थापन कार्य जून 2010 तक पूरे होने की उम्मीद	
				6. डीएसएनजी सिस्टम (3) के दोबारा टेंडर होने हैं	5 डीएसएन जी सिस्टम क्यू-1 टैंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
					क्यू-2 तकनीकी मूल्यांकन और वाणिज्यिक निविदा पूर्ण होने की उम्मीद। 3 क्यू खरीद प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। क्यू-4 उपकरण आपूर्ति की जाती है।	
				7. एम एस एस टर्मिनल-आदेश दे दिए गए थे, लेकिन फर्म द्वारा कोट किए गए उपकरणों के मोडल नम्बरों में बदलाव स्वीकार्य नहीं थाक्ष आदेश पहले ही निरस्त। चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं इसलिए फंड अन्य परियोजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा।		
3.	एम.डब्ल्यू सेवाओं का विस्तार	प्राथमिक कवरेज क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाने के लिए ट्रांसमीटरों का उन्नयन	30.00		पूर्ण	
4.	एफ एम सेवाओं का विस्तार	एफ एम कवरेज को विस्तार देना जो कि उच्च गुणवत्ता के चलते प्रसिद्ध हुए हैं।	30.00	1) 1 के डब्लू एफ एम ट्रांसमीटर (3) -श्रीकाकुलाम प्रतिस्थापन पूर्ण नई टिहरी भवन निर्माण और प्रति स्थापन पूर्ण, ट्रा. खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन -गैरसण-भवन और प्रतिस्थापन पूर्ण, ट्रां. प्राप्त किए 50 एम टावर के लिए टेंडर तकनीकी मूल्यांकन के तहत	1) के डब्लू एफ एम ट्रांसमीटर (3) - श्रीकाकुलम क्यू-3 प्रतिस्थापन शुरू, ट्रांस प्राप्त लेकिन विजयवाडा में प्रतिस्थापन क्यू-3-4 प्रतिस्थापन पूर्ण - नई टिहरी क्यू-2 ट्रांस भवन पूरा होने की उम्मीद, ट्रांस प्राप्त होने की उम्मीद और विभागीय कार्य शुरू	जारी स्कीमों के क्रियांवयन के बाद एफएम कवरेज बढ़ने की उम्मीद

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
					क्यू-3 टावर खड़ा करने की उम्मीद क्यू-4 प्रतिस्थापन पूरा होने की उम्मीद -गैरसण-वही	
				ii) 5 केडब्लू एफ एम ट्रां. (3) -उज्जैन भवन निर्माण और प्रतिस्थापन कार्य पूरा, सिविल कार्य सौंपा गया ट्रां. खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन लक्ष्य - सितम्बर 2010 100 मी टावर पूर्ण - बागेश्वर - उपरोक्त (60 मी. टावर को छोड़कर) - करीम नगर - 100 मी. टावर और भवन तैयार, प्रतिस्थापन किया जाना है।	ii) 5 के डब्लू एफ एम ट्रां. (3) - उज्जैन-क्यू 1 भवन कार्य पूर्ण, विभागीय कार्य शुरू क्यू-2 - ट्रां. प्राप्ति, प्रतिस्थापन शुरू क्यू-3 ट्रा प्रतिस्थापन पूर्ण क्यू-4 परीक्षण और माप बागेश्वर - वही करीमनगर क्यू-4 प्रतिस्थापना पूर्ण, ट्रां. प्राप्त लेकिन हैदराबाद में स्थापित इसे वापस लाया जाएगा।	
				iii) 10 के डब्लू एफ एम ट्रां. (44) - सूर्यापेट को छोड़कर भवन निर्माण पूर्ण, इस का लक्ष्य 2010 दिसम्बर - 44 स्थानों के लिए ट्रां. प्राप्त किए जाने, ट्रान का लक्ष्य दिसम्बर 2010 - सात स्थानों (लखीमपुर खीरी, बांद्रा, मोनतभंजन, बालारधार, पटना श्रीनगर और विजयवाड़ा के लिए पैनल एंटीना प्राप्त किए जाने हैं) लक्ष्य-दिसम्बर 2010 (5)	iii) 10 के डब्लू एफ एम ट्रां (44) क्यू 1-सूर्यापट के लिए भवन निर्माण शुरू पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू क्यू-2 पैनल एंटीना और कंसोल प्राप्त क्यू-3 ट्रां. भवन पूर्ण क्यू-4 प्रतिस्थापन पूर्ण	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
				लखनऊ, मसूरी, कसौली (चंडीगढ़ के लिए) रांची और पटना के लिए पैनल एंटीना प्राप्त किए जाने हैं। लक्ष्य-दिसम्बर 2010, सूर्यापेट के लिए टावर प्राप्त करना, लक्ष्य-दिसम्बर 2010 रिकार्डिंग और ट्रां. की प्राप्ति लक्ष्य सितम्बर 2010		
				20 के डब्लू एफ एम (4) -फाजिल्का और अमृतसर-उपकरणों की प्राप्ति और प्रति सथापन, टैंडर प्रक्रियाधीन लक्ष्य जनवरी-2011 3000 मी० टी.वी. टावर तैयार होने के बाद अमृतसर में भवन निर्माण कार्य शुरू होगा फ़ाजिल्का और अमृतसर के लिए पैनल एंटीना प्राप्त किए जाने हैं लक्ष्य-सितम्बर 2010 रायबरेली-अधिग्रहण और भवन निर्माण कार्य पूर्ण चौटानहिल-भवन और प्रतिस्थापन पूर्ण, एस.एफ.सी. संशोधित	20 के डब्लू एफ एम (4) फाजिल्का-क्यू 1 आदेश किए जाने हैं क्यू-2 पैनल एंटीना प्राप्त होने हैं क्यू-3 पैनल एंटीना प्रतिस्थापना क्यू-4 ट्रां. प्राप्त होने हैं ओर प्रतिस्थापना होना है अमृतसर क्यू1-क्यू2-उपरोक्त क्यू-3 300 मी. टीवी. टावर पूरा होने की उम्मीद क्यू-4 पैनल एंटीना प्रतिस्थापन की उम्मीद रायबरेली - राज्य सरकार द्वरा साइट आबंटन के बाद सिविल कार्य शुरू होगा चौटान हिल-भवन कार्य शुरू ट्रां. आदेश दिए जाने हैं क्यू-3 भवन निर्माण पूर्व, क्यू-4 ट्रां. प्राप्त होने हैं	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
5.	निर्माण सुविधाओं का डिटिजटलीकरण	कंटेंट की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना	1.00	1. डिजिटल कंसोल - डिजिटल कंसोल की प्राप्ति (27) - खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन - डिजिटल रिकार्डिंग कंसोल (16) -खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन	डिजिटल कंसोल- क्यू१ - ऑर्डर जारी होने की संभावना। क्यू 3- कुछ कंसोल मिलने की उम्मीद। क्यू 4- बाकी बचे कंसोल के प्राप्त होने की उम्मीद।	डिजिटल कंसोल, डिजिटल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग उपकरणों से कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ेगी।
6.	स्टूडियो सुविधाओं तथा विविध स्कीमों का ऑटोमेशन		6.00	1. सिल्चर तथा देहरादून में केप्टिव अर्थ स्टेशन (अपलिंक) उपकरणों की प्राप्ति तथा प्रतिस्थापन तकनीकी रूप से कोई टेंडर स्वीकार्य नहीं पाया गया। नया एनआईटी जारी किया जाना है।	सिल्चर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन- क्यू 1- ऑर्डर दिए जाएंगे। क्यू 3 उपकरण प्राप्त हो जाएंगे और इंस्टॉलेशन शुरू होगा।	डिजिटल अपलिंक स्टेशन और कंप्यूटरीकृत वर्क स्टेशन कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।
				2. 48 स्टेशनों के लिए हार्डडिस्क आधारित वर्क सिस्टम प्राप्त करना।	48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसआईटीसी)की खरीद- क्यू 1- ऑर्डर दिए जाएंगे। क्यू 3- कुछ ऑर्डर मिलने की उम्मीद। क्यू 4- बाकी बचे ऑर्डर के प्राप्त होने की उम्मीद।	
				5. राजकोट-1000 के डब्ल्यू एम डब्ल्यू ट्रां - ट्रां. की प्राप्ति और प्रतिस्थापना। अग्रिम एटीके खिलाफ मामला सर्वोच्च न्यायालय में। ट्रः की खरीद के लिए नवंबर 2010 तक ऑपचारिकता दे दी गई है।	राजकोट- 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर- क्यू 1- लोक निर्माण कार्य पूरा और विभागीय काम शुरू। क्यू 3- ट्रांसमीटर प्राप्त और इंस्टॉलेशन का काम शूरू। क्यू 4- इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	पुराने ट्रांसमीटर को नए डिजिटल ट्रांसमीटर द्वारा बदला जाएगा, जिसकी क्षमता अधिक है।
				6. तवांग में स्थाई स्टूडियो (कार्य मौसम सीमित) हीटिंग छोडकर अधिकता कार्य पूर्ण	लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो- (कार्य का सीमित मौसम) क्यू 1- इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	डिजिटल कंसोल डिजिटल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग उपकरण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
					क्यू-1 बाकी प्रतिस्थापन कार्य पूर्ण	
				जयपुर में स्थाई स्टुडियो इंस्टालेशन का कार्य प्रक्रियाधीन जो मार्च 2010 तक पूरा होने की उम्मीद है। डिजीटल कंसोल प्राप्त करना प्रक्रियाधीन है।	क्यू-1-लंबित बिंदुओं का कार्य पूर्ण क्यू-2-संयुक्त निरीक्षण और कार्य देना	
7.	मेट्रो शहरों में स्टाफ क्वार्टर	प्रसार भारती स्टाफ के लिए मेट्रो केंद्रों पर क्वार्टर बनाना	दूरदर्शन द्वारा धन दिया जा रहा है।	दिल्ली-चरण 1 (323 क्वा) का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर तथा चरण-11 का कार्य सोंपा गया।	दिल्ली-क्यू 4-निर्माण पूर्णता की ओर	दूरदर्शन द्वारा कल्याण गतिविधियों के लिए धन दिया जा रहा है।
				मुंबई-68 कवार्टरों का निर्माण चार ब्लॉकों के लिए स्थानीय निकाय से मंजूरी चेन्नई-भवन योजना के लिए स्थानीय निकाय से मंजूरी की प्रतीक्षा	मुंबई-क्यू 1-उच्च ढांचा निर्माण हेतु टेंडर निकालना क्यू 4-कार्य जारी चेन्नई सीएमडीए को भवन योजना स्वीकृत करना बाकी। संस्थान अन्य अधिकारों की मांग की लेकिन लागू नहीं क्योंकि जमीन सरकारी।	
				कोलकाता-भवन निर्माण के लिए स्थानीय निकाय से मंजूरी की प्रतीक्षा	कोलकाता-स्थानीय निकाय से मंजूरी लंबित	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
	नई स्कीम		**102.98**			
2.1	ट्रांसमीटरों, स्टूडियो और कनेक्टिविटी तथा डी टी एच का डिजिटलीकरण	डिजिटल मोड में देशभर में कवरेज के लिए एस. डब्लू डीआरएम ट्रां.	30.00			
2.1.1	एम डब्लू डी आर एम ट्रांसमीटर					
2.1.1.ए	मौजूदा स्टेशनों पर 31 पुराने ट्रांसमीटरों को नए डीआरएम ट्रांसमीटरों से बदलना			ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में अनुमोदन हेतु	ईएफसी प्रस्ताव और उपकरण के लिए टेंडर मंगाना क्यू-2 टेंडर और टीई की प्रक्रिया क्यू-3 निविदा खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया क्यू-4 आर्डर जारी करना	ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में अनुमोदन हेतु
बी	1) अरुणाचल-चीन सीमा पर कैप्टिव पावर प्लांट के साथ तीन ट्रां. का उन्नयन			- वही -	- वही -	ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय में अनुमोदन हेतु
सी	डीआरएम ट्रां. से 10 के डब्लू एम डब्लू मोबाइल से 6 को बदलना			19 करोड़ रुपए की एसएफसी के लिए मंत्रालय से अनुमति पहले ही प्राप्त। ट्रां. के लिए एडवांस एटी की घोषणा डीपी-दिसम्बर 2010	क्यू-3 ट्रां. प्राप्त होने वाले हैं जिन्हें साइट पर रखा जाएगा	
डी	36 मौजूदा डीआरएम कंपेटिवल को डी आर एम में बदलना			ईएफसी प्रस्ताव मंत्रालय के पास मार्च 2010 तक उपकरण प्राप्ति और प्रतिस्थापन का लक्ष्य	क्यू-1 ई एफ सी प्रस्ताव और उपकरण के लिए टेंडर मंगाना क्यू-2 पीएसी प्रमाणन के लिए टेंडर प्रक्रिया क्यू-3 खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया और ऑर्डर क्यू-4 प्रतिस्थापन पूर्ण	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2	एफ एम डी आर एम + कंपेटिबल ट्रांसमीटर					
2.1.2.ए	मौजूदा 24 एआईआर टीवी स्थलों पर एफएम विस्तार तथा डीडी के 100 मौजूदा एलपीटी			ई एफ सी प्रस्ताव मंत्रालय में, उपकरण प्राप्ति मार्च 2011 तक	क्यू-1 - ई एफ सी प्रस्ताव तथा उपकरणों के लिए टेंडर मंगाना क्यू-2 टेंडर और टीई की प्रक्रिया क्यू-3- वाणिज्यिक निविदाएं खोलना और खरीद प्रस्ताव प्रक्रिया क्यू-4 आर्डर निकालना	
बी	40 मौजूदा स्टेशनों पर उच्च शक्ति वाले ट्रां. से एफएम/एम डब्लू ट्रां. को बदलना			- वही -	- वही -	
2.1.3	एस डब्लू डी आर एम ट्रां. पांच (2 दिल्ली, 2 अलीगढ़, 1 बेंगलूरु) को बदलना			- वही -	- वही -	
2.1.4	स्टूडियो					
2.1.4.ए	98 स्टूडियो और नेटवर्किंग का डिजिटलीकरण			वर्ष के दौरान 36 स्टूडियों में उपकरण प्राप्ति की उम्मीद	- वही -	
बी	दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा बढ़ाना और चेन्नई, मुंबई				क्यू 1- ई एफ सी स्वीकृति तथा प्राप्ति प्रस्ताव बनाना क्यू-2 विशिष्टताओं को अंतिम रूप देना और उपकरणों के लिए टेंडर मंगाना	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
	कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखीय सुविधा सृजन				क्यू-3 टेंडर और टी ई प्रक्रिया क्यू-4 वाणिज्यिक निविदा खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया	
सी.	मौजूदा 44 यूनिटों का आटोमेशन तथा 7 क्षे.स.ई. का सृजन				क्यू-3 टेंडर और टी ई प्रक्रिया क्यू-4 वाणिज्यिक निविदा खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया	
2.1.5	डिजिटल कनेक्टिविटी			ईएमसी प्रस्ताव मंत्रालय में		
ए.	एस टी एल कनेक्टिविटी को बदलना			31.50 करोड़ रु की उप-स्कीम को मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, टैंडर का तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है लक्ष्य - मार्च 2011	क्यू-1 - टेंडर के तकनीकी मूल्यांकन के बाद वाणिज्यिक निविदा खोली जानी है क्यू-2 खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू होनी है आदेश दे दिए गए हैं क्यू-4 उपकरण की आपूर्ति होनी है।	
बी. सी.	सीईएस का नया प्रस्ताव एस टी एल, डी एस एंड एन जी				क्यू-1 - ईएसफसी स्वीकृत और प्राप्ति प्रस्ताव बनाना क्यू-2 उपकरणों के लिए विशेषताएं निर्धारित करना और टेंडर मंगाना क्यू-3 टेंडर और टी ई की प्रक्रिया क्यू-4 वाणिज्यिक निविदा को खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया।	
डी.	सी बैंड और एन टी (44) का प्रावधान			4.28 करोड़ के ईएफसी को मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन लक्ष्य-दिसम्बर 2010	क्यू-1 - ईएसफसी स्वीकृत और प्राप्ति प्रस्ताव बनाना क्यू-2 उपकरणों के लिए विशेषताएं निर्धारित करना और टेंडर मंगाना क्यू-3 टेंडर और टी ई की प्रक्रिया क्यू-4 वाणिज्यिक निविदा को खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया।	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
ई.	डी टी एच चैनल बढ़ाना				क्यू-3 टेंडर और टी ई प्रक्रिया क्यू-4 वाणिज्यिक निविदा खोलना और खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया	
2.2	बाह्य सेवाओं को मजबूत करना	एस डब्लू ट्रां. का डिजिटलीकरण	0.10	मंत्रालय द्वारा 100 करोड़ रुपए की उप-स्कीम को मंजूरी		
2.2.1	दिल्ली और अलीगढ़ में 250 के वी एस डब्लू, टर्मिनल को डी आर एम मोड में बदलना			पी ए सी के लिए स्वीकृत संबंधी गतिरोध दूर कर दिया गया है। दिसम्बर 2010 तक उपकरण प्राप्त किए जाएंगे। प्रस्ताव आंतरिक वित्त विभाग के पास	क्यू-1 खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू होगी क्यू-3 उपकरण प्राप्त होने की उम्मीद क्यू-4 एस आई टी सी कार्य पूर्ण होने की उम्मीद	इन ब्राह्य सेवा ट्रां. पर डीआरएम सेवा लक्षित श्रोताओं को उपलब्ध होगी।
2.3	ई.-गर्वेनस, ट्रेनिंग संसाधन, सुरक्षा आई.ओ.एफ., डी/जी का तटीय क्षेत्रों में बढ़ाना अतिरिक्त अधिकारी का समायोजन कल्याण गतिविधियों और स्टाफ क्वार्टर	ढांचागत सुधार	21.38			
ए	ई-गर्वेनस और आई टी सुविधाओं का विस्तार			मंजूरी के लिए एस.एफ.सी. प्रस्ताव आई एफ ए को भेजा गया। हार्डवेयर की प्राप्ति हो सकेगी।	क्यू-3 टेंडर और टी ई प्रक्रिया क्यू-4 आदेश दे दिए गए हैं	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
बी	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं सहित एसटीआई (टी) और एसटीआई (पी) वर्ग बढ़ाना			मंजूरी के लिए एस एफ सी प्रस्ताव प्रसार भारती को भेजा गया	- वही -	
सी	मौजूदा केन्द्रों पर आई ओ एफ			- वही -	- वही -	
डी	श्रीनगर में छात्रावास सहित गुवाहाटी में कार्यालय/स्टाफ क्वार्टर			एसएफ प्रस्ताव आई एफ ए द्वारा मंजूर तथा मंजूरी के लिए प्रसार भारती सीईओ को भेजा गया।	क्यू 1-सिविल कार्य के लिए प्राथमिक आंकलन की प्रक्रिया क्यू-2 आकलन की मंजूरी और टेंडर मंगाना क्यू-3 टेंडर की प्रक्रिया और कार्य देना क्यू-4 कार्य प्रगति पर होने की उम्मीद	
2.4	नई प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (आर एंड डी)	सेटेलाइट और स्थलीय मोड में मल्टी मीडिया प्रसारण वेवकास्टिंग पोड कास्टिंग	1.50			
2.4.1	नई प्रौद्योगिकी					
	सेटेलाइट और स्थलीय मोड में मल्टी मीडिया प्रसारण			उपकरण प्राप्ति के लिए ऑर्डर दिए जाने हैं।	क्यू 1- ई एफ सी स्वीकृति तथा प्राप्ति प्रस्ताव बनाना क्यू-2 विशिष्टताओं को अंतिम रूप देना और उपकरणों के लिए टेंडर मंगाना	
	वेबकास्टिंग/पोड कास्टिंग			3.70 करोड़ रु का प्रस्ताव सीईओ द्वारा मंजूर, परियोजना मार्च 2010 तक पूरी होगी	मार्च 2010 तक परियोजना पूरी होगी।	

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
2.42	अनुसंधान और विकास			स्वीकृति प्राप्त। उपकरण विशिष्टताओं को अंतिम रूप। उपकरण हेतु ए/ए तथा ई/एस जारी।	क्यू-1 - ई एफ सी प्रस्ताव तथा उपकरणों के लिए टेंडर मंगाना क्यू-2 टेंडर और टीई की प्रक्रिया क्यू-3- वाणिज्यिक निविदाएं खोलना और खरीद प्रस्ताव प्रक्रिया क्यू-4 आर्डर निकालना	
	डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए पहुंच तथा रिसेप्शन सर्वे सिस्टम का विकास					
	उच्च शक्ति ट्रां. एंटीनाओं का विकास					
	प्रसारण ट्रां. के लिए आधुनिक टेलीमेट्री का विकास					
	26 मेगा हर्ट्ज एस डब्ल्यू बैंड में एलपी डीआरएम के लिए पायलट परियोजना					
	मॉनीटरिंग केंद्र टोड़ापुर में अकॉस्टिक लेबोरेटरी का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण					
	एम डब्ल्यू ट्रां के लिए उचित					

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	स्वीकृत व्यय 2010-11	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता तिमाही लक्ष्य	टिप्पणियां/जोखिम
1	2	3	4	5	6	7
	लागत वाले एंटीना का प्रदर्शन उपाय					
2.5	सॉफ्टवेयर	प्रतिस्पर्धी वातावरण में एआईआर श्रोताओं को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला सॉफ्टवेयर तैयार करना	10.00	करोड़ रुपये के संशोधित ईएफसी प्रस्ताव को प्रसार भारती के पास भेजा रहा है। जिसे आगे सू.एवं प्र. मंत्रालय के पास भेजा जाना है।	100.00 करोड़ रुपये का ईएफसी प्रस्ताव सीईओ द्वारा स्वीकृत मंत्रालय को पहले ही भेज दी गई है।	
2.6	जे.एंड के चरण-III	जे.एंड के के सीमा क्षेत्रों में एफ एम में सुधार	40.00	ईएफसी स्वीकृत के लिए 2010-11 के दौरान ट्रां. तथा संबंधित उपरकण प्राप्त किए जाएंगे तथा निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।	क्यू-1-ईएफसी स्वीकृत तथा उप. के लिए टेंडर तथा सिविल कार्य के लिए प्राथमिक आकलन क्यू-2 टेंडर तथाटीई को प्रक्रिया। क्यू-3 वाणिज्यिक बिड को खोलना तथा खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया। क्यू-4 ऑर्डर दे दिए गए हैं।	हिल टॉप पर तीन उच्च शक्ति ट्रां. लगाने का प्रस्ताव तथा एक एफएम ट्रां. मौजूदा डीडी केंद्र पर लगाने का प्रस्ताव, इसके अलावा, बिना कवरेज वाले क्षेत्रों में एफपीटी लगाने का प्रस्ताव
	कुल		**183.48**			

प्रसार भारती

परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्यों का वक्तव्य (2010-11)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2010-11)	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)		टिप्पणी/ जोखिम घटक
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
1.	जम्मू-कश्मीर विशेष योजना चरण-I तथा II (पूंजी)	जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज प्रसारण में सुधार। अमृतसर में टावर निर्माण के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज का पहला चरण कार्यान्वित हो गया है, टावर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण की गुणवत्ता तथा कवरेज एरिया में सुधार होगा। योजना के द्वितीय चरण में कंटेंट के सुधार पर जोर दिया गया है।	4.00	अमृतसर में 300 एमटीआर टावर अमृतसर में 300 मीटर ऊंचे टावर पर लगे एंटिना से डीडी-1 तथा डीडी-न्यूज एचपीटी का आरंभ	सीमापारीय क्षेत्रों में टीवी कवरेज में वृद्धि सीमापारीय क्षेत्रों में डीडी-1 तथा डीडी-न्यूज चैनल उपलब्ध कराना	2009-10 में अमृतसर में टावर निर्माण कार्य पूरा 2009-10 में अमृतसर में एचपीटी कार्य पूरा	- शून्य -
	राजस्व	डीडी कशीर 24 घंटे को सेटेलाइट चैनल के लिए कार्यक्रमों का निर्माण/अधिग्रहण/ कमीशनिंग और डीडीके श्रीनगर, जम्मू व लेह के लिए क्षेत्रीय सेवा	31.00	6500 एपीसोड का कार्यक्रम	डीडीके श्रीनगर, जम्मू और लेह की डीडी कशीर/क्षेत्रीय सेवा के लिए नए और गुवत्रावास सॉफ्टवेयर	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान	- शून्य -
2.	निर्माण सुविधाओं (स्टूडियो/ओबी) का आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण		10.00	स्टूडियो केंद्र, केंद्रीकृत रिकार्डिंग, संपादन तथा प्लेबैक का सभी 17 मुख्य दूरदर्शन केंद्रों में आधुनिकीकरण। ओ बी सुविधाओं का विस्तार तथा तीव्र न्यूज डिलीवरी प्रणाली	स्टूडियो का डिजिटलीकरण	कार्य चालू है	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
3.	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज चरण-I तथा II (पूंजी)	पूर्वोत्तर तथा अंडमान-निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज का सुदृढ़िकरण। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपीय इलाकों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए सरकार ने मई 06 में 256.85 करोड़ रुपये (हार्डवेयर - 134.3, साफ्टवेयर 122.55) की लागत से एक विशेष पैकेज (द्वितीय चरण) को मंजूरी दी।	4.00	**क.** कोकराझार में 150 मीटर टावर का कार्य पूर्ण। **ख.** गुवाहाटी में अपलिंकिंग सुविधा में बढ़ातेरी। अंडमान निकोबार में डीटीएच उपलब्ध जिसे किसी अन्य डीटीएच सेवा ने इस समय कवर नहीं किया। 10 केवीएचपीटी की कमीशनिंग उत्तर पूर्व के लिए चार और अंडमान निकोबार के लिए एक डीएसएनजी यूनिट	टीवी कवरेज तथा तकनीकी गुणवत्ता में सुधार। क्षेत्रीय ट्रांसमीशन के कवरेज और तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार में समाचार एकजग सुविधा	टावर निर्माण कार्य 2009-10 में पूर्ण। दूसरी तिमाही में ट्रांसमीटर का इस्टॉलेशन और कमीशनिंग	एक डीजीएनजी यूनिट की आपूर्ति की गई और अधिक यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया गया।
	राजस्व	डीडी नार्थ ईस्ट चैनल 24 घंटे के सेटलाइट चैनल और उत्तर पूर्व के 11 क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए कार्यक्रमों का निर्माण अधिग्रहण कमीशनिंग	21.00	6880 एपीसोड के कार्यक्रम	उत्तर पूर्व में डीडी चैनलों और 11 क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए नए और गुणवत्तावान सॉफ्टवेयर	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान	शून्य
4.	डीटीएच	इस योजना का उद्देश्य शेष बचे क्षेत्रों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है। डीटीएच की वर्तमान क्षमता 50 टीवी चैनल है।	0.00				डीटीएच सेवा शुरू हो चुकी है
5.	एचडीटीवी	यह वह तकनीक है जो उत्कृष्ट पिक्चर तथा वाइड स्क्रीन इमेज के कार्यों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तकनीक से 35 मी.मी. फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह तकनीक डिजिटल सराउंडिंग साउंड भी उपलब्ध कराती है। एचडीटीवी फिल्ड प्रोडक्शन के लिए प्रायोगिक परियोजना का कार्य चालू है।	2.00	एचडीटीवी प्रोडक्शन के लिए पायलट परियोजना स्वीकृत करना।	प्रायोगिक योजना एचडीटीवी फार्मेट में निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।	एचडीटीवी कैमरे तथा वीसीआर प्राप्त करना	फील्ड निर्माण वेन प्राप्त कर ली गई है
6.	**दसवीं योजना की अनुमोदित योजना**		10.00				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
	स्टाफ के लिए आवास, बुनियादी ढांचे तथा सुरक्षा में वृद्धि।	स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। बुनियादी ढांचे में वृद्धि/ विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा को मजबूत करना।		4 मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण। 11 स्थानों पर स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण।	चार मेट्रो तथा गैर मेट्रो स्थानों पर स्टाफ के लिए आवास निर्माण कार्य चल रहा है।	तीसरी तिमाही पटना, संभलपुर तथा बंगलौर में स्टाफ के लिए आवासों का काम 8 स्थानों पर स्टाफ के लिए आवास बना लिए गए।	
	अन्य योजनाएं						
	i) स्टूडियो संबंधित योजना	स्टूडियो केंद्रों के निर्माण तथा उत्पादन सुविधाओं की वृद्धि से स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराना।		तीन स्टूडियो की स्थापना।	नेटवर्क में शामिल स्टूडियो में निर्माण की गुणवत्ता में सुधार।	दूसरी तिमाही में चंडीगढ़, जम्मू तथा लेह में 2009-10 में स्टूडियो परियोजना पूर्ण। पणजी और गोरखपूर में काम पूरा।	
	ii) ट्रांसमीटर संबंधित योजना	स्थलीय कवरेज में सुधार		आटोमोड एलपीटी 50 एलपीटी-2	स्थलीय प्रसारण तथा कवरेज क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार।	पहली तिमाही- एलपीटी की आपूर्ति, दूसरी तीसरी तिमाही में एलपीटी का इस्ट्रालेशन पहली तिमाही-विलासपुर में ट्रांसमीटर की आपूर्ति, तीसरी तिमाही में एचपीटी का काम पूरा पहली तिमाही - महत्वनगर एचपीटी के लिए ट्रॉसमीटर की आपूर्ति, वहां टावर लगाने का काम चालू है।	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)		टिप्पणी/
1	2	3	4	5	6		7
	नई योजना						
	ट्रांसमीटर का डिजीटलीकरण, आधुनिकीकरण, ट्रांसमीटर उपकरणों की वृद्धि तथा नये उपकरण लगाना।		20.00				स्वीकृति/ अनुमोदन जारी करना बाकी है।
	ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण	स्थलीय ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण	15.00	डीटीटी के लिए 40 उपकरणों की खरीद - **आंशिक परिणाम**।	स्थलीय ट्रांसमिशन के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू - **आंशिक परिणाम**।	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण।	
	ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा दूसरे उपकरण लगाना।	ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा तकनीक पुरानी हो जाने और उपकरण के पुराने पड़ जाने के कारण नये उपकरण लगाना।	5.00	15 एचपीटी तथा 60 एलपीटी के स्थान पर आटोमोड एलपीटी लगाना। **आंशिक परिणाम**।	स्थलीय ट्रांसमिशन की गुणवत्ता तथा कवरेज में सुधार **आंशिक परिणाम**।	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण।	
	आपदा प्रबंधन, आपातकालीन आवश्यकताएं।	आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन जरूरतें।		आपदा प्रबंधन और आपात कालीन उपकरणों की खरीद **आंशिक परिणाम**	**आंशिक परिणाम**।	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूरी की जाएगी।	
	स्टूडियो डिजीटलीकरण : आधुनिकीकरण, वृद्धि, स्टूडियो/ ओबी उपकरणों का प्रतिस्थापन		**25.00**				स्वीकृति/ अनुमोदन जारी करना बाकी है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
	स्टूडियो का डिजीटलीकरण	निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, संपादन तथा अभिलेख सुविधाओं का पूर्ण डिजीटलीकरण।	**20.00**	छोटे केंद्रों के 31 स्टूडियो का आंशिक तथा पूर्ण डिजिटलीकरण तथा आठ केंद्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण - **आंशिक परिणाम**।	उत्पादन सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण - **आंशिक परिणाम**।	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा।	
	डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा स्टूडियो उपकरणों का प्रतिस्थापन	निर्माण संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन।	5.00	सभी छोटे तथा 66 बड़े केंद्रों पर निर्माण, पोस्ट प्रोडेक्शन, आडियो, लाइटिंग तथा विद्युत आपूर्ति में वृद्धि - **आंशिक परिणाम**।	तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि - **आंशिक परिणाम**।	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा।	
	ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाएं	नेटवर्क में ई-गवर्नेंस का समावेश तथा कार्यान्वयन।		ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य प्रवाह, प्रबंधन प्रणाली तथा स्टूडियो संचालन - **आंशिक परिणाम**।	डिलीवरी की प्रभावी प्रणाली - **आंशिक परिणाम**।	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा।	
	अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशिक्षण	नेटवर्क में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की वृद्धि।		प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओ में वृद्धि, एक स्थान पर उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में एसटीआईटी - **आंशिक परिणाम**।	**आंशिक परिणाम**	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा।	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
	डीटीएच : आधुनिकीकरण, वृद्धि, उपग्रह प्रसारण उपकरणों का प्रतिस्थापन		**5.00**				
	डीटीएच	हाइब्रिड मॉडल के साथ डीटीएच पर चैनलों की संख्या 50 से बढ़ाकर 198 करना (फ्री-टू-एयर चैनल तथा पेड चैनल)		डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनल में वृद्धि	**आंशिक परिणाम**	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा।	योजना को मंजूरी मिलनी है।
	उपग्रह प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन	पुराने हो चुके उपग्रह उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा नये डिजिटल उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापन, समाचार जुटाने की सुविधा में वृद्धि।		अर्थ स्टेशन का उन्नयन - वी सेट की संख्या 10 करना, 50 वी सेट टर्मिनल, 9 नए डीएसएनजी, 6 पुराने डीएसएनजी, तथा अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन के साथ 5 नये अर्थ स्टेशन - आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से काम किया जाएगा।	10 अर्थस्टेशन का उन्नयन चौकी तिमाही में 3 अर्थ स्टेशनों का उन्नयन, चौकी तिमाही में 6 डीएसएनजी की आपूर्ति, सीपीसी और डीडीके श्रथ्नगर (तीसरी तिमाही) में पीडीए रिप्लेसमेंट का काम पूरा।	6 डीएसएनजी के टेंडर मंगाए गए पीडीए के टेंडर मिले और उनकी जांच जारी।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
	एचडीटीवी	एचडीटीवी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तथा प्रसारण सुविधा	**15.00**	दिल्ली, मुंबई में एचडीटीवी प्रोडक्शन सुविधा	एचडी फारमेट में प्रोडक्शन अपलिंकिंग और क्षेत्रीय प्रसारण	दिल्ली में एचडीटीवी अपलिंक सुविधा का काम पूरा दूसरे उपकरणों का ऑडिट किया गया।	
				दिल्ली में प्लेआउट एक्टिविटी		पहली त्रिमाही दूसरे उपकरणों के लिए ऑर्डर चौथी तिमाही उपकरणों की आपूर्ति	
				दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा		पहली त्रिमाही दूसरे उपकरणों के लिए ऑर्डर चौथी तिमाही उपकरणों की आपूर्ति	
				दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के लिए फील्ड प्रोडक्शन सुविधा		पहली त्रिमाही दूसरे उपकरणों के लिए ऑर्डर चौथी तिमाही उपकरणों की आपूर्ति	
				दिल्ली, मुम्बई में आउटडोर प्रोडक्शन सुविधा के लिए मल्टी कैमरा मोबाइल उपकरण		पहली त्रिमाही दूसरे उपकरणों के लिए ऑर्डर चौथी तिमाही उपकरणों की आपूर्ति	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6		7
				दिल्ली में फ्लाई ओवर प्रोडक्शन सेट अप दिल्ली, मुम्बई कोलकाता, चेन्नई के लिए प्रिव्यू सुविधा दिल्ली, मुम्बई कोलकाता, चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर दिल्ली में एचडीटीवी अपलिंक सुविधा और उसे डीटीएच प्लेटफार्म पर डालना		पहली त्रिमाही दूसरे उपकरणों के लिए ऑर्डर चौथी तिमाही उपकरणों की आपूर्ति पहली त्रिमाही दूसरे उपकरणों के लिए ऑर्डर चौथी तिमाही उपकरणों की आपूर्ति 4 ट्रांसमीटर के लिए ऑर्डर दूसरी तिमाही काम पूर्ण	
5.	**स्टॉफ के लिए आवास अन्य कार्य**	स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि और सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	**5.00**	7 स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर 22 स्थानों पर गेस्टहाउस 10 स्थानों पर कम्यूनिटी सेंटर गुवाहाटी पर जोनल ऑफिस की इमारत 17 स्थानों पर डीएमसी भवन 10 स्थानों पर एलपीटी भवन डीडी भवन, काम्प्लैक्स में टावर सी भवन मौजूदा दूरदर्शन कार्यालयों में बुनियादी ढांचे व सुरक्षा में सुविधा	स्टाफ क्वार्टर, गेस्टहाउस, कम्यूनिटी सेंटर, डीएमसी भवन, एलपीटी भवन, जोनल ऑफिस के भवन, टावर सी भवन का निर्माण	सभी कार्यों को सौंपा गया। 4 एलपीटी भवन और 4 डीएमसी भवन का काम पूरा। चौथी तिमाही टावर सी का काम सौंपा गया (इन्सटी तिमाही)	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6		7
	सॉफटवेयर अधिग्रहण	डीडी उर्दू, डीडी भारती, डीडी इंडिया, आर एलएसएस, अभिलेखागार, सीसीयू व क्लासिक्स आदि चैनलों के लिए कार्यक्रमों का निर्माण। अधिग्रहण/ कमीशनिंग	**5.00**	5614 एपीसोड के	डीडी उर्दू, डीडी भारती, डथ्डी इंडिया, आरएलएसएस, अभिलेखागार सीसीयू और क्लासिक्स आदि के लिए नए व गुणवत्तावान साफ्टवेयर	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान	अगले दो वर्षों के लिए 485 करोड रुपये के व्यय के लिए योजना आयोजना संबंधित मंत्रालयों को ईसफसी सौंप दी गई है।
		कुल	**157.00**				
		पूंजी	**100.00**				
		राजस्व	**57.00**				
	राष्ट्रमंडल खेल कुल	**प्रसार भारती** **आईटीओपी**	**232.00** **64.67** **296.77**				

अध्याय-3

(सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल)

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

जहां तक पारदर्शिता का संबंध है, सांगठनिक ढांचा, फिल्म प्रमाणन दिशा-निर्देश, प्रवर्तन विवरण, प्रमाणन प्रक्रिया संबंधी सभी सूचनाएं वेबसाइट पर डाली गई हैं। आरटीआई एक्ट-2005 के अंतर्गत पीआईओ*/एपीआईओ* और सभी कर्मचारियों की सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। नागरिक घोषणा पत्र, पूछताछ, शिकायतें तथा जन विचारों को वेबसाइट पर डाला गया है ताकि सीबीएफसी की फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया संबंधी अथवा किसी भी व्यक्तिगत शिकायतों पर आम जनता प्रश्न पूछ सके।

*** जनसूचना अधिकारी**

*** सहायक जन सूचना अधिकारी**

बाल फिल्म समिति, भारत

सीएफएसआई के पूर्व अध्यक्ष ने फिल्म सिटी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भूमि आवंटित करने के लिए अनुरोध किया। महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज तथा सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड ने फिल्म सिटी, गोरेगांव में 1600 व.मी. जगह का प्रस्ताव दिया है। सीएफएसआई अब वित्तीय जरुरतों के साथ महाराष्ट्र सरकार के अनुमोदन का इंतजार कर रही है।

सीएफएसआई का उद्देश्य यहां एक राष्ट्रीय महत्व के आधुनिक बाल फिल्म परिसर का निर्माण करना है, जिसमें फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं सहित एक एनीमेशन तथा पपेट स्टूडियो का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य अच्छी फिल्मों का निर्माण करना है। इस परिसर में बाल फिल्म अभिलेखागार स्थापित करने की भी योजना है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

निदेशालय अपने कार्मिकों की संख्या को उचित स्तर पर लाकर स्वयं को नया स्वरूप दे रहा है ताकि इसकी कार्यक्षमता में सुधार हो। निदेशालय का मुख्य जोर जनजातीय, सीमावर्ती क्षेत्र, दूरदराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ाने पर है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहुंच से बाहर है। इस प्रक्रिया में, निदेशालय ने राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों की अपनी 61 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां या तो बंद कर दी हैं या उन्हें दूसरी इकाइयों में मिला दिया है तथा कर्मचारियों को ऐसी इकाइयों में भेजा गया है जहां कर्मचारियों की आवश्यकता है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य एवं प्रचार निदेशालय भारत सरकार की केन्द्रीकृत विज्ञापन एजेंसी है जो सामाजिक-आर्थिक उत्थान से जुड़े कार्यक्रमों/योजनाओं और राष्ट्रीय एकता, आतंकवाद विरोधी, सांप्रदायिक सदभाव से जुड़े मुद्दों की जानकारी प्रदर्शनियां, समाचार पत्रों, विभिन्न केबल एवं सैटेलाइट चैनलों, रेडियो, डिजीटल सिनेमा, बाह्य प्रचार माध्यमों (आउटडोर पब्लिसिटी) और मुद्रित प्रचार सामग्री इत्यादि द्वारा देश भर में प्रचार किया जाता है। सरकार ने मुद्रित माध्यम के लिए नई विज्ञापन नीति लागू की है तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिए विज्ञापन/प्रचार के संबंध में आडियो-विजुअल नीति भी लागू की है जिससे प्रचार तथा विज्ञापन के विविध पहलूओं को एकरूप किया जा सके। इन नीतियों के लागू होने से पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिला है। डीएवीपी एक ऐसी नोडल मल्टीमीडिया एजेंसी है जो आम लोगों को सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के विषय में जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी से विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए विकासात्मक गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करत ेहै। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, डीएवीपी ने नई आधुनिक प्रौद्योगिकी, विज्ञापन तकनीक, जन प्रचार, प्रशासन और प्रबंध में कम्प्यूटर साक्षरता और सूचना-प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कर रहा है। यह उपाय बेहद कारगर है तथा देश को प्रभावी ढंग से प्रचार करने के साथ ही संदेश को प्रभावी ढंग से आत्मसात करने मं सहायक सिद्ध होता है जिससे श्रोता (संदेश प्राप्तकर्ता) को बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित भी करता है। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत डीएवीपी के आधुनिकीकरण जैसी नी योजनाओं पर भी डीएवीपी मे काम कर रहा है। डीएवीपी के आधुनिकरण योजना के तहत 2007-08 की वार्षिक योजना के बाद से ही निदेशालय द्वारा कर्मचारियों की कौशल और क्षमता के उन्नयन के लिए आवश्यक ढांचागत क्षमता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे योजनाों के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी साथ ही लक्षिति लाभार्थी तक संदेश पहुंचाने में बेहतर सहायक साबित होगा।

फिल्म समारोह निदेशालय

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2010 का आयोजन तथा 2009 के लिए 57वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना।

डीएफएफ वर्ष भर भारत में भारतीय पेनोरमा फिल्मों के प्रदर्शन तथा विश्व भर में फिल्म महोत्सवों में भागीदारी जैसी अपनी नियमित गतिविधियां चलाता रहेगा।

फिल्म प्रभाग

परिणाम सुधार और योजना उपलब्धि

गैर सरकारी संगठनों एवं बाहर के निर्माताओं के द्वारा वृत्तचित्र का निर्माण सामाजिक समस्या और उसके हल से समाज में सुधार और बदलाव का प्रयास सरकार कर रही है।

मुविंग ईमेज संग्रहालय की फिल्म प्रभाग मुंबई में स्थापना से फिल्मों के इतिहास की जानकारी दृश्य-श्रव्य माध्यम से और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फिल्म निर्माण, निर्देशक, निर्माता इत्यादि सामग्री दर्शायी गई। यह संग्रहालय फिल्म निर्माताओं, छात्रों, जागरुक और समीक्षकों के साथ फिल्म निर्माण से अन्जान व्यक्ति वो भी इससे रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। फिल्मों की समृद्धता से सिर्फ भारत ही नहीं विश्व के लोग परिचित होंगें।

भारत और विदेशों में फिल्म बाजारों में भागीदारी

फिल्म क्षेत्र हालांकि ज्यादातर निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है परंतु यह भारत में एक सशक्त सांस्कृतिक उद्योग है। भारत का संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक फिल्में बनाने वाले देशों में पहला स्थान है। किंतु, राजस्व हासिल करने की दृष्टि से विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की भागीदारी नगण्य है। प्रौद्योगिकी में प्रगति की फिल्म उद्योग के विकास के सभी क्षेत्रों—यानी फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका है।

विदेशी फिल्म समारोहों/बाजारों में भागीदारी : विश्व बाजार में भारतीय फिल्मों की हिस्सेदारी प्रोत्साहित आयोजन करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/बाजारों में हिस्सा लेता है। केन्स फिल्म समारोह/बाजार में भारतीय पेवेलियन का आयोजन निजी उद्योगों की शीर्ष संस्था एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ मिलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बर्लिन में यूरोपीय फिल्म बाजार, 2009 में हिस्सा लिया।

एनीमेशन, गेमिंग तथा दृश्य प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना

इस संबंध में, यह कहना है कि जब योजना आयोग से पहले सैद्धांतिक अनुमति मांगी थी, उन्होंने हमें ईडीपीआर दाखिल के निर्देश दिए। हमने मौजूदा फिल्म एवं टेलीविजन स्कूल पुणे और कोलकाता तथा आईआईएमसी को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह के केंद्र के साथ पुनः निरीक्षण करने की प्रार्थना की। सैद्धांतिक अनुमति विस्तृत एच आर गेप अध्ययन के आधार पर योजना आयोग से मांगी गई थी। इस अध्ययन को एक परामर्शक ने किया था जिसने एनीमेशन, गेमिंग तथा विशेष प्रभाव के लिए मानव संसाधन की मांग तथा आपूर्ति के बीच निश्चित रूप से एच आर अंतर की बात मानी थी। इसलिए, परामर्शक ने केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया। परामर्शक ने वर्तमान में तथा निकट भविष्य में इस उद्योग के लिए विभिन्न कौशल की आवश्यकता पर भी एक अध्ययन किया।

योजना आयोग की आवश्यकता के अनुसार तथा मंत्रालय में विस्तृत विचार विमर्श के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसमें शामिल है क्या परियोजना पीपीपी मोड अथवा पीपीपी के विभिन्न रूपों में स्थापित किया जाना चाहिए। इस संबंध में विशिष्ट सुझावों के लिए परामर्शक की आवश्यकता पड़ेगी। अंत में यह मानना है कि मंत्रालय आईएफडी के परामर्श से इस उद्देश्य के लिए परामर्शक तय करने की प्रक्रिया में है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

फिल्म निर्माण की कला और तकनीक में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला प्रमुख संस्थान होने के नाते इसके स्थायित्व, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा प्रशिक्षण वातावरण के उन्नयन के लिए भारत सरकार की नीति अनुदान-सहायता के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्रदान करती है।

एफटीआईआई को अनुदान सहायता स्कीम के अंतर्गत उपकरण की प्राप्ति, सिविल एवं विद्युत निर्माण आदि में उपलब्धियों के जरिए भौतिक तथा वित्तीय निगरानी सांकेतिक है। इसके अलावा हार्डवेयर वस्तुओं की प्राप्ति/साफ्टवेयर सामानों का उत्पादन, संबंधित कार्य जैसे अनुसंधान, लॉयल्टी, प्रतिभा शुल्क आदि, साथ ही संबंधित कार्य जैसे कार्यक्रमों का निर्माण, फिल्मों में रुपांतर, श्रोता अनुसंधान आदि तथा छात्रवृत्ति और छात्रों के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रमों सहित एचआरडी पहलुओं के अंतर्गत आदान प्रदान/प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहचान में उपलब्धि के अंश के माध्यम से सांकेतिक है।

जन सूचना प्रणाली : एफटीआईआई द्वारा संचालित पाठ्क्रमों और अन्य अकादमिक गतिविधियों को उच्चतम स्तर तक पारदर्शी बनाने के लिए बेबसाइट/प्रिंट मीडिया में विज्ञापन दिए जाते हैं। मशीनरी और उपकरणों की प्राप्ति भी दोनों मीडिया में खुले विज्ञापन में सार्वजनिक टेंडर के माध्यम से की जाती है।

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

दो नए अकादमिक विभागों के निर्माण के अतिरिक्त संस्थान की इमारत में एक अतिआधुनिक फिल्म स्टूडियो के निर्माण का प्रस्ताव है। बड़ी पारदर्शिकता का परिचय देने के लिए संस्थान में एक शिकायत प्रकोष्ठ है और नागरिक घोषणा पत्र का प्रकाशन भी किया जाता है जो संस्थान की वेबसाइट (www.Srfti.gov.in) उपलब्ध है।

एक शैक्षिक संस्थान होने के नाते एसआरएफटीआई की समाज में निभाने के लिए सीमित/विशिष्ट भूमिका है। अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रुप से प्रभावी अभियान चलाया जाता है। ऑडिटोरियम, छात्रावास आदि सभी तरह की सुविधाएं अलग प्रकार के व्यक्तियों (देखने और सुनने में अक्षम व्यक्तियों को छोड़कर क्योंकि संस्थान दृश्य मीडिया है) के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। इंटरनेट कक्ष और लाइब्रेरी भूतल पर स्थित हैं ताकि सभी की पहुंच आसान हो। जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों और शिक्षकों द्वारा नियमित कार्यशालाएं तथा परिचर्चाएं आयोजित की जाती हैं। अलग तरह के योग्य व्यक्तियों के लिए संस्थान में समान अवसर हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान

जो व्यक्ति या महिला मीडिया संस्थानों से जुड़कर काम करना चाहते हैं यह संस्थान उनको इस क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल/तकनीक और अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। यह संस्तान अपने छात्रों को समाज के लिए उपयोगी सदस्यों के रुप में विकसित करने के लिए प्रयास करता है। यही प्रयास इस संस्थान और इसके छात्रों को एक अलग परिचय और चरित्र प्रदान करता है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

फिल्मों तथा अनुषंगी सामग्री का डिजिटाइजेशन

सभी तरह की फिल्में रसायनों का मिश्रण होती हैं जिन्हें यदि आदर्श स्थितियों में न रखा जाए तो नष्ट हो सकती हैं। निम्न स्तरीय भंडारण से और नुकसान होता है जिसके चलते गंदगी और कवक के कारण क्षरण का शिकार हो जाती हैं और गंदी, धब्बेदार तथा फट जाती हैं। फिल्म क्षरण से निपटने का व्यावहारिक तरीका फिल्म और मेग्नेटिक मीडिया को डिजिटल फॉर्मेट में बदलना है जोकि टिकाऊ है, भंडारण में आसान है, बारंबार इस्तेमाल के चलते कटने-फटने का डर नहीं और दीर्घकालीन प्रौद्योगिकीय मियाद है। पोस्टर, फिल्मों और अनुषंगी सामग्री को खोजने और उसे प्राप्त करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को हासिल करते हुए, एनएफएआई का अपना लगभग 5000 फिल्मों तथा गीत पुस्तिकाओं, वाल पोस्टरों, तस्वीरों, पत्र कतरनों, लगभग 40,000 पटकथाओं, दुर्लभ पुस्तकों और पत्रिकाओं जो 30 के दशक तक पुराने हैं, का संग्रह है। बदलती प्रौद्योगिकी के साथ, एनएफएआई ने फिल्मों और अनुषंगी सामग्री को डिजिटाइजेशन और जीर्णोद्वार का कार्य हाथ में लिया है। रिपोर्ट अवधि के दौरान लगभग 100 महत्वपूर्ण फिल्मों का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है। जहां तक अनुषंगी सामग्री का संबंध है, सभी वाल पोस्टरों, गीत पुस्तिकाओं, स्टिल्स तथा पत्र कतरनों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

सुधार के उपाय और नीतिगत पहलें

1. ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण के लिये एनएफडीसी को सरकारी मदद देने का निर्णय लिया गया है।

2. यह प्रस्ताव है कि एनएफडीसी सहनिर्माण के क्षेत्र में भी काम करेगा और संभावनाशील अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी सहनिर्माताओं को बुनियादी पूंजी मुहैया करायेगा। इसके लिये जरूरी पूंजी की पूर्ति कंपनी के आईईबीआर से की जायेगी।

3. एनएफडीसी ने निम्नलिखित उद्देश्यों से विदेशी फिल्म और टेलीविजन बाजार में भागीदारी करने की निर्यात रणनीति बनायी है :

i. प्रदर्शन के विभिन्न माध्यमों के जरिये विदेश वितरण के लिए भारतीय फिल्मों का निर्यात

ii. अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण के लिये साझेदारों की पहचान

iii. लाइन प्रोड्यूसर के रूप में एनएफडीसी की सेवाओं का विकास

iv. भारत को फिल्मों की शूटिंग के स्थल के रूप में प्रचारित करना

v. भारतीय बाजारों के लिये विदेशी फिल्मों का आयात

vi. फिल्म निर्माण एवं एनिमेशन में विदेशी ग्राहकों के लिये अधिकृत निर्माण के काम को हाथ में लेना।

4. भारतीय फिल्म परियोजनाओं की गुणवत्ता, उसके दायरे तथा उसकी आकांक्षाओं में विस्तार करने के उद्देश्य से एनएफडीसी फिल्म उद्योग को विभिन्न तरह की पटकथा की उपलब्धता को व्यापक बनाने के अपने प्रयास के तहत उसने पटकथा विकसित करने के लिये हर साल खास संख्या में भारतीय लेखकों को सहायता देने का लक्ष्य बनाया है ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार को उच्च गुणवत्ता वाली तथा बाजार में बिक सकने वाली सामग्रियां विकसित हो सके।

5. चूंकि एनएफडीसी पिछले कुछ वर्षों से घाटे में है, इसलिये इससे पुनर्जीवन के लिये इसके मामले को बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (बीआरपीएसई) के पास सौंपने का फैसला किया गया था। तदानुसार एसबीआई केपिटल मार्केट्स लिमिटेड की सहायता से एनएफडीसी द्वारा तैयार एक पुनर्जीवन प्रस्ताव बीआरपीएसई को भेजा गया है।

6. सरकार ने एनएफडीसी को छोटा किंतु दक्ष निकाय बनाने के लिये इसके मानव संसाधनों को सुसंगत बनाने के लिये 2008-09 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के एनएफडीसी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इस कड़ी में, 2008-09 की अवधि में वीआरएस के अंतर्गत 69 कर्मचारी मुक्त किं जा चुके है और 2009-10 में निगम की मानव शक्ति को 209 से 140 तक लाना है। 5.91 रुपये के योजना परिव्यय के साथ संगठन को हल्का और प्रभावी बनाने के लिए 40 अधिशेष मानव शक्ति छंटनी के लिए निगम वीआरएस का एक और चक्र शुरु करने का प्रस्ताव ला रहा है।

पत्र सूचना कार्यालय

लोगो को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के संबंध में जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह कार्यालय मीडिया प्रतिनिधियों के पेशागत सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आम आदमी तक पहुंचने के सरकार के प्रयासों के तहत, पीआईबी राष्ट्रव्यापी जनसूचना अभियान आयोजित कर

रहा है। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों की जानकारी देना और जागरुकता बढ़ाना है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन, सूचना का अधिकार, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम, समग्र बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों का कल्याण आदि।

यह कार्यालय नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रेस केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसके लिए इसे भूमि का आबंटन किया जा चुका है। यहां राष्ट्रीय औरअंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। ईएफसी ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और एनबीसीसी को कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त किया जा चुका है। एनडीएमसी/डीयूएसी आदि की मंजूरी नवं/दिसं 2008 ईएफसी से ताजा मंजूरी 15 सितम्बर को प्राप्त हुई।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अतिरिक्त, प्रवासी भारतीय दिवस भी 11वीं योजना से योजना स्कीम में शामिल कर लिया गया। देश की मिली-जुली संस्कृति को दर्शाने और जानकारी प्रदान करने के लिए भारत सरकार के पास प्रतिष्ठित अवसर हैं। सिलिए पीआईबी इन दोनों गतिविधियों के लिए मीडिया सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

पीआईबी अन्य देशों के साथ बेहतर समझ को प्रोत्साहित करने के और मीडियाकर्मियों के बीच अधिकाधिक आदान-प्रदान के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिमका निभा रहा है। इसके लिए सूचना और जनसंचार के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और संयुक्त कार्य आयोग/संधि का मार्ग अपनाया जाता है।

भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद ने अर्द्ध न्यायिक संस्था होने और प्रेस के आचरण संबंधी मानदंडों के नियमन का उत्तरदायित्व संभालते हुए निम्नलिखित सुधार के उपाय और नीतिगत पहलें की हैं :

1. नीतिगत उपाय :

(क) समाचारों के लिए भुगतान करना

(ख) मीडिया ट्रायल पर मार्ग निर्देश

(ग) स्टिंग पत्रकारिता पर मार्ग निर्देश

(घ) फोटो पत्रकारिता पर मार्ग निर्देश

(ङ) परिषद द्वारा आदर्श, प्रत्यायन विज्ञापन नियमावली न अपनाये जाने के कारण लघु और मध्यम समाचार पत्रों के सम्मुख चुनौतियां/समस्याएं।

पारदर्शिता

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू करना

2 भारतीय प्रेस परिषद का नागरिक चार्टर्ड इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. प्रेस परिषद की पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

4. फैसलों और परिषद की अन्य संदर्भित रिपोर्टों को वेबसाइट पर डालना।

5. शुल्क वसूली बकाया को वेबसाइट पर डालना।

6 पत्रकारों के लिए आचरण संहिता वेबसाइट पर।

7. परिषद की वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर है।

8. पीआरएबी के आदेशों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य विभिन्न सरकारी संगठनों के लिए प्रगति और विकास के लिए फोटोग्राफ्स और दृश्य प्रलेखन तैयार करना तथा राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों से संबंधित दृश्यों को उपलब्ध कराना है। संदर्भों की जांच-पड़ताल करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने, तस्वीरों को एक स्लाइड में रखने ताकि चित्रों तक पहुंचने की सुविधा मिल सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास संबंधित कार्यकलापों तथा जम्मू कश्मीर जैसे स्थानों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप जैसे योजना कार्यक्रमों से संबंधित स्थानों के दृश्य प्रलेखों को प्राप्त किया जा सके। डिजीटल लाइब्रेरी सिस्टम (अंकीय पुस्तकालय प्रणाली) को और प्रभावी बनाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक अंकीय तस्वीरों को सुरक्षित रखकर प्रभावी प्रणाली बनाए रख सके और ऐतिहासिक महत्व की गुणवत्ता सम्पन्न तस्वीरों को प्राप्त किया जा सके और ऐसे क्षेत्रों जिन्होंने विकास किए हैं, लेकिन उनके दृश्य अभिलेख उपलब्ध नहीं है, उनके भी फोटो अभिलेख व्यापक रूप से प्राप्त किए जा सकें।

प्रकाशन विभाग

सुधार के उपाय व नीतिगत पहल

इस विभाग के प्रशासनिक, संपादकीय, कारोबार, उत्पादन और योजना शाखाओं में किए गए नीतिगत पहल निम्नलिखित हैं :-

इस विभाग के लिए जरुरी वस्तुओं और सेवाओं की मंजूरी और खरीदने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाया और इनको जीएफआर के नियमों के अनुरुप बनाया गया।

प्रशासनिक मुद्दों प्र प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए और अगर कोई समस्या है तो इसके समाधान के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ नियमित टेलीफोन संपर्क शुरु किया गया।

किताबों के लिए प्रयुक्त होने वाले कागज की गुणवत्ता के संबंध में विनिर्देशों में कड़ाई करने के बाद इसमें काफी सुधार हुआ।

किताबों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए एक पुस्तक समिति गठित की गई जिसने किताबों के प्रस्तावों की जांच की और सहमति के आधार पर उनको मंजूरी दी।

कलाकारों को इंटरनेट से विचार लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया और किताबों के आवरणों के डिजायन को बिल्कुल नया रुप दिया गया।

विशिष्ट पुस्तकों के प्रकाशन, विज्ञापन, पुस्तक समीक्षाओं महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों और पुस्तक मेलों में भागीदारी द्वारा विभाग इसकी पुस्तकों और पत्रिकाओं के स्वरुप में सुधार लाने के लिए जोर-शोर से प्रयास किए गए।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

गैर-योजना

i) **कुल राजस्व एवं शुद्ध अधिशेष**

रोजगार समाचार ने 2007-08 में 5143.73 लाख रुपये की तुलना में 2008-09 में 5765.86 लाख रुपये का कुल राजस्व कमाया। खर्च निकालने के बाद शुद्ध अधिशेष 2007-08 के दौरान 2790.24 लाख रुपये की तुलना में 2008-09 में बढ़कर 3342.61 लाख रुपये हो गया। दिसंबर 2009 तक राजस्व 5568.60 लाख रुपये तथा शुद्ध अधिशेष 4265.86 लाख रुपये है।

ii) राजस्व

रोज़गार समाचार ने नौकरी बाजार में अपनी सर्वोच्च स्थिति को बरकरार रखा हुआ है तथा वर्ष के दौरान अधिक विज्ञापन लेने में सफल रहा है। स्टाफ की कमी के बावजूद विज्ञापन राजस्व 2008-09 में बढ़कर 1619.14 लाख रुपये हो गया है। इस साप्ताहिक पत्र ने चालू वित्त वर्ष (दिसंबर 2009 तक) में 4265.86 लाख रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया।

iii) पेजों की औसत संख्या

रोज़गार समाचार में छापे जाने वाले पृष्ठों की औसत संख्या 2005-06 में 50.61 पृष्ठों से बढ़कर 2007-08 में 58.46 पृष्ठों तक पहुंच गई। वर्ष 2008-09 में इन पृष्ठों की औसत संख्या प्रति अंक 61.54 है।

iv) नेटवर्क में विस्तार

रोजगार समाचार अपने पाठकों तक पहुंचने के लिए ज्यादातर अपने नेटवर्क पर निर्भर करता है। दूर-दराज के क्षेत्रों में कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पाठकों के पास सीधे ग्राहक बनने की भी सुविधा है। रोजगार समाचार ने खुले विज्ञापन के जरिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करके वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान डीलरों के अपने आधार को विस्तारित किया है। 2010-11 में विभाग की देशभर में अपने नेटवर्क विसतर की योजना है।

v) इंटरएक्टिव वेबसाइट

रोजगार समाचार की सबसे बड़ी सफलता इसकी वेबसाइट employmentnews.gov.in को शुरू करना है जिसे प्रतिदिन 3 लाख से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वेबसाइट सरकारी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग हो रही है। वेबसाइट के जरिए पेश की जा रही ऑन लाइन सेवाओं में कैरियर परामर्श, सरकारी क्षेत्र में रिक्तिओं के बारे में अग्रिम जानकारी तथा यह जानकारी सीधे पाठकों के ई-मेल पर उपलब्ध कराना शामिल है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

पिछले कुछ वर्षों में प्रिंट मीडिया का जिस तरह से विस्तार हुआ है उससे वह प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 के दायरे के भी बाहर निकल गया है। पी.आर.बी. अधिनियम 1867 के अनुसार और इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की गई है ताकि उन्हें प्रिंट मीडिया के वर्तमान परिदृश्य के अनुसार प्रासंगिक बनाया जा

सके। समाचार पत्रों के त्वरित, कुशल और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पी आर बी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की कड़ी जांच करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं और 2007-12 तक की 11वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी और मध्य क्षेत्र भोपाल में दो नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की जा रही है। आर एन आई में व्यक्तिगत स्तर पर की गई प्रार्थना और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निर्दिष्ट समाचार पत्रों के लिए 1.6.2006 से प्रभावी नई विज्ञापन नीति के लागू हाने के बाद 75000 या इससे अधिक की प्रसार संख्या वाले बड़े समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की कड़ी जांच करना। आर एन आई में पैनलबद्ध किए गए चार्टड एकाउंटेंटों द्वारा समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की जांच की जाती है।

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग ने दो नये नीतिगत कदम उठाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रभाग ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए नयी नीति को 11वीं योजना में शामिल किया है। इन कदमों का उद्देश्य मीडिया की शक्ति का उपयोग कर जन कल्याण और पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को बढ़ावा देना है।

मीडिया पुरस्कार जैसी स्कीमें जन सामान्य जन के कल्याण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक उदाहरण है।

राष्ट्रीय मीडिया लाइब्रेरी को वर्चुअल लाइब्रेरी में परिवर्तित करना एक स्मरणीय संस्थान के निर्माण की दिशा में एक सार्थक कदम है जो शोधकर्ताओं और नीति-निर्धारकों के लिए सामग्री और सूचना के स्रोत के संग्रह का कार्य कर सके।

मास मीडिया में अनुसंधान विशिष्ट मीडिया-संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान करने, फीडबैक लेने और आमराय मानने की स्कीम है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसकी मीडिया इकाइयों को नीति निर्धारण एवं उन्हें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर लागू करने में मददगार होगी।

गीत एवं नाटक प्रभाग

प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार माध्यम के रूप में पारंपरिक कलाओं और विलुप्त हो चुकी लोक कलाओं को फिर से पुर्नजीवित करने के उद्देश्य से एक छोटी प्रयोगात्मक इकाई के रूप में की गई थी। प्रभाग ने कलाओं के माध्यम से समकालिक विचारों, मुद्दों और तरीकों को अपनाकर लोगों के साथ तात्कालिक तारत्म्य स्थापित किया जिससे प्रभाग ने जनता के बीच में एक जीवन्त माध्यम के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। गीत और नाट्य प्रभाग दुर्गम पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान और सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन स्तर पर लोगों के सात प्रभावी ढंग से संपर्क स्थापित करके अपनी पहुंच और प्रभाव के दायरे में बहुत विस्तार किया है।

अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभाग ने लोक और पारंपरिक कलाओं के विभिन्न रूपों जैसे नाटक, गीत नाटक, ओपेरा, नृत्य नाटिका लोक गीतों, कठपुतली, जादुगरी के विस्तृत भंडार को लोकप्रिय बनाया है। इसके अलावा प्रभाग ने सांप्रदायिक सदभाव, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम और सैकड़ों कलाकारों के सात भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किये हैं।

पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रभाग का आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। इससे कार्यक्रमों के अनुसंधान और विकास और उनके प्रभाव और पहुंच की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकेगा।

एफ. एम. रेडियो (निजी)

निजी एफ.एम. रेडियो का कार्य एफएम चरण I नीति के माध्यम से 1999 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। प्रथम चरण में बड़े पैमाने पर हुई खामियों को ध्यान में रखते हुए और ट्राइ की सिफारिशों और अन्य सार्थक कारकों को ध्यान में रखते हुए निजी एजेंसियों (चरण II) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवा का विस्तार करने की नई नीति को 30 जून 2005 में स्वीकृति दी गई और 13 जुलाई 2005 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। एफएम रेडियो प्रसारण के चरण II के कार्यान्वयन का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। कुल 337 चैनलों को प्राइवेट एफएम रेडियो के दूसरे चरण में लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया और उनमें से 280 चैनलों के लिए बोलियां सफल रहीं। जांच पड़ताल के बाद 245 एफएम चैनलों के संचालन के लिए विभिन्न कंपनियों को आशय-पत्र भेजे गए। इस समय 250 चैनल चालू हैं जिनमें 21 चैनल चरण I के अंतर्गत संचालन कर रहे है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र

एस एफ सी (आर सी ई) की योजना स्कीम के तहत 2007-08 के दौरान 19.65 करोड़ रुपये की कुल लागत से ईएमएमसी की स्थापना की गई थी। 11वीं योजना के तहत कुल जरूरत 16.75 करोड़ रुपये की है जिसमें से 11.65 करोड़ रुपये परियोजना लागत है तथा 2.00 करोड़ रुपये वार्षिक रख-रखाव और उन्नयन इत्यादि के लिए हैं। 2009-10 की वार्षिक योजना के दौरान कुल परिव्यय 2 करोड़ रुपये में से 1.20 करोड़ रुपये परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, मंत्रालय के अधीन पीएसयू ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट लिमिटेड (बीईसीआईएल) को जारी किए गए। परियोजना 9 जून, 2008 से शुरू हुई। इसके तहत 2008-09 के दौरान 150 टी वी चैनलों (24×7) की मानीटरिंग की जा रही है। इसकी मॉनीटरिंग क्षमता मार्च 2010 तक 300 चैनलों तक बढ़ाई जाएगी। इएमएमसी अभी अपने प्रारंभिक चरणों में है लेकिन पिछले कुछ समय से यह टीवी चैनलों के विषयवस्तु के अनुश्रवण में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है, जैसा कि इसकी स्थापना में निहित उद्देश्य में शामिल है। विषय वस्तु की निगरानी के अलावा केबल टीवी नियामक, अधिनियम 1995 में स्थापित कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की निगरानी के साथ केबिनेट सचिवालय सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा मांगी जाने वाली विशेष की रिपोट भी तैयार कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

मोटे तौर पर किए गए अनुमानों के अनुसार व्यय 100 करोड़ रुपये होगा। प्रसार भारती को इसके लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया है।

सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां

दिसंबर, 2002 में, भारत सरकार ने आईआईटी/आईआईएम जैसे स्थापित शैक्षिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएम) स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्रदान करने की नीति को स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत 104 संस्थानों से आवेदन प्राप्त किए गए। इसमें से 63 योग्य संस्थानों को जवाबी पत्र भेजे गये और 45 संस्थानों ने लाइसेंस समझौतों पर हस्ताक्षर किये। वर्तमान में 41 सामुदायिक रेडियो केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में चलाये जा रहे हैं।

मई 2004 में आयोजित कार्यशाला की सिफारिशों के साथ-साथ सांसदों की परामर्श समिति आदि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा इस मुद्दे पर पुन: विचार-विमर्श किया गया और दिसंबर, 2006 में विकास और सामाजिक परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर आम नागरिकों तथा अलाभकारी स्वयंसेवी संस्थानों जैसे संगठनों को इस नीति के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।

सूचना भवन का निर्माण

वर्ष 2006 के दौरान, सूचना भवन के चरण-V के निर्माण का एक प्रस्ताव मंत्रालय के नीति योजना एकांश को इस आशय के साथ भेजा गया कि इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में शामिल किया जाए। योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सूचना भवन के पांचवें चरण के निर्माण के लिए 12 मार्च, 2008 को व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 74.60 करोड़ रुपये लागत की सीमा निर्धारित करते हुए इस परियोजना को इस शर्त पर मंजूरी दे दी कि लागत सीमा को पार नहीं किया जाएगा।

योजना आयोग ने वार्षिक योजना वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान बजट का आबंटन निम्नलिखित विवरण के अनुरूप किया :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	आबंटित बजट	वार्षिक योजना
1	सूचना भवन के (नई दिल्ली, लोधी रोड सीजीओ काम्पलेक्स) पांचवें चरण का निर्माण	1.00 करोड़ रुपये	2007-08
2	- वही -	3.53 करोड़ रुपये	2008-09
3	- वही -	10.00 करोड़ रुपये	2009-10
4	- वही -	10.00 करोड़ रुपये	2010-11

प्रस्ताव के अनुसार, सूचना भवन के पांचवें चरण का निर्माण 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

इस स्कीम में मीडिया क्षेत्र में नीति संबंधी अध्ययनों का प्रावधान किया गया है। यह अध्ययन उपयुक्त नीतिगत सुधारों को शुरू करने में इस क्षेत्र के विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने में बहुत मददगार होंगे।

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को शामिल करने के उद्देश्य से विदेशों में स्थित संस्थानों से प्रशिक्षकों को बुलाने का भी प्रस्ताव है ताकि मंत्रालय के अधीन विभिन्न मीडिया इकाइयों की प्रासंगिकता के अनुसार इनमें कार्यरत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। इन इकाइयों में कार्यरत प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों के अनुभवों से मीडिया इकाइयों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

प्रसार भारती

प्रसार भारती के पास प्रसारण और टेलीकास्टिंग के क्षेत्र में ढांचागत, श्रमशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता के संदर्भ में संसाधनों का व्यापक भंडार है। ढांचागत भंडार में, विशेष रूप से भूमि, इमारत, टावर, ट्रांसमीटर, स्टूडियो, सेटेलाइट अर्थ स्टेशनत, अभिलेखकरण की सुविधा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण (तकनीकी)संस्थान, अनुसंधान और विकास आदि शामिल है। 500 डब्ल्यू मीडियम वेव ट्रांसमीटर से शुरुआत करते हुए आकाशवाणी आज प्रमुख प्रसारक संगठन बन गया है। 375 रेडियो ट्रांसमीटर के सात यह 91.82 प्रतिशत क्षेत्र और 99.16 प्रतिशत आबादी के दायरे में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त डीडी डायरेक्ट प्लस के फ्री टू एयर डीटीएच प्लेटफॉर्म पर 21 रेडियो लगभग पूरे देश में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दूरदर्शन 31 चैनलों से बढ़कर 39 सेटेलाइट अर्थ स्टेशनों तक फैल गया है और विभिन्न क्षमताओं वाले इसके 1416 ट्रांसमीटर देश की 92 प्रतिशत आबादी को अपने दायरे में लिए हुए हैं।

अपनी क्षमता के सदुपयोग के लिए आकाशवाणी ने मई 2001 में अपने संसाधनों को स्वतंत्र केंद्र के रूप में स्थापित किया जिससे व्यापक ढांचे से राजस्व अर्जित किया जा सके। निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, अगले 10 से 15 वर्षों में आकाशवाणी के संसाधनों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से राजस्व उत्सर्जित किए जा सकते हैं :

- निजी प्रसारकों, मोबाइल सर्विस प्रदाताओं/इग्नू के साथ लाइसेंस फीस आधार पर प्रसार भारती (पीबी)के ढांचागत संसाधन, जैसे टावर (एसटीएल टावर, स्व सहायक एस डब्ल्यू टावर, एकीकृत टीवी/एफएम टावर)निर्माण और भूमि को बांटना। अभी पीबी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निजी एफएम चरण 1 और चरण 2 योजना के तहत निजी एफएम प्रसारकों के साथ अपने ढांचागत संसाधनों को बांट रहा है। इस योजना के तहत वे अपने एंटीना को माउंट कर सकते हैं और अपने ट्रांसमीटर और दूसरे सहायक उपकरणों के इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस खोल और बंद कर सकते हैं। भविष्य में, अगर पीपीपी के माध्यम से अपेक्षित हो, तो हम अपने ढांचागत संसाधन की व्यापक हिस्सेदारी कर सकते हैं।

- इसके अतिरिक्त प्रसार भारती परिसर में लगे अपने उपकरण इंस्टॉल करने वाले निजी एफएम प्रसारकों को संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए एआईआर/डीडी स्टेशनों को श्रमशक्ति आउटसोर्स करने की अनुमति देने की जरूरत होगी क्योंकि श्रमशक्ति की पहले ही कमी है। पीबी निजी प्रसारकों के स्टूडियो और ट्रांसमीटरों को इंस्टॉल और कमीशन करने का काम भी कर सकता है।
- प्रसार भारती पहले से अपने ज्ञानवाणी के लिए इग्नू के एफएम ट्रांसमीटर के इन्सटॉलेशन और कमिशनिंग का काम कर रहा है।
- आकाशवाणी/डीडी सेटअप के साथ कोसाइट करने वाले चैनल/इग्नू ट्रांसमीटरों के संचालन और रखरखाव का काम भी आकाशवाणी/डीडी स्टेशन कर रहे हैं। प्रसार भारती की योजना है कि भविष्य में इग्नू के ट्रांसमीटरों के लिए भी यह कार्य किया जाएगा।
- मौजूदा समय में आकाशवाणी स्टूडियो और ट्रांसमीटरों का खाली समय इग्नू को किराए पर दिया गया है। जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी और अगर भविष्य में ऐसा समय देना संभव होगा तो प्रसार भारती दूसरे शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों और आउटस्टेशन एजेंसियों को प्रतिस्पर्धात्मक दर पर, मौजूदा ट्रांसमिशन घंटों के लिए किराए पर ये सुविधाएं प्रदान करेगा।
- प्रसार भारती श्रोताओं को आईवीआरएस और एसएमएस आधारित सेवा जैसी मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीकॉम सेवाओं के साथ एक समझौता कर रहा है। इस प्रकार की लोकप्रिय सेवाएं प्रदान करके, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मिलने वाले राजस्व में से आकाशवाणी को भी राजस्व प्राप्त हो सकता है। दूरदर्शन पहले से दिल्ली से मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है और जल्द इसे दूसरे शहरों में भी विस्तार देना चाहता है।
- आकाशवाणी के नेटवर्क में एमडब्ल्यू/एफएम/एसडब्ल्यू प्रसारक ट्रांसमीटर का एयर टाइम शैक्षणिक/कृषि संस्थानों को किराए पर दिया जा सकता है।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/आवासीय स्कूलों में 50/100 वॉट के एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित करने में भी प्रसार भारती मदद प्रदान कर सकता है।
- प्रसार भारती विभिन्न आकाशवाण/दूरदर्शन केंद्रों पर ब्रॉडकास्टिंग के विभिन्न क्षेत्रों में ऑन साइट और संस्थात्मक प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है। कुछ केंद्रों में यह प्रशिक्षण पहले से दिया जा रहा है जिसका आगे चलकर विस्तार किया जा सकता है।
- डेटा ऑडियो चैनल (डीएआरसी) सेवा के माध्यम से प्रसार भारती राजस्व अर्जित कर सकता है।

लैंगिक बजट

वर्तमान वित्तीय वर्ष में, क्षेत्रीय केंद्रों/चैनलों पर लैंगिक बजट को प्रस्तावित किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष में सभी केंद्रों/चैनलों में लैंगिक मुद्दों पर कार्यक्रम बनाने के लिए 20 प्रतिशत बजट आवंटित करना तय किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में दूरदर्शन केंद्रों पर कार्य करने वाली महिलाओं को अधिक सुविधाएं देने के प्रावधान किए जाएंगे, जैसे मनोरंजक क्लब, क्रेश, अलग शौचालय, रेस्ट रूम आदि।

डिजिटलीकरण

आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण और सीमांत क्षेत्रों में आकाशवाणी/डीडी के दायरे को बढ़ाना मौजूदा वित्तीय वर्ष की प्रमुख गतिविधियों में से एक था। इस वर्ष आकाशवाणी और दूरदर्शन में सॉफ्टवेयर प्रॉडक्शन/अधिग्रहण की एक नई योजना भी चलाई गई जिसका उद्देश्य गुणात्मक कन्टेंट प्रदान करना था।

एनालॉग ट्रांसमिशन से स्विच ऑफ डेट से लेकर डिजिटल ट्रांसमिशन और विभिन्न योजनाओं, जिसमें डीटीएच योजना शामिल है, के लिए पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मॉडल को तलाशना व्यापक नीतिगत संरचना का अंग है।

इस समय लोगों के पास ऐसे टीवी सेट हैं जिनके लिए एनालॉग ट्रांसमिशन देकने के लिए सिर्फ एक यागी एंटीना की जरूरत पड़ती है। पर डिजिटल ट्रांसमिशन देखने के लिए लोगों को डिजिटल सेट टॉप बॉक्स (डीएसटीबी)और एक यागी एंटीना की जरूरत पड़ेगी। दर्शक को डीएसटीबी की कीमत प्रति टीवी चार से पांच हजार रुपए चुकानी होगी।

एचडीटीवी

इसे एशियाई खेलों के बाद ब्रॉडकास्टिंग के इतिहास का मील का पत्थर कहा जा सकता है। एचडीटीवी के प्रारंभ के साथ, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रॉडक्शन और ट्रांसमिशन करके, दूरदर्शन बहुत जल्द दूसरे बड़े परिवर्तन का अग्रदूत बनेगा। यह भी योजना है कि डीडी इंडिया को एचडीटीवी चैनल में परिवर्तित कर दिया जाएगा और डीडी इंडिया के कन्टेंट को वॉयस ऑफ इंडिया में बदल दिया जाएगा। डीडी-डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, एचडीटीवी मोड में एक मूल्य संवर्धित चैनल की भी योजना है।

दूरदर्शन की डीटीएच सेवा 'डीडी डायरेक्ट प्लस'

दूरदर्शन ने दिसंबर 2004 में 33 टीवी चैनलों (दूरदर्शन और निजी चैनल)के साथ निशुल्क डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य स्थानीय प्रसारण से छूट गए क्षेत्रों को कवरेज उपलब्ध कराना था। डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता को बढ़ाकर 58 टीवी चैनल कर दिया गया है। टोडापुर, नई दिल्ली स्थित डीटीएच सेंटर से डीटीएच सिग्नल इनसेट 4 बी उपग्रह को अपलिंक किए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर डीटीएच सिग्नल (कू बैंड) द्वारा हर स्थान पर एक छोटे डिश द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस समय दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म पर 58 टीवी चैनल हैं। पहले चरण में इस प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ाकर 100 चैनल और दूसरे चरण में 200 चैनल कर दी जाएगी। 10 डीडी चैनल के साथ सी बैंड की डीटीएच सेवा, विशेष रूप से एंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए, सितंबर 2009 में शुरू की गई है।

अध्याय IV
पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
वार्षिक योजना 2009-10

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत परिव्यय	वार्षिक योजना 2009-10				
			स्वीकृत परिव्यय	दिसंबर 2009 तक वास्तविक खर्च	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	कमी का कारण
1.	2.	3	4	5.	6.	7.	8.
1.	कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	350.00	50.00	11.80	सीबीएफसी में नेटवर्किंग, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में इंटरनेट सुविधाएं। पंजीकरण और प्रमाणीकरण मॉड्यूल पर फीडबैक, सर्च मैनेजमेंट की डाटा एंट्री, तकनीकी उपकरणों की खरीद तथा सीबीएफसी में ढांचागत विकास।	चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, तिरुअनंतपुरम, बंगलूरू और हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यक उपकरणों के साथ नेटवर्किंग स्थापित कर दी गई है। अध्यक्ष के मॉड्यूल पर यूएटी पूर्ण। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सर्च मैनेजमेंट मॉड्यूल पर डाटा एंट्री का कार्य प्रगति पर है। पे-रोल पैकेज में डाटा एंट्री का कार्य प्रगति पर है। लेपटॉप, टी.वी., वीसीडी की खरीद।	कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।
2.	नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना।	312.00	85.00	10.57	क्षेत्रीय अधिकारियों के तीन तथा एक एल डीसी के तीन नए सृजित पदों को भरना	तीन क्षेत्रीय कार्यालय सीबीएफसी अधिकारियों तथा स्टाफ द्वारा संभाले जाते हैं	—

3.	प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी और आधुनिकी-करण	500.00	50.00	29.52	बोर्ड सदस्यों और पैनल सदस्यों के लिए नियमित अंतराल पर अध्ययन, सेमिनार। कार्यशालाओं का आयोजन करना। प्रत्येक केंद्र पर एक कार्यशाला तथा सभी क्षेत्रीय केंद्रों में एकरूपता के लिए अखिल भारतीय पैनल कार्यशाला		कार्यशालाओं/सेमिनार का आयोजन
	कुल	**1162.00**	**185.00**	**51.89**			

- नई दिल्ली में 6.4.09 को अध्यक्ष के साथ क्षे.अ. की बैठक
- 10 तथा 11.5.09 को मणिपुर में कार्यशाला
- नई दिल्ली में 6.7.09 को क्षे.अ. की बैठक-सह-कार्यशाला
- नई दिल्ली में 24.7.09 को क्षे.अ. की बैठक
- केरल में 20 और 21.8.09 को फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ सीबीएफसी की बैठक
- नई दिल्ली में 12.9.09 को 119वीं बोर्ड बैठक
- नई दिल्ली में 18.9.09 को बोर्ड सदस्यों की कार्यशाला
- नई दिल्ली में 29.9.09 को अध्यक्ष के साथ बीएम तथा क्षे.अ. की बैठक
- नई दिल्ली में 2.10.09 को कार्यशाला-सह-क्षे.अ. की बैठक
- नई दिल्ली में 20.10.09 को कार्यशाला-सह-क्षे.अ. की बैठक
- कोलकाता में 11.11.09 को क्षे.अ. की बैठक/कार्यशाला
- जोधपुर में 20.12.09 को 120वीं बोर्ड बैठक सह-कार्यशाला
- नई दिल्ली में 12.1.10 को नए सलाहकार सदस्यों के साथ कार्यशाला

केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड

(लाख रुपये में)

क्रं.सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11 तक	मात्रात्मक प्रतिफल	दिसंबर, 2009 तक खर्च
1.	कंप्यूटरीकृत प्रबंधन तथा सीबीएफसी में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	सीबीएफसी में प्रमाणन प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए उपकरण खरीद तथा ढांचा उन्नयन	90.00	कंप्यूटर से नौ क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ा जाना है तथा टीवी, वीसीडी, डीवीडी और अन्य तकनीकी उपकरणों की खरीद और ढांचा उन्नयन	दिसंबर 2009 तक 11.80 लाख रुपये खर्च
2.	नई दिल्ली, कटक, तथा गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय खोलना	इस क्षेत्र में निर्मित फिल्मों के प्रमाणन के लिए	80.00	उत्तर पूर्व, उत्तर भारत तथा उड़ीसा के निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों (सेल्युलॉइड तथा वीडियो फॉर्मेट दोनों) तथा विज्ञापनों को प्रमाणित करना सिनेमेटोग्राफ एक्ट, 1952 के तहत प्रावधानों के उल्लंघन को रोकना	10.57 लाख रुपये खर्च
3.	प्रमाणन प्रक्रिया की निगरानी तथा आधुनिकीकरण	बोर्ड सदस्यों/पैनल सदस्यों के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार तथा अध्ययन आयोजित करना	50.00	बोर्ड सदस्यों तथा सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करना। प्रमाणन प्रक्रिया संबंधी अध्ययन/ सूचना संग्रह करना	50 लाख रुपये एसबीजी के मुकाबले दिसंबर 2009 तक 29.52 लाख रुपये खर्च
	कुल		220.00		

बाल फिल्म समिति, भारत

पिछले प्रदर्शन की समीक्षा
(वास्तविक उपलब्धियां)

	उपलब्धियां 2008-09	लक्ष्य 2009-10	2009-10 की संभावित उपलब्धियां	
			अप्रैल 2009 से दिसंबर 2009 तक	जनवरी2010 से मार्च 2010 तक
योजना : निर्माण				
निर्माण	4 फीचर + 1 लघु फिल्में	5 फीचर फिल्म, 2 लघु फिल्म	3 फीचर	3 फीचर तथा 2 लघु फिल्में
डबिंग	6 फिल्में	14 फिल्में	7 फिल्में	
उपशीर्षक	-	10 फिल्में	11 फिल्में	
खरीद	-	3 फिल्में	2 अंग्रेजी फिल्में	
प्रिंट की लागत	नई बनी फिल्मों के 35 मिमी के 17 तैयार कर लिए गए हैं।	-	मांग के अनुसार	
योजना : डिजिटल रूपांतरण और वेबकास्टिंग				
डिजिटल रूपांतरण	-	लगभग 230 फिल्में	31.03.10 तक लगभग 160 फिल्मों का डिजिटलीकरण की आशा	
वेबकास्टिंग	वेबसाइट अद्यतन है	सीएफएसआई वेबसाइट का रखरखाव	-	
योजना : नगर निगम के स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन				
नगर निगम के स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन	35 लाख से ज्यादा बच्चों के के लिए 12957 प्रदर्शन किए गए	25 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए 5000 प्रदर्शनों का आयोजन	18 लाख बच्चों के लिए 3903 प्रदर्शनों का आयोजन	3,20,000 बच्चों के लिए 750 प्रदर्शन
योजना : फिल्म महोत्सव				
आईसीएफएफ (16वां) का आयोजन	-	-	1 (16वां आईसीएफएफ)	-
अंतर्रा. फिल्म महोत्सवों में भागीदारी	5	मांग के अनुसार	8	फैसला नहीं हुआ

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा

वास्तविक कार्यक्रम गतिविधियां

	2008-09		2008-09		
कार्यक्रम	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**2009-10**		**2010-11**
			लक्ष्य	**उपलब्धियां (दिसम्बर, 09 तक)**	**लक्ष्य**
दौरे वाले दिन	23568	22006	23568	20709	23568
फिल्म शो	46500	36403	46500	27546	46500
विशेष कार्यक्रम	4968	10430	4968	8469	4968

वार्षिक योजना 2008-09 में केवल दो योजनाओं को मंजूरी मिली है-(i) दौरों का आयोजन/दक्षता उन्नयन तथा (ii) क्षेत्रीय कार्यालयों एवं क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन। इन योजनाओं की लागत 2.00 करोड़ रुपए है।

दौरों का आयोजन/दक्षता उन्नयन योजना के तहत 12 दौरे किए गए। दूसरी योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय के लिए 120 कम्प्यूटर 38 मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, 10 वायरलैस पी ए प्रणालियां, 38 डीवीडी, 5 डिजिटल वीडियो कैमरे।

वित्तीय कार्य निष्पादन

(लाख रुपये में)

योजना/गैर-योजना	**2008-09**		**2009-10**		
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां (दिसंबर, 09 तक)**	**2010-11 लक्ष्य**
योजना	200.00	180.65	149.00	24.14	555.00
गैर-योजना	2625.00	3238.04	4127.00	3346.00	3572.00
कुल	**2825.00**	**3418.69**	**4276.00**	**3370.14**	**4127.00**

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

वर्ष 2008-09 के लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्तीय

(लाख रुपये में)

(बजट अनुमान 2008-2009)			(संशोधित अनुमान 2008-2009)			वास्तविक व्यय 2008-09		
योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
2176.00	5260.00	7436.00	4818.00	5331.00	10149.00	4817.34	7074.87	11892.21

वास्तविक प्रदर्शन

वार्षिक योजना 2008-2009

वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना को एक जारी कार्यक्रम **विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार** के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत 2176.00 लाख रुपये के परिव्यय की मंजूरी दी गई है। हालांकि संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान के चरण में 4818.00 लाख रुपये का अतिरिक्त कोष दिया गया है। मार्च 2009 तक 4817.34 लाख रुपये की धन राशि व्यय हुई है तथा वित्तीय लक्ष्य के संदर्भ में 99.99 प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुई है। यह योजना बाह्य प्रचार माध्यम, मुद्रित प्रचार माध्यम, प्रदर्शनी, डिसप्ले और वर्गीकृत विज्ञापन तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा सूचना के प्रसार द्वारा लागू किया गया है।

वास्तविक उपलब्धियां

प्रदर्शनी : वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना के तहत देश भर में निम्न महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जैसेकि आजादी एक्सप्रेस, 1857 क्रांति यात्रा, एड्स जागरूकता एवं स्वस्थ मां स्वस्थ बच्चा इत्यादि।

डिसप्ले विज्ञापन : 'भारत निर्माण' पर जारी किए गए विज्ञापन।

दृश्य-श्रव्य : 'भारत निर्माण' पर स्पॉट का निर्माण तथा उसका प्रसारण/प्रेषण

मुद्रित प्रचार माध्यम : विभिन्न भाषाओं में 486 मदों का मुद्रण।

बाह्य प्रचार माध्यम : होडिंग्स, बस पैनेल,कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाओं इत्यादि के जरिए अभियान चलाया गया है।

डीएवीपी का आधुनिकीकरण : आधुनिकीकरण की योजना के तहत कान्फ्रेंस हाल के अद्यतन किया गया है तथा प्रदर्शनी खंड में डिजीटल लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदान किया गया है और निदेशालय के 140 कर्मचारियों कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग

वर्ष 2008-2009 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :

क्र.सं.	ब्योरा	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी	650	563
2	डिसप्ले/वर्गीकृत विज्ञापन	18000	13029
3	रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन@	3000	3253
4	मुद्रित प्रचार	137	166
5	बाह्य प्रचार	250	482

@ इसके अंतर्गत सभी भाषाओं में तैयार किए गए रेडियो स्पॉट/प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम और विडियो स्पॉट शामिल हैं। यह प्रसार 104506 प्रसारणों तथा 123287 टेलीकास्ट द्वारा किया गया।

II) वर्ष 2009-2010 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष 2009-10 के लिए बजट आबंटन

(लाख रुपये में)

योजना	गैर-योजना	कुल
2688.00	6487.00	9175.00

वर्ष 2009-10 के लिए संशोधित बजट

(लाख रुपये में)

योजना	गैर-योजना	कुल
3688.00	6700.00	10388.00

वास्तविक प्रदर्शन

वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना : वर्ष 2009-10 में दो योजनाओं को बनाई गई है : **(1) विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार** (चालू योजना) के लिए मंजूर 2508.00 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर संशोधित परिव्यय में बढ़ाकर 3508.00 लाख रुपये कर दिया गया है।

(2) डीएवीपी का आधुनिकीकरण : 'योजना' जो कि नई योजना है, को 11वीं योजना में वर्ष 2009-10 के लिए 180.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए हैं। योजना और गैर योजना मदों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2009 तक 7336.00 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

उपलब्धियां

योजना : विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा तथा प्रसार

प्रदर्शनियां : वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान निम्न महत्वपूर्ण प्रदशनियों का देश भर में आयोजन हुआ जैसे कि 'स्वस्थ भारत', फ्लेश शिप कार्यक्रम, 'भारत निर्माण', एच1 एन1-प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)।

बाह्य प्रचार : बाह्य प्रचार के अंतर्गत होर्डिंग्स, बस पैनल, कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाओं के जरिए 'इंडिया प्रोग्रेसिंग' अभियान किया गया।

मुद्रित प्रचार : विभिन्न भाषाओं में 150 कार्य और 302 मदों की महत्वपूर्ण बुकलेट की छपाई करवाई गई।

योजना : डीएवीपी का आधुनिकीकरण

कार्यालय खर्च : आधुनिकीकरण की योजना तहत वित्तीय वर्ष के दौरान ऑन लाइन विलिंग के लिए कम्प्यूटर तथा जरूरी हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर खरीदे गए। साथ ही डीएवीपी मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आफिस-फर्नीचर खरीदा गया।

योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2009-10)

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य	31.12.2009 तक उपलब्धियां	31.3.2010 तक अनुमानित उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी	650	305	345
2	डिसप्ले/वगीकृत विज्ञापन	15560	9905	5655
3	रेडियो/टीवी के लिए विज्ञापन@	2182	3507	1600
4	मुद्रित प्रचार	175	131	44
5	बाह्य प्रचार	250	125	125

@ इन लक्ष्यों में विभिन्न भाषाओं में तैयार रेडियो स्पॉट/प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम और विडियो स्पॉट शामिल हैं। इन्हें 106900 प्रसारण तथा 125000 टेलीकॉस्ट के जरिए प्रसारित किया गया।

(III) वर्ष 2010-2011 के लक्ष्य

वित्तीय

योजना	गैर योजना	कुल
4450.00	6228.00	10678.00

वित्तीय लक्ष्य

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2010-2011)

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य
1.	प्रदर्शनी	500
2.	डिस्प्ले/वर्गीकृत विज्ञापन	15600
3.	रेडियो/टीवी विज्ञापन	5300
4.	मुद्रित प्रचार	160
5.	बाह्यय प्रचार	250

2010-2011 की वार्षिक योजना

वर्ष 2010-2011 के वार्षिक योजना में : (1) ''विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार'' के लिए 4350.00 लाख रुपये की योजना तथा (2) ''डीएवीपी का आधुनिकीकरण'' के लिए 100.00 लाख रुपए की योजना को मंजूरी वाली दो योजनाओं को शामिल किया गया है।

चल रही योजना ''विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार'' के तहत राष्ट्र के महत्वपूर्ण फ्लैगशिप अभियान तथा मल्टीमीडिया प्रचार जैसे कि प्रदर्शनी, बाह्प्रचार, इलेक्ट्रानिक मीडिया सूचना प्रदान करना, डिसप्ले एवं वर्गीकृत विज्ञापन की सहायता से सरकार की नीतियों के प्रसार का कार्य है।

लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऊपर्युक्त योजनाओं में अर्थात ''विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार, ''डीएवीपी का आधुनिकीकरण'' को योजना आयोग ने कम्प्यूटरीकरण और डिजीटलीकरण, आफिस का बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन के विकास को शामिल किया है।

फिल्म समारोह निदेशालय

योजना शीर्ष के तहत 2008-09 तथा 2009-10 के वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2008-09 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2008-09	कमी के कारण	2009-10 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2009-10 (31.12.09 तक)	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा	2010-11 के लिए लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	विदेशी यात्रा खर्च	-	-	-	-	-	प्रशासनिक खर्च	
2.	(i) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सहित भारत तथा विदेश में फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्धन	01	01	शून्य	01	01	शून्य	(01)
3.	(i) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी	45	51	शून्य	45	24	-	45
	(ii) भारतीय पैनोरमा	01	01	शून्य	01	01	शून्य	01
4.	फिल्म समारोह परिसर— फेरबदल और संयोजन	आने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2010 को देखते हुए सुविधाओं में सुधार	कार्य प्रगति पर	शून्य	राष्ट्रमंडल खेल 2010 को ध्यान में रखकर सिरीफोर्ट ऑडियोरियम में सुविधांए	कार्य प्रगति पर	टेंडर के लिए प्रशासनिक अनुमति जारी	राष्ट्रमंडल खेल 2010 से पहले सभी कार्य पूर्ण करना
5.	प्रिंट यूनिट का उन्नयन	फिल्मों का डिजिटलीकरण	शून्य	योजना आयोग से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा	डीवीडी प्लेयर, रिकार्डर इत्यादि उपकरणों की खरीद	उपकरण खरीदने के लिए अनमिति प्रदान।	2009-10 के लक्ष्य पूरे किए जाएंगे।	2007 भारतीय पैनोरमा फिल्मों का डिजिटलीकरण तथा यू मेटिक प्लेयर डीजीपी बीटा प्लेयर, एसपी प्लेयर आदि की खरीद

गैर योजना

2008-09 तथा 2009-10 (31.12.2009 तक)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2008-09 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2008-09	कमी के कारण	2009-10 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2009-10 (31.12.09 तक)	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा	2010-11 कं लिए लक्ष्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह	12	15	-	12	10	-	12
2.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	1	1	-	1	1	-	1

फिल्म प्रभाग

पूर्व प्रदर्शन की समीक्षा

1. न्यूज़ मैगज़ीनों सहित वृत्त चित्रों के निर्माण के संबंध में फिल्म प्रभाग का प्रदर्शन इस प्रकार है :

2007-08	उपलब्धियां 2008-09	लक्ष्य 2009-10	उपलब्धियां 2009-10 अप्रैल, 2009 से दिसंबर 2009 तक
I. **फिल्म प्रभाग में ही निर्माण कार्य** अ. गैर-योजना (i) न्यूज मैगजीन	15		10
(ii) वृत्तचित्र सिनेमा रिलीज	17	26	20
(iii) वृत्तचित्र गैर-सिनेमा रिलीज	18	10	09
(iv) प्रशिक्षण-शिक्षण एवं शिक्षा संबंधी फिल्में	—	—	—
II. बाहरी निर्माताओं से कराए गए निर्माण	3	—	5
कुल	**53**	**36**	**44**
अन्य मंत्रालयों द्वारा वित्त पोषित फिल्में	—	—	—
बाहरी निर्माताओं के जरिए सीधे भुगतान आधार पर फिल्म निर्माण	8	—	3
जोड़	**61**	**36**	**47**

2. फिल्म प्रभाग वृत्तचित्र और न्यूज मैगजीनों का थियेट्रिकल और गैर-थियेट्रिकल वितरण करता है। थियेट्रिकल वितरण सिनेमा हॉलों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें जरूरी प्रदर्शन योजना के अधीन पारित फिल्में (609 मीटर अर्थात् 2001 फीट अधिकतम सीमा तक) प्रदर्शित करनी पड़ती हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं :

प्रिंट एवं कैसेट की संख्या	**उपलब्धियां 2008-09**	**लक्ष्य 2009-10**	**उपलब्धियां 31-12-2009 तक**
थियेट्रिकल रिलीज	7917	14000	8214
गैर थियेट्रिकल रिलीज	121	—	66
बीटा (कलर)	3	5	3
डीवीडी (कलर	279	—	1575
वीसीडी (कलर)	5879	5500	2500

3. सिनेमा हाउस की संख्या जिन्हें प्रति सप्ताह पारित फिल्में सप्लाई की जाती हैं निम्न हैं:

2007-08	8038
2008-09	8007
2009-10	8219

4. सिनेमाघरों में वितरण हेतु, फिल्म प्रभाग एक न्यूज मैगजीन अथवा एक वृत्त फिल्म प्रति सप्ताह पूरे देश को एक इकाई के तौर पर रिलीज करता है। 256 प्रिंट प्रति सप्ताह थियेट्रिकल वितरण हेतु वर्ष 2009-10 में तैयार किये गए हैं।

5. विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी का विवरण इस प्रकार है :

	समारोहों की संख्या	**प्राप्त फिल्मों की संख्या**
राज्य फिल्म समारोह राष्ट्रीय फिल्म समारोह	08	51
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	03	07
कुल	**11**	**58**

भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म बाजारों में भागीदारी

फिल्म स्कन्ध में दो मुख्य सचिवालय योजना कार्यक्रम हैं, यानी (i) विदेशी समारोह/बाजारों में भागीदारी और (ii) एनीमेशन गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। वर्ष 2008-09 के दौरान उपर्युक्त दोनों योजनाओं का कार्य निष्पादन इस प्रकार रहा :-

(i) **विदेशी समारोह/बाजारों में भागीदारी :** यह योजना एसएफसी द्वारा 2007 में मंजूर की गयी थी। इसका उद्देश्य फिल्म उद्योग द्वारा स्वंय निर्यात संवर्द्धन के उपाय करने में समर्थ होने अथवा इस निर्णय को देखते हुए कि कुछ बाजारों का लाभकारी दोहन नहीं किया जा सकता, उसकी सहायता करना है। वास्तव में फिल्म बाजारों में फिल्म उद्योग की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने पर खर्च करने की आवश्यकता है।

फिल्म बाजारों में भागीदार का प्रयोजन भारतीय फिल्म उद्योग को उजागर करना है, और साथ ही फिल्मों से संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी हासिल करना है ताकि वास्तविक व्यापार में संलग्न होने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। विश्व में केंस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और बाजार, बर्लिन फिल्म समारोह और अमरीकी फिल्म समारोह आदि प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार हैं। सरकार का प्रयास है कि भारत में फिल्म बाजार के आयोजन सहित भारतीय फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन का प्रत्येक अवसर प्रदान किया जाए।

इस कार्यक्रम के लिए भौतिक लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। इसी प्रकार स्वयं में उद्योग की बढ़ोतरी और विदेशों में भारतीय फिल्म निर्माताओं की बढ़ती भागीदारी लाभ के संकेत हैं।

(ii) एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना-

एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मानव संसाधन पर एक अध्ययन हेतु एम/एस पीडब्ल्युसी को नियुक्त किया था। पीडब्ल्युसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें ऐसे केंद्र की स्थापना की सिफारिश की गई है। इसी के अनुरूप मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी के लिए योजना आयोग से संपर्क किया है। योजना आयोग की सलाह पर यह मंत्रालय एफआर/डीपीआर तैयार करने के लिए एक परामर्शक नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

(पूर्व की निष्पादन समीक्षा)

वर्ष 2009-10 के दौरान संस्थान में विभिन्न पाठ्क्रमों के लिए 144 छात्रों ने पंजीकरण कराया :

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम का नाम	छात्रों की संख्या
1.	फिल्म एवं टी.वी. में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	48
2.	टी.वी. में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	42
3.	अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा	21
4.	फीचर फिल्मों में पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	12
5.	कला निर्देशन एवं प्रोडक्शन डिजाइन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	11
6.	एनीमेशन तथा कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	10
	कुल	**144**

वर्ष 2009-10 के दौरान टी.वी. विंग में बेसिक वीडियोग्राफी में अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव रखा गया था जिन्हें 3 नवंबर से 9 नवंबर 2009 में पूरा कर लिया गया।

एचआरडी स्कीम के तहत 11वीं योजना के लिए निम्नलिखित गतिविधियां कवर की गईं :

1. विभिन्न कार्य क्षेत्रों में स्टाफ तथा संकाय के लिए प्रशिक्षण।
2. संस्थान की पत्रिका लेंसाइट का प्रकाशन तथा अन्य अनुसंधान संबंदी वित्त पोषित प्रकाशनों, आवधिकों आदि का प्रकाशन।
3. सेमिनारों, व्याख्यानों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा संबंधित पहलुओं पर खर्च हुआ।
4. संस्थान की लाइब्रेरी के लिए मानव संसाधन संबंधी पुस्तकों की खरीद।
5. संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों संबंधी कार्यशालाओं के लिए विजिटिंग स्कॉलरों पर खर्च हुआ।
6. मेजिक फाउंटेन जैसी एजेंसियों से लाइब्रेरी के लिए डीवीडी विशेषकर वृत्तचित्र प्राप्त करना।
7. एफटीआईआई के स्वर्णजयंती वर्ष समारोह के 21 मार्च 2009 को हुए आयोजन के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

सभी छात्र उत्तीर्ण हुए। पूर्व की तरह, एफटीआईआई छात्र तकनीकी क्षेत्रों तथा सौंदर्य अपील दोनों में सिनेमा का स्तर बढ़ाने में सहायक बने हैं। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान स्टष्ट दिखाई देता है। निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक अनुदान सहायता के तहत स्कीमों को पूरा किया जा रहा है।

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

गैर योजना

वर्ष 2008 के दौरान शैक्षिक सत्र, 2008-11 के लिए त्रिवर्षीय पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 40 छात्रों ने पंजीकरण करवाया। वर्तमान में अध्ययनरत (प्रत्येक विशेषज्ञता क्षेत्र में 10) बैच सहित 112 छात्र हैं। 2009-12 बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है और 29 मार्च, 2010 से कक्षाएं शुरू होंगी।

योजना स्कीम

इसके तहत संस्थान के लिए सहायता अनुदान की मिश्रित स्कीम है। स्कीम के हिस्सों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :

क्र. सं.	योजना स्कीम का नाम	2008-09 के दौरान वास्तविक प्रदर्शन
1.	नए शैक्षिक विभाग का सृजन : फिल्म और टेलीविजन में निर्माण प्रबंधन	1. निर्माण के लिए बुनियादी योजना तैयार; कोलकाता नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद तुरन्त सिविल निर्माण कार्य शुरू करेगा। 2. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती प्रक्रिया शुरू।
2.	नए शैक्षिक विभाग का सृजन : एनिमेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग	1. निर्माण के लिए बुनियादी योजना तैयार; कोलकाता नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद तुरन्त सिविल निर्माण कार्य शुरू करेगा। 2. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती प्रक्रिया शुरू।
3.	कंप्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण	1. कुछ अति आधुनिक उपकरण खरीदकर लगाए गए। 2. ई-बिजनेस स्यूट का इस्तेमाल करते हुए ईआरपी के क्रियान्वयन के लिए सॉल्युशन डिजाइन पूर्ण, दूसरे चरण का क्रियान्वयन शुरू। 3. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 4. नए फिल्म स्टूडियो तथा फिल्म अभिलेखागार की डिजाइन तथा योजना तैयार करने के लिए जादवपुर विश्वविद्यालय के वास्तु विभाग द्वारा सौंपी गई स्थानीय निकाय से अनुमति के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
4.	एचआरडी पहलू/छात्रवृत्ति/छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम/इंटर्नशिप	1. एसआरएफटीआई के संपादन विभाग के छात्रों ने अप्रैल 08 में इटली के ज़ेलिग फिल्म स्कूल का दौरा किया। 2. जून, 08 में जेलिग फिल्म स्कूल के छात्र एसआरएफटीआई आए। 3. एसआरएफटीआई के 11 छात्रों को मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
5.	प्रशिक्षण और कौशल विभाग	1. संकाय सदस्यों के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में संस्थान ने तीन फिल्में बनाईं। फिल्में सामाजिक विषयों पर आधारित हैं। 2. विभिन्न संगठनों द्वारा फिल्म और टेलीविजन संबंधी सेमिनार/कार्यशालाओं में संस्थान के कुछ संकाय सदस्यों ने हिस्सा लिया। 3. संस्थान के निदेशक ने सिलेक्ट (अंतर्राष्ट्रीय फिल्म स्कूल संगठन) की नवंबर 2008 में बीजिंग में आयोजित आम सभा तथा कांग्रेस में हिस्सा लिया।
6.	एसआरएफटीआई में सामुदायिक रेडियो (सीआरएस) की स्थापना	1. बेसिल से मंगाए उपकरण स्थापित। 2. प्रसारण लाइसेंस हासिल। 3. 24 मई 2008 को सीआरएस का सफलतापूर्वक उदघाट्न तथा 90.4 मेगा हटर्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण 4. मई 2008 से नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।
7.	एसआरएफटीआई में केप्टिव टीवी चैनल (सीटीवीसी) की स्थापना	1. बेसिल से उपकरण हासिल

भारतीय जनसंचार संस्थान

पाठ्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धियां

गैर योजना

वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए वास्तविक उपलब्धियाँ और वर्ष 2010-11 के लिए लक्ष्य

योजना/ गतिविधि	वित्तीय वर्ष 2008-09		वित्तीय वर्ष 2009-10		वित्तीय वर्ष 2010-11	
	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	विभिन्नता के कारण	वास्तविक लक्ष्य
जनसंचार में प्रशिक्षण/ शिक्षण और शोध भारतीय जनसंचार संस्थान	**पीजी डिप्लोमा कोर्स आयोजित करना :** 1. पत्रकारिता (हिन्दी) (40) 2. पत्रकारिता (अंग्रेजी) (40) 3. पत्रकारिता (उड़िया) (15) 4. विज्ञापन और पब्लिक रिलेशंस (45) 5. रेडियो और टीवी पत्रकारिता (30) 6. विकास पत्रकारिता में दो दो कोर्स (40 भगीदारों के साथ) केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत कर्मियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं (रक्षाकर्मी समेत 330 से 450); आईआईएस अधिकारियों के लिए सेवारत पाठ्यक्रम सरकार की आवश्यकता के अनुसार। जनसंचार के विविध पहलुओं पर शोध अध्ययनों को आयोजित करना और अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं और छात्रों के लैब जर्नलों को प्रकाशित करना।	इस संस्थान द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न डिप्लोमा कोर्सों में इस वर्ष के दौरान कुल 246 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। संस्थान ने विकास पत्रकारिता में भी दो कोर्स आयोजित किए (कुल 36 भागीदारों के साथ) इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान कुल 15 अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए (कुल 426 भागीदारों के साथ) जन संचार के विविध पहलुओं पर 7 प्रयोजित शोध अध्ययनों को आयोजित किया। डिप्लोमा कोर्सों के छात्रों द्वारा लैब जर्नल निकाले गए। इस वर्ष के दौरान संस्थान ने डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए ओबीसी आरक्षण कोटा लागू किया। (पहला चरण)	पीजी डिप्लोमा कोर्स आयोजित करना : 1. पत्रकारिता (हिंदी) (53) 2. पत्रकारिता (अग्रेजी) (54+54+108) 3. पत्रकारिता (ओड़िया) 20 4. विज्ञापन व पब्लिक रिलेशंस (61) 5. रेडियो व टीवी पत्रकारिता (40) 6. विकास पत्रकारिता (40-45) 7. अल्पकालीन कोर्स/ कार्यशाला (330-450) आई आई एस अधिकारियों के लिए सेवारत पाठ्यक्रम (सरकार की आवश्यकतानुसार) शोध और अन्य गतिविधियाँ : शोध अध्ययन आयोजित करना (3-4 परियोजनाएँ)	इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं :- 1. पत्रकारिता (हिन्दी) (49) 2. पत्रकारिता (अंग्रेजी) (48+42=90) 3. पत्रकारिता (ओड़िया) (20) 4. रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता (39) 5. विकास पत्रकारिता : (i) पाठ्यक्रम पूरा हुआ (25) (ii) पाठ्यक्रम चल रहे हैं (24) आई आई एस ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए जनवरी 2009 से सेवारत पाठ्यक्रम (i) आई आई एस ग्रुप ए (9 माह अवधि) (3 भागीदार के	नियोजित लक्ष्यों के अनुरूप संस्थान द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रिक्त शैक्षणिक पदों को नहीं भरे जाने के कारण (संपादक के पद समेत) संस्थान इस वर्ष के दौरान अपनी अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं को नहीं निकाल सका)।	पी जी डिप्लोमा कोर्स आयोजित करना : - पत्रकारिता (हिन्दी) (62) - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62) - पत्रकारिता ओड़िया (23) - विज्ञापन व पब्लिक रिलेशंस (70) - रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46) - विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा कोर्स (40-45) **अल्पकालीन कार्यक्रम** - अल्पकालीन कोर्स/ कार्यशालाएं (400-500) - आई आई एस अधिकारियों के लिए जारी सेवारसत पाठ्यक्रमों को पूरा करना - शोध अध्ययन (4 से 5 अध्ययन) - अर्द्धवार्षिक जर्नलों अंग्रेजी में कम्यूनिकेटर

			अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं को निकालना (कम्यूनिकेटर और संचार माध्यम) और छात्रों के लैब जर्नल)	साथ) (ii) आई आई एस ग्रुप बी (6 माह अवधि) (29 भागीदार के साथ) **अल्पकालीन कोर्स/ कार्यशालाएं** जनवरी 2009 के मध्य तक संस्थान ने कुल 771 भागीदारों के साथ पहले ही 29 अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर चुका है। मार्च 2010 तक कुछ और कोर्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। डिप्लोमा कोर्सों के छात्रों द्वारा लैब जर्नल निकाले गए हैं। **शोध अध्ययन :** शोध विभाग ने पिछले वर्ष के जारी अध्ययनों को पूरा करने के अलावा भारत में विदेशी न्यूज एजेंसियों के न्यूज ऑपरेशन और नीतिगत मुद्दों पर एक नया अध्ययन शुरू किया। इस वर्ष के दौरान संस्थान ने डिप्लोमा कोर्सों में प्रवेश के लिए ओबीसी आरक्षण कोर्ट का दूसरा चरण लागू कर दिया।		और हिन्दी में संचार माध्यम और छात्रों के लैब जर्नलों को प्रकाशित करना। तीसरे वर्ष के दौरान अपने अंतिम चरण में ओबीसी आरक्षण के कोटे को लागू करना

नोट : कोष्ठक के अंदर दिए आंकड़े छात्रों की संख्या को सूचित करते हैं।

वित्तीय समीक्षा

योजना स्कीम

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वास्तविक व्यय 2007-08	वास्तविक व्यय 2008-09	एस.बी.जी. 2009-10	आर.ई. 2009-10	वास्तविक व्यय दिसंबर, 09 तक
1.	**चालू योजना** फिल्मों की प्राप्ति एवं अभिलेखीय फिल्मों का प्रदर्शन	0.90	1.76	4.00	7.00	2.20
	कुल	**0.90**	**1.76**	**4.00**	**7.00**	**2.20**

गैर-योजना

2.52 करोड़ रुपए एस.बी.जी. के मुकाबले आर.ई. 3.10 करोड़ रुपये थी। वेतन तथा बिजली दरों में बढ़ोतरी के चलते 31.12.2009 तक वास्तविक व्यय 2.44 करोड़ रुपये था।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

वास्तविक लक्ष्य (2008-09 तथा 2009-10)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	वास्तविक लक्ष्य 2008-09	वास्तविक उपलब्धियां 2008-09	वास्तविक लक्ष्य 2009-10	वास्तविक उपलब्धियां 31.12.2009 तक	कमी के कारण यदि कोई है
1.	**चालू योजना** अभिलेखा फिल्मों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन	600 फिल्में/डीवीडी, वीएचएस प्राप्त करना 80 फिल्मों का डिजिटाइजेशन, 16 फिल्मों का जीर्णोद्वार करना	805 फिल्में/ डीवीडी, वीएचएस प्राप्त कीं।	600 फिल्में/डीवीडी, वीएचएस प्राप्त करना, 100 फिल्मों का डिजिटाइजेशन तथा पोस्टर, स्टिल्स जैसी अनुषंगी सामग्री का डिजिटाइजेशन	701 फिल्में/डीवीडी/ वीएचएस प्राप्त कीं तथा 75 फिल्मों का डिजिटाइजेशन और 20 फिल्मों का जीर्णोद्वार 2,07,498 फिल्मों की सामग्री का डिजिटाइज़ेशन आदि।	कोई कमी नहीं

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

पूर्व निष्पादन समीक्षा

योजना स्कीमें

2009-10 के दौरान योजना स्कीम के संबंध में निष्पादन नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्वीकृत परिव्यय 2009-10 के लिए			2009-10 के लिए उपलब्धियां	
		वित्तीय		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक
		बीई	आर.ई			
1.	विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण	6.50	7.84	5 फिल्में	6.50	4 फिल्मों के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं तथा कानूनी कार्यवाही चालू है जिसके बाद ही निर्माण शुरू होगा।
	कुल	**6.50**	**7.84**	**5 फिल्में**	**6.50**	**वही**

पत्र सूचना कार्यालय

1. वर्ष 2009-10 के दौरान पहले 9 महीनों में योजना और गैर योजना प्रदर्शन

2. वर्ष 2008-09 के दौरान योजना एवं गैर-योजना प्रदर्शन

वार्षिक योजना 2008-2009

मार्च 2009 तक योजना व्यय विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	स्कीम परिव्यय		सरकार द्वारा अनु. सहायता/ ऋण जारी	वास्तविक व्यय 31.3.09 तक	उत्तर-पूर्व के क्षेत्र में परिव्यय (08/09	31.3.2009 तक व्यय	कमी के कारण (यदि कोई हो)
		एसबीजी 2007-08	आर.ई. 2007-08					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना	437.00	437.00	-	शून्य	नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन पूरे देश के लाभार्थ हैं, अत: उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पृथक राशि नहीं रखी गई है		डीयूएसी/सीपीडब्लूडी से मंजूरी नवंबर-दिसंबर 2008 में प्राप्त होने के कारण एनपीसी की स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जा सका। तथापि कुल परियोजना लागत बढ़ जाने के कारण मंत्रालय से नवीन स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास शुरू किए गए।
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	960.00	960.00	905.00	897.84	0.96	0.96	व्यय की स्थिति संतोषजनक रही।
3.	**विशेष कार्यक्रमों का प्रचार** इस योजना में तीन उप-स्कीमें शामिल हैं:							राज्य में शोक की स्थिति मे चलते कुछ प्रमुख कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके, इसलिए केवल 1.30। लाख रुपए व्यय किए गए।
क.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	1.00	7.00	1.90	1.30	0.00	0.00	
ख.	प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	1.00	1.00	0.85	0.84 मामूली कमीं	0.00	0.00	

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	स्कीम परिव्यय		सरकार द्वारा अनु. सहायता/ ऋण जारी	वास्तविक व्यय 31.3.09 तक	उत्तर-पूर्व के क्षेत्र में परिव्यय (08/09	31.3.2009 तक व्यय	कमी के कारण (यदि कोई हो)
		एसबीजी 2007-08	आर.ई. 2007-08					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग.	मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम	44.00	44.00	4.40	शून्य	0.00	0.00	इस मद को लागु करना अन्य देशों पर निर्भर करता है।
घ.	राष्ट्रमंडल खेल 2010 हेतु मीडिया प्रबंधन और सुविधाओं हेतु प्रस्ताव	180.00	180.00	120.00	119.63	चूंकि खेल पुणे और दिल्ली में आयोजित हुए/होने हैं, अत: उत्तर-पूर्व के लिए प्रथक राशि वहीं रखी गई है।		कोई कमी नहीं
	कुल	**1628.00**	**1769.00**	**1032.15**	**1019.61**	**100.40**	**96.00**	

पत्र सूचना कार्यालय

दिसम्बर 2009 तक योजना व्यय विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	स्कीम परिव्यय				उत्तर पूर्व परिव्यय 2008/09	31-12-2009 तक व्यय	कमी के कारण (यदि कोई हो)
		एसबीजी	संशोधित परिव्यय	अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय 31.12.09 तक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना	500.00	400.00		शून्य	चूंकि नई दिल्ली की इमारत पूरे देश के लाभ के लिए है एनई क्षेत्र के लिए कोई फंड निर्दिष्ट नहीं किया गया है		कुल परियोजना लागत बढ़ गई है, मंत्रालय/ईएफसी से नया अनुमोदन 15.9.2009 को प्राप्त किया गया।
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	950.00	950.00		437.00	96.00	30.00	15वीं लोकसभा की निर्वाचन अवधि के दौरान आचरण संहिता लागु हाने के कारण मई 2009 तक कोई पीआईसी आयोजित नहीं की जा सकीं। हालांकि दिसम्बर 2009 तक 49 पीआईसी, 3 प्रेस दौरे और 49 सफलता समाचार आयोजित किए गए। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पीआईसी हेतु अग्रिम राशि ले ली गई है।
3.	विशेष कार्यक्रमों का प्रचार इस स्कीम के निम्नलिखित तीन हिस्से हैं :							राज्य में शोक अवधि के कारण कुछ प्रमुख कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सके और इसलिए केवल 1.30 लाख रुपये खर्च किए गए।
	1. भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	7.50	7.50		3.20	शून्य	शून्य	32 लाख रुपए इफ्फी पर व्यय किए गए
	2. प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	1.80	1.80		—	शून्य	शून्य	चूंकि इसका आयोजन जनवरी 2010 में किया गया अत: दिसंबर 2009 तक कोई व्यय नहीं किया जा सका
	3. मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम	44.00	44.00		—	4.00	शून्य	इस हिस्से का क्रियान्वयन अन्य देशों पर निर्भर है।
4.	पुणे के राष्ट्रमंडल युवा खेल 2008, तथा दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए मुख्य मीडिया केंद्र तथा अन्य मीडिया केंद्र	1000.00	1000.00		50.12	पुणे और दिल्ली में खेल आयोजित होने के कारण एनई क्षेत्र के लिए कोई फंड निर्दिष्ट नहीं किया गया।		कोई कमी नहीं।
	कुल	**2503.00**	**2403.00**		**490.00**	**100.00**	**30.00**	

भारतीय प्रेस परिषद

पिछले प्रदर्शन की समीक्षा

प्रेस परिषद के कार्य अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं और यह प्रेस के आचरण संबंधी स्तर को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है। अत: इसके कार्यों को भौतिक आंकड़ों और प्राप्त परिणामों के आधार पर आंका नहीं जा सकता। मापने योग्य गतिविधि केवल अर्द्ध-न्यायिक गतिविधि की है। 2009-10 और 2010-11 की अवधि में प्राप्त शिकायतें ओर उनके निपटारे की स्थिति तालिका में दिखाई गई है। इनके अतिरिक्त वर्ष के दौरान देशभर में और राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोहों के अंतर्गत वाद-विवाद आयोजित किए गए तथा प्रेस की उत्तरदायिता और सामाजिक प्रभाव का न केवल आदर्श की दृष्टि से अपित युवा पत्रकारों को इन मूल्यों और आदर्शों का महत्व समझाने की दृष्टि से अध्ययन कराना, जो समाज, राष्ट्र और मानवीयता के हित में समर्पित पत्रकारों का मार्ग प्रशस्त कर सके, इसकी गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु रहे। इस वर्ष का राष्ट्रीय प्रेस दिवस ''भारतीय मीडिया का बदलता स्वरूप'' को समर्पित था।

''पत्रकारों के व्यवहार के नियम'' के 2005 अंक का अध्ययन किया गया है और 2010 का अंक शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

अपनी परामर्शदायी क्षमता में, परिषद ने सरकार और अन्य अधिकारियों को इन विषयों पर राय दी :

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से दिनांक 24.3.2009 को प्राप्त संवाद, जिसमें दूसरी एआरसी-8वीं रिपोर्ट-आंतकवाद से मुकाबला पर टिप्पणी/एटीएन मांगी गई थी।
2. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दुरूपयोग और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत इसे रोकने की आवश्यकता संबंधी याचिका।
3. राज्यों में प्रेस परिषद की शाखाएं खोलना प्रेस स्वतंत्रता सुरक्षा परिषद, चेन्नई से प्राप्त सुझाव।
4. पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का सम्मेलन 2007-मीडिया पर प्रभाव डालने वाली अनुशंसाओं पर कार्रवाई।
5. सामुदायिक दंगों पर जांच आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद के कार्यसमूह की अनुशंसा संबंधी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ।
6. असत्य और अश्लील विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए विभिन्न समाचारपत्रों के खिलाफ विशेष कार्यबल (उ.प्र.) लखनऊ के एसएसपी की श्री अमिताभ व्यास की शिकायत।
7. प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रकाशित विज्ञापनों के खिलाफ निपटाई गई शिकायतों के संबंध में भारत की विज्ञापन गुणवत्ता परिषद (एएससीआई) से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अग्रसारित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अवर सचिव श्री शामलाल से प्राप्त पत्र।
8. पत्रकारिता में सुधार के संबंध में डा. आई.एस. शर्मा (गुरुजी), लखनऊ की याचिका की प्रति अग्रसारित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव सुश्री रेणु अरोड़ा से प्राप्त पत्र।
9. पत्रांक 2/14/2009-आईपी एण्ड एससी दिनांक 6.10.09 द्वारा राज्यों एवं संघ प्रदेशों के सूचना एवं सिनेमैटोग्राफी मंत्रियों के 27वें सम्मेलन (सिमकॉन XXVII) के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र।

समाचारों के लिए भुगतान

परिषद ने 9.6.2009 को आयोजित अपनी बैठक में अप्रैल/मई 2009 में लोकसभा चुनावों के दौरान उम्मीदवारों की कवरेज के लिए मीडिया द्वारा अनैतिक भुगतान प्राप्त करने संबंधी अभिवेदन स्वीकार किए। अभिवेदन सर्वश्री प्रभाष जोशी, कुलदीप नैयर, बी.जी. वर्गीज़, अजीत भट्टाचार्जी तथा माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के उपकुलपति उच्युतानंद मिश्र जैसे वरिष्ठ पत्रकारों के समूह ने दिए। इस चलन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इस मुद्दे पर विचार करने और चुनाव आयोग सहित विभिन्न हितधारियों के प्रमाण इकट्ठे करने के लिए एक उपसमिति गठित की गई है।

प्रेम की स्वतंत्रता पर खतरों की निगरानी स्व संज्ञानों निर्णयों, सुझावों, आदि के जरिए की गई।

स्वयं संजान

परिषद ने चेन्नई में दिनामलार के समाचार सम्पादक की गिरफ्तारी पर स्वयं संगान लेते हुए इस घटना की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया। दिनामलार के सम्पादक और तमिलनाडू सरकार के मुख्य सचिव एवं सचिव गृह (पुलिस) विभाग से भी टिप्पणी मांगी गई। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मीडिया को पूर्ण सुरक्षा देने तथा न्याय सुनिश्चित करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई मामला प्रक्रियाधीन है।

31.1.2010 तक मामलों की स्थिति

क्र.सं	ब्योरा	2008-09	2009-10	अप्रैल 2010 से मार्च 2011 (संभावित)
1.	लम्बित मामले	759	904	1062
2.	दर्ज मामले	726	655	700
3.	परिषद द्वारा मामलों पर निर्णय	138	250	250
4.	अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए जाने वाले मामले	443	117	200
5.	31.03.2010 को लंबित मामले	904	1192*	

* 80 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और निर्णय सुनाना लम्बित है, 50 मामले सुनवाई के अंतिम चरण में हैं।

2009-10 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति

1. तीन राज्यों के फीस न देने वालों की बकाया राशि चरणबद्ध तरीके से वेबसाइट पर डालना - **लगभग सम्पन्न**
2. 'मीडिया शिक्षा का स्तरीकरण' हितकारियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। प्रक्रिया पूरी होने में एक-दो वर्ष लग सकते हैं। - **चालू है**
3. प्रेस की आज़ादी से संबंधित निर्णयों/आदेशों में निहित सिद्धांतों का संग्रह तैयार करना - **चल रहा है**
4. ई-संवाद को बढ़ावा - **संतोषजनक प्रगति,** सभी अनुभाग ईमेल तक पहुंच रखते हैं और इसे पत्र व्यवहार के लिए प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।
5. परिषद के कर्मियों के सेवा रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण - **चल रहा है** और 2010-11 में पूरा होने की संभावना है।
6. प्रेस द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर वर्ष 2008-09 के दौरान परिषद द्वारा दिए गए निर्णयों की सूची वेबसाइट पर है।
7. प्रेस के खिलाफ शिकायतों पर वर्ष 2008-09 के दौरान परिषद द्वारा सुनाए गए निर्णयों की सूची वेबसाइट पर है।
8. प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की धारा 8ग के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के प्रेस एवं पंजीकरण अपीली बोर्ड के आदेशों की सूची वेबसाइट पर है।
9. 1965 में परिषद की स्थापना के समय से प्रेस रिपोर्टों को चरणबद्ध तरीके से इलेकट्रानिक रुप में बदलने का काम चालू है।
10. वर्ष 1982 से पीआरएबी द्वारा दिए गए निर्णयों का डेटा बैंक सृजिक करना-सम्पन्न।
11. पुस्तकालय खरीद रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण - **सम्पन्न**

फोटो प्रभाग

लक्ष्य एवं कार्य निष्पादन 2008-09

वित्तीय

(लाख रुपए में)

स्वीकृत बजट अनुदान			वास्तविक परिव्यय		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
55.00	243	298	50.28	283.81	334.09

2009-10

(लाख रुपए में)

	योजना	गैर-योजना	कुल
स्वीकृत बजट अनुदान	70.00	335.00	405.00
संशोधित अनुदान	210.00	380.00	590.00
1/2010 तक वास्तविक परिव्यय	33.94	300.53	334.47

बजट अनुमान 2010-11

योजना	गैर-योजना	योग
255.00	355.00	610.00

		2009-10		2010-11
क्र.सं.		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1.	निर्धारित कार्य	4000	17320	5000
2.	श्वेत-श्याम प्रिंट एवं रंगीन प्रिंट	100000	93000	120000
3.	वीआईपी प्रजेन्टेशन फोटो एलबम	150	160	200
4.	अंकीय तस्वीरों का इन-हाउस संग्रह	100000	214600	150000

प्रकाशन विभाग

लक्ष्य और कार्य

2008-09, 2009-10 (31.12.2009 तक) और 2010-11 के दौरान

वित्तीय

(लाख रुपये में)

वास्तविक व्यय 2008-09			बजट आकलन 2009-10			संशोधित आकलन 2009-10			वास्तविक व्यय 2009-10 (31.12.2009 तक)			बजट आकलन 2010-11		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
40.99	1926.77	1967.76	29.00	2414.00	2443.00	29.00	2469.00	2498.00	19.00	1728.11	1747.11	20.00	2104.00	2124.00

वास्तविक

	2008-09		2009-10		2010-11 (लक्ष्य)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
पत्रिकाएं	20	20	20	20	20	-
पुस्तक	120	116	120	55 (दिसंबर 2009 तक)	100	-

4.2 नेट पर इंडिया 2010 और भारत 2010

प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर इंडिया 2010 और भारत 2010 के 2700 से भी अधिक पृष्ठों के संदर्भ वार्षिकी को ई-पीडीएफ फॉर्मेट में डिजीटलीकृत किया गया है। यह वेबसाइट है www.publicationsdivision.nic.in

4.3 सार्वजनिक निजी भागीदारी

प्रकाशन विभाग की किताबों को बेचने के लिए शीर्ष पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों को शामिल करके सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग में मानव श्रम कम होने के कारण पांडुलिपि, प्रूफरीडिंग, अनुवाद इत्यादि से संबंधित कार्य बाहर से करवाए जा रहे हैं। स्वचलन से संपूर्ण प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और माऊस को क्लिक करके सारी सूचना प्राप्त की जा सकेगी। प्रकाशन विभाग की वेबसाइट www.publicationsdivision.nic.in के माध्यम से निविदा संबंधी सभी पूछताछ को इंटरनेट पर डाला जा रहा है।

4.4 प्रकाशन विभाग ने वर्ष 2010-11 में योजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रस्ताव दिया है।

(लाख रुपये में)

घटक का नाम	प्रस्तावित राशि
दो बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण और एक मोबाइल वैन की खरीद	20.00
कुल	**20.00**

वितरण और बिक्री को बढ़ावा :

प्रकाशन विभाग की पुस्तकें बिक्री केन्द्रों/आउटलेटों, पुस्तक प्रदर्शनियों और 450 से भी अधिक एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचती हैं। ये बिक्री केन्द्र नई दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, कोलकता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं। बंगलुरु और गुवाहाटी में योजना कार्यालय में बिक्री के आउटलेट हैं।

प्रकाशन विभाग ने अप्रैल 2009 से जनवरी 2010 तक पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों में जो आयोजन किया या भागीदारी की उसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	अवसर	आयोजन स्थल	आयोजित करने वाली इकाई	अवधि
1.	तीसरे सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	मुख्यालय	21.04.2009
2.	लंदन पुस्तक मेला	लंदन	मुख्यालय	20.4.2009 से 12.7.2009
3.	12वां नीवेली पुस्तक मेला	नीवेली	एस ई, चेन्नई	3.7.2009 से 12.7.2009
4.	दिल्ली पुस्तक समारोह	जामिया मिलिया इस्लामिया	एस ई, ओल्ड सेक्टेरियट	1.8.2009 से 9.8.2009
5.	ताल बेहात महोत्सव-2009	ललितपुर जिला (यूपी)	एस ई, लखनऊ	15.8.2009 से 29.8.2009
6.	15वां दिल्ली पुस्तक मेला	प्रगति मैदान, नई दिल्ली	मुख्यालय	29.8.2009 से 6.9.2009
7.	पुस्तक प्रदर्शनी लोदी ईस्टेट, नई दिल्ली	सरदार पटेल विद्यालय	मुख्यालय	10.9.2009 से 11.9.2009
8.	7वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2009	लखनऊ	एस ई लखनऊ	11.9.2009 से 20.9.2009
9.	विशेष पुस्तक प्रदर्शनी	पुणे	एस ई, मुम्बई	22.10.2009 से 31.10.2009

क्रम संख्या	अवसर	आयोजन स्थल	आयोजित करने वाली इकाई	अवधि
10.	7वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला	जयपुर	मुख्यालय	31.10.2009 से 8.11.2009
11.	फैजाबाद पुस्तक मेला-2009	फैजाबाद	एस ई, पटना	7.11.2009 से 15.11.2009
12.	अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2009	पटना	ए.ई. पटना	7.11.2009 से 15.11.2009
13.	राजभाषा समारोह के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	चेन्नई	एस ई, चेन्नई	17.11.2009
14.	13वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला	कोच्चि	एस ई, तिरूवनंतपुरम	27.11.2009 से 12.12.2009
15.	10वां राजधानी पुस्तक मेला	भुवनेश्वर	एस ई, कोलकाता	28.11.2009 से 9.12.2009
16.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला-2009	लखनऊ	एस ई, लखनऊ	5.12.2009 से 27.12.2009
17.	23वां हैदराबाद पुस्तक मेला	हैदराबाद	एस ई, हैदराबाद	17.12.2009 से 10.1.20010
18.	33वां चेन्नई पुस्तक मेला	चेन्नई	एस ई, चन्नई	30.12.2009 से 10.1.2010
19.	पुस्तक मेला-2010	इलाहाबाद	एस ई, लखनऊ	1.1.2010 से 10.1.2010
20.	विजयवाड़ा पुस्तक मेला	विजयवाडा	एस ई, हैदराबाद	1.1.2010 से 11.1.2010
21.	देवघर पुस्तक मेला-2010	देवघर (झारखंड)	एस ई, पटना	5.1.2010 से 13.1.2010

प्रकाशित विभाग ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों को आयाजित करने या इसमें भाग लेने की योजना बनाई है :

1.	कोलकाता पुस्तक मेला-2010	नई दिल्ली	मुख्यालय	27.1.2010 से 7.2.2010
2.	विश्व पुस्तक मेला-2010	नई दिल्ली	मुख्यालय	30.1.2010 से 7.2.2010

इसके अतिरिक्त प्रकाशन विभाग ने अप्रैल 2009 से जनवरी 2010 तक जन सूचना अभियानों के अवसर व पुस्तक प्रदर्शनियों को भी आयोजित किया था:

1.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	अराकोनम (तमिलनाडु)	एस ई, चेन्नई	26.7.2009 से 30.7.2009
2.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	पुसाद (महाराष्ट्र)	एस ई, मुम्बई	6.8.2009 से 10.8.2009
3.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	चिदम्बरम (तमिलनाडु)	एस ई, चेन्नई	5.9.2009 से 9.9.2009

क्रम संख्या	अवसर	आयोजन स्थल	आयोजित करने वाली इकाई	अवधि
4.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	नरसारावपेटा गुंटूर जिला (आंध्र प्रदेश)	एस ई, हैदराबाद	5.9.2009 से 13.10.2009
5.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	मिर्जापुर जनपथ केलहट (उत्तर प्रदेश	एस ई, लखनऊ	9.10.2009 से 13.10.2009
6.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	कानपुर (उत्तर प्रदेश)	एस ई, लखनऊ	4.12.2009 से 8.11.2009
7.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	कुन्द्रातुर	एस ई, चेन्नई	17.11.2009 से 21.11.2009
8.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	एस ई, लखनऊ	8.12.2009 से 12.12. 2009
9.	जन सूचना अभियान के अवसर पर पुस्तक प्रदर्शनी	पुरम्बलूर (तमिलनाडु)	एस ई, चेन्नई	12.12.2009 से 16.12.2009

प्रकाशन विभाग ने जनवरी 2010 तक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं पर अपने कुछ बिक्री आउटलेटों पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:-

1.	विश्व पुस्तक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	20.4.2009 से 30.4.2009	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
2.	ग्रीष्म पुस्तक प्रदर्शनी	15.6.2009 से 26.6.2009	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
3.	स्वतंत्रता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	10.8.2009 से 21.8.2009	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
4.	शिक्षा दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	31.8.2009 से 11.9.2009	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
5.	हिन्दी पखवाड़ा पुस्तक प्रदर्शनी	14.9.2009 से 25.9.2009	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
6.	गांधी जयंती पुस्त्क प्रदर्शनी	1.10.2009 से 9.10.2009	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
7.	राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पर पुस्तक प्रदर्शनी	9.11.2009 से 20.11.2009	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
8.	क्रिसमस तथा नव वर्ष पुस्तक प्रदर्शनी	23.12.2009 से 08.01.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में

प्रकाशन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं पर अपने बिक्री केन्द्रों काउंटरों पर स्वस्थानीय पुस्तक प्रदर्शनियों को आयोजित करने की भी योजना बनाई है :

1.	गणतंत्र दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	22.01.2010 से 05.02.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में
2.	उपभोक्ता अधिकार दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	13.03.2010 से 24.03.2010	इसके 10 ब्रिक्री आउटलेट में

राजस्थान राज्य सरकार, गुजरात राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, हरियाणा राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार इत्यादि से बड़ी संख्या में आर्डर प्राप्त करने के लिए और राजा राममोहनराय लाइब्रेरी फाउंडेशन स्कीम, कोलकता के तहत बड़ी मात्रा में खरीद के लिए प्रकाशन विभाग देश भर में बिक्री को बढ़ावा देने वाले दौरों का भी आयोजन करता है।

प्रकाशन विभाग को अप्रैल 2009 से दिसंबर 2009 तक पुस्तकों, पत्रिकाओं की बिक्री और विज्ञापनों के माध्यम से (रोजगार समाचार को छोड़कर) 305 लाख और 31 हजार रुपये की कुल आमदनी हुई।

अपने प्रकाशनों और जर्नलों के अलावा प्रकाशन विभाग अन्य सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, सी एस आई आर, आई सी ए आर, आई सी सी आर, लोकसभा सचिवाला और राज्यसभा सचिवालय जैसे स्वायत्त संगठनों द्वारा निकाले गए प्रकाशनों का विपणन भी संभालता है।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार

2007-08 के दौरान उपलब्धियां अत्यंत संतोषजनक रही क्योंकि एम्प्लाइमेंट न्यूज को पूर्व वर्ष की तुलना में विज्ञापन से अधिक राजस्व तथा अधिक लाभ अर्जित हुआ। यह प्रवृत्ति मौजूदा वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान भी बनी रही और 4600 लाख रुपये के राजस्व के लक्ष्य की तुलना में कुल 5765.86 लाख रुपये का राजस्व अर्जित हुआ।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

वर्ष 2009-10 (31.12.2009 और 2010-11, 2008-09 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां)

वित्तीय

(लाख रुपये में)

गतिविधि का नाम	वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
अनुमानित बजट	2008-09	20.00	234.00	307.47
वास्तविक बजट	2008-09	14.69	292.78	254.00
अनुमानित बजट	2009-10	17.00	391.50	408.00
संशोधित अनुमान	2009-10	17.00	386.00	403.00
अनुमानित बजट	2010-11	17.00	359.00	376.00

योजना आयोग की सहमति से मंत्रालय द्वारा 88.06 लाख रुपयों के कुल परिव्यय से 'आर एन आई' के सुदृढ़ीकरण' की योजना को स्वीकृति दी गई। वर्ष 2009-10 के दौरान 17.00 लाख रुपये जारी किये गये।

भौतिक

क्र. सं.		2008-09		2009-10		2010-11
	कार्यक्रम/गतिविधियां	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
अ.	**गतिविधियां**				दिसंबर 2009 तक	
1.	शीर्षक देने का कार्य (आवेदन)	22000	21077	***	16373	***
2.	शीर्षकों को मुक्त करना	***	10332	***		
3.	पंजीकरण	3000	4969 (4341-नये 828-संशोधित)	***	3425 (2774-नये 651-संशोधित)	***
4.	प्रसार के दावों की जांच	***	19	***	10	
5.	प्रिंटिंग मशीनों के आयात के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए	***	02	***	02	
6.	एफसीआरए,1976 के अंतर्गत समाचार पत्रों को जारी प्रमाणपत्रों की संख्या	***	13	***	06	
7.	अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों को जारी किये गये योग्यता प्रमाणपत्रों की संख्या	***	775	***	992	
8.	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत किये गये आवेदनों की संख्या	***	308	***	408	
ख.	**कार्यक्रम**					
9.	आरएनआई की वार्षिक रिपोर्ट (भारत के समाचार पत्र)	2007-08 रिपोर्ट	2007-08 रिपोर्ट	2008-09 रिपोर्ट	2008-09 रिपोर्ट	2009-10 रिपोर्ट

नोट : प्रकाशकों द्वारा प्राप्त किये गये आवेदनों पर आधारित इन श्रेणीयों में अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमान के लिए योजनागत परिव्यय	:	15.00 लाख
वर्ष 2008-09 के लिए योजनागत कार्य/उपलब्धियां	:	14.69 लाख
2009-10 के लिए योजनागत परिव्यय		
2009-10 के लिए स्वीकृत बजट सहायता	:	17.00 लाख
2009-10 के लिए संशोधित अनुमान	:	17.00 लाख
2010-11 के लिए बजट अनुमान	:	17.00 लाख
11वीं योजना के कार्यक्रमों का नाम	:	आर एन आई का सुदृढ़ीकरण और
कुल योजना परिव्यय	:	**88.06 लाख**

11वीं योजना में आरएनआई का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2007-08 के दौरान 88.06 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृत 11वीं योजना में आर एन आई में सुदृढ़ीकरण को शामिल किया गया। इसके अन्तर्गत आर एन आई के दो क्षेत्रिय कार्यालय एक गुवाहाटी में और एक भोपाल खोलने का प्रावधान रखा गया। वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए 2007-08 की वार्षिक योजना में 5.88 लाख रुपये और 2008-09 के अनुमानित बजट में 2.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 2008-09 के लिए स्वीकृत बजट सहायता में 20.00 लाख रुपये की मंजूरी दी गई और संशोधित अनुमान और अंतिम सहायता के लिए 15.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 31.3.2009 तक व्यय में 14.69 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। 2009-10 के स्वीकृत बजट सहायता में 17.00 लाख रुपये निर्धारित किये गये। वर्ष 2009-10 के वित्त वर्ष के दौरान 31.12.2009 तक 11.16 लाख रुपये निर्धारित किये गये।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में समाचार पत्रों के प्रकाशकों की सुविधा के लिए गुवाहाटी और भोपाल में दो नये कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। योजना के पूरी तरह कार्यान्वित हो जाने के बाद से पंजीयन, शीर्षक के लिए प्रकाशकों द्वारा किये गये आवेदनों की संख्या, अखबारी कागज और प्रिंटिंग मशीनरी के आयात आदि के लिए कार्य सुविधाजनक हो जाएगा। नये क्षेत्रिय कार्यालय खोलने से इन क्षेत्रों के प्रकाशकों को पूछताछ के लिए मुख्यालय पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। संबंधित जानकारी वह इन क्षेत्रीय कार्यालयों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इन क्षेत्रों के प्रकाशकों के आवेदन इन क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ही मुख्यालय पहुंचेंगे।

भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कार्यालय का स्थान का निर्धारण कर लिया गया है। आर एन आई भोपाल ने भवन को अपने अधीन ले लिया है।

कम्प्यूटरीकरण

पंजीयन और जांच की कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के अलावा, जांचे गये समाचार पत्रों के सभी शीर्षकों को आर एन आर्ड की वेबसाइट *http//.rni.nic.in* पर देखा जा सकता है और आवेदनों द्वारा उन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद से कोई भी व्यक्ति/प्रकाशक आर एन आई की वेबसाइट पर देख सकता है कि शीर्षक

उपलब्ध हैं या नहीं। यह डाटा राज्य/भाषा वार उपलब्ध है। इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी लिंक के लिये जिसे निक्सी (एन आई सी एस आई) द्वारा 10वीं योजना के अन्तर्गत रखा गया था को एम टी एन एल के साथ 2 एमबीपीएस क्षमता वाली लाइन से जोड़ा गया है।

प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम की समीक्षा

प्रचार माध्यमों के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखकर प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 और इसके अन्तर्गत प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है।

राजभाषा

भारत के समाचार पत्र पंजीयक के कार्यालय में 14-28 सिंतबर के दौरान मनाये गए हिन्दी पखवाड़े में राजभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभाग की छमाही प्रत्रिका 'पंजीयन भारती' का नवीनतम अंक फरवरी माह में निकल रहा है जो राजभाषा को समर्पित है। आर एन आई को इस साल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया एककों के बीच हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रथम पुरस्कार मिला हैं। विभाग में हिन्दी में कार्य करने, अनुवाद और राजभाषा के कार्यान्वयत और निगरानी रखने के लिए।

लोक शिकायतें

आर एन आई के कार्यालय में लोक शिकायतें सुनने का कार्य किया जा रहा है। कार्यालय के उपपंजीयक को विभाग की शिकायतों को दूर करने का काम सौंपा गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उठाये गए कदम

आर एन आई ने 2007-08 में पूर्वोत्तर क्षेत्र और साथ ही मध्य क्षेत्र में अपनी पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दो नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना करने का फैंसला किया। यह कार्यालय गुवाहाटी और भोपाल में खोले जा रहे हैं। अभी तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का कार्य आर एन आई के कोलकाता कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय से किया जा रहा था। गुवाहाटी और भोपाल में खोले जा रहे दो नये क्षेत्रीय कार्यालय समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करेंगें।

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

(क) गतिविधि के आधार पर वर्गीकरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि वर्गीकरण	2008-09 के लिए वास्तविक			2009-10 के बजट अनुमान			संशोधित अनुमान 2009-10			बजट अनुमान 2010-11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1.	गवेषणा, संदर्भ और प्रलेखन तथा प्रशिक्षण	14.83	165.00	179.83	118.00	200.00	318.00	30.00	197.00	227.00	25.00	197.00	222.00

(ख) उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि वर्गीकरण	2008-09 के लिए वास्तविक			2009-10 के बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			2010-11 के बजट अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
1.	वेतन	–	133.00	133.00	–	164.00	164.00	–	164.00	164.00	–	160.60	160.00
2.	चिकित्सा	–	2.77	2.77	–	3.00	3.00	–	3.00	3.00	–	3.00	3.00
3.	ओवरटाइम भत्ता	–	0.07	0.07	–	0.40	0.40	–	0.40	0.40	–	0.40	0.40
4.	घरेलू यात्रा व्यय	–	0.39	0.39	10.00	1.50	11.50	–	1.40	1.40	–	1.50	1.50
5.	कार्यालय व्यय (ओ ई-आई आईएस प्रशिक्षण	14.83	25.19	40.02	108.00	28.00/	136.00	30.00	25.20	55.20	–	28.00	28.00
6.	अन्य प्रशासनिक व्यय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.00	–	25.00
7.	बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टेक्स	–	0.00	0.00	–	0.10	0.10	–	0.00	0.00	–	0.10	0.10
8.	प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	सूचना प्रौद्योगिकी	–	3.58	3.58	–	3.00	3.00	–	3.00	3.00	–	3.40	3.40
	कुल जोड़	**14.83**	**165.00**	**179.83**	**118.00**	**200.00**	**318.00**	**30.00**	**197.00**	**227.00**	**25.00**	**197.00**	**222.00**

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

वास्तविक उपलब्धि (गैर-योजना) (2010-11)

योजना का नाम	2008-09		असमानता के कारण	2009-10		असमानता के कारण	2010-11
	लक्ष्य	प्राप्ति		लक्ष्य	प्राप्ति मार्च 2009 तक		लक्ष्य
1. एनडीसीएमसी आवर्ती सेवाओं द्वारा मास मीडिया की प्रवृत्तियों और घटनाओं की जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना और उनका प्रसार करना।	59	55	प्रलेखन अधिकारी का एक पद खाली रहना।	59	46	स्टाफ की कमी	59
मास मीडिया इन इंडिया वार्षिक प्रकाशन का संकलन एवं संपादन करना।	1	1	-	1	0	- लागू नहीं -	1
2- संदर्भ एकांश 'इंडिया-वार्षिक संदर्भ' ग्रंथ का संकलन एवं संपादन	1	1	- लागू नहीं -	1	1	- लागू नहीं -	1
'डायरी ऑफ इवेन्ट्स' पाक्षिक का प्रकाशन	24	24	- लागू नहीं -	24	20	- लागू नहीं -	24

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

वास्तविक परिणाम (योजना) (2010-11)

योजना का नाम	2008-09		2009-10		असमानता के कारण	2010-11
	लक्ष्य	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**मार्च 2009 तक उपलब्धि**		**लक्ष्य**
1. गवेषणा इकाई मास मीडिया में शोध।	20 अनुसंधान पत्र जारी करना	1	1	2 पिछले वित्त वर्ष में सौंपा गया)	- लागू नहीं -	1
2. अ) संदर्भ इकाई लाइब्रेरी का आधुनिकीकरण करना।	50 बुक रैक, 1000 किताबें ई-बुक और आवती पत्रिकाएं खरीदना। पिछले वर्ष खरीदे गए आई टी उपकरण के लिए वार्षिक रखरखाव समझौता करना।	630 पुस्तकें और ई-एनआरएस रिपोर्ट प्राप्त की।	5000 किताबें/ई-बुक, आवर्ती पत्रिकाएं और पिछले वर्ष खरीदे गए आईटी उपकरण के लिए एएमसी खरीदना।	योजना स्कीम के तहत कोई पुस्तक नहीं खरीदी जा सकी	पुस्तकालय के लिए जगह की कमी।	500 पुस्तकें /ई-पुस्तकें, आवर्ती पत्रिकाएं और पिछले वर्ष खरीदे गए आई टी उपकरण के लिए एएमसी खरीदना
2. ब संदर्भ इकाई राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार।	राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार चयन समिति का गठन करना, पुरस्कारों के लिए चयन करना, स्मृति चिह्न का डिजाइन कास्टिंग और गढ़ायी करना, पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करना।	शून्य	राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार और चयन समिति का गठन करना, पुरस्कारों के लिए चयन करना, स्मृति चिह्न का डिजाइन कास्टिंग और गढ़ायी करना, पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करना।	शून्य	योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।	प्रिंट मीडिया की सात श्रेणियों में 21 पुरस्कार

गीत एवं नाटक प्रभाग

वर्ष 2009-10 के दौरान प्रभाग ने राष्ट्रीय और सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित प्रेरणादायक अभियानों के माध्यम से अपनी सेवायें जारी रखीं। मल्टी मीडिया प्रचर केन्द्र बिन्दु में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, आजादी की लड़ाई, ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एडस की रोकथाम और, स्वच्छता, दृष्टिहीनता का निमन्त्रण, नागरिक सुरक्षा, तम्बाकू निरोधक रक्तदान, महिला एवं बाल विकास, स्वाइन फ्लू डेंगू, चिकनगुनिया रोगों से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषय रहे।

वर्ष 2009-10 की महत्वपूर्ण गतिविधियों में आतंकवादी विरोधी, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव के विषयों पर चुने हुए 75 जिलों में विशेष प्रचार अभियान चलाया गया। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर सहित पूरे देश में साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर विशेष कार्यक्रम चलाया गया। जिसके अन्तर्गत सांझा न्यनतम कार्यक्रम का प्रचार सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर की विशेष योजनाओं का प्रचार किया गया। इसके अलावा प्रभाग ने सभी प्रमुख मेलों और त्योहारों जैसे गणतंत्र दिवस, विश्व जनगणना दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, बालदिवस कौमी एकता सप्ताह, शिक्षक दिवस, भारतीय अन्तराष्ट्रीय व्यापरार मेला में कई कार्यक्रम प्रस्तुत किये। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की आवश्यकता के अनुसार प्रचार अभियानों को चलाकर गीत एवं नाटय प्रभाग ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

2008-09 के दौरान भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य कार्यक्रम	कार्यक्रम उपलब्धियां	टिप्पणी
(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोष के अन्तर्गत चलाई जा रही गतिविधियां				
1.	गैर योजना	5100	6243	
2.	योजना	5362	7373	
(ख) अन्य मंत्रालयों/विभागों के कोष से चलाई जा रही गतिविधियां				
3.	व्यापार मेला, नई दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	170	170	
4.	आयोडीन युक्त नमक	1400	1970	
5.	नेको (राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम) रेड रिबन एक्सप्रेस सहित	1428	1515	
6.	महिला और बाल विकास	150	150	
7.	एन एफ एस एम	3498	3852	
8.	अन्य		495	

2009-10 (दिसंबर 09 तक) के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य कार्यक्रम	उपलब्धियां
क. सूचना और प्रसारण कोष के अन्तर्गत चलाई जा रही गतिविधियां			
1.	गैर योजना	5100	5044
2.	योजना	5980	7715
(ख) अन्य मंत्रालयों के कोष के अन्तगर्त चलाई जा रही गतिविधियां			
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	130	130
4.	आयोडीन युक्त नमक	1700	729
5.	स्वाइन फ्लू	6000	5213

एफ.एम. रेडियो (निजी)

परियोजना अप्रैल 2006 में शुरू हुई। अप्रैल 2009 तक परियोजना की स्थिति निम्नलिखित है:

क्र. सं.	साइट का नाम	स्थिति		टावर तैयार होने के लिए निर्धारित लक्ष्य	पूर्ण होने का संभावित समय
		नींव	टावर		
1.	जयपुर	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2007	पूर्ण
2.	हैदराबाद	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2007	पूर्ण
3.	नई दिल्ली	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2007	पूर्ण
4.	चेन्नई	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2007	पूर्ण
5.	कोलकाता	नींव का काम शुरू	ढांचे का कार्य प्रगति पर	मार्च, 2007	...
6.	देहरादून	पूर्ण	पूर्ण	मार्च, 2009	पूर्ण

* कोलकाता में आकाशवाणी द्वारा स्थल की अनापत्ति निलंबित

छह शहरों में इस परियोजना पर हुए व्यय का ब्योरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	**शहर का नाम**	**स्वीकृत लागत**	**अब तक खर्च राशि**
1.	जयपुर	166.12 लाख रुपए	1084.79 लाख रुपए
2.	हैदराबाद	166.12 लाख रुपए	
3.	चेन्नई	220.83 लाख रुपए	
4.	नई दिल्ली	439.05 लाख रुपए	
5.	कोलकाता	220.83 लाख रुपए	
6.	देहारादून	98.29 लाख रुपए	
	कुल	**1311.24 लाख रुपए**	**1084.79 लाख रुपए**

परियोजना की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा मासिक एवं त्रैमासिक छमाही और वार्षिक आधार पर की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र

यह परियोजना, 10वीं योजना अवधि में कुछ अपरिहार्य कारणों से क्रियान्वित नहीं की जा सकी। इसमें सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आबंटित पुष्पा भवन की छत पर ऐंटिना और अन्य उपकरण लगाने की मंजूरी न मिलने का कारण भी शामिल है। 9 जून 2008 को शुरू हुई यह परियोजना अब 14-बी, रिंग रोड, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली में लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत 150 चैनलों की निगरानी चौबीसों घंटे की जा रही है। मार्च 2010 तक इसकी क्षमता 300 चैनलों के अनुश्रवण तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

अंतर्राष्ट्रीय चैनल

लागू नहीं है क्योंकि योजना अभी प्राथमिक चरण में है।

सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां

सामुदायिक रेडियो के लिये आईईसी गतिविधियों के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली के एशियाई राष्ट्रमंडल शैक्षिक मीडिया केंद्र के साथ मिल देश भर में कई केन्द्रों पर कार्यशालाएं/गोष्ठियां और परामर्श बैठकें आयोजित की गई। इस तरह की पहली परामर्श बैठक का आयोजन लखनऊ में 28-30 नवंबर 2007 और दूसरी परामर्श बैठक 24 और 25 मार्च 2008 में कोलकाता में आयोजित की गई। इस समय काम कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रबंधकों के लिये क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में 13 फरवरी 2008 किया गया।

वर्ष 2008-09 के दौरान निम्न विवरण के अनुसार सात परामर्श/कार्याशालाए आयोजित की गई :-

परामर्श	**राज्य**	**स्थान**	**माह और वर्ष**
तीसरा क्षेत्रीय परामर्श	दक्षिण ज़ोन	श्री मानाकुला इंजीनियरिंग कालेज, पुडुचेरी	1-2 जुलाई, 2008
चौथा क्षेत्रीय परामर्श	पश्चिम ज़ोन	विद्या प्रतिष्ठान प्रौद्योगिकी संस्थान बारामती, महाराष्ट्र	8-9 सितम्बर, 2008
पाचवां क्षेत्रीय परामर्श	गुजरात, राजस्थान	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अहमदाबाद, गुजरात	24-25 नवम्बर, 2008
छठा क्षेत्रीय परामर्श	सभी पूर्वोत्तर राज्य	कृष्णकांत हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, गुवाहाटी	28-29 जनवरी, 2009
सातवां क्षेत्रीय परामर्श	हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ (यू.टी.)	एम.एस. पंवार इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिकेशन सोलन, हिमाचल प्रदेश	13-14 मार्च, 2009
आठवां क्षेत्रीय परामर्श	छत्तीसगढ़, ओडीशा, मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	24-25 मार्च, 2009
दूसरी क्षमता निमार्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम	सभी राज्य	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	10-11 फरवरी, 2009

सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां नामक योजना के लिए डीएवीपी द्वारा अंग्रेजी हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विभिन्न समाचार पत्रों विज्ञापन देकर सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिसमें अहर्ता की शर्ते, वर्तमान स्थिति और आवेदन के लिए संक्षेप में जानकारी दी गई है।

सूचना भवन का निर्माण

वार्षिक योजना वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान सूचना भवन के पांचवें चरण के निर्माण के लिए सीसीडब्ल्यू : एआईआर को क्रमशः 1 करोड़ रुपये और 1 करोड़ 76 लाख 20 हजार रुपये की राशि जारी की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2009-10) के लिए सूचना भवन के पांचवें चरण के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आबंटित कर दी गयी है। अगले वित्त वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना के लिए 10.00 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं जिससे सूचना भवन के पांचवें चरण का निर्माण कार्य किया जाएगा।

विकास संबंधी पहलों का आर्थिक विश्लेषण (नई योजना)

निम्नलिखित अध्ययन कार्य किए गए हैं :

1. **वार्षिक योजना 2007-08**
   ''उत्तर पूर्व तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में जनसंचार मीडिया का प्रभाव और पहुंच'' : रिपोर्ट भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा सौंपी गई।

2. **वार्षिक योजना 2008-09**
   ''भारत में अंत:मीडिया स्वामित्व'': प्रारूप रिपोर्ट भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद (एएससीआई) द्वारा सौंपी गई।

3. फिल्म खंड की दो चालू स्कीमों का मूल्यांकन, तथा; (i) फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा ''फिल्म समारोहों के जरिए निर्यात संवर्द्धन'' और (ii) मुख्य सचिवालय द्वारा ''देश और विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी'' प्रारूप रिपोर्ट भारतीय जन प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा 2009-10 में जमा की जानी है।

4. 2009-10 के दौरान निम्नलिखित दो अध्ययनों को पूरा किया जाना है :-
   I. ''एफएम पर संगीत के लिए मॉडल आईपीआर व्यवस्था''। यह अध्ययन 2008-09 में मंजूर किया गया था। लेकिन इसके बाद एजेंसी ने इसे पूरा करने में असमर्थता जता दी। इसलिए यही अध्ययन 2009-10 में पूरा किया जा रहा है।
   II. ''प्रसारण उद्योग के कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकार''।

मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

लक्ष्य 2009-10 के परिणाम

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आंबटन	भौतिक उत्पादन	दर्शाये गये परिणाम	जोखिम/टिप्पणी
1.	भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिए विदेशों में स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण	150	विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए 83 अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया।	मीडिया इकाईयों में अधिकारियों की क्षमता में सुधार/उन्नयन के जरिये संगठन के प्रभाव को सुधारना।	कोई विशिष्ट जोखिम नहीं

प्रसार भारती
आकाशवाणी - वार्षिक योजना (2009-10)
परिव्यय परिणाम/लक्ष्य

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
क	**चालू योजनाएं** पूंजी राजस्व		**113.60** 110.60 3.00	19.59 19.59 **0.00**				
1	जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष पैकेज पूंजी राजस्व	जम्मू एवं कश्मीर में रेडियो कवरेज	4.00 4.00	0.12 0.12 0.00	जम्मू कश्मीर में पैकेज चरण 1 की योजना पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर पैकेज चरण 2 में 62.5 केवीए (6) के डीजी सेटों एवं 15 केवीए (8) की खरीद की गई है। यूपीएस (6) के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। डीजी सेट 1 एमवीए (3) एवं डीजी सेट 500 केवीए (2) के लिए आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, जांच और कमीशनिंग के आधार पर एनाईटी जारी किए गए हैं।	क्यू 1- 62.5 केवीए (6) और 15 केवीए (8) डीजी सेट- खरीद और इंस्टॉलेशन का काम पूरा। यूपीएस (6) - खरीद और इंस्टॉलेशन का काम पूरा। क्यू 2 डीजी सेट 1 एमवीए (3) ऑर्डर दे दिए गए। क्यू 3- डीजी सेट 500 केवीए (2)- एसआईटीसी ऑर्डर देने की उम्मीद।	1- 62.5 केवीए (6) और 15 केवीए (8) डीजी सेट- खरीद और इंस्टॉलेशन। 40 केवी यूपीएस (6) - ऑर्डर दिए गए। काम दिसंबर 09 तक पूरा किया जाना है। डीजी सेट 1 एमवीए (3)- एसआईटीसी के आधार पर दो के लिए ठेके दिए गए। 500 केवीए डीजी सेट (2)- एसआईटीसी के आधार पर ठेका देने के	जम्मू और कश्मीर में मौजूदा रेडियो स्टेशनों पर अतिरिक्त डीजी सेटों और यूपीएस उपलब्ध कराने से कैप्टिव बिजली आपूर्ति मजबूत होगी और बिजली चले जाने पर और आपातकाल या प्राकृतिक आपदा के दौरान सतत प्रसारण सुनिश्चित हो सकेगा।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
						क्यू 4- एसआईटीसी कार्य के प्रक्रियाधीन होने की उम्मीद।	लिए नीलामी पर काम चल रहा है।	
2	पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज	पूर्वोतर में रेडियो कवरेज बढ़ाना	43.00	6.81	1 19 नए एफएम स्टेशन स्थान का अधिग्रहण और एमएम ट्रांसमीटरों की खरीद के प्रस्ताव की उम्मीद है।	1. 19 नए एफएम स्टेशन-10 साइटों का अधिग्रहण कर लिया गया। 4 साइट्स को राज्य सरकारों को प्रदान करना है। एक स्थान के लिए लागत की प्रतीक्षा है। चार स्थानों की पहचान की जानी है। क्यू 1- स्थान पर बाड़ा लगाने का काम शुरू। भवन निर्माण के लिए अनुमान मंजूर। एफएम ट्रांसमीशन प्राप्त होने की संभावना। क्यू 2- अधिग्रहित स्थानों के लिए भवन निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद।	1. 19 नए एफएम स्टेशन-14 साइटों, जिसमें वर्तमान वर्ष की चार साइट्स भी शामिल हैं, का अधिग्रहण कर लिया गया और 1 साइट का अधिग्रहण किया जाना है। मणिपुर के तेमांगलांग और उखरुल, नगालैंड के जुनेहबोटो और अरुणाचल प्रदेश के अनिनी स्थित चार साइट्स को अंतिम रूप देना है।	इससे सीमांत सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कवरेज में सुधार होगा।
	पूंजी		40.00	6.81			दो स्थानों पर सुरक्षा फेंसिंग का काम पूरा और 8 स्थानों पर काम चल रहा है। चंगलंग में विवाद के चलते काम शुरू नहीं हो पाया। चंगलंग के जिलायुक्त ने मामला जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही है।	संबंधित राज्य सरकारों को चेम्फई, फेंक, गोलपाड़ा और कोलासिब में आकाशवाणी साइट्स तक सड़क मार्ग बनाना होगा। तुइपंग और कोलासिब तक स्थानीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी एचटी लाइन शिफ्ट करना बाकी है जो हमारी जमीन पर है। इससे कार्य में बाधा आ रही है। इस विषय पर काम बाकी है।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	राजस्व		3.00	**0.00**			गोलपारा, कोलासिब और तुइपंग के लिए ठेके दे दिए गए हैं और दापोरिजो, उदयपुर और नूतन बाजार के लिए निविदा पर काम चल रहा है। चंगलंग के लिए अनुमानों को मंजूरी मिल गई है। खोंसा के लिए प्रक्रियाधीन है। चंगलंग में विवाद के कारण काम शुरू नहीं हो पाया। अन्य स्थानों के लिए अनुमानों का इंतजार है। 1 केवी के एफएम ट्रांसमीटर को कोलकाता में प्राप्त कर लिया गया है और राज्य राजधानियों में जांच के लिए भेज दिया गया है।	
					2. सिलचर- 5 केवी के एफएम ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन के लिए निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।	2. सिल्चर 5 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर- क्यू 1- ऑर्डर जारी होने की उम्मीद। क्यू 3- ट्रांसमीटर इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू 4- इंस्टॉलेशन का काम पूरा ।	2. सिलचर- 5 केवी के एफएम ट्रांसमीटर- ट्रांसमीटर का ऑर्डर मंजूरी के लिए प्रक्रियाधीन है। पैनल एंटीना की निविदा टीई के अंतर्गत है।	सिल्चर में ट्रांसमीटर के लिए ऑर्डर रद्द होने के कारण खरीद लंबित हो गई चूंकि कंपनी निरीक्षण के लिए ट्रांसमीटर प्रदान करने में विफल रही। अब 5 केवी एफएम ट्रांसमीटर के साथ इसकी खरीद की जाएगी।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					3. गैंगटॉक- 10 केवी के एफएम ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन का काम करना। डिलिवरी जुलाई 09 तक।	3. गैंगटॉक 10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर- क्यू 2- ट्रांसमीटर की प्राप्ति इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू 4- इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	3. गैंगटॉक- 10 केवी के एफएम ट्रांसमीटर- कानूनी प्रक्रिया के कारण ट्रांसमीटर की खरीद में विलंब हो गया। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायाल में 21.05.09 को निरस्त हो गया। बहरहाल, एल-1 फर्म अपेक्षित फॉरमेट के अनुसार, प्रदर्शन बैंक गारंटी नहीं दे पाई। आगे की कार्रवाई के लिए इस मामले पर काम चल रहा है।	
					4. चिन्सुरा- 1000 केवी एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर का लोक निर्माण पूर्ण, ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन	4. चिन्सुरा 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर- क्यू 1- लोक निर्माण कार्य पूरा और विभागीय काम चालू। क्यू 3- ट्रांसमीटर प्राप्त और इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू 4- ट्रांसमीटर के इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	4. चिन्सुरा- 1000 केवी के मीडियम वेव ट्रांसमीटर- निर्माण कार्य पूरा, भवन के भीतर को छोड़कर, जो औपचारिक एटी देने के बाद शुरू होगी। एडवांस एडी के खिलाफ मामला उच्चतम न्यायालय मे दिया गया था। ट्रांसमीटर की खरीद के लिए औपचारिक एटी देने के साथ नवंबर 2010 तक उसकी डिलिवरी देनी है।	
					5. डीएसएलजी/ एमएसएस टर्मिनल की खरीद व्यावसायिक नीलामी खोली	5. डीएसएनजी/ एमएसएस सिस्टम्स- क्यू 1- डीएसएनजी सिस्टम्स के लिए ऑर्डर और एमएसएस की प्राप्ति। क्यू	5. डीएसएनजी- एमएसएस टर्मिनल- (1) डीएसएनजी निविदा स्वीकृत नहीं हुई और दोबारा मंगाई गई। (2) एमएसएस	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					गई। फर्म के प्रस्ताव की वैधता बढ़ाने से इनकार किया और निविदा दोबारा मंगाई गई। एमएसएस टर्मिनल ऑर्डर रिप्लेस किया।	4- उपकरणों की प्राप्ति और स्थापना।	टर्मिनल के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं लेकिन फर्म द्वारा कोटेशन में दर्ज उपकरणों की मॉडल संख्या में फेरबदल किया गया जो स्वीकार्य नहीं था। ऑर्डर रद्द करने का प्रस्ताव दिया गया।	
					6. 100 दूरदराज के क्षेत्रों में वॉट एफएम स्थापना का कार्य समाप्त। 16 स्थानों पर इंस्टॉलेशन का काम पूरा और 17 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। 24 स्थानों के लिए निविदाएं मंजूर।	6. 100 वॉट एफएम रिले सेंटर्स- क्यू 1- ट्रांसमीटर के इंस्टॉलेशन का काम पूरा होने की उम्मीद।	6. 100 वॉट एफएम रिले सेंटर - 76 सेंटर पर इंस्टॉलेशन पूरा और 12 स्थानों पर प्रक्रियाधीन। बचे हुए 11 स्थानों पर (मिजोरम में 7 और मणिपुर में 4) ट्रांसमीटर लगाने के लिए राज्य सरकारों के साथ निरंतर सहयोग किया जा रहा है।	मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। मिजोरम को स्थान आवंटित करने हैं।
3	एमडब्ल्यू सेवाओं का विस्तार	प्राथमिक कवरेज क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ट्रांसमीटर का आधुनिकीकरण करना	**0.05**	**0.06**	डूंगरपुर के लिए 1 केवी का एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर स्थापित। स्टेशन की कमीशनिंग के लिए ओएंडएम स्टाफ मंजूरी का इंतजार	स्टेशन का परिचालन शुरू होने की संभावना	स्टाफ की मंजूरी की प्रतीक्षा है।	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	एफएम सेवाओं का विस्तार	बेहरतीन गुणवत्ता के कारण लोकप्रिय हुए एमएम कवरेज का विस्तार	42.00	7.22	10 केवी एफएम ट्रांसमीटर प्राप्ति और इंस्टॉलेशन करना, 41 उन्नत एटी के ऑर्डर जारी। जुलाई 09 तक डिलिवरी की उम्मीद।	10 केवी एफएम ट्रांसमीटर (41) क्यू 2- प्राप्ति और इंस्टॉलेशन की शुरुआत। क्यू 4- इंस्टॉलेशन पूरा।	कानूनी प्रक्रिया के कारण ट्रांसमीटर की खरीद में विलंब हो गया। यह मामला दिल्ली उच्च न्यायाल में 21.05.09 को निरस्त हो गया। बहरहाल, एल-१ फर्म अपेक्षित फॉरमेट के अनुसार, प्रदर्शन बैंक गारंटी नहीं दे पाई। आगे की कार्रवाई के लिए इस मामले पर काम चल रहा है।	चालू योजनाओं के लागू होने के बाद एफएम कवरेज बढ़ने की उम्मीद है।
5	निर्माण सेवाओं का डिजिटलीकरण	सामग्री की तकनीकी गुणवत्ता	2.75	1.32	डिजिटल कंसोल खरीद प्रस्ताव की प्रक्रिया चालू है।	डिजिटल कंसोल- क्यू1 - ऑर्डर जारी होने की संभावना। क्यू 3- कुछ कंसोल मिलने की उम्मीद। क्यू 4- बाकी बचे कंसोल के प्राप्त होने की उम्मीद।	डिजिटल डबिंग कंसोल और डिजिटल स्विचिंग कंसोल की खरीद।	डिजिटल कंसोल, डिजिटल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग उपकरणों से कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ेगी।
6	स्टूडियो सुविधाओं और अन्य योजनाओं का स्वचलन		21.80	4.06	सिल्चर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना उपकरणों की खरीद एवं इंस्टॉलेशन	सिल्चर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन- क्यू 1- ऑर्डर दिए जाएंगे। क्यू 3 उपकरण प्राप्त हो जाएंगे और इंस्टॉलेशन शुरू होगा।	सिल्चर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन (अपलिंक)- कोई निविदा तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं की गई। नई निविदा मांगी जाएंगी।	डिजिटल अपलिंक स्टेशन और कंप्यूटरीकृत वर्क स्टेशन कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
						48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसआईटीसी)की खरीद- क्यू 1- ऑर्डर दिए जाएंगे। क्यू 3- कुछ ऑर्डर मिलने की उम्मीद। क्यू 4- बाकी बचे ऑर्डर के प्राप्त होने की उम्मीद। ।	48 स्थानों पर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली (हाई एंड सर्वर वाले एसआईटीसी)- कोई निविदा तकनीकी रूप से स्वीकृत नहीं की गई। संशोधित विनिर्देशों के साथ दोबारा मंगाई जा रही हैं।	
					राजकोट- 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर टावर- लोक निर्माण कार्य पूरा करना। ट्रांसमीटर और वायुरोधी की खरीद करना, नए मास्ट की खरीद के ऑर्डर जारी। डिलिवरी अवधि अक्टूबर 2009 तक।	राजकोट- 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर- क्यू 1- लोक निर्माण कार्य पूरा और विभागीय काम शुरू। क्यू 3- ट्रांसमीटर प्राप्त और इंस्टॉलेशन का काम शूरू। क्यू 4- इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	राजकोट- 1000 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर- ट्रांसमीटर की खरीद और इंस्टॉलेशन का काम पूरा। ट्रांसमीटर के लिए एडवांस एटी दे दी गईं। एडवांस एटी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में। ट्रांसमीटर की खरीद के लिए औपचारिक एटी दे दी गई है जिसकी डिलिवरी नवंबर 2010 तक की जानी है। 156 एम एमडब्ल्यू के मास्ट को लगाने और उसकी मरम्मत का काम पूरा और तीन दूसरे मास्ट को पेंट करने का काम पूरा।	पुराने ट्रांसमीटर को नए डिजिटल ट्रांसमीटर द्वारा बदला जाएगा, जिसकी क्षमता अधिक है

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो- (कार्य का सीमित मौसम)का का कार्य प्रगति पर और अगले कार्य मौसम में समाप्त होने की उम्मीद।	लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो-(कार्य का सीमित मौसम) क्यू 1- इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	लेह और तवांग में स्थायी स्टूडियो- (कार्य का सीमित मौसम)- लेह में इंस्टॉलेशन का काम पूरा और निरीक्षण। तवांग में इंस्टॉलेशन का काम पूरा, सिर्फ हीटिंग प्लांट्स का काम बाकी है जो प्रक्रियाधीन है।	डिजिटल कंसोल, डिजिटल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग उपकरण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाते हैं।
					जयपुर में स्थायी स्टूडियो- उपकरणों को इंस्टॉल करने का कार्य पूरा। भवन कार्य संपन्न	जयपुर में स्थायी स्टूडियो - क्यू 1- इंस्टॉलेशन का काम शुरू। क्यू 4- इंस्टॉलेशन का काम पूरा।	जयपुर में स्थायी स्टूडियो - इंस्टॉलेशन का काम प्रक्रियाधीन।	
					आईएसडीएन कोडेक्स के 66 सेट। खरीद प्रक्रियाधीन।	आईएसडीएन कोडेक्टस (66 सेट) क्यू 2- उपकरणों के मिलने की संभावना।	आईएसडीएन- 66 सेटों की खरीद।	
7	मेट्रो शहरों में स्टाफ क्वार्टर बनाना	प्रसार भारती के स्टाफ के लिए मेट्रो शहरों में स्टाफ क्वार्टर बनाना			दिल्ली चरण 1 निर्माण कार्य पूरा होने के करीब और चरण 2- ठेका दिया गया।	दिल्ली- निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना।	दिल्ली- चरण 1 (323 क्वार्टर) - काम पूरा, सिवाय म्यूनिसिपल सीवरेज और जल आपूर्ति के काम के। चरण 2- (203 क्वार्टर) 128 क्वार्टर के लिए काम प्रक्रियाधीन। 75 (डी टाइप) क्वार्टर के लिए एमसीडी की मंजूरी मिलनी बाकी।	कल्याण गतिविधियां

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					मुंबई- क्वार्टरों का निर्माण। दो प्रखंडों के लिए स्थानीय निकाय से मंजूरी मिली।	मुंबई- क्यू 1- निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद। क्यू 4- काम जारी रहने की उम्मीद।	मुंबई- बीएमसी द्वारा चार प्रखंडों के लिए लागत योजना मंजूर। पाइल फाउंडेशन का काम चालू है।	
					चेन्नई- स्थानीय निकाय से भवन निर्माण योजना को मंजूरी मिलनी बाकी।	चेन्नई-क्यू 1- निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद। क्यू 4- काम जारी रहने की उम्मीद।	चेन्नई- सीएमडीए को भवन निर्माण योजना को मंजूरी देनी बाकी है। सीएमडीए ने अतिरिक्त ढांचे और सुविधा शुल्क की मांग की है जिसे पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि जमीन सरकार की है। मामले पर काम जारी है।	
					कोलकाता- केएमसी द्वारा उत्परिवर्तन की कमी से भवन योजना को स्थानीय निकाय की मंजूरी मिलना बाकी।	कोलकाता- क्यू 1 स्थानीय निकाय द्वारा मंजूरी मिलने की संभावना। क्यू 2- निर्माण का ठेका दिए जाने की उम्मीद।	कोलकाता- केएमसी द्वारा उत्परिवर्तन की कमी से भवन योजना को स्थानीय निकाय की मंजूरी मिलना बाकी और केएमडीए द्वारा एकपक्षीय विदड्रॉअल। कोलकाता उच्च न्यायालय में याचिका दायर।	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	नई योजनाएं		**147.00**	**0.07**				
1	ट्रांसमीटर स्टूडियो, कनेक्टिविटी और डीटीएच चैनल को डिजिटल बनाना	एसडब्ल्यू, डीआरएम ट्रांसमीटर के राष्ट्रीय स्तर के कवरेज को डिजिटल मोड में करना, एफएम विस्तार, स्टूडियो को डिजिटल बनाना और कनेक्टिविटी बढ़ाना	28.00	0.00	पुराने एमडब्ल्यू मोबाइल ट्रांसमीटरोंकी जगह 10 केवी एमडब्ल्यू डीआरएम टर्मिनल (6) बदले जाएंगे। खरीद की जानी है। एनआईटी जारी।	क्यू 1- निविदा खोले और तकनीकी मूल्यांकन के लिए खोले जाने की उम्मीद। क्यू 3- ऑर्डर जारी किए जाने की उम्मीद।	ट्रांसमीटर की डिलिवरी के लिए एडवांस एटी देनी है।	
					सी बैंड टर्मिनल (44) निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है। स्टूडियो के लिए डिजिटल स्टूडियो ट्रांसमीटर कनेक्टिविटी लिंक्स की खरीद- निविदा खोली जाएगी और तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा।	सी बैंड टर्मिनल- क्यू 1- ऑर्डर जारी करने की उम्मीद। क्यू 4- उपकरण मिलने की उम्मीद। क्यू 1- निविदा का तकनीकी मूल्यांकन पूरा होगा। क्यू 2- व्यावसायिक नीलामी खोली जाएगी और खरीद प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। क्यू 4- उपकरण पहुंचने की उम्मीद।	नीलामी खोली गई है और खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	विदेश सेवा को मजबूत करने के लिए उसे डिजिटल बनाना	एसडब्ल्यू का डिजिटलीकरण	3.00	0.00	दिल्ली और अलीगढ़ में 250 केवी एसडब्ल्यू टर्मिनल को डीआरएम मोड में बदलने के लिए उपकरणों की खरीद- मैसेर्स फैलकन को निविदा जारी और कंपनी से कोटेशन प्राप्त।	क्यू 1- उपकरणों के आदेश दिए जाएंगे। क्यू 3- कार्य पूरा होने की उम्मीद।	खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। पीएसी सर्टिफिकेट के लिए एफएसी ने जांच बैठाई है। मंत्रालय से पीएसी सर्टिफिकेट हासिल करना है। अनुमति के लिए प्रस्ताव आंतरिक वित्त विभाग के पास है।	विदेशी सेवा ट्रांसमीटर पर डीआरएम सेवा चुनींदा श्रोताओं को ही उपलब्ध होंगी।
3	ई गर्वनेस, प्रशिक्षण, सुरक्षा अतिरिक्त कार्यालय परिसर, स्टाफ क्वार्टर बनाना	संरचना में सुधार	1.00	0.00	एसएफसी/ईएफसी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।	क्यू 4- श्रीनगर होस्टल आवास का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद।	एसएफसी प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है।	
4	नई तकनीक और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सेटेलाइट और क्षेत्रीय मोड में मल्टीमीडिया प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग और पॉड-कास्टिंग	1.40	0.00	परियोजना चालू। अन्य योजनाओं के लिए एसएफसी/ ईएफसी अनुमति के लिए भेजी गईं।	क्यू 4- वेबकास्टिंग और पॉडकास्टिंग का काम पूरा होने की उम्मीद।	वेबकास्टिंग और पॉडकास्टिंग- एनआईसी द्वारा एसआईटीसी कार्य प्रक्रियाधीन है। एसएंडटी के अंतर्गत अन्य योजनाओं के लिए मंत्रालय की मंजूरी हासिल करनी है। उपकरणों संबंधी विनिर्देश अंतिम रूप में हैं। ए/ए और ई/ एस जारी किए गए हैं।	

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	वर्ष 2009-10 के दौरान व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के अनुसार	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5	जम्मू कश्मीर चरण 3	योजना से जम्मू एवं कश्मीर के सीमांत क्षेत्रों में एफएम और टीवी कवरेज में सुधार	100.00	0.00	पीएमओ के निर्देशानुसार 100 करोड़ के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंत्रालय को भेजा गया है।		ईएफसी प्रस्ताव अनुमति के लिए मंत्रालय के पास भेजे गए हैं। स्थानों की पहचान कर ली गई है और जोनल कार्यालयों को राज्य सरकारों के सहयोग से स्थान चुनने को कहा गया है। उपकरणों संबंधी विनिर्देश अंतिम रूप में हैं।	उच्च पावर वाले तीनों एफएम ट्रांसमीटर पहाड़ों की चोटियों पर लगाए जाएंगे और एक एफएम ट्रांसमीटर मौजूदा डीडी सेंटर में लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त निम्न पावर वाला ट्रांसमीटर बैकवर्ड क्षेत्रों में लगाए जाने का प्रस्ताव है।
6	सॉफ्टवेयर अधिग्रहण		14.00	0.00	पीएमओ के निर्देशानुसार 100 करोड़ के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को पीएमओ को भेजा गया है।			
ग	कुल आकाशवाणी		**261.00**	**19.66**				

आकाशवाणी-वार्षिक योजना (2008-09)

परिणाम बजट के परिणाम/लक्ष्य

(लाख रुपये में)

क्रम	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2008-09	व्यय 2008-09	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	उपलब्धियां (31 मार्च 2009 तक की स्थिति) कॉलम 6 के संदर्भ में	टिप्पणी
			योजना बजट					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ.	चालू योजनाएं							
	पूंजी		111.35	53.00				
	राजस्व		6.83	1.96				
1.	जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज	जम्मू-कश्मीर राज्य में रेडियो कवरेज विस्तार के लिए।			करगिल में होस्टल की मरम्मत तथा छोटे-मोटे कार्यों के अतिरिक्त प्रथम चरण की योजनाएं पूरी हो गई हैं। द्वितीय चरण के तहत जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्टेशन के लिए डीजी सेट तथा यूपीएस की खरीद की मंजूरी मिल गई है।	क्यू 2 - करगिल में होस्टल मरम्मत का कार्य पूर्ण। क्यू 1 - आर्डर के लिए टेंडर दिए जाने की उम्मीद है। क्यू 3 - उपकरणों की आपूर्ति शुरू। क्यू 4 - उपकरण लगाने तथा परीक्षण का कार्य पूर्ण।	करगिल में होस्टेल मरम्मत का कार्य पूर्ण। जम्मू-कश्मीर विशेष योजना के द्वितीय चरण के तहत 62.5 केवीए (6) तथा 15 केवीए (9) की खरीद। 7 यूपीएस के टेंडर का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। 1 एमवीए (3) तथा 500 केवीए डीजी सेट (2) के लिए काम चल रहा है। एसआईटीसी कार्य के लिए टेंडर का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।	जम्मू-कश्मीर के मौजूदा स्टेशन में डीजी सेट तथा यूपीएस के प्रावधान से कैप्टिव विद्युत आपूर्ति ठीक होगी तथा आपातकालीन और प्राकृतिक आपदाओं के समय विद्युत आपूर्ति ठप हो जाने की स्थिति में प्रसारण जारी रहेगा।
	पूंजी		2.41	0.32				
	राजस्व		3.80	1.53				

2.	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज	पूर्वोत्तर में रेडियो कवरेज को बढ़ाना			1. 19 नए एफएम स्टेशन - एफएम ट्रांसमीटर की खरीद तथा स्थान अधिग्रहण	1. 19 नए एफएम स्टेशन - 4 स्थान का अधिग्रहण कर लिया गया है। 5 स्थान राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे, 2 स्थानों के लिए भुगतान कर दिया गया है तथा 3 स्थानों के लिए लागत लेनी है। 5 अन्य स्थानों की पहचान की जानी है। क्यू 1 - एफएम ट्रांसमीटर के लिए आर्डर देने की संभावना है। क्यू 4 - लिए गए स्थानों के लिए सिविल कार्य सौंपने की संभावना।	1. **19 नए एफएम स्टेशन** - चालू वित्त वर्ष के दौरान 6 स्थानों के अधिग्रहण के साथ ही 10 स्थानों का अधिग्रहण कर लिया गया है। 3 स्थानों पर भूमि आकाशवाणी को सौंप दी गई है। एक स्थान के लिए भुगतान कर दिया गया है तथा दूसरे के लिए प्रक्रिया विचाराधीन है। उखरूल के लिए लागत की मांग की गई है। चेरापूंजी, जूनीबोटो तथा अनीनी तीन स्थानों के लिए विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। उदयपुर तथा नूतन बाजार में सुरक्षा बाड़ लगाने का कार्य प्रगति पर है। तुपिंग, कोलाशीव, गोलपाड़ा, खोंनसा, चम्फी, बोमडिला, दापोरजी, लुम्डिंग तथा चांगलांग में सुरक्षा बाड़ लगाने का कार्य प्रगति पर है। कोलाशीव में भवन निर्माण की अनुमानित लागत को मंजूरी दे दी गई है तथा दापोरजी, चांगलांग, गोलपाड़ा, उदयपुर और तुपिंग में यह प्रक्रिया चल रही है। एफ एम ट्रांसमीटर के लिए आर्डर दे दिया गया है। ट्रांसमीटर का डिस्पैच प्रक्रियाधीन है।	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज के द्वितीय चरण के लिए सरकार ने मई 2006 के अंतिम सप्ताह में मंजूरी दे दी थी। इससे इस क्षेत्र में आकाशवाणी कवरेज मजबूत होगा।
	पूंजी राजस्व		36.00 3.03	10.95 0.43	2. सिलचर पांच किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर - ट्रांसमीटर लगाने का सिविल कार्य पूर्ण। पांच किलोवाट के लिए नवंबर 2007 में आर्डर दिया गया है। 3. गंगटोक 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर - सिविल कार्य पूर्ण, ट्रांसमीटरों की खरीद।	2. सिलचर पांच किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर - क्यू 1 सिविल कार्य शुरू। ट्रांसमीटर डिलिवरी की संभावना। क्यू 3 - सिविल कार्य पूर्ण स्थापना का कार्य शुरू। क्यू 4 - स्थापना का कार्य पूर्ण। 3. गंगटोक 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर - सिविल कार्य पूर्ण, ट्रांसमीटरों की खरीद।	2. सिलचर पांच किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर - सिविल कार्य पूर्ण। सिलचर में पांच किलोवाट एफएम स्टेशन का आर्डर रद्द कर दिया गया है क्योंकि फर्म परीक्षण के लिए ट्रांसमीटर पूरा नहीं कर सकी। अब इसे अन्य चार पांच किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के साथ खरीदा जाएगा, जिनके लिए टेंडरों का व्यवसायिक मूल्यांकन किया जा रहा है। 3. गंगटोक 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर - सिविल कार्य पूर्ण, ट्रांसमीटरों की खरीद तथा डिलिवरी आर्डर जुलाई 2009 है।	

					4. चिंसुरा-एक हजार किलोवाट ट्रांसमीटर-सिविल कार्य पूर्ण, ट्रांसमीटरों की खरीद तथा मास्ट की मरम्मत। ट्रांसमीटर खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिलनी है। आर्डर जल्दी ही दिए जाने की संभावना है।	चिंसुरा-एक हजार किलोवाट ट्रांसमीटर - क्यू 1 सिविल कार्य सौंपा गया। क्यू 4 सिविल कार्य पूर्ण तथा ट्रांसमीटर मिला।	चिंसुरा-एक हजार किलोवाट ट्रांसमीटर - सिविल कार्य प्रगति पर है। ट्रांसमीटर का आर्डर दे दिया गया है तथा डिलिवरी अक्टूबर 2009 में मिलने की संभावना है। अभी आर्डर को चुनौती दी गई है तथा मामला न्यायालय में है।	
					5. डीएसएनजी/ एमएसएस टर्मिनल्स - उपकरणों की खरीद। खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।	डीएसएनजी/एमएसएस टर्मिनल्स - क्यू 1 उपकरणों के आर्डर। क्यू 4 उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापना।	5. डीएसएनजी/एमएसएस टर्मिनल्स - डीएसएन जी प्रणाली के व्यवसायिक निविदाएं खोली गई हैं। हालांकि फर्म ने वैलीडेशन ऑफर का विस्तार करने से मना कर दिया अत: नए टेंडर मंगाए गए हैं। एमएसएस टर्मिनल के लिए आर्डर दे दिया है हालांकि फर्म ने उपकरणों के मॉडल नंबर में परिवर्तन की बात कही है जिसे स्वीकार नहीं किया गया है। आर्डर को रद्द करने के लिए कानूनी सेल द्वारा जांच की जा रही है।	
					6. सिल्चर तथा गंगटोक के लिए स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक	6. सिल्चर तथा गंगटोक के लिए स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक - क्यू 1 आर्डर दिए जाने की संभावना है। क्यू 4 उपकरण मिलने की संभावना है।	6. सिल्चर तथा गंगटोक के लिए स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक - टेंडरों का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।	
					7. सौ सुदूरवर्ती स्थानों पर 100 वाट एफएम रिले सेंटर-राज्य सरकार की सहायता से स्थानों की पहचान के काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा ट्रांसमीटर लगाने के लिए आर्डर दे दिए गए हैं।	7. 100 सुदूरवर्ती स्थानों पर 100 वाट एफएम रिले सेंटर आकाशवाणी, दूरदर्शन की मौजूदा 55 साइट पर ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है तथा शेष 45 स्थानों के लिए राज्य सरकार द्वारा उचित स्थान तथा विद्युत आपूर्ति	7. 100 सुदूरवर्ती स्थानों पर 100 वाट एफएम रिले सेंटर- ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए राज्य सरकार उचित स्थान विद्युत आपूर्ति के कार्य को देख रही है। 41 स्थानों पर ट्रांसमीटर लगाने का कार्य पूरा हो गया है तथा 9 स्थानों पर कार्य चल रहा है। 12 स्थानों के लिए टेंडर दिए गए हैं।	

						आदि मुहैया कराई जाएगी। क्यू 1 ट्रांसमीटर की आपूर्ति पूरी हो जाने की संभावना। क्यू 4 कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना।		
3.	मेगावाट सेवाओं का विस्तार	प्राथमिक कवरेज क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए ट्रांसमीटरों का उन्नयन।	0.08	0.53	डूंगरपुर में एक किलोवाट मेगावाट तथा कोटा में 20 किलोवाट मेगावाट ट्रांसमीटर का भुगतान होना है।	डूंगरपुर में एक किलोवाट मेगावाट की स्थापना का कार्य पूरा होने वाला है। कोटा में 20 किलोवाट मेगावाट ट्रांसमीटर का कार्य 2007-08 में शुरू हुआ है।	डूंगरपुर में एक किलोवाट मेगावाट ट्रांसमीटर की स्थापना तथा कार्य प्रदर्शन का परीक्षण चल रहा है। स्टाफ के लिए मंजूरी मिलनी है। कोटा में 20 किलोवाट मेगावाट ट्रांसमीटर का कार्य 2007-08 में शुरू हुआ है।	
4.	एफएम सेवाओं का विस्तार	अच्छी गुणवत्ता के कारण एफएम सेवाओं के कवरेज का विस्तार।	39.03	19.26	36, 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर -10 किलोवाट एफएम के 41 ट्रांसमीटर की खरीद का काम चल रहा है।	36, 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर -क्यू 4 ट्रांसमीटरों की स्थापना तथा प्राप्ति।	36, 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर - आर्डर दे दिया गया है तथा जुलाई 2009 में प्राप्ति की संभावना है।	चालू योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद एफएम कवरेज में वृद्धि की संभावना है।
5.	प्रोडक्शन सुविधाओं का डिजिटलीकरण	कंटेंट की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना	1.30	3.79	डिजिटल कॉन्सोल की खरीद - 74 रिकार्डिंग तथा 91 ट्रांसमीशन कॉन्सोल	डिजिटल कॉन्सोल - क्यू 1 आर्डर देने की संभावना है। क्यू 3 पार्ट डिलिवरी की उम्मीद। क्यू 4 शेष उपकरणों की डिलिवरी।	डिजिटल कॉन्सोल - टेंडरों के तकनीकी मूल्यांकन के बाद कोई भी टेंडर उचित नहीं पाया गया। अत: नए टेंडर मंगाए गए हैं।	डिजिटल कॉन्सोल, डिजिटल अपलिंक, डिजिटल डाउनलिंक जैसे उपकरणों से कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
6.	स्टूडियो सुविधाओं का ऑटोमेशन तथा अन्य योजनाएं		26.02	11.73	1. सिल्चर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन	सिल्चर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन - क्यू 1 आर्डर देने की संभावना है। क्यू 3 उपकरणों की प्राप्ति तथा स्थापना की संभावना।	सिल्चर में कैप्टिव अर्थ स्टेशन - कोई भी टेंडर तकनीकी रूप से उचित नहीं पाया गया। अत: नए टेंडर मंगाए गए हैं।	डिजिटल अपलिंक स्टेशन तथा कंप्यूटरीकृत वर्क स्टेशन से कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

					2. उपकरणों की खरीद – 564 हार्ड डिस्क वर्क स्टेशन के लिए आडियो कार्ड तथा सर्वर, खरीद आदेश जल्दी ही दिया जाएगा।	2. उपकरणों की खरीद – 564 हार्ड डिस्क वर्क स्टेशन के लिए आडियो कार्ड तथा सर्वर। क्यू 2 पार्ट आपूर्ति की संभावना। क्यू 3 शेष आपूर्ति होने की उम्मीद।	2. उपकरणों की खरीद – 564 हार्ड डिस्क वर्क स्टेशन के लिए आडियो पार्ट तथा सर्वर की खरीद।	
					3. 110 सीडी प्लेयर।	3. 110 सीडी प्लेयर – क्यू 2 आर्डर दिए जाएंगे। क्यू 4 डिलिवरी पूरी होने की संभावना।	3. 110 सीडी प्लेयर खरीद। प्रस्ताव फाइनेंस विंग में प्रक्रियाधीन है।	
					4. 255 हाथ से पकड़े जाने वाले रिकार्डर	4. 255 हाथ से पकड़े जाने वाले रिकार्डर – क्यू 2 आर्डर दिए जाएंगे। क्यू 4 डिलिवरी पूरी होने की संभावना।	4. 255 हाथ से पकड़े जाने वाले रिकार्डर – उपकरणों के आर्डर दे दिए गए हैं तथा डिलिवरी 2009–10 की तीसरी तिमाही में होने की उम्मीद है।	
					5. राजकोट में 1000 किलोवाट मेगावाट ट्रांसमीटर – सिविल कार्य तथा ट्रांसमीटर और मास्ट की खरीद का कार्य पूरा हो गया है। नए मास्ट के आर्डर दे दिए गए हैं। डीपी जुलाई 2008 में। तीन मौजूदा मास्ट की मरम्मत के आर्डर दे दिए गए हैं। ट्रांसमीटर के खरीद प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है। आर्डर जल्दी ही दिया जाएगा।	5. राजकोट में 1000 किलोवाट मेगावाट ट्रांसमीटर – क्यू 2 सिविल कार्य पूर्ण। ट्रांसमीटर की आपूर्ति के बाद तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा। नए मास्ट लगाने का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। क्यू 3 – तीन मौजूदा मास्ट की मरम्मत पूरी हो जाने की संभावना। क्यू 4 – ट्रांसमीटर प्राप्ति की संभावना।	5. राजकोट में 1000 किलोवाट मेगावाट ट्रांसमीटर – क्यू 2 ट्रांसमीटर के आर्डर दे दिए गए हैं। डिलिवरी अक्टूबर 2009 में हो जाएगी। ट्रांसमीटर लगाने के बाद तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा। नए मास्ट लगाने तथा तीन मौजूदा मास्ट की मरम्मत चल रही है।	पुराने ट्रांसमीटरों के स्थान पर नए ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे।
					6. लेह तथा तवांग में स्थाई स्टूडियो – (सीमित कार्य अवधि) – तकनीकी क्षेत्र में सिविल कार्य पूर्ण	6. लेह तथा तवांग में स्थाई स्टूडियो – (सीमित कार्य अवधि) – क्यू 1 स्थापना कार्य शुरू। क्यू 3 स्थापना का कार्य पूर्ण।	6. लेह तथा तवांग में स्थाई स्टूडियो – (सीमित कार्य अवधि) – लेह में हीटिंग प्लांट के अतिरिक्त स्थापना का कार्य हो गया है तथा हीटिंग प्लांट का कार्य भी जल्दी।	डिजिटल कॉन्सोल, डिजिटल अपलिंक/ डाउनलिंक जैसे डिजिटल उपकरणों से कार्यक्रम की

					7. जयपुर में स्थाई स्टूडियो - उपकरण लगाने का कार्य पूरा। भवन निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है। 8. आईएसडीएन कोडेक्स - 66 सेट खरीद प्रस्ताव चल रहा है।	7. जयपुर में स्थाई स्टूडियो - क्यू 1 स्थापना का कार्य शुरू, क्यू 4 स्थापना का कार्य पूर्ण। 8. आईएसडीएन कोडेक्स - 66, उपकरण आपूर्ति की संभावना।	ही पूरा हो जाएगा। तवांग में स्थापना का कार्य चल रहा है तथा आगामी कार्य अवधि में पूरा हो जाएगा। 7. जयपुर में स्थाई स्टूडियो - सिविल कार्य में देरी हो रही थी वह अब पूरा होने वाला है। स्थापना का कार्य चल रहा है, यह 2009-10 में पूरा हो जाएगा। 8. आईएसडीएन कोडेक्स - 66, खरीद आदेश जारी। एल/सी शुरू होने के बाद चार माह में आपूर्ति हो जाएगी।	गुणवत्ता में सुधार होगा।
7.	स्टाफ के लिए आवास (मेट्रो शहरों के लिए)	प्रसार भारती स्टाफ के लिए मेट्रो शहरों के लिए आवास योजना।	6.51	6.42	दिल्ली - प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है। मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता - स्थानीय निकाय से अनुमति मिलनी है।	दिल्ली - क्यू 1 प्रथम चरण का कार्य पूरा होने वाला है। मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता - क्यू 1 यदि स्थानीय निकाय की मंजूरी मिल जाती है तो कार्य के लिए टेंडर देने का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।	दिल्ली - विकास कार्य के अलावा प्रथम चरण का पूर्ण। द्वितीय चरण का काम सौंपा। मुंबई - दो ब्लाक के लिए स्थानीय निकाय की मंजूरी मिल गई है। नींव का कार्य चल रहा है। चेन्नई - सीएमडीए ने योजना को मंजूरी के लिए बुनियादी संरचना तथा सुविधा शुल्क के लिए 1.47 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान की मांग की है। चूंकि गुंडी में आकाशवाणी की भूमि सरकारी भूमि है। अत: यह मामला सीएमडीए के साथ उठाया गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में एफ. नं. 212/184/2008 - बी(डी) दिनांक 7-10-2008 द्वारा सीएमडीए को पत्र लिखा है। स्थानीय निकाय से अनुमति का मामला उठाया गया है।	कल्याण गतिविधियां।

							कोलकाता – केएमसी द्वारा भूमि के नामांकन के लिए भवन निर्माण हेतू स्थानीय निकाय की मंजूरी का इंतजार है। यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट में लंबित है। आगामी कार्यवाही कोर्ट के आदेशानुसार की जाएगी।	
बी.	नई योजना							
1.	ट्रांसमीटर, स्टूडियो का डिजिटलीकरण, कनेक्टीविटी तथा डीटीएच चैनल	पूरे देश में डिजिटल क्वालिटी के सिग्नल उपलब्ध कराना। एफएम का विस्तार, स्टूडियो का डिजिटलीकरण तथा कनेक्टीविटी।	63.88	0.00	1. 6, 10 किलोवाट मेगावाट डीआरएम ट्रांसमीटर की खरीद, पुराने मेगावाट मोबाइल ट्रांसमीटर के प्रतिस्थापन को एसएफसी की मंजूरी। एनआईटी के लिए विशिष्टीकरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2. 44 सी-बैंड टर्मिनल।	1. क्यू 3 – टेंडर खोलने तथा तकनीकी मूल्यांकन की संभावना। 2. क्यू 4 – आर्डर की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। 44 सी-बैंड टर्मिनल – क्यू 1 आर्डर देने की संभावना। क्यू 4 उपकरण मिलने की संभावना।	1. टेंडर नवंबर 2008 में खोले गए तथा तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है। 2. 44 सी-बैंड टर्मिनल – मूल्य निविदाएं खोली गईं तथा खरीद प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।	
2.	डिजिटल द्वारा बाह्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।	एसडब्ल्यू ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण	4.74	0.00	250 किलोवाट मेगाबाट ट्रांसमीटरों को बदलने के लिए उपकरणों की खरीद। जिनमें से दिल्ली तथा अलीगढ़ में दो ट्रांसमीटर डीआरएम मोड।	क्यू 1 मूल निर्माता मेसर्स थालेस को टेंडर की जांच दी गई है। क्यू 4 को आर्डर देने की संभावना है।	मूल निर्माता के प्रतिनिधि मेसर्स फेल्कॉन को टेंडर जांच का काम सौंपा गया तथा फर्म से कोटेशन ली गई। आर्डर फाइनेंस विंग में मंजूरी के लिए भेजा गया।	इन बाह्य सेवाओं में डीआरएम सेवा के लिए लक्षित श्रोताओं को ट्रांसमीशन उपलब्ध होगा।
3.	ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण, सुरक्षा, अतिरिक्त कार्यालय स्थान, स्टाफ के लिए आवास आदि।	बुनियादी ढांचे में सुधार।	1.30	0.00	एसएफसी/ईएफसी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।		वेबकास्टिंग तथा पॉडकास्टिंग की योजना पूर्ण।	

4.	नई तकनीकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।	उपग्रह तथा स्थलीय मोड में मल्टीमीडिया ब्राडकास्टिंग, वेबकास्टिंग/पाडकास्टिंग	1.96	1.47	एसएफसी/ईएफसी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।			
5.	साफ्टवेयर अधिग्रहण।		4.94	0.00	प्रसार भारती को ईएफसी प्रस्ताव सौंपे गए।			
	कुल नई योजनाएं पूंजी		**71.88**	**1.47**				
	राजस्व		**4.94**	**0.00**				
स.	**कुल आकाशवाणी**		**195.00**	**56.43**				

प्रसार भारती

दूरदर्शन - वार्षिक योजना (2009-10)

परिणाम तथा परिणाम/लक्ष्य 2009-10

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
	चालू योजनाएं								
1	**जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष पैकेज- चरण 1 और चरण 2 (पूंजी)**	जम्मू कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज प्रसारण में सुधार। अमृतसर में टावर निर्माण के अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर के विशेष पैकेज का पहला चरण कार्यान्वित हो गया है। टावर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण की गुणवत्ता और कवरेज क्षेत्र में सुधार होगा। योजना के दूसरे चरण में कन्टेंट के सुधार पर जोर दिया जाएगा।	5.09	4.14	अमृतसर में 300 मीटर का टावर बनाया गया	सीमापारीय क्षेत्रों में डीडी 1 और डीडी न्यूज चैनल उपलब्ध कराना	अमृतसर में टावर का निर्माण	टावर की लंबाई 120 मीटर तक हो गई है। 282 मीटर तक बनाने के लिए टावर सामग्री साइट पर पहुंच चुकी है।	संस्था द्वारा धीमा काम
					अमृतसर में 300 मीटर ऊंचे टावर पर लगे एंटीना से डीडी 1 और डीडी न्यूज एचटीपी का आरंभ		अमृतसर में एचपीटी कार्य पूरा	भवन निर्माण हो चुका है। एंटीना का ऑर्डर दे दिया गया है। फीडर केबल साइट पर पहुंच चुकी है।	टावर 300 मीटर बनने और एंटीना व फीडर केबल ढोकर ले जाने के बाद इंस्टॉलेशन किया जाएगा, चूंकि मौजूदा ट्रांसमीटर (जो मौजूदा स्टेशन में लगा है) का भी उपयोग करना है।
	राजस्व		**30.00**	**16.70**					

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
2	निर्माण सुविधाओं (स्टूडियो-ओबी) का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण	कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना	20.00	8.96	स्टूडियो केंद्र, केंद्रीकृत रिकॉर्डिंग, संपादन और प्लेबैक का सभी 17 मुख्य दूरदर्शन केंद्रों में आधुनिकीकरण। ओबी सुविधाओं का विस्तार और तेज न्यूज डिलिवरी प्रणाली	स्टूडियो का डिजिटलीकरण	वर्ष 2009-10 में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण योजनाएं पूरी	उपकरणों-विभिन्न उपकरणों की खरीद	
3	पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज, चरण 2 (पूंजी)	पूर्वोत्तर और अंडमान और निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज को मजबूत बनाना। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान निकोबार एवं लक्षदीप के द्वीपीय इलाकों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए सरकार ने मई 2006 में 256.85 करोड़ रुपए (हार्डवेयर-134.3, सॉफ्टवेयर 122.55) की लागत से एक विशेष पैकेज (दूसरे चरण) को मंजूरी दी।	10.95	3.10	कोकराझार में 150 मीटर के टावर का कार्य पूर्ण		टीवी कवरेज	150 मीटर तक टावर बन चुका है।	
					कोकराझार में 150 मीटर के टावर पर लगे एंटीना के साथ 10 केवी के एचटीपी का आरंभ	और तकनीकी गुणवत्ता में सुधार। टीवी सिग्नल प्रदान करना		भवन निर्माण हो चुका है। विभागीय काम हो चुका है। साइट पर एंटीना और फीडर केबल पहुंच चुके हैं। ट्रांसमीटर का ऑर्डर	
					गुवाहाटी- 2 चैनल के अर्थ स्टेशन का आधुनिकीकरण।			गुवाहाटी में अतिरिक्त (2 प्लस 1) अपलिंक चेन का इंस्टॉलेशन हो चुका है।	
					अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के कवरेज के लिए (10 प्लस 1) सी बैंड स्टेशन			अर्थ स्टेशन का इंस्टॉलेशन हो चुका है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए सी बैंड की डीटीएच सेवा पर 17.09. 09 से काम शुरू हो चुका है।	

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
					उत्तर पूर्व के लिए 4 डीएसएनजी यूनिट और अंडमान और निकोबार के लिए 2 डीएसएनजी यूनिट			1 डीएसएनजी यूनिट खरीदी जा चुकी है। एक यूनिट के लिए जनवरी में ऑर्डर दे दिया गया था, पर फर्म इसकी आपूर्ति नहीं कर पाई। 2 डीएसएनजी यूनिट्स का ऑर्डर अगस्त 09 में दे दिया गया था।	
					पोर्ट प्लेयर में डीडी 1 और डीडी न्यूज के लिए एचपीटी का आधुनिकीकरण			मार्च 08 में डीडी 1 और डीडी न्यूज के एचपीटी कमीशन किए गए थे।	
					तीनों वीएलपीटी कमीशन की जा चुकी हैं।			तीनों वीएलपीटी कमीशन की जा चुकी हैं।	अंडमान निकोबार में 37 योजनाएं शुरू की जानी हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान 3 योजनाओं के पूरा होने के साथ, कुल 36 वीएलपीटी योजनाएं पूर्ण और शुरू हो जाएंगी। शेष बची एक योजना के लिए स्थान की समीक्षा की जा रही है।
	राजस्व		**34.00**	**4.68**					

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
4	डीटीएच	इस योजना का उद्देश्य शेष बचे क्षेत्रों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है। डीटीएच की वर्तमान क्षमता 50 टीवी चैनल हैं।	0.00	0.00	कार्य पूर्ण। बचे हुए भुगतान के लिए अनुदान प्रस्तुत।	डीटीएच सुविधा शुरू हो चुकी है			कार्यरत है।
5	एडीटीवी	यह वह तकनीक है जो उत्कृष्ट पिक्चर और वाइट स्क्रीन इमेज के कार्यों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तकनीक से 35 एमएम फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह तकनीक डिजिटल सराउंडिंग साउंड भी उपलब्ध कराती है। एचडीटीवी फिल्म प्रोडक्शन के लिए प्रायोगिक परियोजना का कार्य चालू है।	12.00	7.21	एचडीटीवी प्रोडक्शन के लिए एक फील्ड वैन	प्रायोगिक योजना एचडीटीवी फॉरमेट में निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।	वर्ष 2009-10 में उपकरणों की आपूर्ति और उन्हें लगाना	ईपीएफ वैन खरीदी जा चुकी हैं। एचडीटीवी कैमकॉर्डर और आमंत्रित वीसीआर की खरीद की निविदा निकाली गई है।	
6	दसवीं योजना की अनुमानित योजना		86.75	35.15					
	स्टाफ के लिए आवास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में वृद्धि	स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। बुनियादी ढांचे में वृद्धि- विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा को मजबूत करना।			चार मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए क्वार्टर	चार मेट्रो शहरों और 11 गैर मेट्रो शहरों पर स्टाफ के लिए आवास का निर्माण तथा बुनियादी ढांचे व	पटना, संभलपुर और बैंगलोर में स्टाफ के लिए आवासों का काम 2009-10 में पूरा हो		

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
						सुरक्षा में वृद्धि का कार्य चल रहा है।	जाएगा। चंडीगढ़ में आवास निर्माण का कार्य प्रगति पर है।		
					11 मेट्रो शहरों में स्टाफ के लिए क्वार्टर विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों पर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में वृद्धि			8 स्थानो पर स्टाफ क्वार्टर बनाए जा चुके हैं। बैंगलोर, पटना और संभलपुर में क्वार्टर बनाए जा रहे हैं।	लखनऊ, जयपुर, वाराणसी, भवानीपटना, हिसार, इलाहाबाद, त्रिचूर और इटानगर में स्टाफ क्वार्टर बन गए हैं।
	अन्य योजनाएं								
	स्टूडियो संबंधी योजना	स्टूडियो केंद्रों के निर्माण और उत्पादन सुविधाओं की वृद्धि से स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करना।			7 स्टूडियो की स्थापना	नेटवर्क में शामिल स्टूडियो में निर्माण की गुणवत्ता में सुधार	चंडीगढ़ (अतिरिक्त), जम्मू (अतिरिक्त) और लेह में स्टूडियो परियोजना पूर्ण	चंडीगढ़, लेह, जम्मू में भवन निर्माण का काम पूरा हो गया है। इन स्थानों पर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। देहरादून और तिरुपति में भवन निर्माण का काम चल रहा है।	पणजी और गोरखपुर में स्टूडियो वर्ष 2009-10 से पहले ही बन गए हैं।
	ट्रांसमीटर संबंधी योजना	क्षेत्रीय कवरेज में सुधार			3 ऑटोमोड एलपीटी और एचटीपी	क्षेत्रीय प्रसारण तथा कवरेज क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार	एचपीटी महबूबनगर का कार्य प्रगति पर है। एचपीटी बिलासपुर, कुन्नूर और कुंभकोणम का कार्य प्रगति पर है। एलीपीटी ऑटोमोड की खरीद और इंस्टॉलेशन।	6 एलपीटी के इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो गया है। 35 स्थानों पर काम चल रहा है। 50 एलपीटी खरीदने का काम चल रहा है। एक एचपीटी (सहरसा) कमीशन किया जा चुका है। तीसरी एचपीटी (बिलासपुर) में टावर बनाने का काम चल रहा है और	तकनीकी कारणों से 50 एलपीटी के लिए प्राप्त निविदाओं को रद्द कर दिया गया है। नई निविदाओं पर काम चल रहा है। एचपीटी सहरसा शुरू हो चुका है।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
								ट्रांसमीटर का ऑर्डर दिया जा चुका है। तीसरे स्थान (महबूबनगर) में भवन निर्माण का काम चल रहा है। टावर और ट्रांसमीटर उपकरण के लिए ऑर्डर देने का काम चल रहा है।	
	नई योजना								
1.	ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण, ट्रांसमीटर उपकरणों का संवर्धन और नए उपकरण लगाना		1.00						अनुमति/ अनुसमर्थन जारी करना है।
	क) ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण	क्षेत्रीय प्रसारण का डिजिटलीकरण			40 डीटीटी ट्रांसमीटर के लिए उपकरणों की खरीद (आंशिक परिणाम)	क्षेत्रीय प्रसारण के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होने की संभावना		

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
	ख) ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और दूसरे उपकरण लगाना	ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और तकनीक पुरानी हो जाने और उपकरण के पुराने पड़ जाने के कारण नए उपकरण लगाना।			15 एचटीपी और 60 एलपीटी के स्थान पर ऑटोमोड एलपीटी लगाना (आंशिक परिणाम)	क्षेत्रीय प्रसारण की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होने की संभावना		
	ग) आपदा प्रबंधन, आपातकालीन आवश्यकताएं	आपदा प्रबंधन और आपातकालीन जरूरतें।			आपदा प्रबंधन और आपातकालीन उपकरणों की खरीद (आंशिक परिणाम)	आंशिक परिणाम	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी।		
2.	स्टूडियो डिजिटलीकरण : आधुनिकीकरण, संवर्धन, स्टूडियो-ओबी उपकरणों का प्रतिस्थापन		1.00						अनुमति/ अनुसमर्थन जारी करना है।
	क) स्टूडियो का डिजिटलीकरण	निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, संपादन और अभिलेख सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण			छोटे केंद्रों के 31 स्टूडियो का आंशिक और पूर्ण डिजिटलीकरण और 8 केंद्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण (आंशिक परिणाम)	प्रोडक्शन सुविधा का पूर्ण डिजिटलीकरण (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
	ख) स्टूडियो उपकरणों का डिजिटलीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन	निर्माण संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन, क्योंकि बदलती तकनीक के कारण वे उपकरण पुराने पड़ गए हैं।			सभी छोटे और 66 बड़े केंद्रों पर निर्माण, पोस्ट प्रोडक्शन, ऑडियो लाइटिंग और विद्युत आपूर्ति में वृद्धि (आंशिक परिणाम)	तकनीकी गुणवत्ता में वृद्धि (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		
	ग) ई गवर्नेस, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाएं	नेटवर्क में ई गवर्नेस का समावेश तथा कार्यान्वयन			ई गवर्नेस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य प्रवाह, प्रबंधन प्रणाली और स्टूडियो संचालन (आंशिक परिणाम)	डिलिवरी की प्रभावी प्रणाली (आंशिक परिणाम)	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		
	घ) अनुसंधान और विकास एवं प्रशिक्षण	नेटवर्क में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की वृद्धि			प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं में वृद्धि, एक स्थान पर उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में एसटीआईटी (आंशिक परिणाम)	आंशिक परिणाम	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		
3.	डीटीएच : आधुनिकीकरण, संवर्धन और सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का प्रतिस्थापन		5.00	0.58					

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
	क) डीटीएच	डीटीएच प्लेटफार्म में चैनलों को बढ़ाना			डीटीएट प्लेटफार्म पर चैनलों में वृद्धि	आंशिक परिणाम	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी		योजना को मंजूरी मिलनी बाकी है।
	ख) सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का डिजिटलीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापन	पुराने हो चुके सेटेलाइट उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और नए डिजिटल उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापन, समाचार जुटाने की सुविधा में वृद्धि			अर्थ स्टेशन का उन्नयन, वी सेट की संख्या 10 करना, 50 वी सेट टर्मिनल, 9 नए डीएसएनजी, 6 पुराने डीएसएनजी और अन्य उपकरणों के प्रतिस्थापन के साथ 5 नए अर्थ स्टेशन (आंशिक परिणाम)	प्रगति पर	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी	सीपीसी में 5 चैनल एमसीपीसी के कंप्रेशन उपकरण को बदलने के लिए निविदा मांगी गई हैं। 6 डीएसएनजी वैन के एसआईटीसी के लिए निविदा जारी सीपीसी और डीडीके श्रीनगर में अपलिंक पीडीए के एसआईटीसी के लिए निविदा जारी	अनुमति मिल चुकी है। अनुसमर्थन फरवरी 09 में जारी किया जा चुका है।
4.	एचडीटीवी	एचडीटीवी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रसारण सुविधा	16.00		दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी प्रोडक्शन सुविधा, दिल्ली में प्लेआउट एक्टिविटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए फील्ड प्रोडक्शन सुविधा, दिल्ली, मुंबई में आउटडोर प्रोडक्शन सुविधा के लिए मल्टी मीडिया	प्रगति पर	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी	सीसीईए द्वारा योजना स्वीकृत। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए एचडीटीवी ट्रांसमीटर के लिए एनआईटी जारी	अनुमति मिल चुकी है। अनुसमर्थन अगस्त 09 में जारी किया जा चुका है।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
					कैमरा मोबाइल उपकरण, दिल्ली में फ्लाईअवे प्रोडक्शन सेट अप, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए परव्यू सुविधा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में एचडीटीवी ट्रांसमीटर, एचडीटीवी अपलिंक				
5.	स्टाफ के लिए आवास, अन्य कार्य	स्टाफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि और सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढीकरण	5.00		17 स्थानों पर डीएमसी बिल्डिंग, 10 स्थानों पर एलपीटी, 7 स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर, 22 स्थानों पर गेस्ट हाउस, गुवाहाटी में जोनल ऑफिस बिल्डिंग, डीडी भवन में टावर सी तथा अन्य बुनियादी ढांचे और सुरक्षा संबंधित कार्य	प्रगति पर	11 वीं योजना में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी	सभी भवनों के लिए स्थान तय। एलपीटी भवनों, डीएमसी बिल्डिंग, गेस्ट हाउस और सामुदायिक केंद्रों के लिए टाइप डिजाइन। भवन योजना और योजना अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। टावर सी के लिए योजना अनुमान मंजूरी की प्रक्रिया में हैं।	अनुमति मिल चुकी है। अनुसमर्थन मार्च 09 में जारी किया जा चुका है।

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2009-10 योजना बजट	व्यय (दिसंबर 09 तक)	विवरण योग्य परिणाम/भौतिक परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता		उपलब्धियां (31.12.09 तक) कालम 6 के संदर्भ में	टिप्पणियां/जोखिम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
6.	**सॉफ्टवेयर अधिग्रहण**		**24.21**						
	कुल दूरदर्शन		**251.00**	**80.52**					
	राष्ट्रमंडल खेल	**प्रसार भारती**	**134.00**	**0.71**					
		आईटीपीओ	**11.00**						
		कुल	**145.00**	**0.71**					

दूरदर्शन - वार्षिक योजना (2008-09)

परिणाम बजट के परिणाम/लक्ष्य

(रुपये करोड़ में)

क्रम	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2008-09	व्यय 2008-09	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.09 तक उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	दूरदर्शन								
	चालू योजना								
1.	जम्मू-कश्मीर विशेष योजना प्रथम तथा द्वितीय चरण (पूंजी)	जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन कवरेज प्रसारण में सुधार। अमृतसर में टावर निर्माण के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज का पहला चरण कार्यान्वित हो गया है। अमृतसर में टावर, निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन प्रसारण की गुणवत्ता तथा कवरेज एरिया में सुधार होगा। योजना के द्वितीय चरण में कंटेट सुधार पर जोर दिया गया है। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर, लेह तथा जम्मू की क्षेत्रीय सेवाओं तथा कशीर चैनल पर 24 घंटे के लिए कार्यक्रमों का निर्माण	15.99	17.45	जम्मू में अर्थ स्टेशन का उन्नयन। एचपीटी तथा एल पी टी के लिए 40 यूपीएस, जम्मू-कश्मीर के लिए दस हजार टीवी तथा डीटीएच सेट, अमृतसर में 300 मीटर का टावर जिस पर 300 मीटर का एंटिना लगाया जाएगा	सीमापारीय क्षेत्रों में टीवी कवरेज में वृद्धि। चैनल पर बेहतर तथा नवीन साफ्टवेयर की संख्या में वृद्धि	अमृतसर में एचपीटी या अंतरिम सेटअप पुराने स्थान पर संचालित है। स्थायी सेटअप के भवन के लिए नया स्थान पूरा। 300 एम टावर की नींव का कार्य पूर्ण तथा 40 मीटर का एंटिना लगाने का कार्य प्रगति पर। अंतरिम सेटअप में उपलब्ध उपकरणों की सहायता से अर्थ स्टेशन का उन्नयन। स्थायी सेटअप के लिए टेंडरों का तकनीकी मूल्यांकन, व्यावसायिक टेंडर खोले गए तथा कार्य प्रगति पर है। 39 यूपीएस के खरीद आदेश दिए गए (16 प्राप्त)। एक यूपीएस के आर्डर का काम प्रगति पर। जम्मू-कश्मीर सरकार के नोडल अधिकारी को दस हजार टीवी तथा डीटीएच सेट सौंपे गए। आवंटन के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयुक्त होगा।	जम्मू कश्मीर सरकार के नोडल कार्यालयों तक 10000 डीटीएच और टीवी सेटों का हस्तांतरण	शून्य
	जम्मू-कश्मीर विशेष पैकेज (राजस्व)		20.00	30.31	1904 एपिसोड के कार्यक्रमों का निर्माण				

2.	निर्माण सुविधाओं (स्टूडियो/ओबी) का आधुनिकीकरण तथा डिजिटलीकरण	कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता बढ़ाना	40.81	33.08	सभी मुख्य दूरदर्शन केंद्रों में स्टूडियो का आधुनिकीकरण, केंद्रिकृत रिकार्डिंग, संपादन तथा प्लेबैक, ओबी सुविधा में वृद्धि तथा समाचारों के लिए त्वरित प्रसारण प्रणाली		उपकरणों को हासिल करने का कार्य प्रगति पर है।
3.	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज द्वितीय चरण (पूंजी)	पूर्वोत्तर तथा अंडमान निकोबार क्षेत्र में दूरदर्शन कवरेज का सुदृढ़िकरण। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के द्विपीय इलाकों में दूरदर्शन सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए सरकार ने मई 2006 में 256.85 करोड़ रुपये (हार्डवेयर-134.3 करोड़, सॉफ्टवेयर-122.55 करोड़) की लागत से एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर केंद्रों तथा 24 घंटे के पूर्वोत्तर चैनल के लिए कार्यक्रमों का निर्माण।	15.00	16.15	1. 14 नए वीएलपीटी 2. 10 वीएलपीटी का उन्नयन 3. 2 नार्थ ईस्ट चैनल के लिए अर्थ स्टेशन का उन्नयन 4. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डीटीएच सेवा के लिए 10 चैनल अपलिंक (सी बैंड) 6742 ऐपीसोड के कार्यक्रमों का निर्माण।	दो ट्रांसमीटरों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। एक वीएलपीटी की वैकल्पिक साइट को अंतिम रूप दिया जाना है। एक ट्रांसमीटर के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। अर्थ स्टेशन (दो पूर्वोत्तर चैनलों के लिए उन्नयन) के लिए आर्डर दे दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप में डीटीएच सेवा के लिए 10 चैनल अपलिंक (सी-बैंड) लगा दिए गए हैं। उपलब्धियां-वीएलपीटी (नया) 11. उपलब्धियां वीएलपीटी (अपग्रेड)-9 आवंटन के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयुक्त किया जाएगा।	
	पूर्वोत्तर विशेष पैकेज (राजस्व)		13.53	30.32			

4.	डीटीएच	इस योजना का उद्देश्य शेष बचे क्षेत्रों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है। डीटीएच की वर्तमान क्षमता 50 टीवी चैनल है।	0.00	6.16	कार्य पूर्ण	राज्य सरकार द्वारा निशुल्क नोडल अधिकारियों को 20000 डीटीएच सेट दे दिए गए हैं।	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को 20000 डीटीएच सेट दे दिए गए हैं।
5.	एचडीटीवी	यह ऐसी तकनीक है जो उत्कृष्ट पिक्चर तथा वाइड स्क्रीन के अर्थों में अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस तकनीक से 35 मिमी. फिल्म जैसी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यह तकनीक डिजिटल सराउंडिंग साउंड भी उपलब्ध कराती है। एचडीटीवी फील्ड प्रोडक्शन के लिए प्रायोगिक परियोजना का कार्य चालू है।	0.71	0.00	एचडीटीवी प्रोडक्शन के लिए एक फील्ड वैन	एचडीटीवी ओबी वैन के लिए आर्डर दे दिया गया है।	
6.	10वीं योजना की अनुमोदित योजना		48.80	84.03			
	अ) स्टाफ के लिए आवास, बुनियादी ढांचे तथा सुरक्षा में वृद्धि	स्टॉफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान, बुनियादी ढांचे में वृद्धि/विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा को मजबूत करना।			दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में स्टॉफ के लिए आवासों का निर्माण। 11 गैर मेट्रो स्थानों पर स्टॉफ के लिए आवासों का निर्माण। विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों पर बुनियादी ढांचे तथा सुरक्षा में वृद्धि-आंशिक परिणाम।	स्टॉफ के आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर।	
	ब) अन्य योजनाएं						

	i) स्टूडियो संबंधी योजना	स्टूडियो केंद्रों के निर्माण तथा प्रोडक्शन सुविधाओं की वृद्धि से स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध कराना।			7 स्टूडियो की स्थापना-आंशिक परिणाम	पणजी में परियोजना पूरी हो गई है तथा शुरू हो गई है। जम्मू में भवन निर्माण कार्य पूरा हो गया है। एक अतिरिक्त स्टूडियो।		
	ii) ट्रांसमीटर संबंधी योजना	स्थलीय कवरेज में सुधार			आटोमोड एलपीटी तथा एचपीटी (आंशिक परिणाम)	छतरपुर में कार्य पूर्ण। वड़ोदरा तथा खड़गपुर में स्थाई एचपीटी सेटअप शुरू। सहरसा में टावर खड़ी कर दी गई है। तीन अन्य स्थानों, कुंभकोणम, कुन्नूर तथा बाड़मेर में टावर का कार्य प्रगति पर है। चेन्नई में डीडी 1 एचपीटी कार्य पूर्ण। शेष 42 एलपीटी (यूएचएफ) को लगाने तथा आपूर्ति का कार्य गति पर है। 50 एलपीटी के लिए आर्डर दे दिया गया है। 8 एलपीटी आटोमोड प्राप्त।		
	iii) उपग्रह संबंधी योजनाएं	सिग्नल की गुणवत्ता में वृद्धि तथा अंतरिक्ष घटक क्षमता में बचत। समाचार जुटाने की क्षमता में वृद्धि			चार डीएसएनजी की आपूर्ति। वी-सेट प्रणाली की आपूर्ति। विविध अर्थ स्टेशन उपकरणों की आपूर्ति - आंशिक परिणाम।			
	नई योजना							
	ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण, आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा ट्रांसमीटर उपकरणों का प्रतिस्थापन		24.44	0.00				
	अ) ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण	स्थलीय ट्रांसमीशन का डिजिटलीकरण			डीटीटी के लिए उपकरणों की खरीद-आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		योजना को मंजूरी मिलनी है।

	ब) ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन	ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण तथा वृद्धि तथा तकनीकी पुरानी पड़ जाने और उपकरण पुराने हो जाने के कारण उनका प्रतिस्थापन।			आटोमोड एलपीटी द्वारा 10 एचपीटी तथा 60 एलपीटी का प्रतिस्थापन, सीमावर्ती तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर 5 नये एनालॉग ट्रांसमीटर लगाना – आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		योजना को मंजूरी मिलनी है।
	स) आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन आवश्यकताएं	आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन आवश्यकताएं			योजना बनाई जानी है।	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		योजना को मंजूरी मिलनी है।
	स्टूडियो डिजिटलीकरण: आधुनिकीकरण, वृद्धि, स्टूडियो/ओबी उपकरणों का प्रतिस्थापन		24.16	0.00				
	अ) स्टूडियो का डिजिटलीकरण	प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, संपादन तथा अभिलेखागार सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण			छोटे केंद्रों पर आंशिक से लेकर पूर्ण डिजिटलीकरण तथा 8 केंद्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण – आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		योजना को मंजूरी मिलनी है।

	ब) डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा स्टूडियो उपकरणों का प्रतिस्थापन	निर्माण संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा तकनीकी आवश्यकता और पुराने पड़ जाने के कारण उनका प्रतिस्थापन।			5 स्थानों पर नए स्टूडियो सहित 66 स्थानों पर छोटे तथा सभी बड़े केंद्रों पर प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ऑडियो लाइटिंग तथा विद्युत आपूर्ति में वृद्धि-आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		योजना को मंजूरी मिलनी है।
	स) ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाएं	नेटवर्क में ई-गवर्नेंस का समावेश			ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्य प्रवाह, प्रबंधन प्रणाली तथा स्टूडियो संचालन -आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		योजना को मंजूरी मिलनी है।
	द) अनुसंधान एवं विकास तथा प्रशिक्षण	नेटवर्क में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की वृद्धि			प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं में वृद्धि, एक स्थान पर उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में एसटीआईटी-आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		योजना को मंजूरी मिलनी है।
3.	डीटीएच: आधुनिकीकरण, वृद्धि, उपग्रह प्रसारण उपकरणों का प्रतिस्थापन		14.26	4.17				

	अ) डीटीएच	हाईब्रिड मॉडल के साथ डीटीएच पर चैनलों की संख्या 50 से बढ़ाकर 198 करना (फ्री टू एयर चैनल तथा पेड चैनल)		4.17	144 पे चैनल तथा 50 एफटीए चैनल का हाइब्रिड मॉडल, पीपीपी मॉडल सहित 4 एचडीटीवी चैनल तथा 50 रेडियो चैनल - आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		योजना को मंजूरी मिलनी है।
	ब) उपग्रह प्रसारण उपकरणों का डिजिटलीकरण, वृद्धि तथा प्रतिस्थापन	पुराने हो चुके उपग्रह उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि तथा नए डिजिटल उपकरणों द्वारा उनका प्रतिस्थापन। समाचार जुटाने की सुविधा में वृद्धि।			10 अर्थ स्टेशनों का उन्नयन, वी-सेट हब का विस्तार, 50 वी-सेट टर्मिनल, 9 नए डीएसएनजी। 6 पुराने डीएसएनजी के प्रतिस्थापन सहित 5 नए अर्थ स्टेशन। अन्य विविध उपकरण - आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		संस्तुति दे दी गई है।
4.	एचडीटीवी	एचडीटीवी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा तथा प्रसारण।	9.51	0.00	दो स्थानों पर एचडीटीवी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन तथा फील्ड प्रोडक्शन की सुविधा, 4 स्थानों पर एचडीटीवी ट्रांसमीटर तथा एक मेट्रो सेंटर पर एचडीटीवी अपलिंक सुविधा - आंशिक परिणाम	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		ईएफसी पूर्ण।

5.	स्टॉफ के लिए आवास, अन्य कार्य	स्टॉफ के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे में वृद्धि तथा सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण	0.43	0.00	17 स्थानों पर डीएमसी भवन, 14 स्थानों पर एलपीटी भवन, 14 स्थानों पर स्टॉफ के लिए आवास, 34 स्थानों पर अतिथिगृह, गुवाहाटी में मंडलीय कार्यालय भवन तथा दूरदर्शन भवन में टावर सी तथा सुरक्षा एवं बुनियादी ढांचे संबंधी अन्य कार्य।	11वीं योजना में चरणबद्ध ढंग से पूर्ण		मंजूरी दे दी गई है।
	मध्यस्थता शुल्क			0.10				
	सॉफ्टवेयर		52.30	0.00				
	दूरदर्शन का योग (पूंजी)		194.17	161.14				
	कुल राजस्व		85.85	60.63				
	सकल योग (पूंजी+राजस्व)		280.00	221.77				
	राष्ट्रमंडल खेल (राजस्व)		97.71	7.85				

अध्याय-5

वित्तीय समीक्षा

2007-2008

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008			वास्तविक 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	33600	187570	221170	25900	204900	230800	17980	194920	212900
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	15000	29700	44700	6100	34970	41070	3015	32682	35697
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1200	1200	0	1200	1200	0	818	818
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**15000**	**30900**	**45900**	**6100**	**36170**	**42270**	**3015**	**33500**	**36515**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	46200	235260	281460	51300	265100	316400	67710	258706	326416
5. फिल्म समारोह निदेशालय	38200	49320	87520	32200	65565	97765	22105	52204	74309
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	10100	14940	25040	10100	16405	26505	8992	15692	24684
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहायता	77700	50735	128435	37700	60030	97730	37700	60030	97730
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	27100	4200	31300	27100	8400	35500	26398	8400	34798
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	62100	70515	132615	62100	82500	144600	61282	82500	143782
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	29000	30000	59000	0	30000	30000	0	0	0
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	200	10395	10595	1960	12800	14760	1494	12819	14313
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	1000	39500	40500	100	45000	45100	0	44982	44982
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	234100	613925	848025	158119	343330	501449	182635	326356	508991
15. पत्र सूचना कार्यालय	1210	227015	228225	86000	223700	309700	84378	208447	292825
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	23700	23700	0	25500	25500	0	23682	23682

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008			वास्तविक 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	200	200	0	0	0
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	100	259910	260010	1000	261700	262700	753	239910	240663
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	35600	145415	181015	35600	151200	186800	39583	148655	188238
22. प्रकाशन विभाग	400	134720	135120	8120	143200	151320	6721	142444	149165
23. रोजगार समाचार	100	281700	281800	700	236700	237400	246	235329	235575
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	200	24770	24970	588	22400	22988	459	21894	22353
25. फोटो प्रभाग	200	23310	23510	5500	23200	28700	4800	21975	26775
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1400	1400	0	1400	1400	0	1195	1195
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	1291	1291
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**563510**	**2242830**	**2806340**	**518187**	**2020330**	**2538517**	**545256**	**1906511**	**2451767**
कुल प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**612110**	**2461300**	**3073410**	**550187**	**2261400**	**2811587**	**566251**	**2134931**	**2701182**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008			वास्तविक 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
सहायता अनुदान	1031300	9607600	10638900	1031300	9839100	10870400	1191300	9741400	10932700
कुल-प्रसारण	**1031500**	**9607800**	**10639300**	**1031500**	**9839300**	**10870800**	**1191300**	**9741400**	**10932700**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	205190	0	205190	190190	0	190190	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**1848800**	**12069100**	**13917900**	**1771877**	**12100700**	**13872577**	**1757551**	**11876331**	**13633882**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008			वास्तविक 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	1100	0	1100	3434	0	3434	3295	0	3295
4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	400	0	400	400	0	400	317	0	317
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0		0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5100	0	5100	5100	0	5100	1692	0	1692
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	100	0	100	100	0	100	0	0	0
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	0	0	0	28000	0	28000	28000	0	28000
बी- भवन									
13. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग) - प्रमुख कार्य	50000	0	50000	10100	0	10100	10100	0	10100
15. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रमुख कार्य	34000	0	34000	34000	0	34000	33985	0	33985
18. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	19389	0	19389	19389	0	19389
20. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2007-2008			संशोधित अनुमान 2007-2008			वास्तविक 2007-2008		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
21. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	100000	0	100000	8200	0	8200	8199	0	8199
22. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
25. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	100	0	100	0	0	0	0	0	0
26. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
निवेश									
इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**220800**	**0**	**220800**	**119723**	**0**	**119723**	**115977**	**0**	**115977**
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	31000	0	31000	1000	0	1000	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम राशि	2174400	0	2174400	1667400	0	1667400	2107400	0	2107400
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)									
एकमुश्त प्रावधान	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 6552)									
एकमुश्त प्रावधान	**475000**	**0**	**475000**	**440000**	**0**	**440000**	**0**	**0**	**0**
कुल - पूंजी खंड	**2901200**	**0**	**2901200**	**2228123**	**0**	**2228123**	**2223377**	**0**	**2223377**
कुल - मांग संख्या - 58	**4750000**	**12069100**	**16819100**	**4000000**	**12100700**	**16100700**	**3980928**	**11876331**	**15857259**

वित्तीय समीक्षा
2008-2009

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	115700	213500	329200	100800	290750	391550	91514	283754	375268
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	14200	31200	45400	5500	46600	5100	5977	45344	51321
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1200	1200	0	1500	1500	0	1381	1381
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**14200**	**32400**	**46600**	**5500**	**48100**	**53600**	**5977**	**46725**	**52702**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	110000	249700	359700	110000	302150	412150	59488	304765	364253
5. फिल्म समारोह निदेशालय	40000	65765	105765	40000	65445	105445	32119	69929	102048
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	30000	16400	46400	30000	22450	52450	17623	24372	41995
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहायता	80000	50735	130735	80000	52580	132580	40000	52100	92100
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	40000	8400	48400	40000	9700	49700	40000	9700	49700
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	80000	77500	157500	56900	93267	150167	54400	93267	147667
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	0	30000	30000	0	30000	30000	0	6240	6240
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	10000	12800	22800	2300	16256	18556	1483	16498	17981
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	10000	39500	49500	100	47994	48094	0	46030	46030
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	217600	526000	743600	481800	533100	1014900	481734	707470	1189204
15. पत्र सूचना कार्यालय	109089	223600	332689	109089	296226	405315	101776	293376	395152
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	26300	26300	0	31604	31604	0	31604	31604
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	200	200	0	100	100	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	4900	262500	267400	4900	331428	336328	4129	323987	328116
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	35600	155400	191000	35600	193850	229450	32867	186271	219138
22. प्रकाशन विभाग	4300	140500	144800	4300	198630	202930	4086	192676	196762
23. रोजगार समाचार	600	281900	282500	600	255715	256315	519	242006	242525
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2000	23400	25400	1500	28900	30400	1469	29278	30747
25. फोटो प्रभाग	5500	24300	29800	5500	27630	33130	5028	28381	33409
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1400	1400	0	1400	1400	0	1550	1550
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	1560	1560
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**779589**	**2218300**	**2997889**	**1002589**	**2540425**	**3543014**	**876721**	**2661060**	**3537781**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**909489**	**2464200**	**3373689**	**1108889**	**2879275**	**3988164**	**974212**	**2991539**	**3965751**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
अनुदान सहायता	1787371	9636300	11423671	1325471	11371225	12696696	759600	11429800	12189400
कुल-प्रसारण	**1787571**	**9636500**	**11424071**	**1325671**	**11371425**	**12697096**	**759600**	**11429800**	**12189400**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	179640	0	179640	336040	0	336040	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**2876700**	**12100700**	**14977400**	**2770600**	**14250700**	**17021300**	**1733812**	**14421339**	**16155151**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	15100	0	15100	15100	0	15100	13948	0	13948
4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	400	0	400	400	0	400	204	0	204
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0		0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5800	0	5800	4000	0	4000	1610	0	1610
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	3000	0	3000	100	0	100	0	0	0
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण	71000	0	71000	71000	0	71000	55000	0	55000
13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. रोज़गार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी- भवन									
15. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	50000	0	50000	2000	0	2000	1752	0	1752
17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रमुख कार्य	40000	0	40000	40000	0	40000	39805	0	39805
20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	35300	0	35300	35300	0	35300	17620	0	17620
22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2008-2009			संशोधित अनुमान 2008-2009			वास्तविक 2008-2009		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	43700	0	43700	43700	0	43700	0	0	0
24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	1000	0	1000	1000	0	1000	1000	0	1000
27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0
निवेश									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	80000	0	80000	100	0	100	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**349300**	**0**	**349300**	**216700**	**0**	**216700**	**130939**	**0**	**130939**
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम राशि	3264000	0	3264000	2616600	0	2616600	2383100	0	2383100
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)									
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 6552)									
प्रसार भारती	510000	0	510000	396100	0	396100	0	0	0
कुल - पूंजी खंड	**4123300**	**0**	**4123300**	**3229400**	**0**	**3229400**	**2514039**	**0**	**2514039**
कुल - मांग संख्या - 59	**7000000**	**12100700**	**19100700**	**6000000**	**14250700**	**20250700**	**4247851**	**14421339**	**18669190**

वित्तीय समीक्षा
2009-2010

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2009-2010			संशोधित अनुमान 2009-2010		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड						
प्रमुख शीर्ष '2251'-सचिवालय सामाजिक सेवाएं						
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	135000	394900	529900	130400	380100	510500
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन						
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	13500	56000	69500	7000	55300	62300
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	2000	2000	0	2000	2000
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**13500**	**58000**	**71500**	**7000**	**57300**	**64300**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार						
4. फिल्म प्रभाग	63000	378900	441900	68000	360600	428600
5. फिल्म समारोह निदेशालय	42700	75700	118400	42700	97200	139900
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	40000	25200	65200	70000	31000	
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को अनुदान सहायता	70000	60000	130000	70000	60000	130000
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	40000	11200	51200	40000	17500	
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	60000	95000	155000	95000	129400	224400
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	0	48000	48000		28700	28700
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	11800	20000	31800	3000	19700	22700
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	7000	50000	57000	7000	78500	85500
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	268800	648700	917500	368800	670000	1038800
15. पत्र सूचना कार्यालय	190300	342200	532500	190300	372600	562900
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	35000	35000	0	45600	45600
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100

वित्तीय समीक्षा
2009-2010

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2009-2010			संशोधित अनुमान 2009-2010		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	4900	412700	417600	4900	406600	411500
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	40000	200200	240200	40000	222500	262500
22. प्रकाशन विभाग	1900	241400	243300	1900	246900	248800
23. रोजगार समाचार	500	285900	286400	500	231900	232400
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	1700	39100	40800	1700	38600	40300
25. फोटो प्रभाग	7000	33500	40500	21000	38000	59000
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1400	1400	0	1500	1500
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**849600**	**3006200**	**3855800**	**1024800**	**3098900**	**4123700**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**998100**	**3459100**	**4457200**	**1162200**	**3536300**	**4698500**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2009-2010			संशोधित अनुमान 2009-2010		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)						
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)						
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)						
वेतन	100	100	200	100	100	200
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)						
वेतन	100	100	200	100	100	200
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)						
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)						
अनुदान सहायता	2131900	14221400	16353300	1754600	12464200	14218800
कुल प्रसारण	**2132100**	**14221600**	**16353700**	**1754800**	**12464400**	**14219200**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना						
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	389700	0	389700	249700	0	249700
कुल-राजस्व खंड	**3519900**	**17680700**	**21200600**	**3166700**	**16000700**	**19167400**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2009-2010			संशोधित अनुमान 2009-2010		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
पूंजी खंड						
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	8500	0	8500	8500	0	8500
4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	500	0	500	500	0	500
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	10000	0	10000
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0
10. केन्द्रीय फिल्म निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	5000	0	5000	5000	0	5000
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	100	0	100	100	0	100
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - मशीनरी तथा उपकरण	18000	0	18000	18000	0	18000
13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	1000	0	1000	1000	0	1000
14. रोजगार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण	100	0	100	100	0	100
बी —भवन						
15. फिल्म प्रभाग हेतु बहुमंजिला भवन-प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0
16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग) - प्रमुख कार्य	125000	0	125000	125000	0	125000
17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई) निर्माण	0	0	0	0	0	0
18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0
19. फिल्म समारोह परिसर-अतिरिक्त और वैकल्पिक-प्रमुख कार्य	39000	0	39000	39000	0	39000
20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0
21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	100000	0	100000	1000000	0	100000
22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2009-2010			संशोधित अनुमान 2009-2010		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	50000	0	50000	40000	0	40000
24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0
25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना	20000	0	20000	20000	0	20000
26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	32000	0	32000	32000	0	32000
27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0
28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	2000	0	2000	2000	0	2000
निवेश						
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	100	0	100	100	0	100
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**411300**	**0**	**411300**	**401300**	**0**	**401300**
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष-6220)						
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)						
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण						
(लघु शीर्ष)						
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम						
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)						
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण						
प्रसार भारती						
ऋण और अग्रिम राशि	3558400	0	3558400	1302100	0	1302100
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत						
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)						
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण	900	0	900	900	0	900
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत						
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 6552)						
प्रसार भारती	509500	0	509500	199000	0	199000
कुल - पूंजी खंड	**4480100**	**0**	**4480100**	**1903300**	**0**	**1903300**
कुल-मांग संख्या-59	**8000000**	**17680700**	**25680700**	**5070000**	**16000700**	**21070700**

वित्तीय समीक्षा
विषय-शीर्षानुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2007-2008		संशोधित अनुमान 2007-2008		वास्तविक 2007-2008		बजट अनुमान 2008-2009		संशोधित अनुमान 2008-2009		वास्तविक 2008-2009		बजट अनुमान 2009-2010		संशोधित अनुमान 2009-2010		बजट अनुमान 2010-2011	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
राजस्व खंड																		
वेतन																		
स्वीकृत	1850	966179	470	965531	247	927023	1200	977181	700	1423481	0	1403351	3450	1798750	700	1841720	3200	1681960
भारित	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मजदूरी	0	7185	0	27043	50	5784	384	26529	0	26419	0	8168	340	36210	340	20312	300	5590
समयोपरि भत्ता	300	8230	100	8411	50	7601	20	8406	0	7588	0	6770	70	8565	101	7503	300	8575
चिकित्सा व्यय	150	28575	5	27943	0	19956	300	27160	0	25549	0	19664	300	29495	1	28690	20	29565
घरेलू यात्रा व्यय	5520	43260	4345	45868	3609	41532	5699	47238	2699	43411	1688	40863	6500	48980	5300	47150	6300	48550
विदेशी यात्रा व्यय	3400	5250	3200	7250	2118	5129	3950	8000	3950	7200	178	7017	10200	7550	10300	6795	7600	7950
कार्यालय व्यय	8970	140880	26523	171463	25673	160307	59476	172908	42680	170723	38015	171177	59840	192240	60658	190765	52380	197370
किराया, महसूल और कर																		
स्वीकृत	1600	35191	1600	34791	1435	24327	1600	35933	1600	29838	1059	26487	1600	30830	400	35215	0	39740
भारित	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	300
प्रकाशन	0	28900	0	39650	0	38929	0	34450	0	41105	0	41225	0	36750	0	43835	0	39420
बैंकिंग नकदी लेन-देन कर	0	440	0	213	0	105	0	160	0	20	0	56	0	10	0	0	0	10
अन्य प्रशासनिक व्यय	1790	8850	3930	11992	2901	12431	21860	12340	21860	11796	14063	10744	114700	15170	115900	15640	232500	16225
आपूर्ति एवं सामग्री	7245	254300	9345	213700	7610	219301	11900	259060	11900	233214	5497	223749	12600	261400	12600	216400	35100	261400
पी.ओ.एल.	400	16300	600	17040	749	15196	0	17840	0	16060	0	14956	900	18455	1000	16735	0	18455
विज्ञापन और प्रचार	235070	553100	238779	278600	261791	277652	277300	462800	551500	421515	554674	596583	336450	497520	436600	497065	560000	497570
लघु कार्य	0	49500	0	55012	0	47252	0	52312	0	59927	0	64928	0	74190	0	75440	0	81390
व्यावसायिक सेवाएं	35600	40460	24925	47795	28778	47543	117800	47225	101100	51980	100243	50758	128300	56330	123000	50110	161200	80850
सहायता अनुदान	1199200	9796790	1158300	10061060	1316680	9961359	1997371	9839265	1502471	11606875	894000	11662866	2308900	14473105	1976600	12795680	3644500	14432430
अंशदान	0	3400	0	3400	0	2486	0	3400	0	3400	0	3110	0	3400	0	3500	0	3600
आर्थिक सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एकमुश्त प्रावधान	205190	1200	190190	1200	0	818	179640	1200	336040	1500	0	1381	389700	2000	249700	2000	281200	2000
अन्य प्रभार	105030	38810	101180	67738	105384	47867	189300	53993	189300	51929	118291	51583	140650	57530	167900	76915	162200	57610
अंत लेखा अंतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सूचना और प्रौद्योगिकी	8485	12000	8385	14700	526	13733	8900	13000	4800	16870	6105	16003	5400	31920	5600	28930	7800	31940
केंद्रीय अनुश्रवण सेवाएं	29000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**1848800**	**12069100**	**1771877**	**12100700**	**1757551**	**11876331**	**2876700**	**12100700**	**2770600**	**14250700**	**1733813**	**14421439**	**3519900**	**17680700**	**3166700**	**16000700**	**5154600**	**17542500**

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2007-2008		संशोधित अनुमान 2007-2008		वास्तविक 2007-2008		बजट अनुमान 2008-2009		संशोधित अनुमान 2008-2009		वास्तविक 2008-2009		बजट अनुमान 2009-2010		संशोधित अनुमान 2009-2010		बजट अनुमान 2010-2011	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
पूंजी भाग																		
मशीन और उपस्कर	6700	0	37034	0	33304	0	95300	0	90600	0	110567	0	43200	0	43200	0	75500	0
मुख्य निर्माण कार्य	214100	0	82689	0	82673	0	174000	0	126000	0	20372	0	368000	0	35800	0	550100	0
निवेश	0	0	0	0	0	0	80000	0	100	0	0	0	100	0	100	0	30000	0
ऋण एवं अग्रिम	31000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऋण प्रसार भारती	2174400	0	1667400	0	2107400	0	3264000	0	2616600	0	2383100	0	3558400	0	1302100	0	2274800	0
उत्तर पूर्वी व सिक्किम के लाभ के लिए	475000	0	440000	0	0	0	510000	0	396100	0	0	0	510400	0	199900	0	415000	0
योग	**2901200**	**0**	**2228123**	**0**	**2223377**	**0**	**4123300**	**0**	**3229400**	**0**	**2514039**	**0**	**4480100**	**0**	**1903300**	**0**	**3345400**	**0**
कुल योग	**4750000**	**12069100**	**4000000**	**12100700**	**3980928**	**11876331**	**7000000**	**12100700**	**6000000**	**14250700**	**4247852**	**14421439**	**8000000**	**17680700**	**5070000**	**16000700**	**8500000**	**17542500**

वित्तीय समीक्षा

स्वायत्त संस्थानों के आधार पर वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2007-2008		संशोधित अनुमान 2007-2008		वास्तविक 2007-2008		बजट अनुमान 2008-2009		संशोधित अनुमान 2008-2009		वास्तविक 2008-2009		बजट अनुमान 2009-2010		संशोधित अनुमान 2009-2010		बजट अनुमान 2010-2011	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
बाल फिल्म समिति	27100	4200	27100	8400	26398	8400	40000	8400	40000	9700	40000	9700	40000	11200	40000	17500	40000	14300
भारतीय फिल्म और	62100	70515	62100	82500	61282	82500	80000	77500	56900	93267	54400	93267	60000	95000	95000	129400	80000	125000
टेलीविजन संस्थान पुणे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सत्यजीत रे फिल्म और	77700	50735	37700	60030	37700	60030	80000	50735	80000	52580	40000	52100	70000	60000	70000	60000	70000	60000
टेलीविजन संस्थान कोलकाता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय जनसंचार संस्थान	1000	39500	100	45000	0	44982	10000	39500	100	47994	0	46030	7000	50000	7000	78500	7000	67000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	10000	0	10000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000	0	20000	0
भारतीय प्रेस परिषद	0	23700	0	25500	0	23682	0	26300	0	31604	0	31604	0	35000	0	45600	0	42100
प्रसार भारती	1031300	9607600	1031300	9839100	1191300	9741400	1787571	9636500	1325671	11371225	759600	11429800	2131900	14221400	1754600	12464200	3447500	14123500

उपभोग शेष के समेत विभिन्न निकायों को जारी अनुदान

(रुपये लाख में)

नाम	अवधि में जारी अनुदान				अप्रयुक्त शेष (यदि कोई हो)			
	2007-2008		2008-2009		2007-2008		2008-2009	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
बाल फिल्म समिति	263.98	84.00	380.00	97.00	20.00	शून्य	14.00	शून्य
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	620.00	825.00	528.28	932.67	13.71	शून्य	शून्य	शून्य
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	377.00	600.30	400.00	521.00	90.55	67.53	82.07	शून्य
भारतीय जनसंचार संस्थान	शून्य	423.89	शून्य	452.45	शून्य	10.09	शून्य	0.135
भारतीय प्रेस परिषद	शून्य	236.00	शून्य	316.04	शून्य	0.31	शून्य	0.39
प्रसार भारती	11913.00	97414.00	32013.00	113712.00	शून्य	शून्य	3408.00	शून्य

अध्याय–VI

स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और प्रदर्शन

बाल फिल्म समिति, भारत

अध्याय IV और V में सीएफएसआई के व्यापक वास्तविक तथा वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी दी गई है। उसके अनुसार संगठन का प्रदर्शन संतोषजनक है और सरकार की सीएफएसआई द्वारा जमा की गई रिपोर्ट से सहमति है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

इस संस्थान की स्थापना 1960 में फिल्म निर्माण कला और तकनीक में प्रशिक्षण के लिए की गई थी। 1974 से इसने दूरदर्शन कर्मचारियों को फिल्म निर्माण में प्रशिक्षित करने का काम शुरू किया और इसका नाम भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। यह अपने ढंग का अग्रणी संस्थान है और फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए है।

संस्थान विभिन्न विषयों जैसे निर्देशन, सिनेमाटोग्राफी, संपादन, आडियोग्राफी में फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा; अभिनय, कला निर्देशन एवं प्रोडक्शन डिजाइन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रम; एनीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रमाणपत्र के लिए डेढ़ वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम; निर्देशन, इलेक्ट्रानिक सिनेमाटोग्राफी, वीडियो संपादन, आडियोग्राफी एवं टी.वी. इंजीनियरी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम तथा फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चला रहा है। कार्यरत पेशेवरों और इस क्षेत्र में रूचि रखने वालों के लिए एफटीआईआई लघु पाठ्यक्रम चलाता है।

इस समय संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 337 विद्यार्थी हैं। संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इससे पता चलता है कि यह पाठ्यक्रम समाज द्वारा सराहे जा रहे हैं। इस संस्थान से निकले बहुत से छात्र सिनेमा क्षेत्र में काफी अच्छा कर रहे हैं। छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्में देश और विदेश दोनों जगह के महोत्सव में गई हैं। इन वर्षों के दौरान डिप्लोमा फिल्मों का एक विशाल संग्रह बन गया है, इनमें से कई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

1. श्री ऑफ अस (उमेश कुलकर्णी)-प्रथम पुरस्कार (मानसिक रूप से अक्षम वर्ग), 6वा प्रतिस्पर्धी वी केयर फिल्म फेस्ट 2009, नई दिल्ली।

2. उधेड़ बुन (सिद्धार्थ सिन्हा) श्रेष्ठ लघु कथा-निर्देशक तथा निर्माता को रजत कमल तथा नकद पुरस्कार।

3. आदमी की औरत अन्य कहानियां (अमित दत्ता)-66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, हॉरिजन (औरिज़ोंटी खंड) प्रतियोगी खंड में विशेष उल्लेख।

4. क्रमश:-श्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी (सविता सिंह) रजत कमल तथा नकद पुरस्कार।

   श्रेष्ठ ऑडियोग्राफी (अजीत सिंह राठौर) रजत कमल तथा नकद पुरस्कार

5. नरमीन (निर्देशक - दीप्ति गोगना) - 'बॉलीवुड एंड बियोंड' भारतीय फिल्म महोत्सव, स्टुटगार्ट, जर्मनी 2009 में श्रेष्ठ लघु फिल्म पुरस्कार। लॉन्स एंजेल्स के 7वें वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में श्रेष्ठ लघु कथा का जूरी पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव सलेंटो फिनिबस टेरेइन, इटली के 7वें संस्करण में 'चिल्ड्रेन वर्ल्ड' खंड के लिए जूरी का विशेष उल्लेख पुरस्कार।

इसके स्थायित्व, प्रशिक्षण सुविधाओं और वातावरण के उन्नयन के लिए अनुदान, सहायता के माध्यम से भारत सरकार वित्तीय सहयोग प्रदान करती है स्कीम के तहत संस्थान फिल्म एवं टीवी पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक मशीनरीं, उपकरण तथा पुर्जे प्राप्त कर रहा है। चिह्नित सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का उन्नयन हो गया है। विभिन्न कार्यक्षेत्रों में संस्थान स्टाफ तथा संकाय के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

फिल्म तथा टेलीविजन कार्यक्रमों की विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित मानवशक्ति उपलब्ध कराने के मकसद से भारत सरकार ने एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कोलकाता के सत्यजीत राय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना की थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मशहूर फिल्मकार श्री बुद्धदेब दासगुप्ता हैं।

संस्थान, निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्र छायांकन, सम्पादन और ध्वन्यांकन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कराता है।

वर्ष के दौरान विभिन्न फिल्म महोत्सवों में निम्नलिखित छात्र फिल्में चुनी गई हैं:

1.	जाहो-ा (बांज्ला)	सी-ा, प्रथम स्टूडेंट फिल्म समारोह, विलमिंजट-ा, उत्तरी जारोलिंस	ि-ार्देशज : सुदेश-ाा बोस
2.	बाघेर बच्चा	मेक्सिज्ो अंत. फिल्म समारोह और मोंटेरेडी अंत. फिल्म समारोह 2008, मैक्सिज्ो जे प्रतियोजी जंड में चर्या-ात	ि-ार्देशज : विष्जुदेव हलदर
3.	लाल जूतो	संघाई फिल्म समारोह में बेस्ट ज्रिएटिव आइडिया से पुरस्ज्ृत	ि-ार्देशज : स्वेता मर्चेंट
4.	सोलिडेरिटी (अंज्रेजी)	छठे ज्ल्पा-ार्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु ज्था फिल्म महोत्सव 2008 में प्रदर्श-ा जे लिए चु-ाव तथा भाजीदारी प्रमाजपत्र प्राप्त	ि-ार्देशज : मोहम्मद शज्ील
5.	माया (हिंदी)	छठे ज्ल्पा-ार्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु ज्था फिल्म महोत्सव 2008 में प्रदर्श-ा जे लिए चु-ाव तथा भाजीदारी प्रमाजपत्र प्राप्त	ि-ार्देशज : मोहम्मद शज्ील
6.	राजे हरी बंचे रबी (बांज्ला)	छठे ज्ल्पा-ार्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु ज्था फिल्म महोत्सव 2008 में प्रदर्श-ा जे लिए चु-ाव तथा भाजीदारी प्रमाजपत्र प्राप्त	ि-ार्देशज : ज्ोरज मुर्मू
27.	अंतिम अध्याय (बांज्ला)	छठे ज्ल्पा-ार्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु ज्था फिल्म महोत्सव 2008 में प्रदर्श-ा जे लिए चु-ाव तथा भाजीदारी प्रमाजपत्र प्राप्त	ि-ार्देशज : टी. माधवी
28.	मोरिचिज्ा (बांज्ला)	38वें छात्र फिल्म महोत्सव, सेसुटे, जर्म-ाी में चय-ा	ि-ार्देशज श्री-ाथ रजुलापल्ली

वर्ष 2008-09 के दौरान गैर योजना खर्च 545.84 लाख रुपये था। इसमें 405.82 लाख रुपये वास्तविक रूप से प्राप्त हुए हैं।

कुल अनुदान 400.00 लाख रुपये में से वर्ष के दौरान 309.45 लाख रुपये प्राप्त हुए। 2008-09 के दौरान 317.93 लाख रुपये खर्च किए गए है, बाकी 82.07 लाख रुपयों का उपयोग नहीं हुआ है।

संस्थान के कार्य की निगरानी सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट विवरण के प्रकाश में संस्थान का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है।

भारतीय जन संचार संस्थान

जन संचार में प्रशिक्षण, शिक्षण और शोध के संबंध में आई आई एम सी का प्रदर्शन उच्च कोटि का रहा है। आई आई एम सी सरकार सेना और अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यों को आयोजित करने में पर्याप्त रूप से सफल रहा है। विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से ली गई शोध परियोजनाओं में भी आई आई एम सी ने सराहनीय प्रदर्शन किया है।

आई आई एम सी ने योजना स्कीम के तहत खुद को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया विश्वविद्यालय में रूपांतरण के लिए भी फलदायी कदम उठाए हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए. पहले चरण में आई आई एम सी ने मीडिया उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पत्रकारिता व जन संचार के एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स को दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में बदलने जा रही है जिससे इस कोर्स को मास्टर्स के समतुल्य बनाया जा सके।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद विधि द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। मंत्रालय में व्यय सुधार समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते समय यह महसूस किया गया कि भारतीय प्रेस परिषद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो कि प्रेस की एक स्वनियामक संस्था है, ऐसी समीक्षा न तो उपयुक्त होगी और ना ही उसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए कोई अन्य निगरानी संस्था उपलब्ध है। उक्त निर्णय की जानकारी वित्त मंत्रालय को भी दे दे गयी।

तथापि, प्रेस परिषद के कार्य की समीक्षा संसद द्वारा सीधे उसके समक्ष प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के द्वारा की जाती है।

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। देश के लोगों को जानकारी देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के साथ ही प्रसारण का एक संतुलित विकास सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं आयोजित करने और उन्हें संचालित करने के अधिदेश के साथ 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती की स्थापना की गई।

प्रसार भारती द्वारा वर्ष 2008-09 के दौरान तथा वर्ष 2009-10 तक वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन संबंधी उपलब्धियों का वर्णन अध्याय- IV में दिया गया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार संगठन का कार्य निष्पादन संतोषजनक है और आकाशवाणी की ओर से पेश की गई रिपोर्ट से सरकार सहमत है।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश में सार्वजनिक सेवा प्रसारणकर्ता है तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रसार भारती 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। आम जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा की व्यवस्था करने का प्रसार भारती को अधिकार है। प्रसार भारती पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है।